Fifth Series, Vol. IV, No. 23

Wednesday, June 23, 1971
Asadha 2, 1893 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

Second Session
(Fifth Lok Sabha)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

Price: Re. 1.00

CONTENTS

No. 23—Wednesday, June 23, 1971/Asadha 2, 1893 (Saka)

	Columns
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 662, 664, 668, 670, 674, 676, 678, 679, 684 and 685. ...	1—28
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 661, 663, 665, 666, 671 to 673, 675, 678, 680 to 683 and 686 to 690.	28—39
Unstarred Questions Nos. 2848 to 2850, 2852 to 2872, 2874 to 2910, 2912 to 2925, 2927 to 2963, 2965 to 2973 and 2975 to 2980.	39—133
Calling Attention to matter of Urgent Public Importance—	
Reported Unilateral Action of the Government of Ceylon in Changing the basis for the Grant of Ceylon Citizenship	133—40
Re: Visit of Minister of External Affairs to certain countries	140—43
Question of Privilege against the Editor of *U. K. Kyrwoh Ka Rilum*, Shillong	143—45
Papers Laid on the Table	145—48
Statement re: Railway Accident at Varanasi	148—49
Message from Rajya Sabha	149—50
Demands for Grants, 1971-72—	
Ministry of Home Affairs	150—274
Shri Shankarrao Savant	150—54
Shri Chandrika Prasad	154—60
Dr. Kailas	160—65
Shri M. Satyanarayan Rao	165—66
Shri N. Tombi Singh	167—70
Shrimati Subhadra Joshi	170—77
Shri Biren Dutta	177—79
Shri K. Suryanarayana	179—82
Shri P. K. Deo	182—87
Shri Vekaria	187—90
Shri M. G. Ulkey	190—97

*The sign marked + above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	Columns
Shri Birender Singh Rao	197—200
Dr. Melkote	200—02
Shri Mohammed Tahir	202—12
Shri Shivnath Singh	213—18
Prof. Madhu Dandavate	218—23
Shri M. Ram Gopal Reddy	223—28
Shri N. K. Sharma	228—33
Shri Frank Anthony	233—39
Shri Shashi Bhushan	239—45
Shri M. C. Daga	245—51
Shri Ramavatar Shastri	251—56
Shri Ram Dhan	256—64
Prof. S. L. Saksena	264—66
Shri D. N. Tiwary	266—74
Shri D. Basumatari	274

LOK SABHA

Wednesday, June 23, 1971/Asadha 2, 1893 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Mr. Speaker *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के साथ परामर्श

*662. श्री राम चन्द्र विकल : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध मे जिन विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया है, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) कृषि के सम्बन्ध में किन विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अलग-अलग दो सूचियां, एक जिसमें उन विशेषज्ञों के नाम दिए गए हैं जिनका परामर्श योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में लिया है और दूसरी जिसमें उन विशेषज्ञों के नाम दिए गए हैं जिनसे परामर्श इस समय किये जा रहे चौथी योजना के मूल्यांकन में अभी तक लिया जा चुका है ; सभा पटल पर प्रस्तुत हैं। [ग्रन्थालय में रख दी गई। देखिये संख्या LT—503/71]

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में जिन कृषि विशेषज्ञों का परामर्श लिया गया था उनके नाम सभा पटल पर रखी गई सूची (क) और (ख) में दिये गए हैं। [ग्रन्थालय में रख दी गई। देखिये संख्या LT—503/71]

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना को 1970 के आरम्भ में अन्तिम रूप दिया गया था और उसका प्रकाशित प्रपत्र मई, 1970 में सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था। चौथी योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

श्री राम चन्द्र विकल : योजना का जो मूल्यांकन किया जाना अभी बाकी है, उसको अन्तिम रूप कब तक आप दे देंगे ?

योजना को पहले प्रारम्भिक रूप में बनाया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में विशेष कौन सा अन्तर हैं ? क्या कुछ योजनाए रोक दी जाती हैं और कुछ नई ले ली जाती हैं हाथ में ?

श्री मोहन धारिया : चौथी पंचवर्षीय योजना जो सभा पटल पर दी गई है वह पूरी योजना ही हैं। लेकिन दो साल बीत जाने के बाद हमने जो हाथ में योजना ली है, उसमें से कौन से कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं, कौन से नहीं हुये हैं और हमने जो लोगों के साथ वायदा किया है, उसको पूरा करने के लिए कौन से बदल होने चाहियें, इस बारे में हम जो उनके विचार या परामर्श ले रहे हैं, जिस वक्त वह हो जाएगा, वह योजना का मूल्यांकन होगा। यही फर्क है।

श्री रामचन्द्र विकल : योजना के प्रारम्भिक

रूप में देखा गया है कि अधिकांश योजनायें सर्वे करके छोड़ दी जाती हैं। साथ ही कुछ और योजनाओं को कुछ चला कर छोड़ दिया जाता है। इससे देश को बड़ी आर्थिक हानि होती है। इसका कारण यह होता है कि योजना आयोग के सदस्य और अर्थ शास्त्री समय-समय पर बदलते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री राम चन्द्र विकल : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। योजना आयोग के सदस्यों और विशेषज्ञों की सलाह पहले ली गई थी, थोड़े दिन के बाद उनको बदल दिया गया और जो बाद में आए उनसे ली गई। फिर उनको भी बदल दिया गया और उसके बाद तीसरों से ली गई। इस बदला बदली का अर्थ यह होता है कि हमारी योजना जो पहले चालू की गई थी उसको फिर से बदल दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई स्थायी योजना आयोग बनाने का विचार कर रहे हैं और व्यावहारिक ज्ञान वाले लोगों के द्वारा योजनायें बनवाने का विचार रखते हैं?

श्री मोहन धारिया : योजना का काम तो हमेशा चालू रहता है। कुछ मान्य सिद्धान्तों के अनुसार ही योजना बनाने का काम होता है। इस वास्ते शुरू में उसमें कुछ परिवर्तन भी कर दिये जाते हैं। लेकिन जब योजना बन जाए तो उसको इम्प्लेमेंट करने में हमारी पूरी ताकत लगनी चाहिये। उस रीति से हमने पूरी ताकत नहीं लगाई और कुछ दिक्कत आई। लेकिन फिर भी मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज जो हमारे सामने सवाल हैं, जो समस्यायें हैं, उनको हल करने की दृष्टि से जिस तरह के कार्यक्रम हाथ में लेने चाहियें, ऐसे कार्यक्रम हाथ में जरूर लिए जायेंगे।

श्री जी० पी० मौर्य : अब तक योजना का तरीका यह रहा है कि वे शहरों से चलती थीं और देहातों तक पहुंचते-पहुंचते कुछ नहीं रह जाता था। अब आप इसको क्या उलटा करेंगे? क्या देहात से आप इनको शुरू करेंगे? आज भी देश में ऐसे लाखों गांव हैं जिनमें पीने तक का पानी नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब देहातों से शुरू करके योजनायें शहरों तक जायें, क्या इसको आप करेंगे?

SHRI MOHAN DHARIA : The House would have observed that when the Fourth plan was formulated, old pattern was changed. Now we have adopted district planning and the Fourth plan is based on district plans as they come from below.

श्री भान सिंह भौरा : जो एग्रिकलचरल लेबर है, जो लैंड-लैस पैजेंट हैं, उनके वास्ते क्या आप प्लान में कोई स्पेशल एलोकेशन करेंगे? उनकी अच्छी तरह से तरक्की हो सके, क्या इसके लिए आप कोई प्राविजन करेंगे? पहले एग्रिकलचरल की तरफ तो ध्यान दिया गया है लेकिन एग्रिकलचरल लेबर की तरफ, लैंडलैस पैजेंट्स की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है।

SHRI MOHAN DHARIA : It is true that agricultural labourers have been neglected and it is high time that land reforms are implemented as suggested by the Planning Commission long time back. While making the appraisal of the Fourth plan, it shall be our endeavour to see that the landless labourers and the working millions do get their proper share in planning.

डा० गोविन्द दास रिछारिया : उत्तर प्रदेश की आबादी सम्पूर्ण देश की आबादी का 17 प्रतिशत है। चौथी योजना को अन्तिम रूप देने से पहले क्या आपने यह निर्णय कर लिया है और इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है कि जो रुपया बंटेगा, वह आबादी के लिहाज से बांटा जायेगा?

SHRI MOHAN DHARIA : The National Development Council has given some guidelines on the pattern of the Central

Assistance to the States. Government have accepted those guidelines, according to which 60 per cent of the Central Assistance is distributed on the basis of their population.

Shifting of Telecommunications Channels from Calcutta to Bombay and setting up of Second Satellite Ground Station for International Telecommunication near Delhi

*664. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether certain international telecommunication channels, operating between Calcutta; on one hand, and Australia, Hongkong and Japan, on the other have been recently been shifted from Calcutta to Bombay ;

(b) if so, the reasons for such shifting ;

(c) whether the second satellite ground station is going to be set up near Delhi for international telecommunication service ; and

(d) if so, the reasons why the superior commercial, political, geographical, metereological and other claims of Calcutta in this regard are being over-looked ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (d). A statement giving the information required is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b). Only overseas traffic being carried through the Satellite Communications Ground Station at Arvi is now being routed *via* Bombay. Other overseas traffic from the Calcutta area continues to be handled by the Calcutta Station of the Overseas Communications Service. The traffic has been shifted to satellite system in order to make available reliable and better quality service to the public.

(c) and (d). Yes. It has been decided to set up a second Satellite Ground Station in the northern region during the Fourth Five Year Plan. This decision is based on traffic considerations, as Delhi region ranks next to Bombay region in over-all range of public international telecommunication traffic.

SHRI INDRAJIT GUPTA : In regard to this satellite communication service, is it not a fact that the existing line being very old and subject to frequent breakdown due to heavy rainfall or cyclonic conditions, the traffic to and from Calcutta has to be routed through Bombay now and is also frequently disrupted and this causes great inconvenience to the public, to business, to trade and commerce and so on ? Therefore, is it not desirable that the link up with the satellite communication system should not be only through the station at Arvi but regional ground centres should be set up and Calcutta should have an independent ground station ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : The proposal to set up a ground station near Calcutta is already under consideration. Delhi and Calcutta are the two places which are on the list. Delhi having a higher traffic than Calcutta was preferred first and the second ground station is coming in Delhi. Bombay had the highest traffic and it was chosen first. Next comes Delhi. The third ground is proposed to be put up somewhere in Calcutta when funds are available.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Is it not a fact that before even the Bombay station was set up the foreign experts who were consulted in this matter had adjudged an area near Assansol near West Bengal, to be the best site for the first earth station and is it not a fact that they have suggested this because Calcutta is the country's main centre for expert trade, which has the busiest international air routes, and the whole of South East Asian and Japanese traffic is picked up for the eastern region ? Why is it that this expert advice was ignored and Bombay was given preference first and even now when the second station is to be set up the claims of Calcutta are being ignored ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : So far as the expert opinion referred to by my hon. friend, Shri Indrajit Gupta, is concerned, I am sorry to say that I am not aware of that particular advice. But the facts on record show that Bombay has the highest international traffic in terms of the entire telecommunication range-telephone, telex, telegram and so on and so forth. Thereafter

comes Delhi and Calcutta is the third. Therefore, we have chosen two to put up two centres in the Second Plan itself. But in view of the paucity of funds it was not possible to choose both of them. Delhi is a place where we have these embassies and the traffic is of a very high order. So, we have preferred Delhi first. It is a question of preference and not ignoring.

SHRI SANJEEVI RAO : Are Government taking advantage of the advanced technology of satellite ground station for telecommunication system as such ? What are the effective steps the Government are taking for utilising satellite channels for television as in the case of advanced countries such as United States, Soviet Union and Swedan ?

MR. SPEAKER : This is a very specific question about Calcutta. We cannot have a general discussion on this. He can discuss it when the relevant demands come up.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the hon. Minister kindly tell us if he has received a detailed memorandum from the employees of the Ovearseas Communication Service, Calcutta, giving their technical views on the location of the telecommunication service in India and, if so, what is it and what action has been taken on that ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : The question of setting up a ratellite centre near Calcutta has not yet been finalised. Therefore all sorts of views are before the government. At the appropriate time all these views, including those of my hon. friend, Shri Jyotirmoy Bosu, will be taken into consideration.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : I asked a specific question whether he has received a detailed memorandum from the employees of the Overseas Communication Service.

SHRI H. N. BAHUGUNA : I am not aware of any such memorandum.

Anandpur Barrage Project

*666. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of PLANNING be pleased to state the difficulty on the part of the Planning Commission to approve the Anandpur Barrage Project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : It has not been possible to approve the Anandpur Barrage Project for inclusion in the Fourth Plan of the State since the requisite resources are not in sight to take up the work at present.

SHRI ARJUN SETHI : I want to know whether Salandi Project was considered as an integrated one along with Anandpur Barrage Project.

SHRI MOHAN DHARIA : There are several projects in Orissa. This problem was examined by the Planning Commission. Even though this project has been technically approved, unfortunately no funds are available and naturally it could not be taken up.

SHRI ARJUN SETHI : Is it not desirable to approve of the Anandpur Barrage Project immediately to have the full benefit from the Salandi Project on which we have already spent a sum of Rs. 1.24 crores for canals, investigation and survey ?

SHRI MOHAN DHARIA : The Anandpur Barrage Project, estimated to cost Rs. 21.94 crores, was cleared by the Technical Advisory Committee. But when they took stock of the situation regarding the availability of funds they came to the conclusion that only Rs. 1.75 crores were availble in the plan of the Orissa State for Irrigation projects. So, three medium schemes in backward areas have already been cleared by the Planning Commission and they have been taken up. Even though this project has been technically approved and it is necessary to take up this project, I am sorry it could not be cleared for want of funds.

SHRI S. S. MOHAPATRA : This Anandpur Barrage Project is an integrated project along with Salandi. Unless this barrage materialises the Salandi Project will be set at nought.

MR. SPEAKER : Perhaps the Minister is already aware of it. Let him ask the question.

SHRI S. S. MOHAPATRA : Could some more funds be diverted so that this project could materialise, because it is an integrated project and it will irrigate more than three lakhs acres of land ?

SHRI MOHAN DHARIA : I entirely share the feelings of the hon. Members. This matter is under constant review. Even at the time of the preparation of the Plan for the year 1971-72 this question was discussed. I can assure the hon. Member that if it is found possible to spare some funds, of course out of the State funds, for this irrigation project we shall be only too happy to have it.

Decline in Export of Tobacco

*669. SHRI VISHWANATH JHUNJHUNWALA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whetner the export of raw tobacco is showing signs of fall during the current year ;

(b) if so, the names of countries where the fall has been noticed particularly ;

(c) whether the Indian tobacco is increasingly becoming less competitive in World market ; and

(d) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government to make the position favourable ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA : May I know whether the government have considered the desirability of utilising flue-cured tobacco, which is increasingly becoming less competitive in the world market, for manufacture of cigarettes in India.

MR. SPEAKER : When the Minister says "No, Sir. Does not arise" how do supplementaries arise ?

SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA : May I know whether the government have finally shelved the idea of forming a tobacco board, on the lines of the Tea Board and, if so, the reasons therefor ?

SHRI L. N. MISHRA : The hon. Member has asked two questions, one about the quality of tobacco and the other about the constitution of the tobacco board. At present we have no proposal to have a tobacco board. Agriculture Ministry do not feel it necessary to have a tobacco board at this stage. Then, there should be no apprehension that because of the quality our tobacco export is going down. In fact, our tobacco export is going up and it is not going down. While last year our export was to the tune of Rs. 22 crores this year it is Rs. 23 crores. Therefore, there should not be any apprehension on this account. The quality of our tobacco has been good and there has been no downward trend in our exports,

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA—*rose.*

MR. SPEAKER : How is she interested in tobacco ?

SHRIMATI LAKSAMIKHNTHAMMA : Why should you presume that ladies do not smoke ?

May I know whether there is any scope for greater expor. of tobacco to foreign countries ? Since Andhra Pradesh is a major tobacco-producing State it has asked for the establishment of a Tobacco Board in Andhra. Will Government give consideration to this proposal ?

SHRI L. N. MISHRA : As I said earlier, the prospects of the constitution of a tobacco board are not bright.

SOME HON. MEMBERS—*rose,*

MR. SPEAKER : It is not a general question about tobacco. The question is whether the export of raw tobacco is showing signs of a fall and he said, "No."

SHRI JYOTIRMOY BOSU : It is a very important question.

SHRI AMRIT NAHATA : There is an important supplementary about the export of tobacco.

MR. SPEAKER : He says, "No."

SHRI AMRIT NAHATA : There is another aspect. There is a monopoly.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHHMMA : If it is advantageous, why should they not form a board ?

SHRI PRABODH CHANDRA : The Minister in his defence said that export has gone up from Rs. 22 crores to Rs. 23 crores. Is he aware of the fact that of the other exporting countries the export has increased much more as compared with the increase in the export of tobacco from India ? The number of smokers has increased at least by 5 per cent, while the increase in our export is not even 5 per cent.

MR. SPEAKER : With the exception of my community.

SHRI L. N. MISHRA : The question is as to what is the position of our export. Our export in the four or five months of this year has been Rs. 23 crores as against Rs. 22 crores last year. So far as increase in other countries is concerned, it is a fact that we are facing competition from some countries like Thailand. Philippines, Indonesia and Pakistan. New competitors have been coming up. But till now we have been holding on to the market and our position has been improving. Therefore, there should not be apprehension on that account.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, अभी मन्त्री महोदय ने प्रश्नोत्तर के बीच बताया कि हमने निर्यात में काफी प्रगति की है और काफी निर्यात किया है तो यह जो निर्यात किया गया है यह सारा माल उन व्यापारियों के माध्यम से लिया गया है और उन्हें उसका फायदा गया है लेकिन जो उसकी पैदावार करता है उसे उसका मुनाफा ठीक प्रकार से नहीं मिलता है तो उन्हें ठीक प्रकार से उनकी कमाई का मुनाफा मिले उसके लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह आपने पूछ लिया, वैसे यह इससे उठता नहीं है ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Is it not a fact that your raw tobacco export figures have remained more or less constant, meaning that you have failed to export finished goods of tobacco, and is it also not a fact that the export of raw tobacco of the select variety, golden Virginia flue-cured, has remained a monopoly of the Indian Leaf Tobacco Development Company, a subsidiary of Imperial Tobacco Company ; if so, what have you done to break the monopoly there ?

SHRI L. N. MISHRA : Till now the export of tobacco has been in the private sector and we have no intention of canalising it. The hon. Member had made this suggestions in the Consultative Committee also and we had a long discussion on this point. We do not want to dislocate the present channel of export of tobacco.

Setting up of Export Promotion Council for Oil Seeds and Oil-seed Products

*670. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have since taken any decision for the getting up of an Independent Export Promotion Council for oil seeds and oil-seed products as suggested in a commodity survey jointly made by the Bombay University and the Operations Research Group of the Sarabhai Management Corporation, Baroda ; and

(b) if so, the nature of the decision taken in the matter ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) and (b). Yes, Sir. The Government have decided to set up an Export Promotion Council for Oil-seeds, Oils and Oil-cakes and steps have already been taken towards this end.

SHRI K. LAKKAPPA : I would like to know whether the Export Promotion Council consists of all experts in the matter of promotion of exports of oilseeds and oil-seed products in this country.

SHRI L. N. MISHRA : It will not consist only of experts but there will be representatives of trade, importers and also the main producers and Government representatives.

SHRI K. LAKKAPPA : I want to know whether the Government of India has taken stock of the situation in this country for promotion of exports.

SHRI L. N. MISHRA : The committee has recently been set up. So far as export is concerned, export has shown encouraging figures. But there is no availability of oilcakes in the quantity we want. Maharashtra, where we could get them in plenty, is short of oilcakes. But even in that situation exports have been improving.

Crisis in Film Industry due to Scarcity of Raw Film

*674. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Film Industry in India is facing a serious crisis due to the inadequate institutional financing and scarcity of raw film ; and

(b) if so, the steps taken by Government to solve this crisis ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) The problems of our film industry include the lack of adequate institutional financing and the occassional scarcity of raw film.

(b) Government have set up the Film Finance Corporation Limited to meet the shortage of institutional financing at reasonable rates of interest. This is a public undertaking which of late has been financing the production of comparatively low-budget and purposeful films of high artistic merit. Government have recently augmented the resources of the Corporation and propose to place additional funds at its disposal during the current and subsequent years.

A factory has been set up in the public sector for the production of raw black and white film. Whenever there have been temporary shortages of such films, Government have imported sizeable quantities of such films through State Trading Corporation.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : May I ask what was the total amount sought by applications for film finance during the last year and how much did you actually give ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : Actually we have Rs. 1.32 crores. That is the budget of Film Finance Corporation. It is a fact we get a number of applications but it is not possible to meet those demands of the people who ask for the money. But again, as I have already mentioned in my answer, the purpose of the Film Finance Corporation is to finance those films which are of high artistic quality. So, it is not for the Film Finance Corporation to finance all the films or any one who wants to make films.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : What is the applied amount and how much you actually gave ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : This figures is not available with me now but I will give it later.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : About the raw-material production, as I understand, the requirement of negative film is in the region of 18 million feet a year and for the positive it is about 4.57 lakh feet a year. In view of the failure on the part of the public sector project at Ootacumand to give the required quantity of raw-material to the film industry what specific steps the Government proposes to take to save it from ruination.

Secondly, Mr. Sinha had assured that he will set up a chain of cinemas in the public Sector. What have you none in regard to that ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : Sir, it is a fact that there was shortage of raw film, that is, black and white positive film. The import of black and while positive film is not normally allowed in view of the indigenous production as has been mentioned by the hon. Member. But due to the shortage of film we have allowed import of the black and white positive film and met the demand of the film industry.

SHRI D. N. TIWARY : May I know what is the criteria of a high quality a film or a film with intrinsic qualifications because the applicants who go for finance are harrassed on this norm ? Can you tell me what criteria has been laid down and what steps are taken to see that people are not harrassed ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : I do not agree with the hon. Member that the people are being harassed by the Film Finance Corporation. As I have already mentioned, the resources of the Film Finance Corporation are limited. It is not possible to meet the demand of all people who apply for finance. To decide about the artistic merit of the film, there is an expert committee and there are a number of committees which go through the script the treatment and other things of the film. They examine the whole thing and then decide it.

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी सूची है कि वित्त के बिना या जिन साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे रा-मैटीरियल, उन के बिना कितने चित्र अभी अधूरे पड़े हैं ?

MR. SPEAKER : It need not be answered because that is not a relevant question.

SHRI G. VISWANATHAN : In view of the shortage of films in the country and in view of the import of raw films from foreign countries involving foreign exchange, may I know from the hon. Minister whether the capacity of the Hindustan Photo films will be increased so that we become self-sufficient in raw films and may I know when we will achieve self-aufficiency ?

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : It is not the question of increasing the capacity of Hindustan Photo Films. Actually, these are temporary shortages in production and they are trying to meet the shortages. They are also trying to improve the quality of films.

SHRI AMRIT NAHATA : The production of black and white films in our country has gone down considerably. About 85 per cent of films that are produced in the country are colour films. We do not manufacture raw colour films in our country and immense foreign exchange is being spent over the import of raw colour films. The quality of positive black and white films that are produced in our country is good but the black and white negative is of low quality. Will the Government consider improving the quality of black and white negative in our country and also will the Government consider setting up of a plant for the manufacture of colour films.

MR. SPEAKER : The question is about financing.

SHRI N. K. SANGHI : There is no doubt that there is a very serious crisis in the film industry. More than 300 films are lying on the shelf for want of finance and raw materials. The hon. Minister just now said that the Film Finance Corporation is not in a position to give adequate finance for the production of films. May I know from the hon. Minister whether she will move the Government to recognise film industry as an industry and also move the Government to give financial aid to the film industry so that they can also survive and feel that they are a part of the country and they get out of the crisis. The Hindustan Photo Films has been closed for more than six months. That is the reason why raw material is not available in the country. I would like to know what steps Government are taking in the matter.

MR. SPEAKER : It is not a question but a suggestion.

अखबारी कागज के आयात के बारे में भारत-रूस करार

*676. श्री राजावतार शास्त्री : क्या विदेश-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूस के साथ अखबारी कागज के आयात के सम्बन्ध में करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल०एन०मिश्र): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय राज्य व्यापार निगम ने सोवियत संघ से 40,000 मी० टन अखबारी कागज का भारत में आयात करने के लिये 21 मई, 1971 को मैसर्स एक्सपोर्टल्स, मास्को के साथ एक संविदा की है। माल की सुपुर्दगी जुलाई, 1971 से अप्रैल, 1972 तक की अवधि के दौरान की जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ 40 हजार टन अखबारी कागज मंगाने का जो समझौता हुआ है क्या इसके पीछे कोई शर्त भी है, यदि है तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस तरह की संधियों में जो शर्तें होती हैं, वे इस में भी हैं, जैसे रुपयों में पेमेंट होगा। 1971-72 का जो समझौता व्यापार के बारे में रूस के साथ हुआ है, यह समझौता उसी का एक अंग है। इस किस्म के समझौतों में जो शर्तें होती है, वे ही इस में हैं—डैफर्ड पेमेंट होगा, धीरे-धीरे कीमत देनी है, उसके बदले में माल लेना है। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि दिसम्बर, 1970 में हमने वह करारनामा सभा-पटल पर रखा था।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या सोवियत संघ के अलावा भी कुछ मुल्कों से अखबारी कागज का आयात करते हैं ? अगर करते हैं तो कितना और उन मुल्कों के नाम क्या हैं ? क्या विभिन्न मुल्कों की कीमतों में कोई फर्क हैं ? अगर फर्क है तो उस का ब्यौरा क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मुल्क तो बहुत से हैं—जैसे कैनाडा, जैकोस्लावेकिया, फिनलैंड, वैस्ट जर्मनी, नार्वे, पोलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यू०एस०ए० और यू०एस०एस०आर०—हम इन मुल्कों से अखबारी कागज मंगाते हैं। जहां तक रूस का सवाल है—जितना माल हम मंगाते हैं उसका 31 प्रतिशत रूस से मंगाते हैं। कीमतों के बारे में यहां बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न देशों से विभिन्न कीमतों पर मंगाते हैं और उनका बताना देश के हित में नहीं होगा।

SHRI S. M. BANERJEE : I would like to know whether one of the conditions of the import of newspint from the Soviet Union is that this newsprint will not go to those who preach communalism or provincialism in their newspapers. Is this one of the conditions ?

SHRI L. N. MISHRA : There are no such conditions and we will not accept any such conditions in any trade agreement.

श्री फूल चन्द्र वर्मा : रूस से जो अखबारी कागज हम मंगाते हैं—क्या यह सत्य नहीं है की अन्य देशों से जो अखबारी कागज आता है, उनकी कीमत से रूस की कीमत अधिक है, उस के बावजूद भी हम उनसे खरीदते हैं ?

क्या यह सत्य नहीं है कि जो अखबारी कागज हमारे यहां आता है, वह ऐसे अखबारों या समाचार-पत्रों को दिया जाता है, जो देश विरोधी प्रचार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं को अधिक कागज दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो समझौते के बारे में था।

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक कीमत की बात है में पहले बता चुका हूं कि किस देश से किस कीमत पर लिया जाता है, यह बताना देश के हित में नहीं है, इससे हमारी नेगोशियेटिंग कैपेसिटी पर असर पड़ेगा। जहां तक अखबारों को कागज देने का सवाल है, सब कागजों को पूल कर दिया जाता है और फिर इन्फर्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री उस का बटवारा करती है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि किस देश का कागज किस अखबार को जाना चाहिये।

Ban by Ceylon Government on Import of Indian Onions

*677. SHRI S. A. MURUGANANTHAM :
SHRI M. KALYANASUNDARAM :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Ceylon Government has imposed a ban on the import of onions through the National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India ;

(b) if so, the grounds on which the Ceylon Government has imposed the ban ; and

(c) the steps taken to ensure export of onions to Ceylon without interruption ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) The Ceylon Government imposed a ban on the import of Bombay onions and have a put a price ceiling per ton on import of Red onions ;

(b) The exact reasons for the imposition of ban are not known to us ;

(c) The Government propose to discuss the matter further with the Ceylon Government.

SHRI M KALYANSUNDARAM : According to my information, the ban has been there for over three months now. I wish our young Deputy Minister here was more energetic to get full information. Is our high Commission in Colombo functioning or not ? Is the Government aware that the Foreign Trade Minister in Colombo had stated or had made allegations against our Government that our Government was trying to canalise the export of onions from India for imposing higher prices and that was the reason for banning ? Is it so ? And what action our Government propose to take in this regard ?

SHRI A. C. GEORGE : Sir, our information is this. The Ceylon Government put a ban on 9th of June. This was the information conveyed to us.

AN HON. MEMBER : Your information is wrong.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : What is your personal information ?

SHRI A. C. GEORGE : Regarding the export of onions I may inform the House that actually the import of onions to Ceylon was canalised at least 3 years back. But due to the unhealthy competition and irritants put against our own small exporters, there was a feeling that it is high time that we canalise our exports and, as per that feeling, on the 10th of March we decided to canalise. The high Commissioner of Ceylon met us and discussed about this matter. It was made plain to him that even now we are ready to discuss any outstanding problems and if there are any things which we could solve from our angle, we will be only too happy to do that.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : Whatever may be the reasons that the Ceylon Government may be saying outwardly, is it a fact, or, has the Government any information, that this so-called ban is due to their foreign currency difficulties and if so will the Government extend a helping hand by making some other accommodations ?

SHRI A. C. GEORGE : It is for the Cylon Government to approach us regarding this matter. We have made it plain on more than two occasions that we will be too glad to discuss any problems regarding this matter.

SHRI K. LAKKAPPA : Large procurement has been made by the Marketing Federation of India of onions. Because of this ban of all imports of onions by Ceylon, there has been very much of damage caused to the procured onions in the country. I would like to know the loss which has been caused to the Cooperative Federation in this country in regard to this transaction of export of onions. What steps are the Government of India going to take to meet the situation in this respect ?

SHRI A. C. GEORGE : The small traders themselves have come forward with a suggestion that they will be only too happy to welcome the canalisation and the only suggestion they have put forward is that in regard to canalisation, if the quota system is implemented, they will be only too happy to operate through the national Federation.

SHRI K. LAKKAPPA : This Marketing Federation of India has procured onions for export into Ceylon. As a consequence of this but great damage has been caused. I want to know to what extent this damage has been caused. Why has this Government not been encouraging the export through cooperative basis ?

MR. SPEAKER : Mr. Lakkappa, this is about export to Ceylon, not preservation of onions. You can ask from the other Ministry.

SHRI K. LAKKAPPA : As a consequence of this ban by Ceylon Government, there has been damage in respect of the procurement made by the Marketing Society of India. So, I want to know as to what the extent of damage is. Some small exporters are in clique with Ceylon Government and therefore they are encouraging this cooperative federation.

MR. SPEAKER : This is about export. So far as damage is concerned, that is a difference matter. Please sit down.

SHRI K. LAKKAPPA ; We have not received any such complaint so far.

MR. SPEAKER ; You must also know how to preserve onions.

श्री काले : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक तो यह जानना चाहता हूं कि बाहर न जाने की वजह से कितना नुक्सान हुआ है और दूसरे जो कच्चा माल पकता है उसको पाइदार करने के लिए सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ?

SHRI A. C. GEORGE : We have no such scheme.

SHRI G. VISHWANATHAN : It is unfortunate that our Government has not taken any initiative in this matter of export of onions to Ceylon. It was the High Commissioner of Ceylon who has taken the initiative. I want to know whether some Indian merchants have offered to sell below the price fixed by the Ceylon Government. What initiative is the Government going to take in this matter ?

SHRI A. C. GEORGE ; It is not correct to say that we have not taken initiative in this matter. When the Ceylon High Commissioner met us, it was made to plain to him that if only he sent their Food Commissioner over here, all outstanding problems could be discussed and thrashed out.

Publication of Book Entitled "The Chinese Betrayal" by Former I. B. Chief

*679. SHRI TRIDIB CHAUDHURI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the book entitled "The Chinese Betrayal" written by Shri B. N. Malik, a former I. B. Chief ; and

(b) whether Shri B. N. Malik obtained the permission or approval of Government in regard to the publication of the book dealing with internal and external security intelligence and defence intelligence services of the Union Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHSIN) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

SHRI TRIDIB CHAUDHURI : The answer given by the hon. Minister to part (a) of the question is 'Yes', that means that their attention has been drawn to this book ; the answer given to part (b) is 'No' ; this means that no prior permission or approval was sought.

I would like to read out to the hon. Minister the very first line or the very first sentence of this book by the former Intelligence Bureau Chief, Government of India. It reads thus ;

> "The encouragement to write this book first came from Shri Y. B. Chavan, then India's Defence Minister. Shri Chavan was rather concerned at some unjust and informed criticisms that were being levelled at Government's handling..."

Shri Y. B. Chavan was certainly free to ask the military intelligence or the Chief of the Intelligence Bureau to write this book. But I would have thought that when no less a person that Shri Y. B. Chavan who was then India's Defence Minister, who had

also been the Home Minister and who is now the Finance Minister, encourage a retired official of such an important department as the Intelligence Bureau to write a book, it should be presumed at least by outsiders that this book had the approval of the Government of India. The reason for my saying this is this. This book has already become controversial. Government, of course, may be perfectly justified in hearing no evil, in seeing no evil and speaking no evil. The reply to the question in monosyllables like 'Yes' and 'No' seems to be very intelligent. But this book has already become very controversial. Instead of serving the purpose which Shri Y. B. Chavan had in view, this book has in my view and in the view of very competent readers, rendered the entire Government of India, our late Prime Minister and the functioning of the entire Government and its intelligence system a laughing-stock. May I know why this book was not read earlier and why no approval was sought ?

SHRI MOHSIN : It is true that in this book, Shri Malik has traced the development leading to the India-China conflict in 1962 and he has given an account of the conflict and has analysed the causes that led to India's reverses in the conflict. The book also describes at length the organisation and functioning of the intelligence services in the country, and some of the contents of this book are such as would warrant further consideration as to whether action under the Official Secrets Act could be initiated. The matter is at present under consideration of Government. But under the present rules, only persons who are in service are to take the permission of Government if they are to publish certain books. But there are no rules as such today requiring persons who have retired to take permission for writing such books.

SHRI TRIDIB CHAUDHURI : When this book was really written, as claimed by the author, at the encouragement of one of the important and senior Cabinet Ministers, was it at any time discussed at the highest level, because apart from the functioning of the Intelligence Bureau, it reveals so many things and in such a way that I do not know how and why this man should have been put in charge of our intelligence service ?

SHRI MOHSIN : Yes, Government are aware of the contents of the book. I have already pointed out the main features of the book. Whether to take action against this ex-official or not is actually under consideration.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Has this book any adverse effects on our defence and foreign policies ?

MR. SPEAKER : Too big a question—asking for opinion.

SHRI MOHSIN : That is exactly what is under consideration.

SHRI D. N. TIWARY : How many books on the India-China war of 1962 have been written and have military officials and even an ex-Secretary of the Defence Ministry written books on the subject which give a different picture in a different way, whether Shri Malik's attempt was to present the correct picture of the whole thing and enlighten the public so that they may not be led away by the other writings ?

SHRI MOHSIN : There are some books already written. The first was *Untold Story* by Lt. General Kaul then *Himalayan Blunder* by Brig. Dalvi, then *Guilty Men of 1962* by D. R. Mankekar, then *With Two Presidents* by Major C. L. Dutta, ADC to Dr. Rajendra Prasad and Dr. Radhakrishnan ; the last one was by Mr. Maxwell entitled *India's China War*.

Imported Components in T. V. Sets

*684. SHRI K. C. PANDEY ; Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the sources through which Television sets are available in India ;

(b) the portion of imported components in each type of Television set made in India : and

(c) the measures being taken to reduce the portion of foreign exchange ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHSIN) : (a) Television sets manufactured by four firms in India on the basis of know-how developed by Central Electronic

Engineering Research Institute, Pilani, are available.

(b) Import content of the 23"/24" T. V. receiver is Rs. 260 and of the 19" T. V. receiver Rs. 150. A major part of this is for the T. V. picture tube.

(c) The manufacture of T. V. picture tubes has already been established by Bharat Electronics Ltd.; even so, Rs. 60/- in foreign exchange is needed for the glass bulb imported by BEL for making the picture tubes. The manufacture of other important components at present being imported, is to commence shortly. Indigenous manufacture is also contemplated of glass bulbs for the picture tube ; with this import content would come down to 1% to 2% of the cost of the T. V. set.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या टेलीविजन सैट की आवश्यकता शिक्षा और कृषि ज्ञान प्रसार के लिये भी है ? अगर है तो योजना बड़े-बड़े शहरों, जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, के स्थान पर देहातों में कब तक जाने की आशा हम लोग करें ?

SHRI MOHSIN : The Government is aware of the necessity of the television programme even in rural areas. Government have now decided to extend T. V. coverage to Bombay with relay station at Poona, to Calcutta, Madras and Lucknow with relay station at Kanpur, and to Srinagar during the Fourth Plan period. The Srinagar and Bombay stations are expected to go on the air in the middle of 1972.

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : अध्यक्ष महोदय, वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक सांस्कृतिक केन्द्र रहा है, और आज भी है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वाराणसी, इलाहाबाद की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? क्या यहां भी लगाने की कोई योजना है ? अगर है तो कब तक ?

SHRI MOHSIN : It is suggestion for action.

SHRI INDRAJIT GUPTA : The Minister said in his reply that the Central Electronics Engineering Institute at Pilani had developed know-how for these T. V. receivers. In that case, why is the Government continuing to permit foreign firms like Phillips (India) to increase the production of T. V. receivers with imported foreign technical know-how, when our own indigenous know-how has been developed sufficiently ?

SHRI MOHSIN : Till indigenous know-how is completely developed, we may continue to have the foreign technical know-how for some time.

Import of Aluminium through M. M. T. C.

*685. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd. has imported certain E. C. Grade aluminium recently against specific allocations made by Government ;

(b) if so, the landed cost per metric ton of Minerals and Metals Trading Corporation and indenting commission chargeable on its landed price ;

(c) the price per ton demanded by the Corporation ; and

(d) when the material is likely to be released to the industry ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) to (d). A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The M.M.T.C. purchases aluminium from different sources and at different prices, and the price varies accordingly. It would not be desirable to publicise details of the business operations of the Corporation such as the break-up of its prices.

(c) The sale prices per tonne announced by the M. M. T. C. for the current (April-June 1971) quarter are as follows :

(Rs. per tonne)

	For Export Units	For other Actual Users
A. Ingots :		
(1) Based on concessional rate of customs duty.	6370	6460
(2) Based on non-concessional rate of customs duty.	6640	6740
B. Wire Bars :		
(1) Based on concessional rate of customs duty.	6420	6515
(2) Based on non-concessional rate of customs duty.	6695	6795

(d) Sale notes (allocation letters) covering the allotment made by the licensing authorities/Directors of Industries have already been issued in favour of actual users at the aforesaid prices which are valid for the current quarter ending June, 1971.

SHRI D. D. DESAI : The hon. Minister has declined to disclose the landed cost of aluminium. Is it not true that the aluminium was imported by open world tender and the landed cost is not disclosed to the House to hide the nature of the sales contracts ?

SHRI L. N. MISHRA : The MMTC purchases aluminium from various sources at various prices, and in order that there may not be any differentiation between one consumer and another, it will not be in the public interest to give the figures of purchase from different countries.

SHRI D. D. DESAI : May I know whether it is a fact that the MMTC is bringing economic pressure on the electric power conductors and cables manufacturers through the LSTD by threatening to cut the indigenous aluminium allocation and divert aluminium if the industries fail to lift the aluminium at the extortionate price now demanded ?

SHRI L. N. MISHRA : It has been our endeavour to keep the price of consumer goods at a reasonable level and therefore an effort is made to supply raw materials to the manufacturers at economic rates.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छोटे समाचार-पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में वृद्धि

*661. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे समाचार-पत्रों के लिए अखबारी कागज का कोटा बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) अखबारी कागज के कोटे में वृद्धि कब से की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). जी, हां । सरकार की यह नीति रही है कि छोटे समाचार-पत्रों के अखबारी कागज के कोटे में उदारतापूर्वक वृद्धि की जाए । लाइसेंस अवधि अक्तूबर 1963—मार्च 1964 से छोटे समाचार पत्रों को जो वृद्धियां दी गईं, उनको दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या LT—504/71]

Abolition of Export Duty on Coir Yarn

*663. SHRI C. JANARDHANAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Kerala State Govern-

ment have requested Government to abolish the export duty on coir yarn ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government do not propose to abolish the export duty on coir yarn at present.

Reopening of Cashew Factories in Kerala

*665. SHRI MUHAMMED SHERIFF : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether any agreement was reached by Government and the cashew factory owners in Kerala in May, 1971 ;

(b) if so, the main points thereof ;

(c) whether all the faetories reopened as a result thereof and, if not, the reasons therefor ; and

(d) the steps taken by Government in getting those factories reopened at the earliest ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (d). Discussions were held with some representatives of the cashew factories as a result of which most of the factories have been reopened.

Rupee Trade Agreement with Yugoslavia

*666. SHRI SAMAR GUHA :
SHRI SAMINATHAN :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(e) whether negotiation is going on between India and Yugoslavia regarding the basis of trade payment ;

(b) whether Yugoslavia is unwilling to accept payment in rupee currency ; and

(c) if so, the basis of payment agreed to by the two countries in regard to their mutual trade transactions ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). No agreement has yet been reached as the matter is presently under negotiations between the two Governments.

Taking over of Import and International Trade of Cotton

*671. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have considered the proposal to take over the import and internal trade of cotton ; and

(b) if so, the broad features thereof ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

With effect from 15-9-70, cotton import has been canalized through the Cotton Corporation of India Limited. From that date, import licences for cotton are being issued in the name of the Corporation with endorsement in the name of the user mills. Mills have been allowed freedom to choose their own agents for services hitherto rendered to them for importation of cotton. The Corporation will also render such services wherever asked to do so.

As regards the internal trade, the Corporation will undertake purchases by way of price support, provide ready market to cultivators who grow new varieties of extra long staple cotton and help the National Textile Corporation for the mills under Government management as well as mills in the private sector in procuring domestic cotton.

Trade with Middle East Countries

*672. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether any concerted drive is being made to increase our trade with the Middle East Countries ;

(b) if so, the main features thereof ;

(c) whether Indian goods, e.g. engineering goods, machineries and textiles are in great demand in the Middle East countries and they need market for cotton and

crude oil which are badly needed by India ; and

(d) if so, what efforts are being made to utilise this opportunity of trade expansion to the fullest possible extent ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Yes, Sir.

(c) India is already importing substantial quantities of essential raw materials from countries in the region such as cotton from UAR and Sudan, and Rock phosphate from Jordan. The possibilities of importing other commodities as crude oil and sulphur is being actively explored.

(b) and (d). There is a good demand for both our traditional products such as tea, jute manufactures, cotton textiles, spices including cardamom and non-traditional products such as engineering goods, chemicals and plastics. The following steps are being taken to increase the volume of trade with these countries and, in particular, to promote the exports of non-traditional items :

(i) *Trade Agreements* :—have been concluded with UAR, Sudan, Jordan, Iraq and Syria and with the first four special arrangements are concluded from year to year which provide for an element of growth in our exports.

(ii) *Trade Fairs and Exhibitions* :— We participate in a number of fairs each year where special emphasis is laid in exhibiting exports. Recently two wholly Indian exhibitions have been held in Khartoum and Jeddah.

(iii) *Participation in large value tenders and turnkey projects* :— Exporters are encouraged and assisted to compete successfully in winning the tenders ; large value contracts for textile machinery, setting up of cement plants in two countries in the region, exporting transmission lines and supplying railway equipment have been secured. Further, taking advantage of the development plans of these countries by obtaining consultancy contracts is being encouraged.

(iv) Other measures include exchange of official and unofficial delegations, conducting market surveys and area surveys, fixing appropriate targets and taking steps to assist in their fulfilment, assisting exporters with their special problems, etc. The above list is only illustrative and not exhaustive.

(v) Exports from India to Middle East countries, which were at a level of Rs. 80 crores in 1967-68 are expected to exceed Rs. 150 crores during the current year. A substantial part of the increase is due to non-traditional items.

Report of USAID to set up Tobacco Corporation

*673. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL . Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased ta state :

(a) whether Government have since received the report of the U. S. Agency for International Development which has recommended to set up a Tobacco Corporation in the Public Sector to give a boost to India's exports of Tobacco ; and

(b) if so, the main features thereof and the decision taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRRDE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Restoration of Bombay-Delhi Air Mail Service

*675. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether regular mail service between Bombay and Delhi takes as much as 48 hours to reach destination and mail posted in the Mail Van on a Saturday took as long as five days to reach Delhi ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to restore the overnight delivery of mail by air as used to be the case ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Previously, on account of the use of a smaller type of aircraft on the night air mail service, the entire bulk of mails was not being air-lifted and the left over mails were being carried through morning air service resulting in delivery of mails at Bombay on the third day. Normal air services have been restorted with effect from 15-5-71 and there is no detention of mails on the night airmail service now and articles are generally being delivered on the second day of their posting, both at Bombay and Delhi.

As for mails posted in the RMS Mail Van on a Saturday at Bombay, they reach Delhi on Sunday evening and get delivered on Monday morning.

(b) Does not arise.

Telegrams in Devanagri Script

*678. SHRI T. S. LAKSHMANAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether telegrams in all the languages listed in the Eighth Schedule of the Constitution can now be sent in Devanagri Script ;

(b) the arrangemants made in the case of those regions where Devanagri Script is not known ;

(c) the reasons for the bias in favour of Devanagri Script *vis-a-vis* the regional languages ; and

(d) the difficulties to be encountered in accepting telegrams in the respective script of regional languages ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir.

(b) Besides the facility of accepting telegrams in Devanagari script in some telegraph offices, arrangements exist for accepting telegrams in Roman script in all the Telegraph offices in all regions.

(c) Besides Hindi being an official language of the Union, telegrams can be accepted in Devanagri script also, because it has been possible to develop and manufacture teleprinters for transmitting and receiving in that script.

(d) As the exact phonetic reproductions of the script of regional languages require separate sets of Morse code and teleprinter machines, provision of telegraphs facilities in each language would require extraordinarily large investment besides special course of training and opportunity for the staff to keep up practice and speed. Proliferation of such sets of codes and teleprinter machines representing all or a number of regional languages is not practicable.

Export of Handicrafts

*680. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the total exports of handicrafts during 1970-71 and for the two preceding years ;

(b) the major items and the countries which offer sizeable permanent market ; and

(c) how many times the Handicrafts Export Corporation participated in exhibitions outside India and which are the new markets captured as a result thereof ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Total exports of handicrafts during April, 1970—November, 1970 (for which figures are available) amounted to Rs. 55.10 crores. Exports for the two preceding years *i.e.*, 1968-69 and 1969-70 amounted to Rs. 75.24 crores and Rs. 83.29 crores respectively.

(b) A list of major items of exports of handicrafts and the names of the important markets are given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-505/71.]

(c) The Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd., participated in the important International exhibitions, as given in Annexure II. The Corporation's participation in the International exhibitions has enabled India in developing a new market in Japan to maintain the tempo of increase in exports of handicrafts to U.SA. and Canada.

Enquiry into Robbery Committed in Punjab National Bank, New Delhi

*681. SHRI RAMACHANDRAN KADANNAPPALLI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the enquiry held in the

robbery which took place on the 31st May, 1971 in the Punjab National Bank, New Delhi, has been completed ; and

(b) if so, the findings thereof and the action taken against the culprits ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) The investigation of the case is still in progress.

(b) Does not arise.

Purchase of Rubber by S.T.C.

*682. SHRI C. M STEPHEN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the total quantity of rubber purchased by the State Trading Corporation through its agencies in Kerala during the year 1970-71 as also the percentage thereof in relation to the total quantity offered for sale :

(b) whether the State Trading Corporation will purchase rubber from individual producers and, if not, the reasons therefor ; and

(c) whether his Ministry is aware that the manufacturers are not purchasing rubber at the prescribed price from the producers and whether the Ministry contemplates the grant of permission to export rubber in view of the need to keep up market price to the prescribed level ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). The State Trading Corporation entered the rubber market in October, 1970 to effect purchase of raw rubber RMA Grade I to V and purchased 6,000 tonnes of rubber during 1970-71 from the co-operative societies of small growers and service co-operatives Total quantity available for sale for the period October, 1970 to 31st March, 1971 in the market is not available.

(c) Government have not received any specific complaint against the manufacturers purchasing rubber below the notified prices. The possibility of export of rubber also is being explored.

Import of Aluminium Goods from Nepal

*683. SHRI B. R. SHUKLA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether any articles of aluminium, manufactured in Nepal, are imported into India ;

(b) if so, the extent of annual import ; and

(c) whether aluminium is being exported to Nepal from India ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) : (a) Upto December 31, 1970, there were no restriction on import of aluminium manufactures from Nepal into India. However, according to the available information, there have been no import of aluminium manufactures from Nepal during 1968-69, 1969-70 and April-December, 1970.

(b) Does not arise

(c) Yes, Sir.

Central Assistance for Calcutta Metropolitan Development Authority

*686. SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the amount of Central assistance decided to be given to the Government of West Bengal for the Calcutta Metropolitan Development Authority upto the end of the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the schemes for which such assistance has been given ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) and (b). Central assistance for States' Fourth Five Year Plans is being allocated in the form of block loans and block grants in accordance with an objective formula evolved by the Chief Ministers' Committee of the National Development Council. Its allocation is not linked with any specific schemes or programmes adopted in the plan by a State Government for its rural, urban or metropolitan areas. West Bengal has been allocated a Central assistance of Rs. 221 crores for its Fourth Five Year Plan of Rs. 322.50 crores.

In addition to the Central assistance for West Bengal's Fourth Five Year Plan, it is proposed to provide Central grant upto Rs. 8 crores outside the plan during the Fourth Plan period for Bustee Improvement schemes in the Calcutta Metropolitan Region.

All India Radio Station at Quilon

*687 SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government are considering any proposal to set up a Radio Station at Quilon during the Fourth Plan period ;

(b) if so, the funds allocated for this scheme ; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The area which the station in Quilon could serve will be covered by the high power transmitter in Alleppey which will be commissioned shortly.

Proposal to Develop Regional Co-operation in Asia

*688. SHRI H. M. PATEL : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the names of Indian goods the trade in respect of which has been affected with the formation of groups like R.C.D., A.S.E.A.N. and S.E.A.M.I.C. and support to these groups from certain developed countries and some international organisations ;

(b) whether Government propose to organise and develop regional co-operation in Asia on that basis : and

(c) if so, the steps taken by Government in this direction and the results achieved ?

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI L. N. MISHRA) ; (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The RCD, ASEAM, and SEAMIC which are sub-regional groups, were estabiished primarily to promote economic development, social progress and cultural development among the member countries through mutual cooperation. While these sub-regional groupings are continuing to discuss measures for trade liberalization and expansion among their respective members, no concrete scheme in this field has been evolved as yet. Indian exports to countries belonging to these sub-regional groupings have continued to increase. The Government of India have maintained at various ECAFE meetings that sub-regional groupings should not be insular or "inward looking" in character and that the ultimate aim should be to develop regional co-operation on as broad a basis as possible in accordance with the guidelines set by the Council of Ministers first at their meeting in December 1968 at Bangkok, and subsequently in December 1970 at Kabul. The Resolution on the Strategy for integrated Development of Regional Cooperation in Asia adopted by the Asian Ministers in December 1968 provides a broad framework for the promotion of regional cooperation in Asia to cover all the countries in the ECAFE region. The Government of India continue to play an important role in the forum of ECAFE in implementing the strategy for development of regional economic co-operation.

Export of Rubber

*689. SHRI C. K. CHANDRAPPAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government intend to take immediate steps for the promotion of export of Rubber ; and

(b) whether any other method is contemplated in view of the sharp fall in Rubber prices, to provide fair price to the Rubber growers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Possibilities of exporting rubber is being explored.

(b) The State Trading Corporation propose to increase their purchases of raw rubber and this is expected to provide fair prices to the rubber growers.

Implementation of Ten Year Nuclear Programme

*690. SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) the steps taken so far to implement Dr. Sarabhai's ten ye r nuclear programme;

(b) whether the Planning Commission has raised objections to Sarabhai's programme ; and

(c) the steps taken to ensure speedy and timely implementation of Dr. Sarabhai's nuclear programme ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) to (c). Government has accepted the objectives of the specific programmes in Atomic Energy and Space Research for decade 1970-80 as set out in the Profile presented by the Atomic Energy Commission. The programme envisaged in the Profile is still under discussion with the Planning Commission. In the mean time, the steps required to implement the proposals are g worked out in detail.

इन्जीनियरों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

2 48. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या मध्य प्रदेश मे इन्जीनियरो मे बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हा, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी राशि की सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश के लिए चौथी योजना का आकार

2849. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग के द्वारा अनुमोदित 398 करोड़ रुपये के परिव्यय के स्थान पर मध्य प्रदेश सरकार ने चौथी योजना के लिए 450 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है ।

(ग) चौथी योजना के परिव्यय में 57 करोड़ रुपये की वृद्धि करने के इस प्रस्ताव के समर्थन मे मध्य प्रदेश सरकार ने संसाधनों के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किये है, जिन पर योजना आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के सबद्ध अधिकारियों के साथ हाल ही में विचार-विमर्श किया है । इन अनुमानों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों की जांच करने के बाद इस विषय में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाया जायेगा ।

होशगाबाद तथा पूर्वी निमाड़ जिलों (मध्य प्रदेश) में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

2850. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 के दौरान होशगाबाद और पूर्वी निमाड़ जिलों में नये सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित किये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पूर्वी निमाड़ जिलों में वर्ष 1970-71 के दौरान लम्बी दूरी

का एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोला गया था। इस अवधि के दौरान वहां कोई सार्वजनिक टेलीफोन बूथ स्थापित नहीं किया गया।

टेलीफोन और तार सुविधाओं से सम्पन्न डाकघर

2852. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी और देहाती क्षेत्रों में 30 अप्रैल, 1971 को टेलीफोन और तार सुविधाओं से सम्पन्न डाकघरों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) इनमे से कितने मध्य प्रदेश मे हैं और मध्य प्रदेश के कुल डाकघरों के प्रति उनका प्रतिशत अनुपात क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और कम से कम सम्भव समय के अन्दर लोक सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में डाकघर

2853. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1971 को मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की अलग-अलग संख्या कितनी थी ;

(ख) उनमें से ऐसे डाकघरों की संख्या अलग-अलग कितनी है जो 30 अप्रल, 971 की स्थिति के अनुसार घाटे में चल रहे थे और लाभ पर चल रहे थे ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के शहरी और देहाती इलाकों में नये खोले गये डाकघरों की संख्या अलग-अलग कितनी है ; और

(घ) वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में खोले जाने वाले नये डाकघरों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 30 अप्रैल, 1971 को मध्य प्रदेश में काम कर रहे डाकघरों की संख्या :

शहरी	648
ग्रामीण	5357

(ख) 30 अप्रैल, 1971 को मध्य प्रदेश में काम कर रहे डाकघरों की संख्या :

घाटे पर चल रहे	3241
लाभ पर या बिना हानि के चल रहे	2764

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में खोले गये नये डाकघरों की संख्या :

1968-69	(शहरी	20
	(ग्रामीण	94
1969-70	(शहरी	54
	(ग्रामीण	126
1970-71	(शहरी	29
	(ग्रामीण	211

(घ) 1971-72 के दौरान मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में खोले जाने वाले नये डाकघरों की संख्या : 16

Conversion of Posts of Steno-Typists into those of Stenographers

2854. SHRI S. M. BANERJEE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the posts of Stenotypists in the Government of India have been converted into those of Stenographers (Grade III) and the scale of pay has been revised to Rs. 130-300 ;

(b) whether the scale of pay has also been revised to Rs. 130-300 in the Subordinate offices of the Government of India ;

(c) whether the posts of Stenotypists under the Delhi Administration have also been converted into those of the Stenographers (Grade III) ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b). Orders were issued on 24th July, 1969 (copy is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-506/71], that all the existing posts of Lower Division Clerks and Upper Division Clerks with a special pay of Rs. 20 or Rs. 30 for stenographic work will be converted into posts of stenographers (a) in the scale of Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280 to be called Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service in Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Stenographers' Service and in other Ministries/Departments of the Government of India, and (b) in the scale of Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300 (the same as applicable to Upper Division Clerks) in subordinate offices and other offices of the Government of India.

(c) and (d). The matter is under consideration.

Pact with Hong Kong to Counter U.K. Government's Proposal to Levy Duty on Textiles

2855. SHRI CHANDRA SHEKHAR SHARMA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether any understanding or a pact was recently reached by the Government of India with the Government or Trade in Hong Kong with a view to counter the British Government's proposal to levy 15 per cent duty on the Textile imports in U.K. ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) what other efforts Government have made so far or have in mind to counter the effect of this proposed levy by the U.K. from next year ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) No. Sir

(b) Question does not arise.

(c) Efforts are being made to diversify India's trade and build up existing textile trade in the markets of U.S.A., Australia, New Zealand, Western Europe, Sudan and USSR and other Rupee payment countries.

Strictures Passed by U.P.S.C. on Delhi Municipal Corporation

2856. SHRI R. P. DASS :
SHRI P. GANGADEB :
SHRI NIHAR LASKAR :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the strictures passed by the Union Public Service Commission on the Delhi Municipal Corporation for flouting the advice of the Commission in the matter of appointments ; and

(b) if so, the steps taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes, Sir.

(b) Government are looking into the matter.

दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सलवादी गतिविधियां

2857. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मई, 1971 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिस प्रकार की नक्सलवादी गतिविधियां पश्चिम बंगाल में हुई थीं गत एक वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय में उसी प्रकार की बहुत सी चिन्ता-जनक गतिविधियां हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नक्सलवादियों की बैठकों में कलकत्ता और चीन से प्राप्त प्रचार सामग्री वितरित की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). सरकार ने दिनांक

17-5-1971 के "नवभारत टाइम्स" के समाचार को देखा है। गत एक वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय में नक्सलवादियों तथा अन्य उग्रवादियों की गतिविधियों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है हालांकि कुछ प्रचार साहित्य का सीमित परिचालन देखने में आया है। आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है और जहां भी सम्भव होता है कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

Alleged Violation of Foreign Exchange Regulations by a Deputy Minister of Maharashtra

2858. SHRI M. KATHAMUTHU : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Foreign Exchange Enforcement Directorate had issued a show cause notice to Shri V. B. Hiray, Deputy Minister of Agriculture and Urban Development in Maharashtra for contravening the provisions of Foreign Exchange Regulations ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) No, Sir.

(b) The question can arise only if contrevention of any law is established.

Proposal to make Vasco a Free Port

2859. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Covernment of Goa have requested the Central Government to make Vasco a free port so that it would be developed as a tourist spot ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

औद्योगिक विकास

2860. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री कमलमिश्र मधुकर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश के औद्योगिक विकास के लिए कोई वार्षिक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). 1971-72 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक कार्यक्रम को अन्तिम रूप के लिए दिया गया है वार्षिक योजना प्रलेख, जिसमें आवश्यक सूचना मिल जायेगी, तैयार हो जाने पर सभा पटल पर यथा शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

Inadequate Revenue Laws and Rules for Tribal People in Manipur

2861. SHRI N. TOMBI SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the common people in the tribal areas of Manipur are being exploited by the Chiefs owing to the absence of adequate revenue laws and rules ; and

(b) if so, the steps taken by Government to safeguard the common people's interests in these areas ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) The Government of Manipur have intimated that they have not received any complaint of exploitation of tribal people by the village chiefs.

(b) Does not arise.

न्यायालयों में हिन्दी भाषा का प्रयोग

2802. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां न्यायालयों की भाषा हिन्दी हो गई है ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) तथा (ग) यह तय करना राज्य का काम है कि राज्य मे कार्य कर रहे उच्च न्यायालय/जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयो में किस भाषा का प्रयोग किया जाय। केन्द्र सरकार केवल तभी सम्बन्धित है जब उच्च न्यायालयो के बारे मे संविधान के अनुच्छेद 348 अथवा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न उठता है।

विवरण

देश के न्यायालयों म हिन्दी के प्रयोग स सम्बन्धित स्थिति इस प्रकार है :-

उच्च न्यायालय :

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों में जिरह के लिए, न्यायालयों में दायर किये जाने वाले शपथ पत्रों के लिए और उच्च न्यायालय में कार्यवाहियों के प्रयोग के लिए पेपर-बुकों में शामिल किये जाने वाले बयानों व कागजातों में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है :—

(1) यदि कोई न्यायपीठ चाहे तो उसे हिन्दी मे शपथ-पत्रों, बयानों और दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद किये जाने का विशेषरूप से आदेश देना चाहिये ; और

(2) यदि हिन्दी में अभिवचनों, बयानों और दस्तावेजों आदि से कोई उद्धरण फैसले में शामिल किया जाता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद उसके बाद ही तत्काल ही लिख देना चाहिये।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित अथवा किये गये निर्णय, डिग्री अथवा आदेश के प्रयोजन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी का वैकल्पिक प्रयोग भी प्राधिकृत कर दिया गया है। किन्तु ऐसे किसी आदेश के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्राधिकार में जारी किया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लगाया जायेगा।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय मे उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अथवा पारित निर्णय, डिग्री अथवा आदेश मे हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत कर दिया गया है। किन्तु ऐसे निर्णय, डिग्री या आदेश के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के प्राधिकार मे जारी किया गया उसका अंग्रेजी अनुवाद भी लगाया जायेगा।

(4) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मे उच्च न्यायालय द्वारा पारित अथवा दिये गये निर्णयो, डिग्रीयों और आदेशों को छोड़कर सभी कार्यवाहियों में उपरोक्त पैरा 2 में दी गई दो शर्तों के अधीन हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया है।

जिला तथा अधिनस्थ न्यायालय :

(5) बिहार में न्यायालयों ने हिन्दी में गवाहियां दर्ज करना आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त वे अधिकारी जो हिन्दी का ज्ञान रखते हैं उन्हें हिन्दी में निर्णय तथा आदेश लिखने पड़ते हैं। राजस्थान में न्यायालयों में विभिन्न स्तरों पर हिन्दी का प्रयोग

अनिवार्य है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में हिन्दी, न्यायालयों की कार्यवाहियों के लिए प्रयोग में आने वाली तीन भाषाओं में से एक है। किन्तु निर्णय, डिग्री तथा आदेश इत्यादि केवल अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्णय, डिग्री इत्यादि को छोड़कर हिन्दी को न्यायालय की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। फिर भी, 2,000 रुपये तक के दीवानी मुकदमो तथा फौजदारी मुकनमों में, जिनमें एक वर्ष अथवा कम की सजा हो, निर्णय हिन्दी में पारित किये जाते हैं अथवा दिये जाते हैं। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी अधीनस्थ न्यायालयों ने सामान्यत: हिन्दी में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

Export Orders for Engineering Goods from Abroad

2863. SHRI P. GANADEB :
SHRI S. M. KRISHNA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Union Government are expecting a variety of export orders for engineering goods this year ;

(b) if so, whether some orders have been received and are still under execution ;

(c) if so, the items under execution ; and

(d) which are the countries from where orders have been received and orders are expected ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Export of engineering goods have been rising over the past few years. Exports during 1970-71 have been of the order of Rs. 115 crores and for the year 1971-72, a target of Rs. 165 crores has been fixed by the Engineering Export Promotion Council.

(b) and (c). Orders are being continuously received and processed. Currently large value and turnkey projects worth about Rs. 150 crores for supply of Railway wagons and coaches and equipment, plant and machinery, transmission line towers, structurals etc., are in hand. A sample list of other engineering goods in demand overseas is attached ;

(d) Orders are received from all over the world, the largest aggregate demand being from Asian and African countries.

Statement

1. Automobiles and Auto Parts.
2. Electric Wires and Cables.
3. Bicycles and parts.
4. M.S. Pipes, Tubes and Fittings.
5. Jute, Textile and Knitting Machinery.
6. Iron and Steel Castings (All sorts).
7. Hand Tools, Cutting and Small Tools.
8. Electric Motors, Switchgear, Transformers etc.
9. Machine Tools.
10. Diesel Engine and Parts.
11. Batteries—Dry and Storage.
12. Office Machinery, Data Processing Machines, Typewriters etc.
13. Wire Ropes.
14. Radios and Components.
15. Railway Track Materials.
16. Electric fans and parts.
17. Brass, Copper Sheets, Circule, Rods, Rollers and Tubes.
18. Aluminium Ingots.
19. Wire Nails and other Wire Products (Other than wire ropes).
20. Bright steel bars and shaftings.

Co-ordination Amongst various Agencies of Planning

2864. SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) what precise roles are played by the Planning Commission ; National Development Council ; Ministry of Planning, and the Prime Minister's Secretariat, in the formulation and implementation of plans ;

(b) whether multiplicity of organisations is causing delay, overlapping and distraction ; and

(c) whether Government propose to unify the different agencies to effect better co-ordination ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) A Statement is laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

STATEMENT

(i) Planning Commission (Yojana Ayog)

The Planning Commission is entrusted with the following functions :

1. Assessment of the material, capital and human resources of the country, including technical personnal, and formulation of proposals for augmenting such of these resources as are found to be deficient.
2. Formulation of Plans for the most effective and balanced utilisation of the country's resources.
3. Definition of stages in which the Plan should be carried out on a determination of priorities and allocation of resources for completion of each stage.
4. Determination of the nature of the machinery necessary for the implementation of the Plan in all its aspects.
5. Appraisal from time to time of the progress achieved in the execution of each stage of the Plan.
6. Public Co-operation in National Development.
7. Perspective Planning.

NOTE :—The Planning Commission (Yojana Ayog) will be concerned broadly with technical questions relating to planning and the planning organisation itself. The policy and details of specific schemes included in the Plan are matters to be dealt with by the Central Administrative Ministries and State Governments.

(Reference Rashtrapati Bhavan Notification No. Doc. No. CD-310/71, dated June 17, 1971)

(ii) National Development Council

The functions of the National Development Council are :

(i) to prescribe guidelines for the formulation of the National Plan, including the assessment of resources for the Plan ;

(ii) to consider the National Plan as formulated by the Planning Commission ;

(iii) to consider important questions of social and economic policy affecting national development ;

(iv) to review the working of the Plan from time to time and to recommended such measures as are necessary for achieving the aims and targets set out in the National plan, including measures to secure the active participation and co-operation of the people, improve the efficiency of the adminisitrative services, ensure the fullest development of the less advanced regions and sections of the community and through sacrifice borne equally by all citizens, build up resources for national development.

The National Development Council will make its recommendations to the Central and the State Governments and will comprise of the Prime Minister, all Union Cabinet Ministers, Chief Ministers of all States and Union Territories and the Members of the Planning Commission. Delhi Administration will be represented in the Council by the Lt. Governor and the Chief Executive Councillor, and the remaining Union Territories by their respective Administrators. Other Union Ministries and State Ministers may also be invited to participate in the deliberations of the Council.

The Council may appoint, from time to time, suitable sub-committees or panels.

The Council shall meet as often as may be necessary and at least twice in each year.

The Secretary of the Planning Commission shall act as Secretary to the

National Development Council and the Planning Commission shall furnish such administrative or other assistance for the work of the Council as may be needed.

(Reference Government of India, Cabinet Secretariat, Deptt. of Cabinet Affairs Resolution No. 65/15/CF-67 dated 7th October, 1967)

(*iii*) *Ministry of Planning* (*Yojana Mantralaya*)

The Ministry of Planning is responsible to Parliament in regard to the subject of natural planning.

(Reference Rashtrapati Bhavan Notification No. Doc. No. CD-310/71, dated June 17, 1971)

(*iv*) *Prime Minister's Secretariat* (*Pradhan Mantri Sachivalaya*)

The function of the Prime Minister's Secretariat is to provide secretarial assistance to the Prime Minister.

(Reference Government of India, Cabinet Secretariat, Allocation of Business Rules, 1961—as amended upto September 20, 1970).

Re-appraisal of Trade Relations with Turkey and Iran

2865. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the extent of trade commitments made between India and Turkey and also between India and Iran and the details in kinds and in terms of monetary involvement ;

(b) whether Government propose to make a re-appraisal of our trade relations with these countries ; and

(c) if so, the steps taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) India does not have any trade commitments with Turkey. There is a Trade Arrangement with Iran regarding Import by India of dry fruits, dates, etc., from Iran upto a specified monetary ceiling. The arrangement is reviewed from year to year.

(b) and (c). India and Iran have set up a Joint Indo-Iran Commission for Economic Trade and Technical Co-operation. The Commission has set up a number of Joint Committees including a Committee on Trade. The recommendations made by the Committees are reviewed by the Indo-Iran Joint Commission which has so far held three meetings.

Purchase of Jute from Bangla Desh

2866. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a report published in the *Economic Times*, Bombay, in its issue dated the 15th April, 1971 entitled "Jute traders profit" ;

(b) whether the traders in India, having previous contacts with East Pakistan, are reaping sky-high margins in export quality jute and exchange transactions ;

(c) whether the jute growers in Jessore, Khulna and Kushtia are being fleeced by the traders in Bangla Desh, who buy stocks at Rs. 12 per maund and sell them at Rs. 45 to traders in India, where the ruling price is Rs. 81 ;

(d) if so, Government's reaction thereto ; and

(e) the steps, if any, being contemplated in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Government have no definite information on these points.

(d) Does not arise.

(e) The State Trading Corporation is in constant touch with the industry and trade in the matter.

New Jute Markets captured by India

2867. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether India has captured the Pakistan International market of Jute recently ;

(b) if so, the extent of jute exported as a result thereof ;

(c) the names of countries whose jute

market have been captured by India ; and

(d) the value of foreign exchange likely to be earned therefrom yearly ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (d). All possible steps are being taken to maximise production of export of jute goods. It is too early to assess the exact additional earning.

गुरमुखी लिपि में पंजाबी के प्रयोग के बारे में पंजाब सरकार का परिपत्र

2868. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए इस आशय के एक परिपत्र की ओर आकर्षित किया गया है कि केवल उन्हीं फाइलों पर ध्यान दिया जाये जिनमें टिप्पण गुरमुखी लिपि में पंजाबी में लखे हों ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पंजाब राज भाषा अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के कामकाज के लिए गुरमुखी लिपि में पंजाबी को एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है । राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपरोक्त परिपत्र राज्य सरकार की भाषा नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है ।

Representation to Minorities in I.A.S. and other Allied Services

2869. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the result declared for the I.A.S. and the allied services, recently, shows that minorities are not being properly represented ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps being taken by Government to give due representation to minorities in the I.A.S. and other Allied Services ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (c). Of the vacancies to be filled in the Indian Administrative Service and other services on the basis of the combined competitive examination held in 1970, the prescribed percentage was reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

For filling all the vacancies so reserved, the Union Public Service Commission have recommended candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of the results of this examination.

No reservation has been made in favour of any other minorities, based on religion, language etc

Maharashtra-Mysore Boundary Dispute

2870. SHRI SHANKAR RAO SAVANT :
SHRI T. S. LAKSHMANAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 420 on the 26th May, 1971 and state :

(a) whether any solution has since been found to the boundary dispute between the States of Maharashtra and Mysore ;

(b) if not, the steps taken to find such a solution ; and

(c) whether there are any hitches in

finding a solution to the dispute and, if so, what are those ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) to (c). The question of finding a solution to this matter is still under the consideration of the Government.

Assistance for Development of Backward Regions

2871. SHRI SHANKARRAO SAVANT Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in several States there are some backward regions such as Telengana in Andhra Pradesh and the Konkan in Maharashtra ;

(b) whether Government are thinking of giving Central help for the development of such regions ;

(c) if so, the nature and extent of this help ; and

(d) if not, how Government propose to gear up development activities in such regions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). :

(1) The Committee of Chief Ministers appointed by the NDC has evolved a formula for giving Central assistance to State Governments for the implementation of their development programmes which takes into account, among other things, the needs of individual States which have special problems. After the outlay on the development programme of each State is fixed on the basis of the Central assistance to which that State is eligible according to the objective criteria laid down by the Chief Minister's Committee and the resources which the State itself can make available for the purpose, it is for the State Government to decide what should be the outlay for the accelerated development of backward regions within each State. In advising the State Goverments about the size as well as the sectoral distribution of their outlays and at the time of finally approving such outlays, the Planning Commission takes due care to ensure that the maximum possible invest is made for development programmes designed to meet the needs of the backward regions of each State.

(2) In addition, a special pattern of assistance has been evolved by the Planning Commission for selected backward areas like border districts and hill districts of certain States.

(3) Further, districts which are in need of special attention in the matter of industrial development have been identified and notified with the co-operation of the State Governments, in pursuance of the recommendations of the Pandey and Wanchoo Committee Reports. Preference is being given to these districts in the matter of location of industrial projects in the public sector provided they are found to be feasible on techno-economic considerations. The Licensing Committee also gives preferential treatment to applications from the backward regions. Ratnagiri and Kolata districts of Konkan region are among the districts notified for the purpose of these benefits.

(4) Further, concessional finance is being provided for new industries which may be set up in these backward districts, from financial and credit institutions in the public sector. In addition, the Central Government is giving an outright subsidy amounting to 1/10th of the fixed capital investment to new units having a total fixed investment not exceeding Rs. 50 lakhs each, in two selected districts in each of 9 States identified as industrially backward and in one selected district in each of the remaining States and Union Territories. Ratnagiri district in Konkan region has been selected for the purpose.

(5) The Rural Electrification Corporation which has been set up recently, provides finance on conces-

sional terms to State Electricity Boards for rural electrification programmes in backward areas.

(6) Special programmes of large magnitude are being implemented for the benefit of the weaker sections of the rural population and for the development of dry and arid areas. Under these programmes 46 Small Farmers Development Agency projects, 41 projects for Sub-marginal Farmers and Agricultural Labour and 24 projects for Farmers in Dry Areas have been launched by the Government of India. An amount of Rs. 100 crores has also been provided for an integrated programme of rural works in 54 chronically drought-affected areas.

(7) A crash scheme for rural unemployment has also been launched by the Government of India with an initial provision of Rs. 50 crores.

(8) Surveys of backward districts of Orissa, hill and backward areas of Punjab, primitive tribes of Madhya Pradesh and Basti districts in Uttar Pradesh, have been conducted. A Study Team has carried out a survey of the development programmes of tribal areas. A Central Team has also studied the problems of tribal people in Andhra Prodesh.

(9) The Planning Commission has offered assistance to States for preparing district plans which will result in identifying the problems of backward regions and thereby help in evolving measures for solving their problems.

(10) A special assistance of Rs. 45 crores is being provided to the Government of Andhra Pradesh to enable it to spend this amount during the period ending on 31-3-1974 on the special regional development programme of Telengana area in addition to the Plan outlay in that area. A Telengana Development Committee and a Plan Implementation Committee have been constituted to expedite the progress of development programmes in Telengana area including the special regional development programme of Rs. 45 crores.

(d) Does not arise.

Effect of E.E.C. Exretion on Indian Trade

2872. SHRI NIHAR LASKAR :
SHRI S. M. KRISHNA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there is a move among the European Economic market countries to discuss with Independent Asian countries, particularly with India, the problems which E.E.C. extension would bring to them ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether India has been approached by them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. G. GEORGE) : (a) to (c). In the negotiations between the United Kingdom and the European Economic Community, for the former's entry into the Community the question of relations between the enlarged Community and the Commonwealth countries in Asia and the Far East came to be discussed. It has been agreed by the negotiating sides that in respect of these countries the Community would be prepared to examine with them—after enlargement and taking into account the scope of the Generalised Preference Scheme—such problems as may arise in the trade sector, with a view to finding suitable solutions. In taking this decision we were not consulted. We have pointed out that the Generalised Scheme of Preferences would not take care of many of our trade problems arising out of the enlargement of the Community.

The matter is being pursued through diplomatic channels.

नीमच में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का तैनात किया जाना

2874. डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच (मध्य प्रदेश) में केन्द्रीय

रिजर्व पुलिस के कितने बटालियन तैनात किए गए हैं ;

(ख) उनमें से कितने बटालियन नीमच के बाहर की ओर और कितने नीमच में तैनात किए गए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों तथा अन्य अधिकारियों की रिहाइश के लिए वहां पर पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). एक सिगनल बटालियन समेत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सात बटालियनों के मुख्यालय नीमच में हैं। इन बटालियनों के 611 व्यक्ति देश के विभिन्न भागों में ड्यूटी पर हैं। शेष 1188 व्यक्तियों में, जो मुख्यालय में हैं, ग्रुप सेन्टर स्टाफ, प्रशिक्षक कर्मचारी तथा प्रशिक्षणाधीन रंगरूट शामिल हैं।

इसमें नीमच की केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की अन्य संस्थाओं, जैसे बेस अस्पताल, केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज आदि के कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) तीन वर्ष पहले तैयार किए गए नीले नक्शे के अनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास बनाया जा रहा है। नीमच में लगभग 50 प्रतिशत अधिकृत विवाहित आवास का निर्माण पहले ही हो गया है और शेष 20 प्रतिशत का निर्माण अगले वर्ष शुरू किए जाने की संभावना है। अविवाहित कर्मचारियों के लिए पर्याप्त बैरक आवास उपलब्ध हैं।

Canadian Philanthropic Organisations raising Funds for the Improvement of Calcutta

2875. SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether some philanthropic Organisations in Canada are raising funds to help solve the problems of Calcutta as reported in the *Statesman* of Calcutta dated 22nd May, 1971 ;

(b) if so, whether Government have liaised with these organisations to find out the extent of assistance that will be available through this source ; and

(c) the particular purpose, if any, for which the fund is being raised ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) The Planning Commission is not aware of Canadian Philanthropic Organisations raising funds to solve the problems of Calcutta as reported in the *Statesman* of the 22nd May, 1971.

(b) and (c). Do not arise.

Loading and Unloading of Iron Ore at Nergundi Station by M.M.T.C.

2876. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Minerals and Metals Trading Corporation instead of encouraging labour contract co-operative for loading and unloading of iron ore at Nergundi station on the South Eastern Railway is carrying on this work with the help of a private contractor whose contract has already been terminated since 31st March, 1971 ;

(b) if so, the reasons for the same ;

(c) whether the Regional Manager at Tulsipur, Cuttack/Orissa has been repeatedly reminded to give the work to the Iron Ore Transport and Handling Workers Union, Nergundi ; and

(d) if so, the reasons for not taking any action by the Director of the Minerals and Metals Trading Corporation at Delhi in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (d). The question is about a matter relating to the internal working of the Corporation. It is the policy of Government normally to

leave such matters to be dealt with by the Corporations according to their own best judgement.

Indians Killed by Pak Army

2877. SHRI PRABODH CHANDRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of Indian nationals, both military and civil killed by Pakistanis from 25th March to 30th May, 1971 ;

(b) the steps taken by Government to stop such occurrences ; and

(c) whether any compensation has been paid to the dependents of the deceased ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) According to the information available at present, 49 Indian nationals were killed during this period. No military personnel was killed.

(b) The Border Security Force is in strength all along the border and is ready to meet any situation. Apart from strengthening the border outposts and intensifying patrolling of the border by the Border Security Force, the Army also has been alerted to the ready to throw out any intruding Pakistani troops from Indian soil.

(c) In all these cases, Government of India have lodged protests with the Government of Pakistan and have demanded compensation from Pakistan for property destroyed and for injuries sustained as well as for the families of those killed as a result of Pakistani intrusion into and/or shelling of Indian territory. Extra-ordinary pension and other ex-gratia payments are being given to the dependents of the BSF personnel killed in such incidents. In the case of civilians, wherever possible, relief is given.

Concessions for Backward Areas

2878. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether the two Panels set up by the Planning Commission to examine regional imbalances proposed that concessions to backward areas should be offered ; and

(b) if so, the action taken on the said proposals ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) and (b). Planning Commission had set up two Working Groups to recommend—(i) the Criteria for Identification of Backward Areas, and (2) the Fiscal and Financial Incentives for industries in Backward Areas. The recommendations of these Working Groups were considered at the meeting of the N.D.C. Committee of State Chief Ministers held in September 1969. The following decisions were reached :—

(i) Concessions to be offered by financial and credit institutions for financing industries in backward areas should be available to selected backward areas in all the States and Union Territories.

(ii) The criteria to be adopted for selection of industrially backward districts in the States and Union Territories may be settled by the Planning Commission in consultation with the financial institutions and the State Governments, in the light of the two sets of criteria recommended by the Working Group on Identification of Backward Areas.

(iii) The Central Government may give an outright grant or subsidy amounting to one-tenth of the fixed capital investment of new units having a total fixed capital investment of not more than Rs. 50 lakhs each in two selected districts each of the 9 States identified as industrially backwary by the Working Group (*viz.*, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh) and one district each of the other States and Union Territories ; schemes and projects for new units involving fixed capital investment of more than Rs. 50 lakhs may be considered on merit. Further, the Planning Commis-

sion may also work out what should be the unit of a district.

2. In pursuance of the above and in consultation with the financial institutions regarding the criteria for the selection of districts, proposals were invited from the States and Union Territories for a list of industrially backward districts of their respective States, along with the statistical data, for purposes of concessional finance from the financial institutions. The States and Union Territories were also requested to indicate separately the names of the districts from out of the above list for purposes of the 10 per cent outright grant or subsidy by the Centre.

3. The districts/areas approved so far for (a) concessional finance from the financial institutions, and (b) for the 10% outright grant or subsidy by the Centre, are listed in statements I and II laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-507/71].

4. The Industrial Development Bank of India, the Industrial Finance Corporation of India and the Industrial credit and Investment Corporation of India have announced the terms of the concessional finance for industries to be established in the selected backward districts Briefly, the concessions include (i) lower interest rate of 7 per cent ; (ii) extension of the period for the repayment of the first instalment of the principal amount of the loan from 3 years as at present to 5 years ; (iii) longer period of 15-20 years for the repayment of the loan as against 10 to 12 years normally stipulated ; (iv) reduction of the normal service charges by 50% ; and (v) reduction of the margin of security by the IFCI and the ICICI to 30/35 per cent

5. The details of the scheme of 10% outright grant or subsidy by the Centre including the procedure for disbursement, are being finalised by the Ministry of I. D.

Reduction in Prices of Polyester Fibres

2879. SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have taken any action on the recommendation of the Tariff Commission that there should be drastic reduction in the prices of indigenous Polyester fibres ; and

(b) how does the price of indigenous polyester fibre compare with its price in foreign countries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) The recommendations of Tariff Commission on fair prices of synthetic fibres and yarn are still under the consideration of the Government.

(b) A statement is enclosed.

Statement

Price of polyester fibre of M/s. Chemicals and Fibres India Limited in rupees per kg. effective from 1-3-1970 is as under :

	Above 2 Denier	2 Denier and below
Rate per kg. net ex-factory	25.08	25.08
Less : Price reduction being amount absorbed by CAFI on account of excise duty	4.50	4.50
Revised Price	20.58	20.58
Estimated excise duty on polymer	1.90	1·90
Excise duty on fibre and surcharge of 33-1/3% thereon	28.00	33.33
Total price (including excise duty)	50.48	55.81

The above prices are exclusive of Textile Committee fee, sales tax, octroi, transport charges.

Information on price of polyester fibre in foreign countries is not available. However, prices of polyester fibre of foreign countries offered in India as available are given below :

(i) ICI polyester fibre price in U.K. for 3 Denier and 1.5 Denier is currently quoted at 40 pence per pound or 36.7 new penny per kg. Japan polyester fibre offered in India is quoted

at 36 to 37 pence per pound and of West Germany 38 pence.

(ii) S.T.C. have informed that c.i.f. price of polyester fibre as quoted by foreign suppliers varies between 36 and 37 pence per pound which in terms of rupees per kg. works out to around Rs. 6. To this the following may be added :—

	Rs.
Counter vailing duty	6.00
Customs duty	33.33
Handling charges	1.00
Total	40 33

Thus the landed cost of imperted polyester fibre would come to about Rs. 46 for 2 Denier and above.

Indo-Indonesia Joint Industrial Ventures with U.S. help

2880. SHRI P. GANGADEB :
SHRI NIHAR LASKAR :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether India and Indonesia are holding talks to set up joint industrial ventures with U.S assistance ;

(b) if so, the outcome of the talks ; and

(c) the fields in which the joint ventures are to be taken up ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) No, Sir.

(b) and (c). The question does not arise.

Fixation of Price of T. V. Sets

2881. SHRI P. GANGADEB :
SHRI NIHAR LASKAR :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have decided to fix the price limit of T. V. Set ; and

(b) if so, whether Government also propose to give any financial assistance to the manufacturers of T. V. sets for the rapid progress of this industry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). There is no proposal at present under consideration of Government : (i) to fix the price limit of T.V. Sets ; (ii) of giving special financial assistance to the manufacturers of T. V. sets. Indigenous manufacturers have at present priced T.V. sets of 23" and 19" screen sizes at Rs. 1900 and Rs. 1700 respectively, exclusive of all taxes. Government are contemplating the following important sets which are likely to result in the lowering of the prices of T. V sets :

(i) gradual reduction in the prices of electronic components by setting up large volume production ; components account for a substantial portion of the cost of television sets ;

(ii) larger quantity production of television sets in each unit ; and

(iii) production of transistorised television sets with small screens of sizes 12" to 16".

Crisis in Handloom Industry in Kerala

2882. SHRI M. K. KRISHNAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the serious crisis the handloom industry is facing in Kerala and the large scale closure of handloom factories ;

(b) the estimated number of handloom workers who have been rendered jobless due to the closure of handloom factories ;

(c) whether any steps have been taken by Government to reopen the handloom factories and revitalise this industry ; and

(d) if so, the main features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (d). A number of complaints had been received, about the rise in prices of cotton yarn resulting in difficulties to the consumers in the decentralised sector, *viz.* handloom, powerlooms etc from the various parts of the country, including Kerala State. There was actually no shortage of supplies of cotton yarn as such. The problem mainly related to the increase in prices.

2. This might have resulted in closure of a few handloom factories in Kerala and other States. Exact details in this regard are not available. However, there are no reports regarding large scale closure of handloom factories.

3. With a view to bringing down the prices of cotton yarn and making its supplies available to the decentralised sector at reasonable rates, Government of India have taken the following steps :

(i) To augment the supply of cotton, with a view to meeting the shortfall in domestic production, import of additional foreign cotton and staple fibre in substantial quantities has been arranged. In addition, various measures have been taken to regulate more stringently stocks, credit control and other trading facilities.

(ii) In order to assist the cotton handloom, powerloom and hosiery sectors, a pool of cotton carded yarn has been created. Supplies from the pool are made through the Directors of Industries/Handlooms in the State concerned.

Thefts Committed in Flats in Janakpuri Pankha Road, Delhi

2883. SHRI NATHU RAM AHIRWAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a number of thefts have recently been committed in the flats in Janak Puri, Pankha Road, New Delhi ;

(b) whether the main reason of the operation of anti-social element in that area is that there is no Police Station within a radius of 3 to 4 miles ;

(c) whether the residents of the area consider themselves unsafe because of lack of any arrangement for the Police post in that area ; and

(d) if so, whether a Police Post is proposed to be opened there shortly and, if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) Twenty cases of theft were reported during the period from 1st May 1970 to 30th April 1971.

(b) to (d). This colony is situated at distance of about two miles from Police Station Tilak Nagar. Day and night patrolling is being done in the area by the Delhi Police. It is a recently established colony and is yet to be fully developed. The question of establishing a police post in the area is under consideration.

Increase in price of woollen goods

2884. SHRI N. S. BIST : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether price of woollen goods continue to register sharp rise every year ;

(b) if so, the rise in price thereof during the last three years and the reasons therefor and

(c) the steps taken by Government to bring down the price ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). In line with the general trend of rise in prices, there has been some rise in the price of woollen goods. A statement giving the information is laid on the Table of the House.

(c) To arrest further rise of prices Government have released a larger amount of foreign exchange for import of raw material and steps are being taken for the modernisation and expansion of the woollen industry and creation of addition combing capacity.

STATEMENT

Statement showing the rise in price index of woollen goods since 1968

Index Number of wholesale price base : 1961-62-100.

	1968	1969	1970	1971	%Increase
All commodities	165.3	168.7	179.2	182.1	10.8
Raw Wool	96.7	101.4	107.8	105.5	9.1
Woollen manufactures	160.0	167.3	186.8	183.2	14.1

Grant of Licence to Philips India Ltd. for Manufacture of T. V. Receivers

2885. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have decided to grant a licence to Philips India Limited for the manufacture of TV receivers ;

(b) whether indigenous technical know-how with regard to T. V. receivers had been adequately developed at the Pilani Research Institute, Bharat Electronics Limited and the Physical Research Laboratory, Ahmedabad ;

(c) if so, the considerations for allowing foreign companies to manufacture T. V. receivers in India with their imported technology ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (c). To meet the requirements of TV receivers in the Fourth Plan period, applications were invited from all categories of manufactures ; these are under consideration and a decision will be taken in accordance with the current industrial policy and other relevant factors. No decision has been taken by Government to grant a licence to M/s. Philips India Ltd. for the manufacture of TV Sets.

(b) TV sets manufactured on the basis of technical know-how developed by Central Electrical Engineering Research Institute, Pilani are already in the market. Reports have been received to the effect that certain individuals, laboratories and undertakings have also developed TV sets.

Taking over of Bengal Fine Spinning and Weaving Mills, Konnagar (West Bengal)

2886. SHRI B. K. MODAK : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have received the Investigation Committee's report regarding the proposal to take over the Bengal Fine Spinning and Weaving Mills, Konnagar, West Bengal by the Textile Corporation of India :

(b) if so, the main features thereof and

(c) the reaction of Government thereto

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (c). The Investigation Committee which was appointed, under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, to enquire into the affairs of Bengal Fine Spinning and Weaving Mills Ltd., Konnagar, has submitted its reports and it is being examined, in consultation with the State Government, etc. The report is of a confidential nature and, as such, it would not be in the public interest to disclose its contents.

Closure of Bangodaya Cotton Mills, West Bengal

2887. SHRI MANORANJAN HAZRA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the closure of the Bangodaya Cotton Mills, Panihat, 24-Parganas District, West Bengal ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government propose to appoint an enquiry committee to enquire into its closure ; and

(d) if so, when it will be appointed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (d). The mill which closed down on 9.4.71, due to financial difficulties, has restarted working with effect from 12.5.71.

चम्पारन जिले में पटसन मिल की स्थापना

2888. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार के चम्पारन जिले मे चकिया में पटसन की एक मिल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ऐ० सी० जार्ज) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Pending Cases against Landless Tribals and Scheduled Castes in various Courts in Tripura

2889. SHRI BIREN DUTTA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a large number of Police cases against landless Tribal people and landless Scheduled Castes people are pending in various courts in Tripura from 1962 to March 1971 ;

(b) whether the Lt. Governor of Tripura gave assurance that the cases will be withdrawn ; and

(c) if so, the further action taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) to (c). The Government of Tripura have intimated that the requisite information is being collected. It will be placed on the Table of the House when received.

Coordinating Committee for Development of Eastern States

2890. SHRI BIREN DUTTA :
SHRI M. M. JOSEPH :
SHRI DEVINDER SINGH GARCHA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any scheme to form Coordinating Committee for the development of Tripura, Manipur and Meghalaya areas has been accepted by the Government of India ;

(b) if so, the composition and terms of reference of the Committee ;

(c) wheter it will come into existence before the Statehood Bill for Tripura and Manipur is introduced ; and

(d) if so, the reason thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) to (d). In the context of granting Statehood to Manipur, Tripura and Meghalaya, Government are considering the question of having a coordinating agency for the entire North-Eastern region. The details are being worked out. At this stage it is not possible to indicate the precise nature of the legislation for this purpose.

रतलाम में कताई मिल स्थापित किया जाना

2891. डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने रतलाम में एक कताई मिल स्थापित करने हेतु लाइसेंस देने के संबध मे केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ऐ० सी० जार्ज) : (क) और (ख). वर्ष 1965 में मैसर्स रतलाम को आपरेटिव जवाहर मैमोरियल स्पिनिंग मिल्स, रतलाम से रतलाम में कताई मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस के लिए एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था। धन की अप्राप्यता के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया।

Collection of Cess on Tea in Nilgiri District

2892. SHRI J. M. GOWDER : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the amount of Cess on Tea collected from the Nilgiri District in Tamil Nadu in the past three years ;

(b) the manner in which the cess collected has been utilised ;

(c) whether any procedure has been drawn for the utilisation of the proceeds of the cess in the areas of collections and for the benefit of the industry in general and

for the welfare of the labour in particular ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) The amount of cess collected from the Nilgiri district in Tamil Nadu is given below :

1968-69	Rs. 12,24,566
1969-70	Rs. 13,72,713
1970-71	Rs. 13,84,752

(b) Cess on Tea is collected by Central Excise Department and proceeds thereof are credited to consolidated Fund of India after deducting collection charges at the rate of half per cent. Thereafter Central Government releases such sums of money as it thinks fit with a view to enabling Tea Board to meet expenses incurred by them for carrying out functions enumerated in the Tea Act.

(c) and (d). In keeping with functions of the Board as enumerated in the Tea Act procedures have been laid down in the Tea Rules 1954 for submission of Budget Estimates under various stipulated heads of expenditure like tea development, promotion of tea in India and abroad, research, labour welfare etc. Funds are allocated on the basis of the overall needs of the Tea Board in relation to priority of different aspects of tea industry requiring immediate attention including labour welfare measures not covered by Plantation Labour Act.

New Building for P. and T. Head Office at Irinijalakkuda (Kerala)

2893. SHRI M. K. KRISHNAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the acute lack of space in the present Posts and Telegraphs Head Office Irinijalakkuda, Kerala ;

(b) whether a plan for construction of new building was finalised by the Central Architect years back ; and

(c) the reasons for delay in the construction of new building ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes. A portion of the post office has therefore been shifted to a nearby building which was taken on rent in 1969 in an attempt to solve this problem. The present shortage is about 1100 sq ft.

(b) Only a rough layout plan showing the proposed extension of the building on the site has been received from the Architect in January, 1970 by the Postmaster General, Trivandrum. Detailed plans and preliminary drawings are still under preparation.

(c) The delay is due to several projects having to be attended to at the same time. This project has, however, been given a higher priority and is being expedited.

Export of Agar from Manipur

2894. SHRI N. TOMBI SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned annually from the sale of Manipur Agar to foreign countries ;

(b) the countries buying Agar from Manipur ; and

(c) the agencies appointed for such trade ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (c). State-wise Export Statistics are not maintained.

Song and Drama Division Unit Imphal

2895. SHRI N. TOMBI SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the Imphal Unit of the Song and Drama Division of the Information and Broadcasting Ministry has been equipped with a full-fledged Drama Troupe ;

(b) if so, since when and the strength and paraphernalia thereof ; and

(c) if not, when such a troupe is likely to be introduced ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) to (c). The Imphal Unit of Song and Drama Division is established under Border Publicity Scheme which gives

performances in local dialects and local art forms. Due to the geographical situation of the area, they have to traverse difficult terrain and to perform in small pockets of population dispersed in these areas. Six more similar units are established under the same scheme. This sort of units are more suitable for these areas. There is no proposal to convert them into full-fledged teams.

Security of Service for Artistes of Song and Drama Division

2896. SHRI N. TOMBI SINGH : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government have provided security of service to the various categories of artistes employed by the Song and Drama Division of the Information and Broadcasting Ministry ; and

(b) if so, what are those ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) and (b). The staff artistes in Song and Drama Division, other than those engaged for special short duration assignments, are employed on contracts which are renewed from time to time, subject to their maintaining physical fitness, performing efficiency and good conduct. No contract is terminated unless the case is examined by a screening Committee and orders passed by the competent authority on the findings/recommendations of that Committee. The following instructions have been issued in this connection :

(1) No contract will be terminated without passing written orders on the written findings/recommendations of the Screening Committee.

(2) The findings of Screening Committee will indicate specific reasons while recommending renewal/termination of contracts.

(3) The Director will agree or disagree in writing to the findings of the Screening Committee.

(4) After the Director's orders are obtained and if it is agreed that the contract requires termination, the usual procedure of giving prescribed prior notice will be observed.

Structural Reforms in District Administration of Tripura

2897. SHRI N. TOMBI SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the structural reforms introduced in respect of the District Administration after the division of Tripura into five districts ;

(b) whether reforms were introduced on the recommendations of the Commission or Committee appointed for the purpose ;

(c) if so, the composition of such Committee or Commission, its terms of reference and findings ; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative the basis for the introduction of reforms ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) The Union territory of Tripura was divided into three districts with effect from 1-9-1970 as under :

Name of the District	Sub-Division	Headquarters of the District	No. of Circles	No. of Tehsils
1	2	3	4	5
1. West Tripura District	1. Khowai 2. Sadar 3. Sonamura	Agartala	6	79
2 North Tripura District	1. Dharmanagar 2. Kailasahar 3. Kamalpur	Agartala (Temporary, pending construction of permanent Headquarters in Kumarghat)	5	48

1	2	3	4	5
3. South Tripura District	1. Udaipur 2. Belonia 3. Amarpur 4. Sabroom	Agartala (Temporary, pending construction of permanent Headquarters in Udaipur).	6	50

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) The reorganisation was effected keeping in view the following considerations :

(1) to ensure a direct and integrated approach in the planning and speedy execution of development programmes in the border areas ;

(2) to tackle more adequately the law and order problems, particularly in the remote localities ; and

(3) to help better collection of land revenue and maintenance of land records.

Radio Station at Trichur

2898. SHRI C. JANARDHANAN :
SHRI A. K. GOPALAN .

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum to raise the existing Radio Station at Trichur to an independent Radio Station; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) Yes, Sir.

(b) Work on establishment of permanent studios and improvement of studio facilities is under way.

Commemorative Stamps

2899. SHRI C. JANARDHANAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of Postal Stamps published so far from 1969 to March 1971 to commemorate celebrated events and individuals; and

(b) whether Government are considering to publish stamps in memory of heroic R. I. N. Mutiny of 1946 ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) 55

(b) The proposal was examined by the Philatelic Advisory Committee attached to the P & T Deptt. but the Committee did not recommend the acceptance of the proposal.

Rampur Automatic Telephone Exchange

2900. SHRI ZULFIQUAR ALI KHAN :
SHRI RUDRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether he has received any complaints regarding technical defects in the Rampur Automatic Telephone Exchange in Uttar Pradesh;

(b) if so, the action taken thereon; and

(c) how much time it will take to remove all defects ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H.N BAHUGUNA : (a) Yes Sir.

(b) The exchange equipment has been overhauled under direct supervision of an officer and faulty components of the equipment have been repaired. Action has also been taken for preventive maintenance of subscribers' offices to reduce the number of interruptions.

(c) It will take some time to rectify some of the defects due to non-availability of spare parts. Efforts are being made to arrange the supply of the required spare parts as early as possible.

Foreign Missionaries in India

2901. SHRI BRIJRAJ SINGH-KOTAH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries working in India, State-wise;

(b) the number of persons converted by these missionaries during the last three years; and

(c) the number of missionaries who were asked to leave certain areas and who have come again to start their work ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) A statement showing, State-wise, the number of registered foreign (Including Commonwealth) missionaries in India is placed on the Table of the House.

(b) Except the Madhya Pradesh Dharma Swatantrya Adhiniyam, 1968, which came into force on the 20th October, 1968, there is no law for intimation or registration of conversions from one religion to another. The information asked for is, therefore, not available.

(c) Foreign missionaries who are asked to leave an area are not normally allowed to return to work in the same area.

Statement

Registered Foreign Missionaries present in India.

Sl. No.	State	Number other than Commonwealth Missionaries.	Commonwealth Missionaries
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	263	175 @
2.	Assam	136	73 *
3.	Bihar	328	179 *
4.	Gujarat	167	16 @
5.	Haryana	4	12 @
6.	Himachal Pradesh	6	40 @
7.	Jammu & Kashmir	9	36 @
8.	Kerala	150	35 @
9.	Madhya Pradesh	184	83 *
10.	Maharashtra	433	344 *
11.	Mysore	308	193 @
12.	Nagaland	4	— @
13.	Orissa	90	54 @
14.	Punjab	62	58 *
15	Rajasthan	20	18 @
16.	Tamil Nadu	497	366 @
17.	Uttar Pradesh	264	198 @
18.	West Bengal	205	286 @
19.	Andaman & Nicobar Islands	—	—
20.	Chandigarh	—	—
21.	Dadra & Nagar Haveli	—	—
22.	Delhi	55	74 @
23.	Goa. Daman & Diu	27	21 *
24.	L. M. & A.I.S.	—	—
25.	Manipur	—	—
26.	Pondicherry	10	1 @
27.	Tripura	—	18 @

* As on 1-1-70

@ As on 1-1-71

Activities of Foreign Missionaries

2902. SHRI BRIJRAJ SINGH-KOTAH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is a feeling among public against increasing proselytizing activities of foreign missonaries in the country ;

(b) whether in Bombay some missionaries are attempting to bring about conversions on a 'Commission Basis' ; and

(c) if so, the nature of tourist *visas* and privileges granted to them by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). No reports have been received to show that there is increase in the proselytizing activities of foreign missionaries or that some missionaries in Bombay are attempting to bring about conversions on a 'Commission Basis'.

(c) Foreign missionaries who come to India for tourism are, like other foreigners, granted tourist *visas* valid for three months

stay, extendable to six months. They are not expected to engage in any business or to under take any work paid or unpaid, while in India. No special privileges are accorded to them.

Committee on Centre-State Relations set up by Tamil Nadu Government

2903. SHRI MUHAMMED SHERIFF :
SHRI N. SHIVAPPA :
SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Centre-State Relations Committee set up by the Tamil Nadu Government had given its recommendation for some constitutional amendments that would invest the States with inereased power in matters of planning, finances, taxation and judiciary ; and

(b) if so, the main points thereof and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). Government have seen press reports in this regard. Government have, however, not received a copy of the report for the Government of Tamil Nadu, so far. Questions relating to Centre-State relations have been studied in depth by the Administrative Reforms Commission and the Study Team appointed by the Commission. The Administrative Reforms Commission have come to the conclusion that "the provisions of the Constitution governing Centre-State relations are adequate for the purpose of meeting any situation or resolving any problem that may arise in this field". The recommendations of the Administrative Reforms Commission on Centre-State relationships are under examination.

All India Radio Station in Kanpur

2904. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether All India Radio Station in Kanpur is only meant to relay Vividh Bharati Programme ; and

(b) if so, the reason for not converting it into a regular Broadcasting Station ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): (a) Yes, Sir.

(b) This area is very well served by the station at Lucknow.

Setting up of an Electronic Commission

2905. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Electronics Commission visualised in the President's Address last March has been set up ;

(b) whether its members have been appointed ;

(c) if so, their names and other details ; and

(d) what programme of research and development is going to be taken up by the Commission in the first instance ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) Yes.

(b) and (c). Prof. M. G. K. Menon is the Chairman of the Electronics Commission and Secretary to the Government of India in the Department of Electronics. The following have been nominated as members of the Electronics Commission :—

1. Shri T. Swaminathan,
   Cabinet Secretary.
2. Shri B. D. Pande,
   Secretary to the Government of India,
   Ministry of Finance.
3. Shri A. S. Rao,
   Managing Director,
   Electronics Corporation of India Ltd.
   Hyderabad.
4. Shri M. S. Pathak,
   Chairman and Managing Director,
   Engineers (India) Ltd ,
   New Delhi.

Members of the Commission will hold office for a period of two years.

(d) The Electronics Commission will not itself carry out research and development work. In this regard the important task before it is of ensuring that R and D of the appropriate type is carried out in the country and full sppport, financial and otherwise made available for this. The

Electronics Commission plans to identify specific areas where massive R and D efforts should be carried out.

Production of Documentary Films at Calcutta Studios

2906. SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI : Will the Minister INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) why the Documentary Films of the Central Government are not being produced from the Calcutta studios ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) Some documentary films of Films Division are assigned to film producers of Calcutta.

(b) Does not arise.

Obscene Posters and Films

2907. SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the specific suggestions or plans of his Ministry for the Film Censors Board in regard to obscene posters and films ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : Exhibition of obscene films is prohibited under the Cinematograph Act, 1952. Censorship of posters falls outside the purview of this Act. State Government and municipal authorities have, however, ample powers to take action against obscene film posters under Section 292 of the Indian Penal Code and other local laws. The attention of all State Governments and Governments of Union Territories has been drawn to this matter with a request to keep a strict watch on display of obscene film posters.

Constitution of Film Development Board

2908. SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether a Film Development Board is proposed to be formed for the general development of Bengali, Tamil, Assames, Oriya and Hindi films ; and

(b) if so, when ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) and (b). Central Government are not aware of any proposal to set up a Film Development Board for general development of Bengali, Tamil, Assamese, Oriya and Hindi films. West Bengal Government had, however, appointed a State Film Consultative Committee in June, 1969. The Committee had recommended, *interalia*, the setting up of a statutory Film Development Board for improving film industry in the State. This recommendation is presently under consideration of West Bengal Government.

Utilization of Atomic Energy for Human Welfare

2909. SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether Government have any plan to utilise atomic energy for human welfare ; and

(b) if so, the main features of the plan ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) Yes, Sir. Details are available in the document entitled "Atomic Energy and Space Research—A Profile for the decade 1970-80" copies of which are available in the Parliament Library.

(b) The plan for the current decade envisages the addition of 2300 MWe of electric power from atomic power stations under construction and to be established in various parts of the country.

The plan for the utilization of radio-isotopes and radiations in the field of agriculture and industry envisages the setting up of irradiators for (a) grain disinfestation (b) treatment of food items such as onions, potatoes, fish, etc., for extending their shelf life (c) sterilisation of medical products, and

(d) industrial applications such as manufacture of wood/plastic products. In the field of medicine, it is planned to establish a number of Radiation Medicine Centres and small Isotope Laboratories in different parts of the country for extending the benefits of nuclear medicine to as wide a cross-section of the population as possible.

Expenses on Bhabha Atomic Research Centre

2910. SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) the actual expenses on the Bhabha Atomic Research Centre ; and

(b) what are the provisions as regards allocation of seats in the said Centre to the States of India ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIARS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) The actual expenses on the running of the Bhabha Atomic Research Centre for the year 1970-71 amounted to Rs. 11.83 crores.

(b) The Bhabha Atomic Research Centre is the national centre for research and development in the field of atomic energy. Recruitment to the various posts in the Centre is made on an all-India basis. The question of allocation of seats does not. therefore, arise.

Rules Governing Recruitment of Munsiffs and Seniority of Mysore Government Employees

2912. SHRI TEJA SINGH SWATANTRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there are any rules governing the recruitment of Munsiffs and the seniority of Government servants in Mysore; and

(b) if so, whether the copies of these rules would be laid on the Table of the House ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b). The requisite information has been called for from the Government of Mysore and will be placed on the Table of the House as early as possible.

Suspension of Employees in Mysore

2913. SHRI TEJA SINGH SWATANTRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the number of Government employees in the Mysore State placed under suspension in 1965 for violation of Rule (5) of the Conduct Rules at Mysore State Employees ;

(b) whether the said Rule (5) was challanged in the Mysore High Court and later Government appealed in the Supreme Court ;

(c) what were the main points of judgements of the two courts ; and

(d) the steps taken by Government in the light of those judgements ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (d). The information is being collected from the Government of Mysore and will be placed on the Table of the House when received

Reconstitution of Programme Advisory Committees of A.I.R.

2914. SHRI MUHAMMED SHERIFF: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government have decided to reconstitute the Programme Advisory Committees attached to All India Radio Stations in the country ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) Yes, Sir.

(b) To make them more representative of the various interests to be reflected in the programmes broadcast from All India Radio.

Test Breeder Reactor

2915. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether the Atomic Energy Commission has succeeded in making Test Breeder Reactor ;

(b) if so, the particulars thereof ;

(c) whether such reactor will facilitate accumulation of further amount of fissionable materials ;

(d) whether, for applying nuclear energy for engineering purposes, the Atomic Energy Commission has drawn out any plan for nuclear blast test ; and

(e) if not, the reasons therefore ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) Detailed designing of the fast breeder test reactor, in collaboration with France, is nearing completion. Construction is expected to commence before the end of the year.

(b) The reactor will be fuelled with plutonium and uranium and will have molten sodium as coolant. It will have a nominal thermal power output of 42.5 MWe. A turbo generator using high pressure steam will provide electrical energy.

(c) The reactor will produce fresh fissionable material, but because of its small size it will not produce more than what it consumes.

(d) and (e). The Atomic Energy Commission is currently studying the situation under which peaceful nuclear explosions carried out underground can be of economic benefit to India without causing environmental hazards.

Admission of Bullet Injured Persons in Indian Hospital who crossed into India

2916. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the bullet injured persons who crossed into India have been admitted into Indian Hospitals of Eastern States ;

(b) the number of such wounded persons admitted in hospitals and how many of them died in hospitals ;

(c) the number of women and children among such patients ; and

(d) how many of these patients belong to political parties ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) to (d). According to the information received from Tripura Government, 468 East Bengal refugees having bullet injuries were admitted to the hospitals as indoor patients. Among them were 96 women and children. Out of 468 refugees, 31 died in the hospitals. No injured refugees have been treated in Manipur hospitals.

Information from the State Governments of West Bengal, Meghalaya and Assam is awaited.

Upgradation of Sub-Post Offices in Cooch-Behar (West Bengal)

2917. SHRI B.K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether requests from local people of Sitai in the District of Cooch-Behar, West Bengal to upgrade the Extra Departmental Post Office to a Sub-Post Office has remained pending for the last three years ;

(b) if so, the reasons therefor and how soon the said Post Office will be upgraded ; and

(c) the number of such requests from the District of Cooch-Behar pending before the Department and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b). Repuest for upgradation of Setaihat extra departmental branch Post Office to a departmental sub-office was earlier examined in 1953, 1958, 1961 and 1963 but each time it was found that the upgradation was not justified. Request for upgradation was again received in may, 1963 and September, 1970 but on these two occasions also upgradation was not found justified. The office will have work for only 3 hours and 21 minutes as against the minimum of 5 hours. Postmaster General,

Calcutta has been asked to examine if the office can be upgraded to an extra departmental sub-office.

(c) There are four requests for the opening of extra departmental branch offices and one request for the opening of a departmental town sub-office which are being examined by the Department. Postmaster General, Calcutta has been asked to expedite examination of these proposals.

Broadcasting Station "Kurseong" at Siliguri

2918. SHRI B.K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether the Broadcasting Station known as "Kurseong" in Siliguri in the weakest Station in India ;

(b) whether the service rendered by this Station frequently goes out of order ;

(c) whether there is any Advisory Body attached to that Station ; and

(d) if so, the criteria for membership of that Advisory Body and the names of the existing members ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) to (c). No. Sir.

(d) Does not arise.

आकाशवाणी तथा टेलीविजन केन्द्र द्वारा राजनैतिक दलों के साथ व्यवहार में कथित असमानता

2919. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राजनैतिक दलों ने यह शिकायत की है कि आकाशवाणी तथा टेलीविजन केंद्र सभी दलों के साथ एक समान व्यवहार नहीं करते हैं तथा शासक दल को विशेष सुविधायें प्रदान करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस सम्बंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) कुछ ऐसी शिकायतें जिनमे सत्तारूढ़ दल की तरफदारी करने के आरोप थे, कुछ अन्य राजनैतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी । जांच करने पर वे शिकायतें निराधार पाई गई ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक

2920. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की समिति की एक बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 22 मई, 1971 को आयोजित हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिए गए है तथा उसके पश्चात् क्या ठोस कदम उठाये गये और उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नही, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

Automatic Telephone Exchange at Kotah

2921. SHRI BRIJRAJ SINGH-KOTAH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state when Government propose to install an automatic Telephone Exchange at Kotah ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : Installation to automatic exchange has already been planned for Kotah. According to present assessment it is hoped it will be possible to commission the exchange by 1975-76.

Plant for Separating Ilmenite Fraction from Monazite Sands for Extraction of Titanium Metal

2922. SHRI DEVINDER SINGH GARCHA : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether the Geologists of the Atomic

Energy Commission have established the existence of precious monazite sands in the east-coast stretching from the mouth of river Mahanadi right upto Southern tip of Lake Chilka ;

(b) whether the Atomic Energy Commission is to set up a plant in which ilmenite fraction will be separated from monazite sands and then concentrated to constitute the source for the extraction of titanium metal ; and

(c) if so, how long it will take to set up the Plant ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) Surveys carried by Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy along the Puri Coast, have received low monazite content in beach sands.

(b) Indian Rare Earths Ltd. (IRE), a public sector undertaking of the Department of Atomic Energy, is currently examining the possibility of separating ilmenite from the mineral sands along the Chhattrapur coast of Ganjam District in Orissa The Company is also exploring the possibility of preparing titanium sponge from ilmenite

(c) A decision to proceed with the new schemes must await completion of the prehminary studies currently in progress.

Farm Broadcast over A.I.R.

2923. SHRI BISHWANATH JHUNJHUNWALA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state i

(a) whether in their Farm Broadcasts, the A.I.R. commentators give specific advice to the farmers in the respective State about the timing for sowing of crops, nature of fertiliser to be used and about the availability of the same ;

(b) if not, whether Government propose to make these broadcasts more purposeful by giving such pieces of advice ; and

(c) how many of the agricultural experts are constantly associated with such programmes and whether the A. I. R. conduct any field survey to assure itself of the efficacy of the broadcasts ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Consultative Panels consisting of four to six agricultural experts are attached to all All India Radio Stations which broadcast farm programmes. In addition, experts of State Governments in the fields in which campaigns are launched and progressive farmers are also associated with these programmes.

Evaluation of these programmes is made on the basis of listeners' letter and by the Listener Research Organisation of All India Radio.

Establishment of National Extension Service for Ginning Factories

2924. SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI N. SHIVAPPA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish a National Extension Service to inspite all ginning factories and give them advice on improvement of their machinery in order to ensure that no damage occur to cotton fibres during ginning ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the funds allocated for this purpose ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) There is no proposal under Government's consideration.

(b) and (c). Do not arise.

Beating of a Couple near India Gate by Delhi Policemen

2925. SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a couple was assaulted by the mounted policemen on the 6th June 1971 at India Gate, New Delhi ; and

(b) if so, what action is being taken against the culprits ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) Three Policemen (including two mounted Policemen) of Delhi are alleged to have assaulted a couple near India Gate on 6th June, 1971.

(b) A case under Section 342/379/323 IPC was registered at Police Station, Parliament Street. All the three accused have been arrested and placed under suspension. The investigation of the case is in progress under the direct supervision of an Additional Superintendent of Police.

Export of "Anand Asahi" Metres to South Vietnam

2927. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether India is exporting 'Anand Asahi' metres to South Vietnam ; and

(b) if so, the annual earning of foreign exchange through this project ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). Official export statistics are maintained commodity-wise and not brandwise. However, the manufacturers of water metres of this particular brand are understood to have secured an order for supply of 28,875 water metres valued at Rs. 12.74 lakhs to South Vietnam out of which exports worth Rs. 2.34 lakhs have already been made during 1970-71.

Growth Rate for 1970-71

2928. SHRI N. SHIVAPPA :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :

Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether expected growth rate of 6.5 per cent for 1970-71 could not be achieved ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) and (b). The Annual Plan 1970-71 envisaged a growth rate of 5.5 per cent. No firm estimate of the growth rate in 1970-71 is yet available. However indications are that the growth rate of a similar order as in 1969-70 may be achieved The growth rate in agriculture has been satisfactory. There has been some shortfall in the case of industrial production in 1970-71. This has been mainly due to shortage of agro-based industrial raw materials, steel, non-ferrous metal and power and deterioration in industrial relations.

(c) In order to step up the rate of growth in the remaining years of the Fourth Plan, Government is taking measures to stimulate industrial as well as agricultural output. A re-appraisal of the Fourth Plan is also under way.

Modernisation of Cotton Gins

2929. SHRI N. SHIVAPPA :
SHRI RAJDEO SINGH :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the names and number of cotton gins in the country, State-wise, at present ;

(b) whether machinery used by the cotton gins are old and require modernisation ; and

(c) whether the machinery required for modernisation of gins are indigenously available or have to be imported ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Statewise number Gins in India according to the information available in the Ministry at present is as under ;

State	No. of working Ginning Factories
1	2
Assam	13
Andhra Pradesh	47
Gujarat	428
Madhya Pradesh	252
Maharashtra	779
Mysore	517
Punjab (earthwhile)	41

1	2
Rajasthan	19
Tamil Nadu	103
Tripura	2
West Bengal	5
All India Total	2211

Information about the names of these gins is not available.

(b) The gins installed in many factories are believed to be old but these are reported to be working satisfactorily with periodic replacement of the working parts like rollers, knife etc.

(c) Single roller as well as double-roller gins are indigenously available. However, sawgins have to be imported.

तम्बाकू का मूल्य

2930. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा गत दो वर्षों में कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया गया ;

(ख) (अमेरिका, ब्रिटेन, तथा पश्चिम जर्मनी में) तम्बाकू का प्रति किलोग्राम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है ; और

(ग) भारत में तम्बाकू उत्पादकों को प्रति किलोग्राम तम्बाकू का कितना मूल्य प्राप्त हो रहा है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ऐ० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1969 तथा 1970 में क्रमश: 33.32 करोड़ रुपये तथा 31.59 करोड़ रुपये मूल्य के भारतीय तम्बाकू का निर्यात हुआ ।

(ख) तथा (ग). तम्बाकू की अनेक श्रेणियां हैं, अत: ठीक ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

मन्दसौर, मध्य प्रदेश में सीधी टेलीफोन व्यवस्था

2931. **डा० लक्ष्मीनारायण पंडे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं जो दिल्ली, भोपाल, इन्दौर, बम्बई, जयपुर, उदयपुर तथा अहमदाबाद के साथ सीधी टेलीफोन व्यवस्था द्वारा जुड़े हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार शेष स्थानों से भी सीधी टेलीफोन व्यवस्था आरम्भ करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (ग). मन्दसौर जिले में कोई भी स्थान दिल्ली, भोपाल, इन्दौर, बम्बई, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद के साथ सीधी टेलीफोन व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है । इस समय इन शहरों के लिए ट्रंक परियात बहुत कम होने के कारण सीधी डायलिंग चालू करने का औचित्य नहीं है ।

मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले में सार्वजनिक टेलीफोन

2932. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्दसौर जिले में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर चालू वर्ष में सरकार द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाने का विचार है ;

(ख) क्या इन स्थानों में नाहरगढ़ और नगावी भी शामिल हैं ;

(ग) क्या जनता ने अनेक बार मांग की हैं कि उक्त स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जावें ; और

(ङ) किसी स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध करने के लिए सामान्यतया किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) माहूरगढ़ और नगावी (ठीक नाम बावरी है) में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

(घ) सामान्यत: किसी स्थान के लिए प्रस्ताव के लाभकर होने पर वहां टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था की जाती है ।

घाटा होने की स्थिति में यदि उसमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी विभाग को होने वाले घाटे की पूर्ति करने के लिए तैयार हो तो किराये और गारंटी के आधार पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा सकती है ।

फिर भी यदि कोई स्थान निम्नलिखित वर्गों में से किसी के अन्तर्गत हो, तो वहां घाटे के आधार पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा सकती है :—

1. जिला मुख्यालय
2. उप-मंडल मुख्यालय
3. तहसील मुख्यालय
4. उप-तहसील मुख्यालय
5 20,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और शहरी क्षेत्रों में 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान ।
6. निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज से 40 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्थान पर सीमित संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं ।
7, निम्नलिखित स्थानों पर भी सीमित संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा सकते हैं :

(क) तीर्थ स्थान/पर्यटन स्थल ;

(ख) सिंचाई और परियोजना स्थल और टाउनशिप ।

Export of Castor and Groundnut Cakes through Canalised Agency

2933. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the volume and value of total exports of Castor and Groundnut Cakes from India ;

(b) whether these items are canalised through an agency, approved and recognised by the Government of India and, if so, the name thereof ;

(c) the detailed procedure that this agency pursues regarding such canalising and approval of export sales of the goods by the private parties ;

(d) the basis for settlement of claims and receipts of payments from the foreign-buyers , and

(e) whether new parties are not allowed to enter in this business of exports ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Castor cake and meal are not separately classified in the Revised Indian Trade Classification and as such their export statistics are not available. Export of Groundnut meal has been as follows :

Groundnut Extractions

Period	Quantity	Value
	('000' tonnes)	(Rs. lakhs)
1968-69	682	4195
1969-70	510	3272
1970-71	483	3279

(b) Export of castor cake is not canalised through any agency. Export of groundnut oil cake (expeller variety) is banned. Export of groundnut extraction is canalised through the Groundnut Extractions Exports Development Association,

which is recognised and approved by Government for the purpose.

(b) The Groundnut Extractions Export Development Association has laid down a code of discipline with a view to achieve diversification and expansion of markets.

(d) The basis for settlement of claims and receipts of payments from the foreign buyers is through normal banking channels and is left to the individual members.

(e) There is no restriction on entry of new parties in export business, provided they become members of the Groundnut Extractions Export Development Association before export and abide by the code of discipline laid down by the Association.

Nomination of Non-Officials to Cashew Corporation

2934. SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the non-officials to the Cashew Corporation have since been selected and nominated by the Government ;

(b) if so, their names ;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay ; and

(d) the time by which the non-official Members will be nominated ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir.

(b) Shri C. M. Stephen, M.P. is the only non-official, considered and nominated to the Board of Directors of the Cashew Corporation of India.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

पछेरीबाड़ी राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोला जाना

2935. श्री शिवनाथ सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के झुनझुनु वाला जिले में पछेरीबाड़ी स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय के खोले जाने के लिए काफी समय से मंजूरी होने के बावजूद भी उस स्थान पर अभी तक भी यह कार्यालय नहीं खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय को कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) राजस्थान के झुंझुनु जिले में पछेरीबाड़ी स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की अभी मन्जूरी नही दी गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Public Call Offices in Rural Areas in Gujarat State

2936. SHRI P. M. MEHTA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that villages in Bhavnagar and Amreli Districts of Gujarat State are deprived of the Telephones facilities of Public Call Offices ; and

(b) if so, the steps taken and proposed to be taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Telephone facility is normally provided at a place if the scheme works out to be remunerative. However, in order to extend this facility to undeveloped areas, the department has evolved a policy according to which telephone facility can be provided on loss basis at certain categories of stations based on their administrative importance, population and remoteness, from general Telecommunications net-work. Limited number of pilgrim/tourist centres, agriculture and Irrigation projects sites and townships are also considered for provision of telephone facility on loss basis.

If a place does not fall in any of the above categories and the proposal to provide telephone facility shows loss, the facility can be provided on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the department against the loss.

In accordance with the above policy all places in Bhavnagar and Amreli Districts entitled to provide provision of telephone facility on loss basis have been provided with the facility.

(b) Action is being taken to provide telephone facility at places for which the demands are received, in accordance with the above policy.

Dispute between Chandigarh Administration and S.T.C. Regarding Prices of Roses

2937. SHRI C. CHITTIBABU : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there is a dispute between the Chandigarh Administration and the State Trading Corporation regarding the prices of Roses to be exported ;

(b) if so, the main points of the dispute ; and

(c) how Government propose to resolve the dispute before India losses the foreign market for Roses ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) to (c). There have been some discussions between the Chandigarh Administration and the S.T.C. regarding the price of Roses bought by the S.T.C. from the Chandigarh Administration. The season for the export of roses is from November-February. Further discussions will be held at an appropriate time before the commencement of the next season with a view to arriving at a mutually acceptable price.

बिहार के चम्पारन जिले में टेलीग्राफ सबडिवीजन

2938. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के चम्पारन जिले में टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने का विचार है ;

(ख) क्या उक्त जिले में एक अलग टेलीग्राफ सबडिविजन बनाने का भी विचार है ; और

(ग) यदि हां तो इसमें कितना समय लगेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) चम्पारन जिले में टेलीफोन सेवा के विस्तार का कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का विचार नहीं है ।

(ख) इस समय चम्पारन जिले में अलग तार सबडिवीजन की मन्जूरी का कोई मामला भी नहीं है ।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

Appointment of a Suicide Enquiry Committee

2939. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have appointed any Suicide Enquiry Committee to tackle the basic problems of suicide cases in the country ; and

(b) the number of women who die of burn injuries annually and the rate of suicide due to domestic unhappiness in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) No, Sir.

(b) According to the statistics compiled by the Central Bureau of Investigation, there were 40,688 cases of suicide in the year 1968 ; of them 24,464 were males and 16,224 females. In 2124 cases (both male and female) suicide was committed by setting fire to oneself ; no separate figures for males and females are available.

Government Quarters for Engineering and Line Staff at Jatni, Orissa

2940. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Goverment that there are no quarters for the employees of the Engineering Line staff working at Jatni in Orissa Circle yet ;

(b) whether the two Railway quarters which have been taken for this purpose are not being repaired for years as a result of which it is not worth living ; and

(c) whether Government are considering to make provision for quarters for the Posts and Telegraphs employees and the Line staff at Jatni ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes Sir, there are no departmental quarters available at Jatni at the moment. However three numbers of Railway quarters have been taken on rent for line staff.

(b) The three (not two) Railway quarters are maintained by the Railway Administration. The Circle Authorities have not received any complaint so far that they are not being repaired and that they are not in a condition worth living.

(c) 12 units of quarters have been sanctioned and are nearing completion for P & T staff at Jatni.

Building for Jatni Telephone Exchange

2941. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Telephone Exchange at Jatni in Orissa has not its own building yet, although it has a piece of land ; and

(b) if so, whether Government propose to construct a building for the telephone exchange soon ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir.

(b) P & T Deptt. has already initiated necessary action for construction of Telephone Exchange Building.

Recruitment to B.S.F. and C.R.P.

2942. SHRI N. S. BIST : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have instructed the Border Security Force and Central Reserve Police to recruit maximum number of persons from Jammu and Kashmir (vide news item appearing in the Statesman dated the 24th May, 1971) ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). The intention of Government is that the Central Forces like the Border Security Force, Central Reserve Police, etc., should recruit its personnel on an all India basis so as to ensure that the Forces bear a national character ; and with this object, Government have issued instructions to the authorities in charge of these forces to ensure recruitment from all parts of the country, with special emphasis on those areas like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, the hill districts of Uttar Pradesh etc., from which recruitment in the past has not been adequate.

प्याज के निर्यात में कमी

2943. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से प्याज के निर्यात में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों मे प्याज के निर्यात में कितनी गिरावट आई है ;

(ग) क्या सरकार ने आयात करने वाले देशों के लिए अपेक्षित प्याज के गुण का पता लगाने के बारे मे कोई सर्वेक्षण किया है अथवा करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) तथा (घ). सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, यद्यपि निजी व्यापारी नये बाजारों में निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं । जहाँ तक भविष्य में इस प्रकार के प्रस्तावित अध्ययन का सम्बन्ध है, इस की आवश्यकता अनुभव होने पर इस पर यथा-समय विचार किया जायेगा ।

Medical Treatment for P & T Employees at Jhumari Tilaiya

2944. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the P and T employees

stationed at Jhumari Tilaiya are facing hardships in getting medical treatment for themselves and their family members due to non-availability of Government Hospital with facilities of Indoor Treatment at Jhumari Tilaiya in Bihar State;

(b) whether the Coal Mines Organisation is running a Medical Hospital at Karma in the Hazaribagh District of Bihar State which is the nearest hospital for the Jhumari Tilaiya Telephone Exchange, Post Office and Kodarma Railway Station;

(c) whether the authorities of Karma Medical Hospital deny treatment to the P and T employees of Jhumari Tilaiya and R.M.S. employees of Kodarma because this hospital is not a recognised hospital for treatment of P and T employees and their family members; and

(d) the steps Government propose to take to get the Karma Medical Hospital recognised for treatment of the P and T employees and their family members stationed at Jhumari Tilaiya and the R.M.S. employees and their family members working at Kodarma Railway Station?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The question of denial of treatment to P and T employees does not arise as treatment is allowed to 'non-entitled' patients on payment.

(d) The question of recognition of the Karma Medical Hospital for Medical treatment of P and T employees and their family members is under active consideration in consultation with the Ministry of Labour and Employment. A final decision in the matter will be taken as early as possible.

P and T Employees' Treatment at Bokaro Steel City Hospital

2945. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8873 on the 7th May, 1970 and state:

(a) whether the Postmaster-General Bihar Circle, has already recommended to the P and T Staff and their family members in the Bokaro Steel City Hospital by according sanction of funds required for the purpose;

(b) whether whenever any officer of the P and T Department has visited the Bokaro Steel City, the Service Unions have represented the case and still no solution of problem has been found out; and

(c) the reasons for not arranging medical treatment and re-imbursement facilities at the Hospital for P and T Staff?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) to (c). Instructions have already been issued by the Postmaster-General, Bihar Circle for treating the Bokaro Steel City Hospital as a 'recognised hospital' for purposes for medical treatment of P and T employees and the members of their families and of payment of advances to employees to enable them to pay the prescribed security deposit of Rs. 200/-, wherever necessary, in order to secure admission in the hospital for indoor treatment. Medical re-imbursement facilities are thus now available to the P and T employees in Bokaro.

Medical Treatment of P and T Employees at Bermo

2946. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the P and T employees stationed at Bermo are facing hardship in getting treatment for themselves and for their family members at Bermo (Hazaribagh District in Bihar State) due to non-availability of Government Hospital with indoor treatment facility at Bermo;

(b) whether authorities of the Phushro Hospital nearest to Bermo run by the Coal Mines Organisations deny treatment to P. and T. employees and their family members there because it is not a recognised Hospital for treatment on the P and T employees and their family members;

(c) whether the P. and T. employees are eligible for receiving medical treatment under the A.M.A. Rules of the Department; and

(d) if so, whether Government propose to take steps to get the P and T employees and their family members treated at the Phushro Hospital under Ministry of Labour?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes.

(b) The question of denial of treatment to P and T employees does not arise as treatment is allowed to 'non-entitled' patients on payment.

(c) Yes.

(d) The question of recognition of the Phusro Hospital for Medical treatment of P and T employees and their family members is under active consideration in consultation with the Ministry of Labour and Employment. A final decision in the matter will be taken as early as possible.

गढ़वाल जिले (उत्तर प्रदेश) में नये डाक-घर

2947. श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में कितने नये डाकघर खोले गये हैं ;

(ख) वर्ष 1971-72 में वहां कितने नये डाक-घर खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) चालू वर्ष में कितने नये डाक घरों में तारघरों की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 9.

(ख) 10.

(ग) 9.

गढ़वाल जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

2948. श्री प्रताप सिंह नेगी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश का गढ़वाल जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त जिले को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़वाल जिले को पहले से ही उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला निर्धारित कर दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Commercial Advertisements over A.I.R.

2949. SHRI S. A. MURUGANANTHAM : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of Radio Stations where commercial advertisements have been introduced ; and

(b) the income derived by each Station from these advertisements ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) Eighteen.

(b) A statement showing gross income at each of these centres is enclosed.

Statement

Statement of Gross Income earned from Commercial Centres of All India Radio.

Stations Date of starting	1967-68 Rs.	1968-69 Rs.	1969-70 Rs.	1970-71 Rs.
1	2	3	4	5
Bombay-Poona-Nagpur 1-11-1967	19,07,222	54,79,913	69,69,556	82,21,768
Calcutta 15-10-1968	—	27,42,635	65,37,087	69,45,473
Delhi 1-4-1969	—	—	51,79,319	54,76,289
Madras-Tiruchi 12-4-1969	—	—	43,58,409	47,43,520

1	2	3	4	5
Chandigarh-Jullunder 4-10-1970	—	—	—	13,91,952
Bangalore-Dharwar 18-10-1970	—	—	—	19,75,791
Ahmedabad-Rajkot 29-11-1970	—	—	—	8,74,916
Kanpur-Lucknow-Allahabad 27-12-1970	—	—	—	7,71,829
Hyderabad-Vijayawada 21-3-1971	—	—	—	71,150
Grand Total :	19,07,222	82,22,548	2,30,44,371	2,95,72,688

N. B. All figures are unreconciled.

Planning Minister's Statement regarding Nationalisation of Foreign Trade

2950. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Planning Minister, Shri Subramaniam, said at Coimbatore (Tamil Nadu) on May 16, 1971 that the import and export trade in the country would soon be nationalised under a phased programme in keeping with the Government's socialist objectives ;

(b) if so, the meaning of the term "phased programme" in this particular context ; and

(c) when the process of nationalisation is expected to be completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. K. GEORGE) : (a) The Planning Minister did make a statement generally on these lines.

(b) It means that Government's plan is to effect the nationalisation step by step.

(c) The objective of nationalisation will be steadily pursued. However it will be appreciated that it is not practicable to fix a precise date for the completion of the process.

Unfilled Vacancies in Membership of Union Public Service Commission

2951. SHRI BHUVARAHAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether 2 or 3 vacancies in the membership of the Union Public Service Commission are lying unfilled.

(b) if so, since how long ; and

(c) the reasons for not filling up these vacancies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) There are two vacancies of Member in the Commission. Both are likely to be filled up within this month.

(b) The first vacancy arose on 9th January, 1970 and the second on 3rd March, 1971.

(c) Selection of Members of the Commission is governed chiefly by the essential requirement that there should be appropriate diversity of experience and talent in the Commission so as to enable expeditious and adequate handling of the various problems which the Commission is expected to deal with. Generally people of eminence in various fields with adequate background which would be useful for the Commission

are selected. Time is taken in consultations and examination of the various proposals as also in obtaining the consent of those selected who take further time in joining the Commission. In these circumstances, some delay in filling up such vacancies is inevitable.

Corporation for Supervision of Atomic Plants

2952. SHRI SAMINATHAN : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether Government have any plan to set up a Corporation under the Atomic Energy Commission to supervise construction and to manage operation of power plants ; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) No, Sir. For nuclear power stations, the Department of Atomic Energy has two units, the Power Projects Engineering Division, for design and construction, and the Atomic Power Authority, to manage operations.

(b) Does not arise.

President's Assent to Maharashtra Trade Union Re-organisation Bill and Andhra Pradesh Industrial Relation Bill

2953. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Government of India's approval and President's assent have been sought by the State Governments of Maharashtra and Andhra Pradesh for the Maharashtra Trade Union Recognition Bill and the Andhra Pradesh Industrial Relations Bill, respectively ;

(b) whether the said Bills embody provisions and principles which were the subject matter of controversy at the recent conferences held by the Labour Minister with the Central Trade Unions and Employees' Organisations ; and

(c) if so, whether Government have decided not to allow piece-meal legislation in various States ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) to (c). The Maharashtra Recognition of Trade Unions and Prevention of Unfair Labour Practices Bill has been received for obtaining the assent of the President. It is being examined in consultation with the concerned administrative Ministries. The Government of Andhra Pradesh has sought approval for the Andhra Pradesh Industrial Relations Commission Bill. They were requested to await enactment of central legislation on the subject. There was no specific reference to the bills in question during the recent discussions with the Trade Union and the Employers' Organisations.

Radio Station at Varanasi

2954. SHRI RAJDEO SINGH :
SHRI SUDHAKAR PANDEY :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the steps contemplated in making Varanasi Radio Station of the level of Allahabad Radio Station ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : The auxiliary centre at Varanasi will be upgraded as a full-fledged station during the Fourth Plan period. For this purpose studios will be set up in the city.

Telephone Subscribers' Plight in Varanasi Region

2955. SHRI RAJDEO SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether he is aware of the sad plight of Telephone subscribers in the Varanasi region because of regular breakdown in the system ;

(b) whether Government have undertaken the task of substituting the metallic content of the wire ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Trunk calls to some stations from Varanasi are delayed. Varanasi Trunk Exchange is

connected to 36 stations. Stations connected by the coaxial systems, the Electrification systems, and the open-wire routes with aluminium/copper-weld conductors are working well; difficulty is experienced in respect of the routes connecting Varanasi with Ballia, Ghazipur, and Azamagarh, on account of repeated thefts of copper wire.

(b) and (c). Estimates have been sanctioned for the replacement of the existing copper-wire by Aluminium conductors for all the affected routes. Orders for 1,20,000 km, of Aluminium conductors have been placed. When supplies are received, aluminium wire will be allotted to the above routes.

Price Fixation of Fine Cloth and Yarn

2956 SHRI R. P. YADAV : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration before Government to fix the price of fine cloth and yarn keeping in view of the consumer interest in the matter; and

(b) the present procedure in fixing the price and marketing the cloth and what changes are being considered in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) No, Sir.

(b) The procedure for fixing prices of controlled cloth has been laid down in the Ministry of Commerce Resolution No. 1(15) Tax (I)/66—Tax (A), dated 15-5-1969, published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section I, dated 15-5-1969. The controlled cloth is marketted through usual commercial channels. The question of increasing the prices of controlled cloth which were fixed with effect from 2nd May, 1968 has been referred to the Bureau of Industrial Costs and Prices and the matter will be considered on receipt of their report.

Extra Departmental Branch Post Office

2957. SHRI TRIDIB CHAUDHURI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state ;

(a) whether Government have taken a decision to demand non-returnable contribution for the cost of running Extra Departmental Branch Post Offices from the members of the public whenever any proposals for the opening of such offices in new areas are made ;

(b) the principles on which the quantum of non-returnable contribution is determined and charged ; and

(c) the exceptions to these set Principles ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Post Offices are opened in rural areas if certain departmental standards like distance of the nearest existing post office from the proposed post office, population to be served and a minimum anticipated income of the proposed office are satisfied and they work within certain permissible limits of loss. A non-returnable contribution is recovered from the interested parties for opening of a post office in their area only when the proposed post office is likely to work at a loss higher than the limits fixed by the Government. The policy adopted in the opening of new post offices is as indicated in the statement.

(b) In cases where a post office is justified according to the departmental standards excepting that it is anticipated to work at a loss higher than the permissible limit, the the amount of non-returnable contribution is equal to the amount of loss above the permissible limit. In case the parent office also works at a loss higher than the permissible limit of Rs. 500 per annum as a result of opening of this office the amount of extra loss above Rs. 500 in respect of the parent office is also recovered as a non-returnable contribution.

In cases where opening of a post office is not justified according to departmental standards, the amount of non-returnable contribution is equal to the entire anticipated loss of the proposed office without allowing any benefit of permissible limit as well as the entire amount of loss of income of the parent office anticipated as a result of the opening the proposrd office without allowing the permissible limit of Rs. 500.

The amount of non-returnable contribution is however limited to the actual cost

of the office itself and the profit if any of the office is offset against the loss of the parent office in calculating the non-returnable contribution.

(c) There are no exceptions to these prescribed rules excepting the final discretion vested in the Government.

STATEMENT

General Conditions for opening of New Post Offices in Rural Areas

I. Remunerative or Self Supporting Category

Post Offices which are expected to be remunerative or self supporting, *i.e.*, the estimated income of which is expected to be more than, or equal to, the estimated cost, may be opened without any restriction as regards population or distance.

II. Post Offices required on Non-returnable Contribution Basis

Post Offices for which non-returnable contribution is offered by any interested party to cover the anticipated loss, may be opened without any restriction as regards population or distance.

III. Villages with Population of 2,000 or more

(i) The loss should not exceed Rs. 750 per annum per post office.

(ii) Distance from the nearest existing post office should not be less than three miles.

IV. Compact Group of Villages with Population of 2,000 or more

(i) Villages to be grouped should be within a radius of two miles from the proposed post office.

(ii) The loss should not exceed Rs. 750 per annum per post office.

(iii) Distance from the nearest existing post office should not be less than three miles.

V. Villages or Groups of Villages with Population of less than 2,000

(i) Post Offices may be opened at the discretion of the Head of the Circle in areas not included in the schedule of backward areas where, due to sparse population and location of villages at long distances, it is not possible to form a group of 2,000 population within a radius of two miles.

(ii) The loss should not exceed Rs. 500 per annum per post office.

(iii) Distance from the nearest existing post office should not be less than three miles.

VI. Villages at Headquarters of Administrative Units like Tehsils, Talukas, Thanas etc.

The loss should not exceed Rs. 750 per annum per post office.

VII. Villages which are Headquarters of Community Project or N.E.S. Blocks or Gram Panchayats where there are Schools run by District Boards. Local Boards or School approved by or receiving Aid from State Government

(i) Distance from the nearest existing post office should not be less than two miles.

(ii) (a) The loss should not exceed Rs. 750 per annum per post office, if the population to be served within a radius two miles is 2,000 or more.

(b) The loss should not exceed Rs. 500 per annum per post office, where the population to be served within a radius of two miles is less than 2,000.

VIII. Areas Scheduled as very Backward for Purpose or Extension of Postal Facilities

(i) The loss should not exceed Rs. 1,000 per annum per post office under the powers of the Heads of Circles and Rs. 2,500

under the powers of the Directorate.

(ii) No population restriction is applicable.

(iii) Post Offices will be located in consultation with local authorities.

"General Conditions"

(i) The opening of a new post office of all the above eight categories is subject to the condition that it does not result in the parent office being worked at a loss beyond the permissible limit, which at present is Rs. 500 per annum for a parent office in rural areas.

(ii) Every post office on its opening should be able to produce an estimated revenue to cover at least 25% of the cost involved in opening it.

NOTE : The parent office is the Head, Sub or Branch Office which serves the the village or group of villages where a new post office is proposed to be opened ; whereas the term 'Account Office' is used in relation to a branch office and refers to a Head or Sub Office in whose accounts the monetary transactions of the branch office are incorporated.

(2) The condition of distance, from the nearest existing post office, where applicable, is relexable at the discretion of the Director-General if a natural barrier like an unbridged river or hill or forest intervenes between the proposed post office and the nearest existing post office.

In Urban Areas

Post Offices should be opened in urban areas only when they are found to be self supporting or remunerative and in the case of opening of departmental S.Os. it should also be ensured that they have got work load of not less than 5 hours per day.

Drawbacks in canalising Operations through M.M.T.C.

2958. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the drawbacks brought to the notice of Government in canalising operations through the Metals and Minerals Trading Corporation ; and

(b) the steps taken to overcome them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Government are not aware of any specific "drawbacks in canalising operations" of the M.M.T.C. Suggestions with regard to the operation of canalised imports are received from time to time. Some of these are as follows :

(i) that free foreign exchange should be released for the import of newly canalised items to enable the State agencies to import goods from the best sources available ;

(ii) that for at least six months after canalisation, the actual users may be allowed to import newly canalised items ; and

(iii) that before imports by private parties are stopped buffer stocks should be created.

(b) The suggestions have been noted for action to the extent considered necessary and practicable.

Unsold Stocks of Handicrafts

2959. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the quantity and value of unsold stocks of handicrafts and how much of it is lying for more than a year ; and

(b) the reasons for such accumulation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) and (b). Since no specific organisation has been mentioned holding unsold stocks of handicrafts, the question implies the unsold stocks in the

whole of the country. This figure is not possible to be collected and if an attempt is made to collect this figure, the effort and labour involved will not be commensurate with the benefit which could be derived by collection of this information. Unsold stocks of handicrafts are possible at all levels of production and marketing, namely with the craftsmen, with the middlemen in the trade and with the exporters spread all over the country.

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में टेलीफोन के तार काटने की घटनायें

2960. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में टेलीफोन के तार काटने की कितनी घटनाये हुई ;

(ख) सरकार को उससे अनुमानित कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने अपराधी गिरफ्तार किए गए ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :

(क) 152

(ख) 1.62 लाख रुपये के मूल्य के तांबे के तारों की हानि हुई है।

(ग) 3 मामलों के सिलसिले में 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) एक मामले में अपराधियों को दोष-मुक्त कर दिया गया है। दो मामले अदालत में अनिर्णीत हैं।

Report of Chandrabhanu Committe on Development in Kerala

2961. SHRI RAMACHANDRAN KADANNAPPALLI : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have received the reports of Chandrabhanu Committee in the matter of the development to be made in Kerala State ;

(b) if so, the main recommendations thereof and the reaction of the Government thereto ; and

(c) the funds sanctioned for the purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Central Government have not received any such report but the Government of Kerala have stated that they received the report of the Chandrabhanu Committee regarding the development of the Kasargod area on the 26th April, 1971.

(b) According to the Government of Kerala, the main recommendations of the Committee cover programmes of development of communications, irrigation, electricity, agriculture, industry, education health programmes, housing, tourism, etc., in the Kasargod area of Kerala. The State Government is yet to examine the report of the Committee with a view to finding out the total financing implications of the different programmes recommended by the Committee, to what extent, if any, the programmes are already included in the Fourth Five Year Plan of Kerala and which of the programmes can be included in the subsequent Plans of Kerala.

(c) Does not arise.

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या

2962. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के अधीन इस समय कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें राजपत्रित कर्मचारी कितने हैं और अराजपत्रित कर्मचारी कितने हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारिवर्ग की कुल संख्या के नवीनतम आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। तथापि,

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की 31 मार्च, 1969 तक कुल संख्या 28,074 लाख थी (जिसमें 26,088 लाख नियमित तथा 1,986 लाख अनियमित थे)

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में से 49,821 राजपत्रित तथा शेष 25,58,962 अराजपत्रित थे।

केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र-व्यवहार करते समय हिन्दी का प्रयोग करने वाली राज्य सरकारें

2963. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के साथ अपना पत्र-व्यवहार करते समय देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग करते हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्र दिल्ली प्रशासन ने केन्द्र सरकार के साथ पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दी को अपनाया है।

Construction of a Branch Post Office in Gujraulia Shankar Misra (Gorakhpur)

2965. SHRI S. L. SAKSENA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the position in regard to the construction of a Branch Post Office in village Gujraulia Shankar Misra, presently served by is Naikot Post Office in Gorakhpur District, about which an application was given to the Superintendent, Post Offices, Gorakhpur and the Post-Master General, Uttar Pradesh in November, 1970 ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : The applications for opening a post office in village Gujraulia Shanker Misra stated to have been given to Superintendent of Post Offices, Gorakhpur and Postmaster-General, Uttar Pradesh in November, 1970 does not appear to have been received by them. The proposal has now been taken up for examination by Postmaster-General, Lucknow. The opening of a Post Office in village Gujraulia Shanker Misra will depend upon fulfilment of departmental standards.

Indian Goods Re-exported from Russia

2966. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the number of times during the last three years, Russia imported from India manufactured goods not consumed within that country and exported them to free market areas thus depriving our country of the precious foreign exchange ;

(b) the extent of foreign exchange lost through these third-country sales ; and

(c) the reasons for routing our exports in those cases through Russia ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Government have received no reports of USSR having re-exported Indian goods to third countries.

(b) and (c). Do not arise.

Per Capita Income in Rajasthan

2967. RAJMATA KRISHNA KUMARI—JODHPUR : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the *per capita* income of Rajasthan as compared to Gujarat, Haryana, Maharashtra and West Bengal ; and

(b) the steps Government propose to take to raise the *per capita* income in Rajasthan so as to bring it at par with the above States ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) The *per capita* income of Rajasthan as compared to Gujarat, Haryana, Maharashtra, Punjab and West Bengal at current prices for 1967-68 which is the latest year for which

such information is available is given below :

Per capita income in rupees at current prices for the year 1967-68

	Rs.
Rajasthan	492
Gujarat	529
Haryana	699
Maharashtra	676
Punjab	828
West Bengal	533

(b) One of the principal objectives of national planning in India is not only to raise the *per capita* income for the country as a whole, but also to ensure that the benefits are evenly distributed. Apart from investment in the private sector and those in the Central and Centrally Sponsored sectors of the Fourth Five Year Plan, which are designed to benefit the country as a whole including Rajasthan, the outlay of Rs. 302 crores which has been approved for the State's Fourth Five Year Plan is designed for the direct improvement of the economy of the State. In addition, liberal allocations have been made for Rajasthan under the Rural Works Programme (in 10 districts), Small Farmers Development Agency (in 3 districts), Projects for Marginal Farmers and Agricultural Labourers (in 2 districts), Projects for Dry Land Farming (3 districts) and Crash Scheme for Rural Employment all over the country, which have been taken up by the Government of India. Further, 16 industrially backward districts of the State have been identified for providing finance to new industries which may be set up in these districts through public financial institutions at concessional rates of interest and two such districts are being selected for grant of subsidy at the rate of 10% of the total capital investment to new industrial units having a fixed capital base of not more than Rs. 50 lakhs each.

Representation against Exorbitant Aluminium Price Demanded by M.M.T.C.

2968. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether a delegation of Conductors Manufacturers Association called on him recently representing against exorbitant Aluminium price demanded by the Minerals and Metals Trading Corporation ; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by him in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) A delegation of the Indian Electrical Manufacturers' Association called on the Minister of Foreign Trade recently to represent against the release price for aluminium fixed by M. M. T. C. which in their opinion was excessive.

(b) The complaint is under examination in consultation with the M.M.T.C.

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में साम्प्रदायिक दंगे

2969. **श्री सरजू पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के हाल के उप-चुनावों के दौरान मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में सांप्रदायिक दंगे हुये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गए और कितनी सम्पत्ति का नाश हुआ ?

गृह-मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 9 व्यक्ति मारे गए। क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मात्रा के सम्बन्ध में सूचना अभी प्राप्त होनी है ।

Proposed Retrenchment of Employees in Sachivalaya of Gujarat State

2970. SHRI SOMCHAND SOLANKI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether during the President's rule, the Government of Gujarat have proposed

to retrench Government employees from the Sachivalaya of Gujarat State ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps taken to absorb them in some alternative posts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) No general retrenchment of employees from Sachivalaya of the State Government is contemplated during the President's Rule in Gujarat.

(b) and (c). Do not arise.

Export of "Instant Tea"

2971. SHRI BRIJRAJ SINGH—KOTAH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government have explored the possibility of exporting tea under the brand and type called Instant Tea ; and

(b) if so, the broad features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir.

(b) At present "Instant Tea" is being produced in the country by two factories. Their production is being exported mainly to U.S.A., U.K. and to a lesser extent to Switzerland and West Germany. In 1970, the country earned Rs. 1.05 crores in foreign exchange from export of "Instant Tea."

Telephone Links in Kotah and Jhalawar Districts of Rajasthan

2972. SHRI BRIJRAJ SINGH—KOTAH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have any plans to link with Telephone the major towns and Tehsil Head Quarters in the Districts of Kotah and Jhalawar in Rajasthan ; and

(b) if so, the names of such places ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Major towns and tehsil headquarters in Kotah and Jhalawar districts of Rajasthan are already linked with telephone.

(b) The details of major towns and tehsil headquarters and the places to which they are linked on telephone are given below :

Kotah District :

Name of Town	Linked on telephone with
Indergarh	Tumerganj Mandi
Kotah	Jaipur, Delhi, Agra, Ajmer and Ratlam
Baran	Kotah
Chhabra	Baran
Ram Ganj	Kotah

Name of Tehsil Headquarters	Linked on telephone with
Pipalda	Sumerganj Mandi
Mangrol	Baran
Digod	Kotah
Kishanganj	Baran
Shahbad	Baran
Sangod	Kotah
Atru	Baran
Chipabarod	Chabbra

Jhalawar District :

Name of Town	Linked on telephone with
Jhalawar	Kotah
Jhalarpatam	Jhalawar
Bhawani Mandi	Kotah
Sunel	Bhawani Mandi

Name of Tehsil Headquarters	Linked on telephone with
Khanpur	Jhalawar
Pachpahar	Bhawani Mandi
Pirwa	Jhalawar
Gangdhar	Chau Mahala

Alleged Misuse of Funds Relating to P. T. I. Building Project

2973. **SHRI N. K. SHARMA :**
SHRI SHASHI BHUSHAN :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state whether Government have come to a decision now to conduct an inquiry into complaints of misuse of funds made against the General Manager, Press Trust of India and contractors and architects of its building project for which Government sanctioned a loan of Rs. 55 lakhs ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : The complaints are being looked into by Inspecting Officers under Section 209(4) Companies Act.

Introduction of Automatic Dialling System in Kerala Cities

2975. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have decided to extend Automatic Dialling system facilities in the cities of Kerala State ; and

(b) if so, in how many cities and when this system is expected to start functioning ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes please.

(b) Out of a total of Nine cities the system is already functioning in six cities.

In the remaining three cities *viz.* Cannanore, Trichur and Palghat, exchanges will be commissioned by 1975.

आयात तथा निर्यात लाइसेंस देना

2976. **श्री शिवनाथ सिंह :** क्या विदेश-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में किन-किन कम्पनियों को आयात तथा निर्यात के लाइसेंस दिये गये थे और क्या उनकी सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ख) कितनी कम्पनियों को एक से अधिक आयात-निर्यात लाइसेंस जारी किया गया था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सभी आयात तथा निर्यात लाइसेंसों का ब्यौरा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन प्रतिष्ठानों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें लाइसेंस जारी किये जाते हैं। "औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

सरकार के हिन्दी सलाहकार की नियुक्ति

2977. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या गृह-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी सलाहकार की नियुक्ति के लिये क्या नियम हैं और उसके कृत्य और कर्त्तव्य क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या उनकी सेवा-अवधि इसके बावजूद बढ़ाई जा रही है कि उनका कार्यनिष्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा हैं ; और

(ग) उनकी सेवा-अवधि किन परिस्थितयों में बढ़ाई जा रही है और सरकार ने राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार के अस्थायी पद का सृजन प्राथमिक रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था और राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री रामधारी सिंह दिनकर को 14 जून, 1965 से इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें निःशुल्क सुसज्जित आवास के अलावा

2,000,000 रुपये मासिक नियत वेतन को स्वीकृत किया गया था। उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवाओं (आचार नियम, 1964) के प्रवर्तन से छूट दी गई थी। इस पद को तीन वर्ष की और अधिक अवधि के लिए अर्थात 13 जून, 1971 तक बढ़ाया गया और श्री दिनकर इस पद पर बने रहे।

हिन्दी सलाहकार

(i) गृह मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पूर्णकालिक उपाध्यक्ष।

(ii) प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति के सदस्य-सचिव।

(iii) हिन्दी कार्य से सम्बद्ध संयुक्त सचिवों की समन्वय समिति के अध्यक्ष।

(iv) शिक्षा, विधि और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों के सदस्य रहे थे।

हिन्दी सलाहकार के कार्य मुख्यत: सलाहकारी थे। उन्होंने समय-समय पर सरकारी काम काज के लिये हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में धीरे-धीरे वृद्धि के लिये अनेक उपयोगी सुझाव दिये और हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत अध्ययन के पाठ्यक्रमों को तैयार करने में सलाह दी।

(ख) हिन्दी सलाहकार के पद का कार्यकाल 13 जून, 1971 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। किन्तु श्री दिनकर का कार्य सन्तोषजनक समझा गया।

(ग) राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम 1969-70 के लिए वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अध्याय 11 (मूल्यांकन तथा प्रतिकारक उपायों) में दिये गये हैं, जिनकी प्रतियां 17/18 जून, 1971 को लोकसभा/राज्य सभा में रख दी गई हैं।

वैध पारपत्रों पर भारत आये पाकिस्तानी राष्ट्रजन

2978. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से अब तक की अवधि में वैध पारपत्रों पर कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये और गुजरात में रहने लगे ;

(ख) उपरोक्त विधि में कितने पाकिस्तानी राष्ट्र अपने वीसा की अवधि समाप्त होने से पूर्व पाकिस्तान वापस लौट गये ;

(ग) उनमें से ऐसे लोग कितने थे जिनको छिप जाने के कारण उपरोक्त अवधि में पाकिस्तान लौटने को बाध्य करना पड़ा था ; और

(घ) इनमें ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनके बारे में तलाश करने के नोटिस जारी किये गये हैं और इस समय छिपे हुये व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) पहली जनवरी, 1968 से 30 अप्रैल, 1971 तक 8,573.

(ख) 8,060

(ग) कोई नहीं।

(घ) कोई नहीं।

समाचार एजेंसियों को सरकारी सहायता की राशि

2979. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1969-70 और 1970-71 में 'प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया,' 'समाचार भरती' तथा 'हिन्दुस्तान समाचार' जैसी समाचार एजेंसियों को अलग-अलग सरकार से कितनी सहायता प्राप्त हुई ; और

(ख) इस अवधि में इन में से प्रत्येक ने कितनी सहायता की मांग की थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को दी गई सजा

2980. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या गृह मंत्री 9 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3973 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन 11,719 और 526 पाकिस्तानियों के विरुद्ध मुकदमें दायर थे उनमें से कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ;

(ख) कितने मामलों का अभी तक फैसला नही हुआ है ; और

(ग) कितने व्यक्तियो को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported unilateral action of the Government of Ceylon in changing the basis for the grant of Ceylon citizenship

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tiruchirapalli) : Sir, I call the attention of the hon. Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

> "Reported unilateral action of the Government of Ceylon in changing the basis for the grant of Ceylon citizenship which would adversely affect the interests of persons of Indian origin."

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : The Government of India have seen reports in the press that the Ceylon House of Representatives has adopted an amendment to the 1967 Indo-Ceylon Agreement (Implementation) Act, linking the pace of grant of Ceylon citizenship with the number of persons repatriated to India, and not merely to their registration in Ceylon as Indian citizens. According to the Indo-Ceylon Agreement of 1964, the grant of Ceylon citizenship and the process of repatriation shall both be phased over a period of 15 years and shall, as far as possible, keep pace with each other in proportion to the relative numbers to be granted citizenship and to be repatriated respectively. The 1967 Indo-Ceylon Agreement (Implementation) Act related the grant of Ceylon citizenship with the grant of Indian citizenship and not with their actual repatriation.

The Prime Minister of Ceylon on the occasion of moving the present amendment, has stated that the Government of Ceylon intend to implement the 1964 Indo-Ceylon Agreement "both in letter and spirit". The present amendment is to the Ceylonese domestic legislation of 1967 and not to the 1964 Indo-Ceylon Agreement. Both Governments have agreed that the Indo-Ceylon Agreement of 1964 shall be implemented fully in letter and in spirit.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : The hon. Minister started by saying that the Government have seen only press reports but the information he has given as compared to even the press reports is very incomplete. I want to know whether the Government is aware that a very serious amendment to the Indo-Ceylon agreement Implementation Act of 1967 was moved by no less a person than the Prime Minister of Ceylon herself to the effect that deferrent punishment will be given to the employers if they continue to employ persons who have obtained Indian citizenship ? The punishment will be two to five years rigorous imprisonment. I want to know why our Government missed this important amendment. What is the implication of this amendment ? Is it not to force persons of Indian origin ? I do not know who coined these terms. These persons have been in Ceylon for over 100 years ; for

[Shri M. Kalyanasundaram]

generations they might not know where their roots are ; except that they speak Tamil. They contributed their sweat, blood and labour for the development of Ceylon and I do not know how that famous agreement, Shastri-Srimavo agreement of 1964 was reached and on what basis they accepted the division of these so called stateless persons and after that in 1966 the officials of both the Governments met and discussed the details of giving effect to the 1964 agreement. Now unilaterally that Government takes steps to amend their Act and it is a matter of serious concern for us as large number of persons would be forcibly repatriated to India. It is next only to, if not as serious as, the refugee problem arising from the influx from Bangla Desh. In 1964, the number was estimated at 9,75,000. Every day the number will be increasing. Two days ago, I think the Deputy Minister gave an answer that 22,000 persons have registered so far as Indian citizens. Corresponding to this figure, 15,000 persons have been granted Ceylon citizenship. What is to happen to more than 9 lakhs of people who will continue to stay in Ceylon, despised by the Ceylon and disowned by India ? What is to happen to them ? Did the Government study the implication of this amendment ? The Government of Ceylon want to force these people to leave Ceylon and go to India. What will they do ?

May I ask the Minister, when you agreed in 1964 to repatriate as many as 5,25,000 Stateless persons,—I think you agreed to it in all seriousness—what is the action taken so far ? Nearly seven years have passed to repatriate them, to give them an honourable abode in their former homeland. The Government of India has not done anything, nor did they take up the matter with the Ceylonese Government to see that the problem is approached in a more realistic way. It is a human problem. The number is much more than what is actually put on record. Now, without consulting the Government of India, they unilaterally amend the Act and I want to know what will be the fate of these people. They are mostly from the southern States, particularly from Tamil Nadu. So, we are very much concerned about it.

Having promised at the time of the agreement, the Government of India failed to treat this as a problem of the Central Government. They did not give sufficient inducement for the Stateless persons in Ceylon to opt for repatriation, and the very few who had come over here are not very happy. When the people who are still in Ceylon come to know this, how will they opt for repatriation to India ? This is the problem.

I want a clear answer from the Minister of External Affairs or even if necessary from the Prime Minister as to what is going to to happen to these people who constitute more than nine lakhs, and what further steps are the Government going to take with the Government of Ceylon. Of course, we want very cordial and friendly relations with all our neighbouring countries, but for that, this is not the way in which you can purchase friendship. There should be some principle in dealing with such human problems. So, let me have an answer from the Minister to all my questions.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : I agree with the hon. Member when he said that this is a very difficult and very complicated problem and it has a human angle. There is no doubt about it. We also share his anxiety and his views that this whole problem has to be dealt with very delicately and very carefully. But the hon. Member, I think, has necessarily painted a very dark and dismal picture in regard to the implementation of the whole scheme.

As regards the amendment of which he has spoken at length, I think the hon. Member must have read it in the newspapers and come to the conclusion that in this amendment we should not see any attempt on the part of the Ceylon Government to either drag their feet in this regard or to back out of the agreement and their commitments. This amendment has been adopted by the House of Representatives merely to bring their own domestic law in line with the 1964 agreement. The House is already aware that in that agreement, the conferment of Ceylon citizenship was linked up with the number of people repatriated to India,—actually repatriated,—and not just registered as Indian citizens in Ceylon. So, there is nothing sinister on invidious on the part of the Ceylonese Government in doing this. They merely brought their

own law in line with the 1964 agreement, to which we have agreed. There is nothing to which we could really take objection.

About the difficulties in the way of the people coming back from Ceylon, we have made elaborate arrangements in consultation with the Tamilnadu Government and there are a number of schemes for rehabilitating them. We will see that all those who come back properly looked after and rehabilitated.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : In the statement itself it is said...

MR. SPEAKER : Why don't you believe the minister ? you are relying on the statement too much.

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : We can depend more on the written statement than on the oral reply.

SHRI M. KALYANASUNDARAM : The statement itself states :

> "The 1967 Indo-Ceylon Agreement (Implementation) Act related the grant of Ceylon citizenship with the grant of Indian citizenship and not with their actual repatriation."

But now it is related to actual repatriation.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : As the House is aware, the 1964 agreement envisaged that a certain number of people will be given Indian citizenship and certain number will be given Ceylon citizenship, the ratio being 7:4. That is, for every seven individuals granted Indian citizenship and repatriated to India, Ceylon will give Ceylonese citizenship to four persons. In the 1967 Act which they enacted later on, they made a slight modification to suit their own requirements. That is, they linked up the question of conferment of Ceylonese citizenship with the number of persons getting registered as Indian citizens in Ceylon. We did not object to it because it did not come into conflict with the old agreement. So far as the latest amendment made by them is concerned, it only brings their own enactment in line with the 1964 agreement. It does not also come into conflict with the 1964 agreement.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : I agree with the Government that we should maintain good neighbourly relations with Ceylon and we do not want to say anything which will create any discord in our friendly, relations. Recently when there was insurrection in Ceylon and open defiance of law and order, the Indian Government went all the way to give them whatever help they wanted to meet the situation. That has created a further friendlier atmosphere. I want this problem also to be solved with a friendly and human approach. But I am sorry to say that the Shastri-Sirimove Pact entered into in 1964 was a departure from the earlier stand taken by Pandit Jawahar lal Nehru, who never accepted the position of so-called Stateless persons. He maintained that whosoever may be in Ceylon, it was the problem of the Ceylonese Government and we could not take any responsibility for them. But the 1964 Shastri Sirimovo Pact made a departure from that stand. The latest amendment to the 1967 Act makes another departure and makes the conditions stringent for the so-called Stateless people there. The agreement of 1964 envisaged that in 15 years 5.25 lakh people should be repatriated to India and 3 lakh people should be given Ceylonese citizenship.

As the Minister has rightly pointed out, and also mentioned in the written statement the Indo-Ceylon Agreement Implementation Act linked the grant of Ceylonese citizenship with the grant of Indian citizenship and not with actual repatriation. That was the position under the 1967 Act. But the present Amendment seeks to link the grant of Ceylonese citizenship with the actual repatriation of those persons opting to come to India. But for the repatriates coming to India there are some difficulties. Even though many persons have registered themselves to come to India, facilities have not been made on the part of the Ceylonese Government to make their exit to India possible and feasible. According to the available statistics while the Indian High Commission in Ceylon have granted Indian citizenship to 72,000 people up to July 1970 the number of Ceylonese citizenship granted during the same period is only 7,300. If you take the latest figure, while we have granted Indian citizenship to 85,000 people Ceylon has granted citizenship to only 15,000 people. So, this ratio of 7 : 4 has not been observed.

[Shri Sezhiyan]

Then, it was accepted in the agreement of 1964 that the repatriates should be permitted to take with them a minimum of Rs. 4,000 per person and a maximum of Rs. 75,000 per family. This amount is to be given in foreign exchange. But the Ceylon Government is not readily giving to the repatriates the minimum and maximum put in the agreement. Even on a conservative estimate, if 35,000 people have to be repatriated per annum, it will come to Rs. 16 million to 17 million per year. The officials of Ceylon say that they find it difficult to manage such a huge sum. That may be one reason for slowing down the repatriation to India.

Therefore, before accepting the amendment of the Act, which seeks to link the grant of Ceylon citizenship with actual repatriation, the Government of India should see whether facilities have been given to those people who have opted for repatriation and whether the Ceylonese Government are fulfilling the obligations they have undertaken under the 1964 Agreement.

Then, there is an apprehension in the minds of those people who are working in the plantations, who are there for the last three generations, that they will be uprooted and thrown out of their jobs so that they will repatriate to India. If they are repatriated suddenly it will put them in a very difficult situation. So, repatriation has to be done in an orderly and human way.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : The hon. Member has asked a number of questions. His main anxiety appears to be that since the amendment has been adopted by the House of Representatives some change has come over which is likely to affect adversely the interests of the people of Indian origin. May I assure him once again that as far as this amendment is concerned it will not make the slightest difference to the agreement ? Both India and Ceylon stand by their commitment. As the House knows, over a period of 15 years 5,25,000 people of Indian origin are to come to India and Ceylon will give citizenship to 3 lakhs people. It is true that there is short-fall on both sides. We have not been able to confer Indian citizenship and repatriate as many as we should have done, nor has Ceylon been able to honour her part of the commitment fully, because there have been a number of difficulties in the way. It is a very difficult scheme to implement because human beings are involved. All these difficulties are now being overcome, procedures are being streamlined and a whole machinery has been set up in order to accelerate the pace of implementation of the agreement to the desired pitch.

As far as the question of providing these people with the necessary facilities is concerned, the House has been kept fully informed in the past that we on our part are providing adequate arrangements to bring these people over here, rehabilitate them and provide all kinds of facilities to them. There is no doubt about that.

So far as the other side is concerned, there should be no apprehension in the minds of the hon. Members that difficulties will be placed in their way by Ceylon itself. The Ceylon Government, specially the present Ceylon Government, is very keen that the scheme should be implemented expeditiously and all those people who have got Indian citizenship should leave Ceylon as early as possible ; that is to say, once a person has opted for Indian citizenship then they would like him to go back to India as quickly as possible. There is no difficulty on our side either in taking them back. To that extent we cannot really quarrel with the Ceylonese Government. In regard to facilities for the repatriation of the assets and other things, I can assure the hon. Member that there is complete co-operation from the other side and there is complete understanding between our two governments and nothing is being done which will create difficulties for the people over there.

12.18 hrs.

RE : VISIT OF MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS TO CERTAIN COUNTRIES

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tiruchirapalli) : Sir, the Minister of External Affairs has returned home after a global tour on a difficult mission. There should be a statement on that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Yes, on the outcome of his tour abroad we want a statement. Then there is the question of arms shipment.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : The Minister of External Affairs should make a statement and the House should be given an opportunity to discuss it. Sir, if you allow it under rule 377, then he will make a statement and we will not be in a position to ask for any clarification.

MR. SPEAKER : If a calling attention is given notice of, it can be considered. So far as the shipment of arms is concerned, the calling attention has been admitted and it will be taken up tomorrow.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : We want a call attention inviting the hon. Minister to make a statement on the outcome of his long tour abroad for the cause of Bangladesh.

MR. SPEAKER : I can very well understand the difficulty of some of the newcomers and their making some novel suggestions. But have you ever heard of a calling attention motion inviting a Minister to make a statement ?

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Whenever during session the Minister goes abroad and returns he should make a statement *suo motu*.

MR. SPEAKER : He must have some patience. Perhaps, he will do it himself.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक तरीका यह हो सकता है कि कल जो कालिंग एटेन्शन नोटिस आ रहा है, आप इस बात की इजाजत दीजिए कि हम उसमें इधर उधर के सवाल भी पूछ सकें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले जो ऐसा करते हैं, क्या वह मेरी इजाजत से करते हैं ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय एक तूफानी दौरा करके आये हैं । वहां पर किसी जगह उनका स्वागत हुआ है, किसी जगह नहीं ; किसी जगह उनकी बात सुनी गई है, किसी जगह नहीं । इसलिए मन्त्री महोदय इस बारे में जो स्टेटमेंट करेंगे, या तो उसके बाद हमें सवालात पूछने का मौका दिया जाये और या इस विषय पर कालिंग एटेन्शन नोटिस मन्जूर कर लीजिए ।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH) : Sir, I am entirely at the disposal of the House. If there is a general desire, I will make a statement. I have learnt that call attention notice on the specific question of the reported supply of Arms has already been admitted. While dealing with that if anything is left then I can make a statement myself.

MR. SPEAKER : I have already allowed a call attention motion on the shipment of arms from U.S.A. So far as the matters relating to that subject are concerned, you are at liberty to ask as many questions and I would not come in the way. Secondly, we have already fixed discussion on the Demands for Grants of the Ministry of External Affairs fixed and that will provide you enough opportunity to discuss all matters concerning foreign affairs.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, it is regarding Bangla Desh—a specific subject.

SHRI SWARAN SINGH : Sir, I do no want to give an impression that I am avoiding making a statement. If, Mr. Speaker, you think that I should make a statement in view of this, I am prepared to make a statement. It can be day after tomorrow, if you like. Tomorrow let the arms supply thing be dealt with and then, if anything is left, I will make a statement the day after.

MR. SPEAKER : We will have a little departure from the accepted practice. I will allow a few questions, not many but only a few concise, precise and very short questions.

SHRI S. M. BANERJEE : One from each party.

MR. SPEAKER : One for each.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Why not have a short duration discussion under rule 193 ?

MR. SPEAKER : The Rules are, when you anticipate a discussion, we cannot allow another one on it. You have already fixed a debate on foreign affairs.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : Will the Members, to whom questions will be allowed, be those who disturb you or who do not ? Who will be the Members who will be privileged to ask questions ?

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : It should be expunged.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We are not disturbing you ; we are very cooperative.

MR. SPEAKER : Shri Salve is a lawyer.

SHRI N. K. P. SALVE : My sincere submission is, kindly give it to those who are perennially troubling you.

SHRI S. M. BANERJEE : It is a very, very cruel joke.

MR. SPEAKER : I thought, by placing him in the Chair I will make him learn certain lessons. But I am sorry that he has not learnt them.

SHRI S. M. BANERJEE : He is jealous because we have come nearer to you.

12.32 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE EDITOR OF *U. KYRWOH KA RILUM*, SHILLONG

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : Sir, under rule 222 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I have given notice to raise a question of privilege against the Editor, Printer and Publisher of the paper called *U. Kyrwoh Ka Rilum* (*Hill Messenger*), which has in its issue dated June 12, 1971, published a news item which in English reads as follows :—

> *"Rs. 750 per month for Refugees Chairman.*
>
> It is learnt that Mr. G. G. Swell has been appointed Chairman of Bangla Desh Refugees on a salary of Rs. 750/- per month. Friends, how do you feel about it ? It is because of this that the A.P.H.L.C. world is not quiet ? This is the real patriot, is he not ?"

I asked Shri G. G. Swell, the Deputy-Speaker, about it and he refuted the news item *in toto*. We know that the Deputy-Speaker is debarred from accepting any other office of profit. But the Deputy-Speaker felt very helpless as he himself could not raise a question here, because he occupies the Chair sometimes. It is not only against an individual but is against the very office of the Deputy-Speaker and the dignity of the House. This very patently false and defamatory imputation casts a reflection not only on the character of Shri G. G. Swell, but on the office and conduct of the Deputy-Speaker of the Lok Sabha and brings that high office in to disrepute and is a gross breach of privilege and contempt of the House. Therefore, I propose and move that the matter may kindly be referred to the Privileges Committee of the House.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I fully support this.

SHRI M. KALYANASUNDARAM (Tiruchirapalli) : We support this.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके खिलाफ हूं। मेरा निवेदन है कि यह मामला पहले आप सम्पादक को लिखें कि क्या उसने इस तरह की खबर छापी है और क्या वह इस पर खेद प्रकट करने के लिए तैयार हैं ? अगर वह तैयार न हों, वैसे तो प्रोफेसर स्वेल भी खण्डन भेज सकते हैं और अगर वह खण्डन प्रकाशित न करें तो फिर प्रिविलेज का मामला बन सकता है। मुझे ताज्जुब है इस अखबार का नाम तो पहली दफा मैंने सुना है। कहीं ऐसा न हो कि इस प्रिविलेज मोशन के द्वारा उस अखबार का प्रचार और

ज्यादा हो जाय। इसलिए अच्छा यह है कि पहले अपनी तरफ से सम्पादक को आप लिखें कि वह इसका खण्डन प्रकाशित करें। अगर वह खण्डन को प्रकाशित करने से इन्कार कर दें तो यह मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा सकता है। इस समय भेजना ठीक नहीं है।

SHRI SEZHIYAN : Even if this matter is referred to the Privileges Committee, they will not take a decision *suo motu*; they will also write to the persons concerned. Meghalaya is a very sensitive area. Bangla Desh refugees are going there. If pernicious rumours like this are floated there, the communal harmony existing there will surely be disrupted. I want that rumours should be nipped in the bud. Therefore, I want this House to take serious note of such allegations against the office of the Deputy-Speaker.

MR. SPEAKER : I examined this. This is a paper issued in Khasi language. This is in Meghalaya. Of course, none of us could read that language. I tried if any Member in this House could read it. And the only person who could read it was the Deputy-Speaker himself. This is the translation we have got.

As the office of the Deputy-Speaker is concerned—if it were just a Member, that is all right—the dignity of the office is much more important than certain conventions that we follow. But in this case I have a mind to forward it to the Privileges Committee. But let us follow the old practice. I will refer this to the Editor of the paper. After I receive the reply, I will consult Mr. Sezhiyan and the Deputy-Speaker. If they are satisfied, I will drop it. Otherwise, this will go to the Privileges Committee. I hope, all of you agree.

HON. MEMBERS : Yes.

12.36 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications under Article 320 of the Constitution in relation to Mysore

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following Notifications under clause (5) of article 320 of the Constitution read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated to 27 March, 1971, issued by the President in relation to the State of Mysore :—

(i) The Mysore Public Service Commission (Consultation) (First Amendment) Regulations, 1970 published in Notification No. G.S.R. 412 in the Mysore Gazette dated the 10th December, 1970. [*Placed in Library. See* No. LT—494/71]

(ii) The Mysore Public Service Commission (Consultation) (Second Amendment) Regulations, 1970, published in Notification No. G.S.R. 427 in the Mysore Gazette dated the 24th December, 1970. [*Placed in Library. See* No. LT—495/71]

(2) An explanatory memorandum (Hindi and English versions) explaining the reasons for laying the above Notifications before Parliament. [*Placed in Library. See* No. LT—496/71]

Mysore Taluk Boards (Guidance of Officers, Grant of copies and Miscellaneous Provisions) Rules, 1971

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHER SINGH) : I beg to lay on the table—

(1) A copy of the Mysore Taluk Boards (Guidance of Officers, Grant of copies and Miscellaneous Provisions) Rules, 1971, published in Notification No. DPC/5/RPA/68 in Mysore Gazette dated the 6th May, 1971, under section 246 of the Mysore Village Panchayats and Local Boards Act, 1959, read with clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 27th March, 1971, issued by the President in relation to the State of Mysore. [*Placed in Library, See.* No. LT—497/71]

(2) A statement explaining the reasons

[Shri Sher Siugh]

as to why the Hindi version of the above Notification could not be laid on the Table simultaneously. [*Placed in Library. See* No. LT—498/71]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आइटम नं० 4 के बारे में एक निवेदन करना है। यह प्रोफेसर शेर सिंह ने जो कागज रखा है मैंने अभी देखा है कि हिन्दी में क्यों नही रखे जा रहे हैं, इसका उन्हों ने विवरण दिया है...

अध्यक्ष महोदय : पहले लिख कर भेज दिया करिये तो अच्छा होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आखिर हिंदी में न रखने का कारण क्या है ?

श्री शेर सिंह : मैंने एक वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या वक्तव्य को देखने के बाद आप इजाजत देंगे पूछने की ?

अध्यक्ष महोदय : रखने वाले तो वह हैं। हमारी इजाजत की बात कहां आती है ?

Review and Annual Report of National Textile Corporation and Annual Administration Report of Tea Board

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers (Hindi version) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i) Review by the Government on the working of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 1969-70.

(ii) Annual Report of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 1969-70 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT—499/71].

(2) A copy of the Annual Administration Report of the Tea Board for the year 1969-70. [*Placed in Libtary. See* No. LT—500/71].

Notification under Essential Services Maintenance Act, 1968

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S. O. 2449 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 22nd June, 1971 declaring service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of Bihar or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purposes of such supply, to be an essential service for the purposes of Essential Services Maintenance Act, 1968, under sub-seetion (2) of Section 2 of the said Act. [*Placed in Library. See* No. LT—502/71].

12.37 hrs.

STATEMENT RE. RAILWAY ACCIDENT AT VARANASI

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : I beg to lay the statement regarding the side-collision between train No. 48 Dn. Bombay-Varanasi Express and a shunting engine at Varanasi Station of the Northern Railway on 22-6-71.

Statement

On 22-6-71 at about 16.42 hours while train No. 48 Dn. Bombay-Varanasi Express was entering line No. 4 at Varanasi Station

of the Northern Railway, it side-collided with a shunting engine which had to perform shunting on train No. 10 Down Dehradun Express already standing at the station.

As a result of the side-collision two coaches *i.e.* the composite First and Third class through coach from Madras to Varanasi which was third from the Train engine and a Third class coach which was fourth from the Train engine of 48 Dn. Bombay-Varanasi Express. got damaged. According to the latest Information available three persons were killed in this accident and another 15 injured of whom 13 were hurt grievously.

Immediately after the accident, the North Eastern Railway's medical van at Varanasi was placed at the site to render medical aid to the injured. After first aid on the spot the injured persons were taken to the North Eastern Railway Divisional Hospital at Varanasi.

The Member, Mechanical, Railway Board and the General Manager, Northern Railway accompanied by the Chief Operating Superintendent have proceeded to the site of the accident. The Divisional Superintendent, Danapur who was at Mughal Sarai, 17 kilometres from Varanasi, and Railway Officers of Varanasi Division stationed at Varanasi rushed to the site to supervise relief and rescue operations.

The Additional Commissioner of Railway Safety Northern Circle is holding an inquiry into this accident on 24-6-71.

12.38 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Bill, 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th June, 1971, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.39 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72—*Contd.*

Ministry of Home Affairs—*Contd.*

MR. SPEAKER : We will now resume further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : May I make a submission, Sir ? Day before yesterday, after 3 O' Clock, we submitted our cut motions to the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. We did not expect that the discussion on these Demands would come up yesterday. We sent our cut motions day before yesterday. We could not move yesterday...

MR. SPEAKER : Tha date was already fixed.

SHRI S. M. BANERJEE : We did not expect that the Demands would come up yesterday...

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : They may be allowed.

MR. SPEAKER : The Demads were taken up yesterday.

SHRI S. M. BANERJEE : The cut motions that we sent day before yesterday were not circulated. How could I move them ?

It was not circulated. Day before I moved. It was not circulated yesterday. It was not circulated even to-day.

MR. SPEAKER : The Demands have already been moved. The Member was on his legs. How can I do it now ? Mr. S. V. Savant to continue.

SHRI SHANKARRAO SAVANT (Kolaba) : Mr. Speaker, Sir, as I said yesterday, I rise to support the Demands of the Ministry of Home Affairs.

[Shri Shankarrao Savant]

The year 1970-71 has been a crucial year in our democratic set up. In 1947 we attained Independence. After three years in 1950, as the Preamble to the Constitution says, we swore to constitute India into a sovereign democratic republic. The world had always doubted our ability to wield this weapon of democracy thanks largely to our medieval background and the existence of a predominantly illiterate electorate which has often shown strange allergy to frenzied communal appeals. But to the consternation of the world, we went through four General Elections more admirably. In the General Elections of 1967 the Congress was badly mauled but still it remained the greatest bulwark of secular democracy. When, therefore, it split into two in 1969, the prophets of gloom vied with each other in predicting in disaster for democracy. When the mid-term poll was announced in 1970, not only the professional astrologers but even the professional politicians began predicting dismal pictures of the things to come. It was openly said then that India was at the cross-road of democracy and mobocracy and that mobocracy in the shape of fronts, coalitions and conglomeration of parties and persons will rule over India. But, thanks to the dynamic leadership of Shrimati Indira Gandhi, just the reverse of whast these laokadaisical pessimists had predicted has come true.

Not only did the Congress get a thumping majority in the Lok Sabha but the air of buoyancy exuded by the results of the General Elections became infectious and it swept before it Governments in nine States—most of them Coalition Governments. In most of these States the political metamorphosis became so devasting that the President's rule had to be invoked to give breathing time to the puzzled politicians to adjust themselves to the new situation.

When the fronts, combinations and conglomerations are thus vanishing from our political arena, we are faced with two monsters that have thrived upon the political insecurity of the last five years. First is communalism and second is Naxalitism.

Communalism is the bane of our politics for several decades. Each year it thrives on new causes. At page 34 of this Report of the Ministry of Home Affairs they have detailed several proposals to curb communalism and I am sure that if these proposals are diligently and honestly worked out, communalism can be curbed. I particularly refer to proposal No. 4—"Timely and adequate action under law should be initiated in respect of inflammatory writings and public utterances which foment communal trouble". This is well said than done. So, I would suggest both the Central and State Goverments should take action on these lines. Such action will go a long way in curbing communal disturbances. But unfortunately that is not done.

That is the reason why communalism always increased from year to year. As a general rule I may say that communalists are loved by none but are wooed by all at least at the time of election. During the last elections, the Muslim League, and the Jan Sangh who are supposed to be the antithesis of each other, combined to make it tough for the Congress. Even the Congress has often showed greater respect to communalist Muslims than to Nationalist Muslims. This has created an atmosphere in which communalism is making surreptitious gains It is therefore necessary that we should stick loyally to the various measures detailed at page 34 of this Report to put down the scourge of communalism.

The Naxalite menace has grown mostly in West Bengal. The political uncertainty created by the internal quarrels in the Congress in 1966 is the main cause of the rise of the Naxalites. It is a matter of shame that publicmen, candidates at elections and high-ranking officials including High Court Judges should be murdered in broad daylight and the culprits could not be found, and if found, should be acquitted in courts of law because no body dares to come forward to depose against the miscreants. The State Government of West Bengal is mainly responsible for this sordid state of affairs. During the President's rule, the Governor too does not seem to have done much to curb this menace. If, therefore, the President's rule is clamped once more upon the hapless State of West Bengal—as seems highly probable,—it will be the duty of the Central Government to see that this baneful menace to public life and to law and order is put down once for all.

It is true that the immediate responsibility for law and order is upon the State

Governments. The Union Government is only a coordinating and supervising agency but even then it can do a lot by way of advice.

Then, I will refer to civil defence. So far as civil defence is concerned, the Centre's responsibility is direct and therefore the present strength of civil defence corps of 2.5 lakhs as against a target of 4.50 lakhs is certainly not commendable. This is not adequate. The Centre must take special steps to see that civil defence staff are put in proper order and to raise the proposed target, especially in view of the present situation of the country particularly our relations with our neighbours.

The Home Ministry's main responsibility is regarding inter-State disputes. They have to solve the disputes amicably and judiciously. The disputes between Punjab and Haryana, between Assam, Manipur and Meghalaya have either been solved or are about to be solved. But the 15 year old dispute between Maharashtra and Mysore is left to stew in its own juice. The Mahajan Report was ready in 1967 but it took 3 years simply for laying it on the Table of the House. Even then, nothing thereafter has been done so far. There is a stray line in this report at page 22 which says :

> "Efforts to resolve the dispute were made but these have not so far been successful."

Absolutely nothing is stated as to what efforts were made, by whom they were made when they were made, what was the reaction of the parties concerned, etc. Only a stray line is put that efforts were made. That is all that is mentioned. How long are the efforts to continue ? How long are the endless and fruitless efforts to continue ? My request to the Prime Minister who is heading the Home Ministry is that she should take up courage in both hands and see that this dispute between Maharashtra and Mysore is resolved at an early date. I had asked one Starred Question. It was turned into an Unstarred Question. I had asked as to what are the impediments which are coming in the way of resolving this particular dispute.

No answer has so far been given, and I do not think that any specific answer will be given. They only want to bide time, and this is a bad procedure. Once there is a dispute between two States and there is a specific responsibility of the Central Government to resolve this dispute, there is no reason and there is absolutely no justification for keeping the dispute unresolved for years on end.

So far as the Mahajan report is concerned, Shri Mahajan has distorted facts and even perverted them. He has really gone beyond his jurisdiction in making certain recommendations, but all that is a different matter ; when we discuss that report, I am sure we shall be able to point out how far he has gone beyond his jurisdiction in making those recommendations.

All that is necessary is that the Union Government must take courage in both hands and decide to solve the dispute in such a way that it will be an example for solving similar other disputes all over India. It is no use giving an *ad hoc* solution, because what we want is that there should be justice, and justice can be said to be there only when that particular formula can be made applicable all over India. Therefore, the present Ministry's attempts at putting off the solution every time are very bad. All that I can say is that the Maharashtra-Mysore dispute which has exercised the minds of persons from both Maharashtra and Mysore should be resolved at an early date and should be resolved along lines which will be laying down sane and sound principles of administration in resolving such disputes.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश गांवो का देश है । गांवों मे विधि और व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है जिसके कारण शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है । गत चुनाव में जो हमारा कमजोर वर्ग था, विशेषकर हरिजन वर्ग उस पर अत्याचार किए गए, उनको मारा पीटा गया, उनके घर फूंके गए, उनपर गोलियां चलाई गई । हमने एलेक्शन कमीशन को तार दिए, भारत सरकार को भी तार दिए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई जबकि वहां पर रिपोर्ट लिखाई गई है । तो मेरा यह कहना है कि जब हमारी यह सोशलिस्ट स्टेट है, इसमें सभी को वोट देने का राइट मिला हुआ है, लोग वोट देते हैं लेकिन उनको अपंग कर दिया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं । आप कानून के जरिये

[श्री चंद्रिका प्रसाद]

उन लोगों को कुछ सजा भी दे देंगे लेकिन हमारी जो सजा हो गई, हमारे जो हाथ पैर टूट गये और रोटी कमाने के लिए मोहताज हो गये तो उनकी तरफ भी भारत सरकार को और हमको सोचना चाहिए कि उनके सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है। उन लोगों को तो सख्त से सख्त सजा दी जाए और साथ-साथ उनकी जायदाद भी ले ली जाए तथा दूसरी तरफ जो लोग गोली से मारे गये हैं उनके परिवार को पेंशन दी जाए, जिनके खेत काटे गये हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए और जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गये हैं उनको भी पेंशन दी जाये। केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर यह नहीं होता है और इस तरह से हमले होते रहते हैं तो जो यह हमारी डिमोक्रेसी है उसकी बिनियाद हिल जाएगी और न तो यह पार्लियामेंट रहेगी और न प्रान्तों में असेम्बलीज रहेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि जनतंत्र को बचाने के लिए गृह मंत्रालय को इस ओर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए।

अध्यक्ष जी, हम धीरे धीरे यह महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो चुनाव की प्रणाली है वह ठीक नहीं है, उसमें हमको आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हरिजनों के गांवों में आपको अलग से मतदान केन्द्र बनाने पड़ेंगे। अगर उनको वोट देने से रोका जा रहा है तो आपको मोबाइल मतदान केन्द्र बनाने पड़ेंगे ताकि वे अपने वोट देने के अधिकार का उपयोग कर सकें। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आप जनतंत्र की रक्षा नहीं कर पायेंगे। एलेक्शन कमीशन जो है वह स्टेट्स की जो मशीनरी है उसके द्वारा ही यहां दिल्ली में बैठकर अपना काम करता है। पिछले चुनाव में जो स्टेट्स हमारे खिलाफ थीं वह एलेक्शन कमीशन के आदेशों का पालन नहीं करती थीं। वहां की सरकारें चाहती थीं कि वहां के अधिकारी हम लोगों के खिलाफ काम करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब एलेक्शन हो तो वह सारा स्टाफ एलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पर रखा जाए और उसके बाद यदि वहां के अधिकारी एलेक्शन कमीशन के आदेशों का पालन न करें तो उनको बैड एन्ट्री दी जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उस समय उनको स्टेट के मातहत न समझा जाए बल्कि एलेक्शन कमीशन की मातहती में उनको काम करना चाहिए ताकि इस देश में फेयर एलेक्शन कराये जा सकें। अगर कहीं पर लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं और लोगों को वोट देने से रोका जाता है तो एलेक्शन कमीशन के मातहत पुलिस और सी० आर० पी० रखनी चाहिये जिससे कि उनकी रक्षा की जा सके। ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं जिनको कि मैं चुनाव आयोग के सम्बंध में कहना चाहता था।

अभी हमारे यू० पी० में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। जिस घर में दस आदमियों के रहने की भी जगह नहीं है उस घर से 150 वोटर्स बढ़ा दिए गए। देहातों से लोगों को म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में वोट डालने के लिए लाया गया। किराये पर औरतों को ला कर बोगस वोट डलवाये गए। अगर इस गुंडागर्दी को वहीं रोका गया तो कोई इमानदार आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा।

इस बार गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव हुआ। मैं सुझाता हूं हर गांव में रेडियो और टेलिविजन हो और हर पार्टी उसके माध्यम से अपना-अपना प्रचार करे और इस कम्पेसिंग को बन्द कर दिया जाए ताकि आज चुनाव जो इतने खर्चीले हो गए हैं उनको रोका जा सके।

आज हम गरीबी हटाने और समाजवाद लाने के लिए कृतसंकल्प हैं लेकिन आज जो हमारे यहां लालफीताशाही की मनोवृत्ति जीवित है, जब तक वह रहेगी तब तक न तो समाजवाद ही आएगा और न गरीबी ही मिटेगी।

गरीबी हटाने के लिए धन संचय करने की जरूरत है। सरकार और जनता मिलकर अधिक परिश्रम करेगी तो धन का संचय हो जायेगा। यह एक लम्बा मार्ग है लेकिन हमें विश्वास है कि गरीबी जरूर हटेगी और समाजवाद जरूर आयेगा। लेकिन हमारी पालिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले जो अधिकारी है वे जब तक समाजवाद में विश्वास नहीं करते हैं तब तक न तो यहाँ से गरीबी हटेगी और न समाजवाद आयेगा। आज 23 साल की आजादी के बाद भी अगर किसी किसान को तकावी लेनी हो तो वह लेखपाल से लेकर कलक्टर तक दौड़ता फिरे, दस दिन के लिए अपना काम बन्द करे और फिर सौ रुपये की जगह पर 50 रुपये लेकर अपने घर आये। जनता तो मालिक है और ये अधिकारी उसकी सेवा करने के लिए हैं। यदि आप इस बात को मानते हैं तो लेखपाल और तहसीलदार को स्वयं किसान के घर पर जाना चाहिये और जो कुछ भी उसे देना हो वह उसे देना चाहिए न कि बेचारे गरीब मजदूर और किसान कचहरियों में दौड़ते फिरें। अगर समाजवाद लाना है तो इस मशीनरी को ठीक करना होगा। आज एम० पी० की चिट्ठियों का एकनालेजमेंट तो आ जाता है लेकिन आम जनता को उसकी चिट्ठियों का एकनालेजमेंट भी नहीं मिलता। इस लिये हर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को समय-समय पर सर्कुलर जाना चाहिये कि चिट्ठियों का एकनालेजमेंट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसान मजदूरों की भी समाज में कुछ प्रतिष्ठा बढ़े तो अधिकारियों को स्वयं उनके घर पर जाना चाहिये। और अब तो बी० डी० ओ० भी कचहरी में ही अपना दफ्तर लगाने लगे हैं।... (**व्यवधान**)...

13.00 hrs.

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्ट्री आफ होम अफयेर्स पर बहस हो रही है, आप उसी पर बोलिये।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : वही मैं कह रहा हूं कि किसानों के अन्दर अगर समाजवाद लाना है...

अध्यक्ष महोदय : इस में खास डिमान्ड्स जो हैं उन पर बोलिये।

श्री चन्द्रिका प्रसाद : जो मोटी बातें हैं वही मैं बतला रहा हूं। अगर मूल बात छूट जाएगी तो हम कहां रहेंगे। जब सरकार धन खर्च कर रही है तो हमको ऐसे काम भी करने चाहिए जिससे लोगों की गरीबी हट सके, जिस को हटाने के लिए हम कृत संकल्प हैं।

पोलिटिकल सफरर्स को नौकरी में कुछ छूट मिलती थी लेकिन वह छूट भी अब छीन ली गयी है। हालांकि सर्कुलर है कि फौजियों को जमीन दी जाय लेकिन होता यह है कि फौजी लोग जा करके लाइन लगाते हैं लेकिन उनको जमीन नहीं मिलती है। फिर आप ही बताइये कि ऐसे आदेश होम मिनिस्ट्री द्वारा निकाले जाने का क्या लाभ है। इन आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन कराया जाना चाहिए।

इसी तरीके से जो लोगों को बुढ़ापे की या स्वतंत्रता सग्राम के सैनिकों को राज्य सरकारों द्वारा पेंशन दी जाती है वह आज कल के समय को देखते हुए कम है। कम से कम 100 रु० पेंशन होनी चाहिए जिससे आज की मंहगाई को देखते हुए लोग अपना जीवन यापन कर सकें। मगर स्टेट की सरकारें इतना खर्च वहन नहीं कर सकतीं तो केन्द्रीय सरकार को उनको सहायता देनी चाहिए। इसका प्रौवीजन इस डिमान्ड में होना चाहिए।

आज हिन्दी की उपेक्षा हो रही है। हम जितने सवाल करते हैं हिन्दी में करते हैं लेकिन उनका जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है और कभी-कभी आप भी हुकम दे देते हैं कि हीयरिंग

[श्री चंद्रिका प्रसाद]

एपरेटस कान में लगा कर अनुवाद सुन लें आप को जवाब मालूम हो जायेगा। इस प्रकार जो भाषा हमारी राष्ट्रभाषा थी वह राजभाषा हो गयी और अब लिंक भाषा बन कर रह गई है। जनतंत्र में जनता का काम जनभाषा में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हिन्दी भाषी प्रदेश, जिन का कुर्बानियों का इतिहास रहा है वह आज पीछे पड़ते जा रहे हैं। हम तमिल, तेलगू भाषा का समान आदर करते हैं, इनका भी बलिदान का इतिहास रहा है, लेकिन जो लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे वह आज आगे आ रहे हैं और तमिल, तेलगू भाषा भाषी लोग आगे नही आ रहे हैं। आज दक्षिण प्रदेशों के लोग हिन्दी भाषा में आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि अभी अखबार में निकला था। यह बड़ी खुशी की बात है कि 78 आदमियों ने परीक्षा दी जिसमें मद्रास के लोगों ने परीक्षा में ऊंचा स्थान पाया और बिहार के लोग पीछे रह गये। यह प्रसन्नता को बात है। लेकिन पोलिटिकल दबाव डाल कर हिन्दी भाषा को उस का उचित स्थान नहीं दिलाया जा रहा है। हालत यह है कि जो बहुमत में हिन्दी जानने वाले हैं वह बेकार घूम रहे हैं। उनको काम न दे कर अंग्रेजी जानने वालों को काम दिया जा रहा है। यह गलत बात है। गृह मन्त्रालय को इस पर विचार करना चाहिए। अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि हिन्दी भाषी प्रदेश पीछे हो जायेंगे।

एक और बात मुझे कहनी है और वह यह कि केंद्रीय सरकार के कई फोर्सेज हैं, जैसे सी० आर० पी०, बी० एस० एफ०, इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स, इनका एक भी भर्ती का केन्द्र हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो हिन्दी जानने वाले लड़के बेकार घूम रहे हैं उनको इन फोर्सेज में ही भेज दिया जाय और भर्ती का एक सेंटर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ले लिया जाय।

बीकर सेक्शन आफ दी सोसायटी को सहायता देने का हम दावा करते हैं, लेकिन होता क्या है उसका एक उदाहरण मैं आप को देना चाहता हूं। हमारे बलिया जिले में सुरहा झील में 40 हजार लोगों की रोजी रोटी का सवाल 23 साल से लटका हुआ है। कई बार गोली बारी हुई लेकिन अभी तक मल्लाहों के हितों की रक्षा नहीं हो पाई है। मछली पकड़ने का काम उस झील में मल्लाह करते हैं, लेकिन जब पानी कम हो जाता है और जमीन निकल आती है तो वह जमीन मल्लाहों को न दे कर बाबू लोगों को दे दी जाती है। जब कि होना यह चाहिये कि जब मल्लाहों को मछली पकड़ने का अधिकार है, तो पानी सूखने पर झील के नीचे से जो जमीन निकली उस पर भी उन मल्लाहों को अधिकार मिलना चाहिये। इस मामले पर 23 साल से लड़ाई चल रही है लेकिन अभी तक इस मामले को हम तय नहीं कर सके है। सारी नदियों और तालाबों पर जहां मल्लाह काम करते हैं वहां अगर पानी कम होने से जमीन निकलती है तो उस जमीन के लिए गोली चलती है। सरकार को आर्डिनेंस निकाल कर पानी पर काम करने वालों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये।

इसी प्रकार प्रदेशों के बार्डर डिस्प्यूट्स के मामले लटके हुए हैं। यू० पी० और बिहार के बोर्डर के झगड़े आज तक खत्म नहीं हुए हैं। हमारे ऊपर बराबर अत्याचार हो रहा है लेकिन वह मसला सुलझाया नहीं गया। पंतजी ने कहा था कि सुलझा रहे हैं लेकिन अभी तक सुलझ नहीं पाया है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इन समस्यायों का समुचित समाधान शीघ्र निकालने की चेष्टा करें।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

DR. KAILAS (Bombay South) : While supporting the demands for grants for the

Ministry of Home Affairs, I would like to draw the pointed attention of the hon. Home Minister to certain things which need his urgent attention. The Home Ministry should effectively alert all its agencies to curb the activities of spies and saboteurs in certain parts of the country and the Government should use all its powers of Preventive Detention Act. In addition the Government should request the law Commission to examine the question of formulating a comprehensive law of treason and espionage. Though the existing law has proved effective but still it does not interefere with the activities of those persons who are openly saying that the 'Chinese Chairman is our Chairman' and who fly flags of foreign nations in our country. Books are published about which questions were asked at question hour only today ; those books are definitely against the security of this country. The hon. Minister while replying the question the morning said that the Government was thinking of taking action under the Official Secrets Act. According to my way of looking at things, the Government is not empowered to take action against such persons under the Official Secrets Act, or against the publishers who are publishing those books. Today at the meeting of the Congress party in the morning, the names of two papers were mentioned : a Bangalore weekly, Nasheman and a Patna paper, Sangam. They were writing pro-Pakistani articles and denounced the policy of the Government in respect of Bangla Desh in their papers. Under the Official Secrets Act as it is at present it seems the Government has not been able to take quick action. Those books were written by the Government officers who retired from Government service. I do not know why quick action is not being taken. Hence as I suggested earlier, hon. Home Minister must request the Law Commission to suggest an effective piece of legislation to take action against such people.

Large sums of foreign money are being utilised by political parties, by persons who stand in elections and persons who are carrying on research work.

I must congratulate the Government that a Council for Social Science Research has been established with a view to reduce dependence on foreign funds, but it seems Government will have to consider some proposals to enact a legislation to impose restrictions on the receipt and utilisation of such funds coming from foreign countries. Such legislation, in my opinion, should include positive provisions so that our parliamentary institutions, political organisations, academic and other voluntary organisations are able to function in a manner consistent with the values of a sovereign, democratic republic. This legislation should contain such clauses that especially the political parties, members of the legislature and the election candidates, must take the prior permission of the Government before accepting this assistance. I am saying this as I am couvinced that these large sums which are accepted or to be accepted by individuals or organisations are eroding the integrity of our country, and the functioning of the national institutions is also being eroded by foreign powers.

We hear of communal disturbances erupting off and on. May I request the Home Minister to request the Home Ministers of the different States and the Chief Ministers of the different States where such communal disturbances occur, that they must deal with such anti-national persons with a very heavy hand ? But I must warn that when the police is dealing with communal disturbances or such demonstrations by labour unions and others endangering the peace of the cities, tries to check them, the course which is adopted at present is firing which they should not do. In this country, we cannot tolerate this thing any more. Whatever and however much provocation may be there by the demonstrators or by those anti-national people, they should not kill but they should fire to disperse. There should be certain procedures laid down for the purpose. A force should be trained to control such anti-social elements or riots of communal nature or of labour agitation. In other countries. there is a police force which controls such crowds or riots without taking a single life. Why should we not develop that, and why should we not give compulsory training to such a police force which should be utilised always for curbing or stopping this communal disharmony and riots.

I know communal harmony cannot be brought about by police. It is the duty of all political parties to come to some understanding to create an atmosphere of communal harmony, which is a great national task. I cannot blame the Home Ministry alone. There are some interested communal parties or political parties which do certain

[Dr. Kalias]

things which influence the psychology of some people leading to such occurrences.

I wish to draw the attention of the Home Minister to the question of brain drain. Being a medical man coming from Bombay, I know instances after instances of our intelligent medical men, engineers and scientists, who used to work in the Haffkine Institute, going abroad either in the name of further study or for getting experience or getting a job. I cannot defend them. I only remind them their first duty is towards the country and not to go abroad to earn money. I know certain steps have been taken by Government to create a scientific pool system and to create some supernumerary posts, but these methods have almost failed. We will have to find a solution to this problem. Those who have gone abroad may or may not come back, but in future we should see that our intelligent and talented scientists do not go abroad to settle down permanently there. A study group formed by the Home Ministry found out that between 1960 and 1967, about 20,000 engineers, 10,000 doctors and 8,000 scientists went abroad and very few came back. The Home Minister should kindly consider whether we can pay more to our doctors, engineers and scientists looking to their status and stature. I kown we cannot afford to pay them so much as they are earning abroad. But if they get Rs. 3000 abroad, we cannot expect them to receive Rs. 300 or 400 here. Let there be some understanding in Government of their status and stature in fixing their pay.

The question of privy purse and special privileges has been hanging fire for a long time. The Fourth Lok Sabha passed a Bill for their abolition but, unfortunately, that Bill could not get through in the Rajya Sabha by only one vote. Perhaps, it was a blessing in disguise for the country. Because of the losing by one vote in Rajya Sabha, the country has taken a positive turn towards socialism and a new image has been created in this country by the people due to the able and efficient leadership of Shrimati Indira Gandhi. May I request the Prime Minister that before this session comes to a close this peace of legislation should be brought forward, or at least an announcement should be made to that effect so that when we go back to our constituencies, we can say that we are going to fulfil what we have promised and that we are following the chosen path.

I am sorry to say that the police department is full of corruption, brutality and inefficiency, barring a few police officers and a few policemen. Though I am not accusing the whole rank and file of the police department, but the fact is that people are afraid of them. So, the people do not go to the police station to give assistance to the police in crimes happening in their presence. So, this question as a whole should be looked into. Today the policemen and police officers are getting low pay. Therefore, young and intelligent persons from respectable families and families of integrity do not come forward to join the police force. Let the Home Ministry make all efforts to see that respectability is given to the police department by some positive action to attract proper persons.

Further, I would say that Union is one of the popular languages of our country. May I suggest that the following things should be done, so far Urdu is concerned? (1) Facility should be provided to those children who wish to study Urdu. (2) Arrangements should be made for training of Urdu teachers at primary and secondary stage. (3) Facilities for instructions in Urdu should be there up to the postgraduate level. (4) Documents in Urdu should be accepted in all courts and this without the necessity of translation. (5) Petitions in Urdu should be accepted. (6) Important laws, rules and regulations and notifications should be issued in Urdu language where that language is prevalent. For this purpose areas may be notified. For doing all this. I suggest that a Urdu Board should be constituted.

Lastly, coming to defections, I would request the Home Minister that is the Prime Minister to kindly bring forward a legislation to put a stop to this as early as possible. Because, at a time when the image of the Congress Party and its leadership has gone so high, opposition parties accuse us of bribing people and instigating defection which I cannot tolerate. Not only this. It is necessary to keep our image the same or even take the image still further up. May I request that the Bill for Defections may kindly be brought in this Session alone. I thank you

very much for giving me little more time to speak.

MR. SPEAKER : Out of the list submitted by the Congress Party before Dr. Kailas, Shri M. C. Daga is still absent ; Shri Devinder Singh Garcha is still absent ; Shri B. K. Daschowdhury is still absent ; Shri Nathu Ram Ahirwar is still absent—Smt. Subhadra Joshi has come back now—so are Shri Darbara Singh and Mohinder Singh Gill. I think those gentlemen who send their names should be present in the House. After all we have dispensed with the lunch hour. It should apply to all.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO (Karimnagar) : Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the demands for grants because I have got my own reasons. As you know, this Telangana problem is there since 2½ years and everybody knows what had happened in Telangana in 1969. After that we have resorted to peaceful methods to solve this problem. But, unfortunately, this Government—particularly this Home Ministry—is not taking any interest to tackle this problem immediately.

13.27 hrs.

[**Mr. Deputy-Speaker** *in the Chair*]

Recently, on the invitiation extended by the hon'ble Prime Minister to Dr. Chenna Reddy he came here and he was very much serious to see that this problem is solved permanently. But, unfortunately, some of the Members on the Congress benches from Andhra Pradesh were not at all interested in tackling this problem. If they are really serious, if they want to solve this problem they must strengthen the hands of the Prime Minister. Instead they are weakening her hands and yesterday an hon'ble lady Member said that she wanted a categorical statement from the Prime Minister that the Prime Minister was not going to accept any demands for separate States. Why ? When she knows talks and negotiations are going on between the Central Government and the Praja Samiti why she should poke her nose unnecessarily. That means she is not interested because, Sir, I know, she is interested in getting berth in the Cabinet. It is not good. They must be very serious about this problem. They must strengthen the Central Government to tackle this problem. The reasons she adduced yesterday that if you are going to from separate Telengana then you will be opening a chapter for disintegration of the whole of India. When Meghalaya is granted Statehood ; when Himachal Pradesh is granted Statehood and when Haryana and Punjab are there why not Telangana. Fazal Ali Commission has come to the conclusion and submitted a report that it is economically a viable State and it should not have been merged in Andhra Pradesh in 1956. In view of this Report why is it undesirable to grant Statehood to Telengana. We are going abroad and stating so many things about Bangla Desh that the regional feelings are there. I want to assure one thing. Last time also I told categorically that we want separation from Aadhra Pradesh but we do not want to secede from India. It is not at all our object. We want to be in India. After all, we are a part and parcel of India. We are very happy about it. Some people seem to be under the impression that once it is granted statehood, something may happen. That is absolutely wrong. There should not be any doubt about it. Do not be under that impression.

Talks were going on. We all MPs from Telangana Praja Samiti were really very much anxious to see that this problem was tackled. I am very thankful to the Prime Minister that she has taken such steps in spite of opposition from the Andhra Pradesh Chief Minister and other leaders. We thought that again Dr. Chenna Reddy would be called here for further talks. But, unfortunately, he has not been invited here. It seems that this Government is not serious to settle this problem.

I request you not to put us in an embarrassing position. On the one hand, you say that we must be prepared for talks ; on the other, when we come here, you are not prepared for talks and you are not inviting Dr. Chenna Reddy. This way you are going to malign us before the people. That way you are not going to strengthen our hands. Then it will be very difficult for you to tackle this problem. Today Dr. Chenna Reddy is there ; tomorrow somebody else may come. I want to make it very clear, please be serious about this problem. I hope that the Prime Minister will take immediate steps to tackle this problem and for this purpose, I hope, the concerned parties, the Chief Minister and Dr. Chenna Rebdy, would be called here immediately.

SHRI N. TOMBI SINGH (Inner Manipur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I must at the outset express our thankfulness to the Prime Minister for her wisdom and also maturity in having taken a decision to grant statehood to Mani Pur and Tripura and to take abequate steps towards quick legislation in this behalf.

Today we are discussing the Demands of the Ministry of Home Affairs at a time in our history wnen the country is facing difficulties in and around her. Naturally, therefore. we are supposed and expected to pay the best of our attention when we make our observations and think of the steps that are likely to be taken in the course of the year.

I am supporting the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs. We have sung and are singing with the poet, "Home, home, sweet home ; there is no place like home." In making a home sweet there are a number of essential ingredients. Of all the essential elements, the maker of the home sweet, the agency which keeps the home sweet, itself does not have sweet problems. Naturally, therefore, in order to make the Home Affairs Ministry sweet to itself as well as to those who are having the protection of the home Ministry, there should be cooperation of a number of elements, and such co-operation should not mere imposition but should come out of self discipline. It should be willing and affectionate cooperation of all the agencies involved. It is here that the role of the police comes in the picture.

So many measures, pieces of legislation that are not welcomed by the other side of the House, and agencies like the police have come to stay because conditions in the country are not improving.

I belong to the eastern region of the country where there have been prolonged problems of law and order arising from different sources. Of all the problems, I would like to pinpoint one which has been long associated with the role played in our country by two of our neighbours, namely, Pakistan and China. As the House is aware, Pakistan has been trying to play such a destructive role in the eastern region of the country through its eastern sector which was only till recently known as East Bengal and now as Bangla Desh. Through its, eastern sector, Pakistan military junta has been trying to educate Indian boys, the youth of our country, from the Mizo Hills, Manipur, Nagaland and tribal areas of Assam and Tripura, to create hostility against our country. Even after what has happened in Bangla Desh, after we see all that has happened in Bangla Desh, we now discover and they also must have discovered that Pakistan military junta has been trying to create hostility among our own citizens without their being able to win over the hearts of the people. After what has happend in Bangla Desh, we shall be hoping for the best and preparing for the best. We do not know what will come out of the Bangla Desh episode. But let us hope the best will materialise under the able leadership of our Prime Minister. It will certainly affect the eastern region. Pakistan military junta should stop training our boys and girls in the use of arms and also financing them through different underhand organisations, encouraging movements over-ground as well as under-ground, to create hostility against our country. thereby trying to separate the eastern zone from our mother land.

Let me today confine to these problems of law and order in that part of the country. I have already made reference to Pakistan military junta trying to educate our youth. Even now, there are quite a number of our boys, a number of youths, from the Mizo Hills, Manipur, Nagaland and the tribal areas of Tripura and Assam in Bangla Desh behind the bars in our country for having tried to cross over the border or for having made such efforts to act against our own country. Now, in this regard, specially about those of them who have been arrested from Manipur, there is one very pertinent thing that it has been found, very satisfactorily and to some extent encouragingly also, that after all this has happened, some of them have changed their hearts and some of them have shown their willingness to change their policies. And they are now disillusioned and have expressed willingness to change their policy. This is indicative of further changes not only in Manipur but in Nagaland and other areas. So, now, I think it is the right time to take advantage of this situation and introduce measures as to change the mind of those who have been extremists and those who have been hostiles under the guidance and inspiration of China and Pakistan because change of heart can take place and we in the Congress Party under the prolonged leadership of Mahatma

Gandhi believe in the change of heart. So, this is the right time. The Home Ministry should through its so many agencies, through the mass media and information and broadcasting and even through the Police agency—I do not want to belittle the importance of the Police in this respect and they can certainly make their own contribution—introduce measures to improve the situation. The policy of the govt. towards these extremists must also change.

Having said this on the subject with your kind indulgence, I would like to point out the necessity of removing the regional disparity in the matter of services, through adequate measures. I am just pointing out this because whatever disparity either in the field of industries or in the field of education of Services that we find to-day, may not be noticeable to-day, but in due course of time, such disparities will come to the fore. If they are not taken notice of at the proper time and prevented timely, they will create serious danger to the whole country because regional disparities may create political and other problems. So, I would suggest tnat in respect of the Eastern Zone, specially in the tribal areas of Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya and the tribal areas of Assam adequate protection should be given in the matter of Services. This I am pleading with all the emphasis at my command and with a sense of justice. A boy born and brought up in Delhi city sitting for the same examination under the U. P. S. C. is on a higher footing than a boy from these tribal and backward areas. They have been brought up in different conditions. It will take a long time for this gap to vanish but for the present, this has to be recognised and some concession has to be meted out. In this regard, we know protections are there for the tribal people and also the Scheduled Castes. It is not enough. For instance, the valley of Manipur to which I belong, may be examined.

Except for my religion, and certain cultural background I do not know how do I differ from my friend in the Tribal area. But I do not know how it happened. We belong to Hindu religion. We do not enjoy any protection. It is regrettable to say that none of our boys and girls has come up in the IAS. Not a single boy has come up because we do not enjoy any protection. This must be considered. If there is and there must be, I believe, enough scope under the existing rules and laws in the Home Ministry to protect such group of people. We are not Scheduled Castes or Scheduled Tribes but we are very backward. For some reason of their cultural background and religious association, they have not been included in this. For these people there must be sufficient protection. With all emphasis at my command, I would like to request the Home Ministry to look into this and take appropriate steps.

Mr. Deputy Speaker, Sir, you have given me more time. In order to strengthen the Eastern Zone, I would like that there should be more and more of cultural integration.

After the Bangla Desh episode, we know that the cultural tie—the tie of blood and the tie of language—is the strongest tie and that the tie that comes through religion is only secondary.

If we are to strengthen the unity and the integrity of the country in the Eastern Zone, it can be done only through this cultural tie and it should not be through the majority culture being imposed upon the minority culture. It should be done through fruitful dialogue between these various groups and sympathetic understanding between the different communities. There is ample scope for that, if the Home Ministry could do some serious thinking on this and take up adequate steps.

Therefore, Mr. Deputy Speaker, I would suggest that attempts should be made to make the different cultural groups big or small, to mix together in that region to strengthen the integrity of the country.

With these words, I support the Home Ministry's Demands.

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स को सपोर्ट करते हुए मैं चन्द चीजों की तरफ होम मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहती हूं। अभी जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में प्रामिजेज और वायदों की बात तो नहीं हैं फिर भी जो समाज का कमजोर हिस्सा है और जो अल्प संख्या में लोग हैं उनकों सरकार से बहुत उम्मीदें हो गई हैं। कुछ जिक्र भी रहा इन चीजों का कि सरकार की इच्छा है कि जो अलग-अलग भेदभाव होते हैं चाहे वह नौकरियों

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

का मामला हो चाहे वह भाषा का हो, चाहे और कोई आर्थिक सवाल हों, उस भेदभाव को सरकार मिटाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूं कि उस चीज को सरकार को फौरन अपने हाथ में लेना चाहिये और अभी भी काफी समय हो गया चुनाव हुए, इस के पहले कि लोगों की निराशा और मायूसी हमारे सामने आए, मैं सोचती हूं कि सरकार को इसके लिए मुनासिब कदम उठाने चाहिए। जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा कि भाषा का जहां तक सवाल है उर्दू के लिए भी खास ध्यान देना चाहिये। यह मैं नहीं मानती कि उर्दू किसी खास अल्पसंख्यक की या किसी खास कम्युनिटी की भाषा है बल्कि एक आवश्यक भाषा है और ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सरकार की सहायता न होने के कारण या सरकार की लापरवाही होने के कारण या लोगों का उर्दू के प्रति अधिक रुझान, उसका अधिक व्यवहार न होने के कारण आज वह खत्म हो रही है। तो मैं भी अपने साथियों की इस राय का अनुमोदन करूंगी कि अगर उस पर ध्यान देने के लिये कोई बोर्ड बना दिया जाय तो लोगों के दिल में इसके प्रति काफी विश्वास हम फिर पैदा कर सकते हैं कि हम देश को सारी भाषाओं पर बराबर तवज्जह देना चाहते हैं।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के आने के 20 साल के दौरान और आज के दिन भी देश के कोने कोने में हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, मैं समझती हूं, वह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। अभी हमारे एक साथी ने बतलाया कि चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान किस तरह से हरिजन लोगों को मारा गया, किस तरह से पीटा गया, और किस तरह से डराया गया। जम्हूरियत में किसी को इस तरह से अपने मत का प्रयोग करने की इजाजत न रहे, तो वह जम्हूरियत का मजाक-सा हो जाता है। इस पर भी सरकार को काफी तवज्जह देने की जरूरत है और फौरन देनी चाहिये।

अब एक खास बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं—देश में इन्टीग्रेशन का जहां तक सम्बन्ध है, उस पर कुछ वर्षों से सरकार काफी ध्यान दे रही है। हम सब के दिमागों में नेशनल इंट्रीग्रेशन का सवाल बहुत जोरों से है और हम सब उसके लिये कोशिश करना चाहते हैं। कुछ साल पहले बहुत धूम-धाम से एक नेशनल इंट्रीग्रेशन कोंसिल बनाई गई थी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितना समय और जितना पैसा उस काम के लिए खर्च किया गया, उतना अच्छा परिणाम या उस प्रपोर्शन में काम हम शायद नहीं कर पाये हैं। कम्यूलिज्म या फिरकापरस्ती के सवाल को समझने के लिए होम मिनिस्ट्री ने कुछ स्टडीज चालू की थीं, जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है कि कुछ चीजों को पढ़ने की और उनका अध्ययन करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरा ऐसा ख्याल है कि इस समस्या की स्टडी ठीक तरह से नहीं की जा रही है। मिसाल के तौर पर जब फिसाद की स्टडी की गई और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई तो ऐसा मालूम हुआ कि होम मिनिस्ट्री इस सवाल को सिर्फ ला-एण्ड-आर्डर का सवाल समझती हैं। उन सवालों के पीछे जो कम्यूनल-पोलिटिक्स है, उस पर—ऐसा मालूम होता है—होम मिनिस्ट्री का ध्यान नहीं गया है। क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे फिसाद हुआ—किसी ने होली का रंग डाल दिया, किसी ने किसी को छेड़ दिया, कोई अफवाह फैल गयी—लेकिन इनके पीछे कौन से कारण हैं, इन की तरफ होम मिनिस्ट्री की तवज्जा नहीं हैं और यही कारण है कि रिपोर्ट आने के बाद होम मिनिस्टर साहब को बार-बार इस हाउस में सफाई देनी पड़ी, समझना पड़ा और यह कहना पड़ा कि यह जो रिपोर्ट है यह सिर्फ इबेंट्स का कलैक्शन है, उसके पीछे क्या कारण है वह पूरी तरह से नहीं हैं।

मेरा ऐसा कहना है कि इस किस्म की रिपोर्टों में जिन में इस समस्या को सिर्फ ला-एण्ड-आर्डर की समस्या समझा जाय, सिर्फ इवेंट्स का वर्णन किया जाय, उससे इंटीग्रेशन नहीं बढ़ता है, बल्कि उससे गलतफहमी फैलती है। इस किस्म की अध-कचरा रिपोर्टें इंटीग्रेशन नहीं फैलती हैं, बल्कि उस को कम करती हैं। इसलिये इस किस्म की रिपोर्टों को छापना कहां तक मुनासिब है, इस पर होम मिनिस्ट्री को खास ध्यान देना चाहिये।

रिपोर्ट में ऐसा भी देखा गया है कि होम मिनिस्ट्री ने कई चीजों का अध्ययन करने की कोशिश की है, उस में अखबारों को भी स्टडी करने की बात है, उसके लिये प्रोजेक्ट बनाया गया है, लेकिन वह प्रोजेक्ट ऐसा बनता है कि जिस दिन से वह प्रोजेक्ट शुरू होगा, उस दिन के बाद अखबारों में जो छपेगा, उसमें क्या कम्यूनल होगा, उसको होम मिनिस्ट्री स्टडी करेगी। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर इस तरह से समाचार-पत्रों का अध्ययन किया जाएगा, जिसका किसी घटना से सम्बन्ध न हो, तो वह एक एकेडेमिक सवाल बन कर रह जायगा, इंटीग्रेशन के मामले में कोई फायदा देने वाली बात नही होगी। मतलब यह है कि जब इस किस्म की फिरकेदाराना घटना किसी शहर या सूबे में होती है, उसके पहले अखबार क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे, उसमें क्या कम्यूनल था, अगर उस चीज की स्टडी की जाय, तब वह इन्टीग्रेशन के ज्यादा काम आयेगी, इवेंट्स को अलग करके अगर अखबारों की स्टडी की जायेगी, तब तो वह एकेडेमिक स्टडी ही रह जायगी, उसका कोई फायदा नही होता है।

जो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन कान्सिल के बने उससे ऐसा भी मालूम होता है कि होम मिनिस्ट्री का रुझान ऐसा मालूम होता है कि इंटीग्रेशन के मामले को समझने के लिए या कम्यूनल मामलों को समझने के लिये शायद मुस्लिम माइण्ड को स्टडी करना ही ज्यादा आवश्यक है। मुस्लिम माइण्ड को स्टडी किया जाय, इसमें कोई नामुनासिब बात नहीं है, लेकिन फिरकापरस्ती के सवाल को या इन्टीग्रेशन के सवाल को किसी एक कम्यूनिटी के साथ जोड़ देना मुनासिब नहीं है। कम्यूनल लोग हर कम्यूनिटी में हो सकते हैं, हर बिरादरी में हो सकते हैं, देश के हर कोने में हो सकते हैं, इस लिये मुस्लिम माइण्ड को स्टडी करने के साथ-साथ सोसायटी में जो दूसरे सैक्शन्ज हैं, कम्यूनल माइण्ड है, फिरकापरस्त दिमाग हैं, दिल है, उनका अध्ययन भी होम मिनिस्ट्री को करना चाहिए और उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस मामले में होम मिनिस्ट्री के दिमाग में अभी तक कन्फ्यूजन है। जब इन्टीग्रेशन कान्सिल की मिटिंग होती है तो वहा पर बहुत अच्छे विचार रखे जाते हैं, बहुत अच्छी बहसें होती है, लेकिन जब काम का प्रोग्राम बनता है, तो वह इम्प्लीमेंट नही हो पाता। इस की बजह क्या है? इस की वजह यह है कि इस कान्सिल में ऐसे तत्वों को जगह दी गई है जिन के इन्टीग्रेशन के बारे में बिल्कुल अलग विचार हैं और ज्यादा तर लोगों के साथ उनके विचार नहीं मिलते है, मसलन जनसंघ के लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में, देश प्रेम के बारे में, सिटिजन्ज के बारे में, नेशन के बारे में, जो भी परिभाषा है, वह दूसरे लोगों से भिन्न ही नहीं, बल्कि *बिल्कुल उलट है। चूंकि होम मिनिस्ट्री* के अपने दिमाग में इस के बारे में कन्फ्यूजन है इस लिए ऐसे लोग कान्सिल में आते हैं और वह काम आगे नहीं बढ़ पाता है, बल्कि उससे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है और कोई भी चीज साफ नहीं हो पाती। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जैसे इस हाउस में चार-पांच परसेंट लोगों को वीटो पावर दे दी गई है, वे चाहें तों काम हो, न चाहें तो काम न हो इन कारणों सें इन्टीग्रेशन कान्सिल का काम आगे नहीं बढ़ पाता है।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

अब सवाल यह है कि जम्हूरियत में इस किस्म की कान्सिलें किस तरह से काम कर सकती हैं। यह ठीक है कि सैक्रेटेरियट में बैठे हुए साहब लोगों के लिए यह रिसर्च का विषय हो, लेकिन इससे देश में इंटीग्रेशन लाने के लिये बहुत काम नहीं हो पाता है, क्योंकि फिरकापरस्ती और फिरकेदाराना जमायतों के बारे में होम मिनिस्ट्री का दिमाग क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय स्वयं संघ को ले लीजिये, जिस के बारे में हिन्दुस्तान के अन्दर और हिन्दुस्तान के बाहर के बड़े-बड़े विद्वान लोगों ने माना है कि उनकी विचारधारा कम्यूनल है, उनका जो संगठन है वह फासिस्ट है। श्री क्रेग बैक्स्टर ने अपनी पुस्तक "जनसंघ ए पोलिटीकल बायोग्राफी" की भूमिका में लिखा है कि उनका सम्बन्ध जनसंघ और आर० एस० एस० के बहुत से नेताओं के साथ नजदीक का रहा है। उन्होंने लिखा है :

RSS is the ideological and organisational ancestor of the Jan Sangh.

गांधी जी ने भी कहा था कि आर० एस० एस० टोटेलिटेरियन आर्गेनिजेशन है, उस का आउटलुक कम्यूनल है। लेकिन होम मिनिस्ट्री अब तक इस बात में साफ नही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कम्यूनल है या नहीं है। उसी का कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस कंफयूजन की वजह से हमारे सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मेम्बर बन सकते हैं। इस हाउस में बार-बार मैंने होम मिनिस्ट्री की तवज्जह दिलाई है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी सियासी जमायत के मेम्बर नहीं बन सकते, कांग्रेस के नहीं बन सकते, कम्यूनिस्ट पार्टी के नहीं बन सकते, सोशलिस्ट पार्टीज के नहीं बन सकते, जनसंघ के नही बन सकते, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मेम्बर बन सकते हैं, इसकी वजह यह है कि होम मिनिस्ट्री का दिमाग इस मामले में साफ नहीं है।

इसकी एक वजह यह भी है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो देश में सैक्यूलर पालिसी को चलाना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी शिक्षा गांधी जी और नेहरू जी के चरणों में हुई है, लेकिन हमारे सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम करते है, जो बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो पालिसीज को लागू करते हैं, उनकी विचार-धारा दूसरी है, उनकी शिक्षा दूसरे माहौल में हुई है। मैं मिनिस्टर साहब को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जो सर्कुलर इस बारे में उनकी मिनिस्ट्री ने निकाला, उस सर्कुलर में कुछ कमी रह गई, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का खुद का दिमाग इस बारे में साफ नहीं है। अगर साफ हो तो उस सर्कुलर में जो कानूनी कमी रह गई है, उस कानूनी कमी को फौरन दूर कर देना चाहिए, तब ही उस दिशा मे कुछ काम हो सकता है।

14.00 hrs.

एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि होम मिनिस्ट्री ने प्रीवी पर्सेज का खात्मा करने के लिए एक आर्डर निकाला। लेकिन डीरिकग्निशन की खबर हफ्तों तक स्टेट्स में नही पहुंची। एक चीफ मिनिस्टर से बार बार असेम्बली में और बाहर भी सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी आया नही है। मैं जानना चाहती हूं यह कैसे हुआ ? डीरिकग्निशन का क्या मतलब है, क्या उसकी परिभाषा नहीं की गई, या लिखा नहीं गया या स्टेट्स में भेजा नहीं गया या उसे रिकार्ड पर चढ़ाकर चीफ मिनिस्टर के सामने रखा नहीं गया ? आखिर जो इंस्ट्रक्शन्स होम मिनिस्ट्री देती है वह भी स्टेट्स में नहीं पहुंचते हैं उसका क्या कारण है ? मैं चाहती हूं होम मिनिस्टर इस किस्म की बातों पर ध्यान रखें।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि दिल्ली में जो पुलिस का शासन है उस पर से दिल्ली के लोगों का विश्वास उठता जा रहा

है। कितने ही कत्ल के केसेज हुए लेकिन जब तक सी० बी० आई० उनकी इंक्वायरी नहीं करती है तब तक कत्ल का मुकदमा भी नहीं बनता है। मीना टंडन का केस हमारे सामने है। इसी तरह से किशनगंज के केस बल्कि हर केस में सेंटर से इंक्वायरी करने के लिए कहा जाता है और इंक्वायरी के बाद कत्ल का केस सामने आता है नहीं तो उसको दबा दिया जाता है। दिल्ली की पुलिस रिक्शे वाले, टैक्सी वाले या खोचे वाले को पकड़ने में लगी रहती है और बन्द करती रहती है लेकिन जो असल में पब्लिक मे भरोसा पैदा करने की बात है वह नहीं करती है। यह बात सही है कि पुलिस की अपनी तकलीफे हैं, उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनके पास वर्दियां नही हैं और उनको समाज का आवश्यक अग समझा नही जाता है। जब सरकार उनको समाज का आवश्यक अंग नही समझेगी तो वे अपना फर्ज भी अच्छी तरह से पूरा नही कर पायेगे और जनता भी उनको आदर की निगाह से नही देखती है मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्री इन बातो पर उचित ध्यान देगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Biren Dutta. Three minutes.

SHRI BIREN DUTTA (Tripura West) : While I rise to participate in this debate, I associate myself with the views expressed by Shri Saroj Mukerjee yesterday. You will understand the correctness of his statements if you go through the figures contained in the Ministry's Report for the year 1970-71.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : I want to raise a pertinent question. The Home Ministry's Demands are being discussed here, but there is no Minister representing the Home Ministry. There may be Ministers representing Parliamentary Affairs or Finance Ministry, but not representing the Home Ministry.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has just gone out for half a minute.

SHRI SEZHIYAN : There are three Ministers. Not one of them is here.

SHRI BIREN DUTTA : There you will find that the Minister has at his disposal a colossal army of 55 battalions of C.R.P., 7 battalions of Industrial Security force, three contingents of Assam Rifles and 6,02,767 Home Guards in all the States of India. At the same time, his counterparts in all the States have strengthened the police and armed constabulary in each State. That is why the police budget has risen from Rs. 3 crores in 1950-51 to Rs. 77 crores in 1970-71. But with what effect ? With the growth of these forces the communal riots have increased. In 1969 according to this report there were 519 incidents of communal riots and in 1970 there were 521 incidents. It has spread over Maharashtra, Bihar, West Bengal, U.P., M.P. and Assam. In this report again you will find violent activities have also spread to Assam, Andhra Pradesh, Kerala. U.P., Punjab, Tripura ; the situation in West Bengal and Bihar is causing anxiety. May I ask the hon. Home Minister why he is demanding such colossal money ? Is it to bring about these riots more and more, violent activities more and more ? He is not keen on ending the Privy Purse. He is not interested in curbing the activities of foreign and native exploiters of our people. He is employing the CRP and the industrial security force, even military against the workers in Tripura. He has deployed CRP in my State of Tripura. I shall mention only one instance. The workers of the State press numbering about 153 went on a strike with the simple demand that their pay scales should be revised and increments should be given properly. Then the CRP was employed in 1969 and still that press is protected by the CRP. The secretary of that union has been suspended from that period. Eleven Government employees had been arrested by the CRP and beaten inside the employees' union's office. A few thousands of employees had been given show cause notice. In this way these forces are used by the Home Ministry. He has not given us the promised statehood ; he has not given us any assurance that there will be regional council for tribal areas. He has not accepted the unanimous resolution of the Tripura State legislative Assembly to exempt 2½ acre holdings from tax even though his partyman is the Chief Minister

[Shri Biren Dutta]

there. All the good proposals are turned down by the Home Ministry.

Tripura has only 17 lakhs of people. Now 10 lakhs of refugees have entered that State. All the roads have been occupied by them and there is no place even to stand. Nobody is to look after them. The camps provide accommodation only to five lakhs of people and all the rest are left without any food and shelter. The Home Minister brought yesterday the West Bengal Security Act, to arrest people who are protesting against these things. I want to draw the attention of the Home Minister, Prime Minister and the Education Minister to one thing. They went to Agartala. He found that our people had been killed by the bullets of Pakistan Army. The Prime Minister saw that with her own eyes. They have not even given a statement in the Press that people were killed. What is the position in Tripura and how are things developing in that State ? You should not suppress us by these police and military forces ? Many people have tried to do so many times in the history and you are also trying. You bluffed the people by saying that you were bringing in socialism. But you have practically showed your intention by these provisions in the budget.

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Mr. Deputy-Speaker, Sir, what has been said yesterday also by some hon. Members from West Bengal has been repeated today by the hon. Member who spoke just before me ; the same thing is being repeated by those friends who are encouraging violence. Wherever these is any *golmal*, wherever there are groups operating against the law, political or something like that, the Government has to take action. For instance, instances have been quoted from Andhra Pradesh. When the people are being encouraged to occupy some lands unauthorisedly, as in West Bengal, what is to be done ? When there is a law, the law has to be administered and order has to be maintained ; the law has to be maintained as passed by the the Assemblies, and the Assembly members, Ministers and the Government are only there to maintain the laws which are passed by the Parliament and the Assemblies. But these parties, particularly the communist—left or right—wanted to take advantage of the innocence of the people in rural areas. Now, they have started in the tribal areas. They have failed in the rural areas and have now started their activities in the tribal areas. The Government are taking proper action not against the innocent Harijans or Girijans there but against the violent methods of the people who are being encouraged by these parties. To suppose that violence, the Government are taking action in different States.

In Andhra Pradesh also, unless our Government has taken those steps against violence, they would have created one more field for violence, as in the West Bengal. When the communist party was in the government in West Bengal, they indulged in all these things, and when the Naxalites came on the scene, it became difficult for them. They began to expose the Naxalites or something like that The point is, wherever there is violence, it should be crushed by all means. It should not be tolerated or encouraged. That is the policy of the Government. And that policy has to be implemented, even though, fortunately or unfortunately, some other government may come in there. What happened in Kerala ? What are they doing ? Are they supporting non-violence or violence against the people there, which is being crushed by the other people ? Wherever any party government is there—communinst party or any other party—they must see that the people have a peaceful life according to law.

Now, mention was made that in 1950-51 the budget for the Home Ministry of the Government of India was only Rs. 3 crores or so, and that now it has come to Rs. 77 crores. It is so only on account of the atrocities encouraged by the communist party. Because of that, the Government have to spend more. Otherwise, if they were not encouraging violence for political reasons, there is no necessity to spend so much. There is no necessity to enhance our budget only for the sake of maintaining the police, etc. It is only to suppress the violent methods indulged in by some parties that it had to be increased.

Coming to my own State. Andhra Pradesh, some of our friends—Shri M. Satyanarayan Rao, and also Shrimati Lakshmikanthamma—mentioned several things. Several times we have agreed to do anything in a peaceful way which is in the interests of the country as a whole. It is not a question of merely going to an elec-

tion in the Panchayat board or to the Assembly, for deciding the issues of Telengana. We must see whether it is in the national interests, whether it is beneficial to the country as a whole. It is not a question of counting in the Assembly, or in Parliament, of any votes. It is not a question of any plebiscite in any one part of the country. The entire country has showed that there is integrity of the country, big and small States together. If they are suffering on any account, the regional committees are there. For example, there is the water dispute wherever there are rivers, the water should be used for the benefit of the country as a whole and not in a regional way or in a language way, whether it is Andhra, Kerala or Madras. Whatever scheme is beneficial to the country, it should be supported by all.

Now, they are saying that the development of Telengana has been neglected. There are several ex-ministers saying like this. But when they were in the Government, what did they do ? Dr. Chenna Reddy was Finance Minister and Mr. V. B. Raju was Planning Minister. We never objected to their taking steps to develop Telangana or other backward areas of Andhra Pradesh when they were in power. They did not do any thing at that time. Now they want to take political advantage of the innocence of the people. We have no objection to the development of not only Telengana but other backward areas also. My district of West Godavari is supposed to be a surplus district. But there only 3 taluks are developed and 5 taluks are not developed. We are going to develop it with the assistance of the Government of India and the State Government. So, wherever there is backwardness and there is necessity for regional development, we are not against any development anywhere. we are prepared to sacrifice for the development of Telengana. They are 10 members here and we are 29. If we join together, there will be 39 members here. Like a joint family, we will fight for the development of Telengana and other areas, because we want not only integration in the country, but integration in our region also.

They have constructed some buildings for the Police Academy Centre in Hyderabad. Now it seems they are contemplating to shift the Academy to Rajasthan or some other place. When the buildings have been constructed, why should they shift it ? I request that it may be allowed to remain in Hyderabad.

It was alleged here that in Andhra Pradesh, 541 people have been recently arrested by the Police Minister, Mr. Vengal Rao. It is false. I enquired and found that only 40 or 50 people have been arrested, because they occupied unathorisedly some other people's lands. In Andhra Pradesh, we have distributed about 10 lakh acres of wastelands to the poor people. No other State has done it. Last year also, somepeople encouraged the grabbing of others' lands forcibly. I want to point out that merely giving land to a poor man will be of no use. He must be given funds to cultivate it properly. For the last 30 years, in my village, without any violence, I have asked the people to cultivate about 200 acres of Government land. The harijans in my area have got one or two acres. But, then, they are exploited by other people. To avoid all this, whenever harijans are given some land by the government, simultaneously they should also be given some finance. Otherwise, because of their acute poverty they are likely to be exploited by the moneyed people. Now the Andhra Pradesh Government have decided that there will be no harijan families without land and no houses without light. But the Andhra Government do not have sufficent funds to implement this scheme.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : What about Kanchikacherla ?

SHRI K. SURYANARAYANA : That is a matter which has gone to court. That need not be discussed here. Here I may say that Shri Thimma Reddy, whose name was menteoned in that connection, his name is being recommended by the Harijan Sevak Sangh for appointment as their Secretary.

Lastly, I would again plead that there should be no question of coming to Delhi to settle the differences between Telegana and Andhra. Let us settle it amongst ourselves. Instead of coming to Delhi, or fighting against each other, let all of us, all the 39 of us, present a joint front before the Government of India and ask for more funds for Andhra Pradesh.

SARI P. K. DEO : Mr. Deputy-Speaker, Sir, as early as 1966 the Administrative Reforms Commission in its first report has recommended to government the establishment of an institution on the analogy of

[Shri P. K. Deo]

the Scandinavian Ombudsman, or the British Parliamentary Commissioner, to go into the grievances of the public and look into the various complaints which can be reported to Parliament. At the same time, they submitted a model Bill. All these years nothing has been done in this regard.

Then a Bill was introduced in this House. That Bill had a chequered career. In the last Lok Sabha, I introduced an indentical Bill and, inspite of the opposition of the Government, the motion for its circulation for eliciting public opinion was passed by the House. Public opinion came from all over the country and under the pressure of public opinion Government had to bring forward a Bill, which was referred to a Joint Committee. It emerged out of the Joint Committee in a much diluted form, which we did not like, but still we passed it and transmitted it to the Rajya Sabha. While the Bill was pending in the Rajya Sabha the Lok Sabha was dissolved and the Bill lapsed. So, I would respectfully submit that it is high time that government brought forward a Bill. where they will eliminate some of the lapses of the earlier Bill. The earlier Bill which we had passed had excluded the Prime Minister from the purview of the Bill. We do not want to make any discrimination between a Minister and the Prime Minister. Further, nobody including the Prime Minister could be Caesar's wife. So, all charges against the Ministers and the Prime Minister should come within the scope of this Bill.

Sir, after this Congress debacle in 1967, the institution of Governors raised a good deal of controversy. A special sympposium was held under the auspices of the Indian Parliamentary Association and later this matter was referred to a panel of eminent jurists and the consensus was that some guideline has to be provided to the Governor.

Sir, the constitutional fiction that the Chief Minister holds office at the pleasure of the Governor has been construed to mean that the Governor has alsolute licence in the matter of hiring and firing the Chief Minister. Sir, when the *vox populi* has collided with the interests of the ruling party some perverse interpretation of the Constitution has resulted to our democratic character of the Constitution. So, it is high time that some guideline like the Instrument of Instruction which used to be in the 1935 Government of India Act or which was envisaged in the Constituent Assembly should be provided because this will save the Governor from the embarrassment of acquisition of partisan attitude. As you know the testing ground of the stability of the Ministry is the forum of the Assembly. The Governor should not arrogate to himself the powers of the Assembly and powers of judgment regarding the stability of a particular Ministry.

Coming to the Centre-State relationship, as you know, this country is a tapestry where the various fabrics of various cultures and customs have been interwoven to make it a beautiful whole and unity in diversity is the characteristic of the federal structure of the Constitution. So, for the uniform development of all the regions and to dispel the regional imbalance in development and non-interference in State autonomy there has been persistent demand day in and day out that the Centre-State relationship should be reviewed in the context of the present developments. The strength of the chain lies at the weakest link and I cannot understand why the inter-State Council has not taken a concrete shape as yet though there has been a provision under Article 263 of the Constitution. The Government has not taken any steps in this regard so far as the inter-State Council is concerned. I am grateful to Rajamannar who has highlighted this aspect. He has stated that :

> "Article 263 contains a provision for the setting up of an Inter-State Council by the President for generally dealing with all matters which are of common interest and for making recommendations for the better coordination of policy and action with respect to any subject. It is clear that the Constituient Assembly considered the setting up of an Inter-State Council as an important instrument of coordination between the Centre and the States. It is, therefore, a matter of great surprise that the Central Government should have ignored this article altogether. The Administrative Reforms Commission strongly recommended the setting up of such a Council. The Rajamannar Committee has recommended the immediate constitution of the Inter-State Council."

I congratulate again the Rajamannar Committee for the Report because Inter-

State Council functions quite differently. It cannot be replaced by the National Development Council because the National Development Council is over-loaded by Cabinet Ministers and by the Members of the Planning Commission and the Chief Ministers cannot pull much weight in the National Development Council.

We are getting reports of serious encroachment by Centre in the State autonomy day in and day out. The wrong economic policy in the shape of deficit financing and inflation and the wrong fiscal policies pursued by the Government at the Centre lead to rise in prices, lead to price spiral and it adversely affects the State autonomy. After every successive Budget there is a clamour for more dearness allowance for the State employees. The State Governments have nothing to say in the Central Budget but it adversely affects the economy of the States. So, all the aspects have to be studied and the Rajamannar Committee report has to be given effect to.

I take this opportunity to point out one aspect regarding the proposed legislation for restricting the flow of foreign money. As we all know, it has been vitiating the public life in this country. No purpose would be served by bringing forward legislation. It is no use to shut the stable after the horse run away from the stable. We demanded that the report on the acitivities of the China Bank should be released and the CBI report regarding the use of foreign money during the 1967 elections, which was conducted by the Home Ministry, should be made public. There should not be a secret about it. We would all like to know which are those parties which have taken recourse to money from foreign sources. This was not intentionally done in 1967 lest it should adversely affect the prospects of the 1971 elections. So, I would like to say that if the Government's intention is to curb such tendencies, no useful purpose would be served by putting a curb on foreign travel by MPs or journalists.

We know very well how newspapers are being patronised. I cite an example of the North Korean Embassy giving full-page advertisements to various papers. We know very well how Soviet literature is being printed in the *New Age* printing press to patronise a particular party. Lastly, the rupee payment trade, which has led to large rupee reserves in this country, is a source of corrupting Indian politics. So, I would like to have a categorical answer from the Government that they will take concrete steps in this regard and try to liquidate the rupee reserves of the foreign embassies in this country. They should also publish the report on the China Bank and the CBI report on the 1967 elections.

Lastly, I would like to say just one word. I speak in this regard as an individual, not on behalf of the Swatantra Party, because some people have spoken on the question of privy purses. We all want an honourable settlement and we all want that there should be a constructive dialogue in this regard.

In this connection I would like to quote a statement of Shri Fatehsinghrao Gaekwad. I would like that it go on record. It is a small statement. It says :

> "According to newspaper reports, the Government is considering a Bill to amend the Fundamental Rights to circumvent certain judicial interpretations of the Constitution. It is also reported that Government is thinking of resorting to this extreme step in order to deal with the constitutional guarantees relating to Rulers. If this be so, we think that no sacrifice by a citizen or a group of citizens would be too great to safeguard the Fundamental Rights of the generality of citizens. I have no hesitation in saying that the Rulers will rise to the occasion and play their part, as they have done before, in the wider interests of their fellow-countrymen, especially if it can save the Fundamental Rights from erosion. Nothing therefore should prevent the Government from taking up the issue with the Rulers for their willing concurrence in an amicable solution.
>
> Fundamental Rights belong to each and every citizen, whatever his place in society, high or low. Without them democracy cannot survive or have meaning. They are the one stable foundation for a progressive, developing society, an inviolable heritage of our young Republic. If the Rulers have in any way helped in establishing democracy in India, as was asserted in the Constituent Assembly and in Government's White Paper on the subject, it is still their obligation to continue to serve the cause

[Shri P. K. Deo]

of democracy and not to become a cause for its reduction."

श्री वेकारिया (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हमारे देश में साम्प्रदायिक अशांति और नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ती जा रही हैं। इसी लिए गृह मंत्रालय के अन्तर्गत होने वाला खर्च बढ़ गया है। देश में जो साम्प्रदायिक झगडे, रायट्स, होते है, जिनमें लोगों की जाने जाती हैं और उन की सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है, उनको रोकने के लिए यह खर्च जरूरी है। मैं साम्प्रदायिक पार्टियों और साम्प्रदायिक अशाति उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों और दलो को कहना चाहता हूं कि वे अशांति फैलाने का प्रयत्न न करें। अगर देश में साम्प्रदायिक शाति बनी रहे और कोई झगड़ा-फसाद या रायट न हो, तो सी०आर०पी० और दूसरी पुलिस फोर्सिज पर, वायरलैस और दूसरे साधनो पर जो खर्च बढ़ता जा रहा है, वह खर्च हम बचा सकते है और इस तरह यह माग कम हो सकती है। लेकिन अभी इस देश में वह स्थिति अभी नही आई है। देश में साम्प्रदायिक रायट्स बढ़ते जा रहे हैं।

अपने इलैक्शन मैनिफैस्टो मे हमने "गरीबी हटाओ" का नारा दिया था। हमने उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। नक्सलाइट्स का सवाल एक आर्थिक सवाल है। जब तक हम देश की आर्थिक कायापटल नही कर सकेंगे, तब तक नक्सलाइट मूवमेंट खत्म नही होने वाला है। हमको शिक्षित और अशिक्षित बेकारी की समस्या को हल करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इस बजट में उसके लिए व्यवस्था की गई है। अगर इस समस्या की तरफ पूरा ध्यान दिया गया, तो नक्सलाइट मूवमेंट में कुछ कमी होगी। लेकिन फिलहाल तो सामान्य जनता के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय के अन्तर्गत यह खर्च जरूरी है।

प्रयत्न करने से साम्प्रदायिक रायट्स और नक्सलाइट मूवमेंट बन्द हो जायेंगे। तब इस खर्च को कम करने की बात ठीक हो सकती है। लेकिन जब तक साम्प्रदायिक रायट्स और नक्सलाइट मूवमेंट जारी रहेंगे, तब तक तो यह खर्च बढता ही जायेगा। जो पार्टियां साम्प्रदायिक रायट्स कराती है और जो नक्सलाइट मूवमेंट के पीछे है, जब तक वे यह बात नहीं समझेगी कि देश की आम जनता पर जो कर लगाया जाता है, उसी में से यह खर्च करना पड़ता है, तब तक साम्प्रदायिक राइट्स और नक्सलाइट मूवमेंट का अन्त नही होगा। अगर साम्प्रदायिक रायट्स और नक्सलाइट मूवमेंट का अन्त नही होगा, तो यह खर्च बढ़ता जायेगा और आम जनता पर ही उसका बोझ पड़ेगा। इसलिए मैं उन पार्टियो से जो साम्प्रदायिकता पर आधारित है और जो नक्सलाइट मूवमेंट इस देश मे बढाने का प्रयत्न करती है उनसे विनती करता हूं कि वह इसमे भाग न ले और ऐसी स्थिति बढाने वाले लोगों के साथ हाथ न बढ़ाए तो देश के लिए अच्छा होगा।

दूसरी बात यह है कि देश में हम ने इतनी इंटेलिजेंस ब्रांचेज रखी है। फिर भी इस देश मे अभी-अभी कहा गया कि फोरन मनी आता रहता है और यह फारेन मनी इस देश में आज इस तरह फैला हुआ है कि कई राजनैतिक पार्टियां और कई राजनैतिक आदमियो को उस से खरीदा जा सकता है। यदि इन फारेन फंड्स को रोका नही जायेगा और यह फारेन फंड्स हमारी राजनैतिक गतिविधियां पर छा गया तो इस देश मे भी वही हाल होगा जैसे दूसरे देशों में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अगर ऐसा ही हाल रहा तो इस देश मे भी डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है। अगर यह फारेन फंड्स कायम रहेंगे तो इस देश में भी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और यह देश साम्राज्यवादियों के हाथ में उनका एक एजेंट बन कर

रह जायेगा। हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति न पैदा हो। इसलिए फारेन फंड्स को रोकने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए चाहे वह किसी भी देश का हो।

दूसरा मेरा कहना यह है कि जो एक दूसरे राज्यों को बीच में अनेक सवाल हैं, बोर्डर के उनको लम्बा करते जाने से हमें वहां रिजर्व पुलिस भेजनी पड़ती है, सी० आर० पी० भेजनी पड़ती है और एक दूसरे राज्यों के बीच गोली-बारी करनी पड़ती है। इसलिए जो यह मसले हैं जैसे केरल और मैसूर, मैसूर और महाराष्ट्र के ऐसे सवालों को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए क्यों यह जो सवाल है यह इस देश के एक राज्य की जनता और दूसरे राज्य की जनता के बीच कडुवापन पैदा करते हैं। इनको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। ऐसे ही कई नदियों के पानी के झगड़े हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में नर्मदा का सवाल है। कई सालों से यह सवाल हमारे सामने पड़ा है। लेकिन उसका कोई हल नही आया। इस वजह से मध्य प्रदेश और गुजरात की प्रजा के बीच में जो कडुवापन आ गया है वह हमारे देश की एकता मे बाधक है। इसलिए यह जो सवाल है इनको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। अगर यह जल्दी हल हो जाए तो इस देश की एकता में फायदा होगा।

दूसरा एक सवाल हमारे गुजरात का ही है। दादरा और नागर हवेली सेंट्रल स्टेट हैं। हम गुजरात के लोग चाहते हैं कि दादरा और नागर हवेली को गुजरात में मिला दिया जाय। दूसरे, जो दादरा और नागर हवेली के आदिवासी लोग हैं वह कितने सालों से अपनी जमीन को बोते हैं। उसके मालिकों की तरह वह उस जमीन में रहते हैं। लेकिन कई बार यहां कहा गया कि दादरा और नागर हवेली के आदिवासी लोगों को उस जमीन का मालिक बनाया जाय, लेकिन अभी तक यहां से वह सवाल हल नही हुआ है। मैं गृह मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वह सवाल जल्दी से जल्दी हल किया जाए। यदि यह हल नहीं किया गया तो जो आदिवासी लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए कई शक्तियां वहां काम कर रही हैं। नक्सलाइट लोग या लेफ्टिस्ट जो लोग हैं वह उनको गुमराह कर रहे हैं। यह नंगे और भूखे इंसान अगर कुछ बैठे तो उसका दोष इन भूखे और नंगे लोगों पर नही होगा, यह दोष हम पर आएंगा। इसलिए यह सवाल हमें तत्काल हल करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। मगर जो दक्षिण के राज्य हैं जो नान-हिन्दी भाषी राज्य हैं वहां उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरा ध्यान हम ने नही दिया है। इसलिए मेरी विनती है कि यदि हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानते हैं और हिन्दी को ही जब राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस देश के सामने रखना चाहते हैं तो यह जो नान-हिन्दी भाषी राज्य हैं उनमें जल्दी से जल्दी हिन्दी का प्रचार और प्रसार किया जाय।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेज जल्दी से जल्दी खत्म करने चाहियें। हमने अपने मैनिफेस्टो मे उनका वचन दिया है। इसलिए जल्दी से जल्दी कास्टीट्यूशन में सुधार करके प्रिवी पर्सेज और प्रिविलेजेज को खत्म करने की मैं मांग करता हूं।

श्री मंगरु उइके (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मंत्रालय के सामने देहाती क्षेत्र में रहने वाले लोगो की कुछ बातें रखनी हैं विशेषतया आदिवासियों की। इस साल जो मर्दुमशुमारी हुई उस मर्दुमशुमारी में सात आठ गांवो की मर्दुमशुमारी का विश्लेषण हम ने किया। आदिवासियों को या हरिजनों को उन की जाति लिखने से ही वह आदिवासी या हरिजन माने जाते हैं, जाति अगर उन्होंने आदिवासी बताई और लिखने वाले ने उस को

[श्री मंगरू उइके]

आदिवासी के कालम में नही लिखा तो आदिवासियों की संख्या में यह नहीं आते हैं, तो इस तरीके से मैंने देखा कि लगभग बीस प्रतिशत जनसंख्या उन की दस बारह गांवों में कम मिली। उन गांवों की मर्दुमशुमारी को मैंने देखा। तो मैं विनती करता हूँ कि 1961 में जो हर एक जिले की मर्दुमशुमारी थी, उसमें उस जिले की अन्य जनता की संख्या में जितने प्रतिशत बढ़ती हुई है उतने ही प्रतिशत बढ़ती आदिवासियों की संख्या में भी होनी चाहिए। आदिवासियों की संख्या भी उसी प्रतिशत में बढ़नी चाहिये चाहे लिखने वालों ने कुछ भी लिखा हो। इस में एक दल विशेष का बड़ा भारी प्रचार रहा कि इन लोगों को जो जातियों के अनुसार आदिवासी और हरिजन लिखा जाता है वह न लिखा जाय। यह बडे जोरों का प्रचार रहा और इस कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई।

14.48 hrs.

[Dr. Saradish Roy *in the Chair*]

दूसरी बात—इन सारे आदिवासियों का कोई धर्म नही होता है, माना नही जाता है कि कोई धर्म उनका होता है पर उनको हिन्दू धर्म के अन्दर लिखा जाता है। 1961 की मर्दुमशुमारी में मेरे मध्य प्रदेश मे 66 लाख आदिवासी थे। उन आदिवासियो का धर्म अलग ट्राइबल रेलीजन लिखना चाहिए था। लेकिन एक भी ट्राइबल रेलीजन में नही आया। सब जनसंख्या हिन्दू धर्म मे लिखी गई। होता क्या है हिन्दू धर्म में लिखने से कि जितनी भी हमारी अदालतें हैं वह हमारे आदिवासियों के विवाह, वारिसान और विवाह विच्छेद के जो मामले होते हैं उनका निर्णय हमारा जो विशेष रीतिरिवाज है उसके अनुसार न करके हिन्दू ला के अनुसार करती है जिससे हमारी मिल्कियतों का खिलाफ फैसला हो जाता है। हमारी मिल्कियतों का फैसला हमारे जो अलग सामाजिक कायदे हैं उनके अनुसार नहीं किया जाता। तो यह बड़ा भारी नुकसान होता है और इसके कारण आदिवासियों की इतनी जमीन हिन्दू ला के अनुसार निकल कर जा रही है कि एक जिले की एक तहसील की बात मैं बताता हूं—पिछले साल 725 आदिवासियों की जमीन इस कायदे के अनुसार निकल गई। एक तो यह बात है। दूसरी बात यह कि आदिवासियों के अन्दर हमारी जो जाति है गोंड जाति मध्य प्रदेश में यह 32 लाख लोग हैं और इन में से 27 लाख गोंडी बोली बोलते है। पर मर्दुमशुमारी में एक भी गोंडी बोली का नही दिखाया गया। हालांकि बोली लिखी जानी चाहिए। लेकिन इनकी बोली नही लिखी गई इस मर्दुमशुमारी में। इस तरीके से हमारी जो बोली है, हमारा जो समाज है उसको खत्म किया जा रहा है। हमारी जनसंख्या कम करने का एक प्रमुख कारण और भी है कि जनसख्या के अनुसार जो विधान सभा की या पार्लियामेंट की सीटें मिलती है या सर्विसेज के अन्दर संरक्षण प्राप्त होता है वह कम हो, यह खास उद्देश्य है हमारी जनसंख्या कम करने का।

दूसरी बात—आज इन का कई प्रकार से शोषण हो रहा है, गृह मन्त्रालय को इस तरफ ध्यान देना चाहिये, इसके लिए भारत सरकार की भी कुछ जवाबदेही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरिजन आदिवासियों के लिए केन्द्रीय सरकार में एक कमीशन होता है, जो हर साल अपनी रिपोर्ट प्रेजिडेन्ट को पेश करती है, उसके बाद वह रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आती है और उस पर यहां चर्चा होती है। लेकिन 12 महीने से कोई कमिश्नर नहीं है और अभी तक एप्वाइन्ट नहीं किया गया है। मैं नही जानता कि इस वर्ष कमिश्नर की रिपोर्ट आयेगी या नहीं आयेगी। यह कमिश्नर इण्डिपेन्डेन्ट होता है, इण्डिपेन्डेन्ट ढग से, स्टेटों के दबाव में न आकर अपनी रिपोर्ट देता है, सही आदिवासी हरिजनों की तकलीफें बयान

करता है, लेकिन इधर 12 महीने से कोई कमिश्नर नहीं है। इस तरफ फौरन ध्यान देना चाहिये।

पहले यह विभाग गृह मन्त्रालय के अन्दर होता था और गृह मन्त्रालय का स्टेटों के चीफ मिनिस्टरों पर प्रभाव होता था। वह हर मामलों को हल कराने की प्रभावी कोशिश करता था। लेकिन अब एक नया विभाग सोशल वेलफेअर खोल दिया गया है और इस विभाग में जो अधिकारी काम करते हैं, आम तौर पर वे राज्यों से आते हैं, इसलिए कोई भी रिपोर्ट अपने राज्य के खिलाफ लिखने से हिचकिचाते हैं।

जहां जहां केन्द्र की तरफ से कोई काम शुरू होता है, जैसे बेलाडिला की खदानो में काम शुरू हुआ, वहां पर आदिवासी परिवार भी जा कर काम करते है। हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है कि उन प्रोजेक्टस में जो लोग बाहर से आकर काम करते हैं, वे लोग आदिवासी युवतियों को अपने यहां मेड-सर्वेन्ट के तौर पर रख लेते हैं। उसके बाद उन लोगों ने उनके स्त्री के रूप में व्यवहार किया और सन्तान हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया। इस तरह का व्यवहार 360 युवतियों के साथ हुआ है। अब वहां के कलैक्टर ने एक आर्डर निकाला है, एक एस० डी० ओ० को एप्वाइन्ट किया है, जो इस बात की देख-रेख करेगा कि बैलाडिला में काम करने वाले आदमी अगर आदिवासी युवतियों को मेड-सर्वेन्ट रखेंगे तो उस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। केन्द्रीय सरकार को इस बात को देखना चाहिये। यह एक ही जगह नहीं होता है, जहां जहां आदिवासी इलाकों में नई फैक्ट्रियां बनती हैं, वहां वहां जो बाहर के लोग आते हैं वे आदिवासी युवतियों को इस तरह से नौकर रहते हैं और उन के भोलेपन का फायदा उठा कर इस तरह का व्यवहार करते हैं।

तीसरी बात—जितना एक्सप्लायटेशन आज इन लोगों के साथ हो रहा है—मैं बहुत ज्यादा तो इस समय नहीं बता सकूंगा, लेकिन इतना जरूर बतला देना चाहता हूं कि जितना शोषण, जितनी लूट आज इन आदिवासियों की हो रही है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। मैं 50 सालों से आदिवासियों के अन्दर काम कर रहा हूं। अभी 30 दिन तक मैंने आदिवासी क्षेत्रों का दौरा किया, अपनी कांस्टीचूएन्सी को छोड़ कर 200 मील दूर के जिलों में गया, डेढ़ दो लाख लोगों से सम्पर्क किया, कई जगह लोगों को रोते हुए पाया। इसका कारण सरकारी महकमें हैं, आदिवासी कल्याण महकमों की तरफ से हर जगह लूट मची हुई है। एक भाई ने अभी नक्सलाइट मूवमेंट का जिक्र किया, मैं यह नहीं कहता कि वह नक्स्लाइट बनेंगे, मैं इस को नक्स्लाइट नाम नहीं देता हूं, लेकिन जब इस तरह की लूट होती है, इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, तो उनके अन्दर भी इस तरह की बात पैदा हो सकती हैं, उनके अन्दर भी एक क्रान्ति पैदा हो सकती है, चाहे वह जमीन के लिए हो, जंगल की उपज के लिए हो या आदिवासी युवतियों के साथ व्यवहार को लेकर हो।

अभी कुछ सालों से राज्य सरकारों ने अपनी शराब की नीति में परिवर्तन किया है, क्योंकि शराब से राज्यों को ज्यादा पैसा मिल सकता है। आज वहां पर जब शराब का ठेका नीलाम किया जाता है, तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि यह 70 फीसदी आदिवासी इलाका है, इसलिए ज्यादा बोली बोलों। अगर कोई पांच हजार बोली बोले तो कहा जाता है कि यहां पर बिक्री ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा बोली लगाओं। मैं आपके सामने इस के आंकड़े रखना चाहता हूं—1960-61 में मध्य प्रदेश में शराब से 4,31,46,552 रुपये की आमदनी हुई थी, जब कि 1965-66 में 7,65,20,998 रुपये की आमदनी हुई। इसके एक ही साल बाद 1967-68 में 10,84,73,270 रुपये की आमदनी हुई। ऐसी बात नहीं है कि शराब की कीमत बढ़ने से ज्यादा आमदनी हुई है। मैं

[श्री मंगरु उइके]

आपको कन्जम्पशन की फिगर्स भी देना चाहता हूं—1960-61 में 50,25,545 लिटर्स शराब का कन्जम्पशन हुआ था, जबकि 1965-66 में 73,19,594 लिटर्स कन्ज्यूम हुई और 1967-68 में 80,42,159 लिटर्स कन्ज्यूम हुई। यह कन्जम्पशन क्यों बढ़ रहा है? इस का कारण यह है कि राज्य सरकार शराब से मनमाना पैसा कमाने के लिए ठेकेदारों की मदद करती है। आप सरगुजा, रायगढ़ जिले में जाएं तो हर गांव में चार-छः मकानों पर आप को सफेद झण्डे लगे हुए मिलेंगे, जिसका अर्थ यह है कि उन आदिवासियों ने शपथ ली है कि वे शराब नहीं पीयेंगे, लेकिन होता क्या है कि अगर किसी ऐसे आदमी के घर में शादी होती हैं जो शराब नहीं पीता है तो वहां का ठेकेदार पुलिस अफसरों को लेकर उसके घर पर जाता है और कहता है कि तुम्हारी जाति में शादी के मौके पर 100 रुपये की शराब जरूर ली जाती है, तुम लो या न लो, लेकिन 100 रुपया तुम को जरूर देना होगा। अगर वह नहीं लेता है और उसके पास पैसा नहीं होता है, तो उन लोगों ने एक कंगाल बैंक खोल रखा है, उससे 100 रुपये की रसीद लिखा लेते हैं और बाद में उस रसीद के आधार पर उसकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं।

मैं शराबबन्दी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे बतलाया कि हम पीते हैं, लेकिन हर दिन नहीं। बाजार जाते हैं उस वक्त थोड़ा बहुत पी लेते है। जो पैसा नमक, कपड़ा, खरीद कर बच जाता है उससे पी लेते हैं, हमेशा नहीं पीते हैं। जब सरकार ने ठेकेदारों को इतनी इजाजत दे दी है कि एक एक गांव में जाकर दो तीन शराब के पीपे ले जाकर बैठ जाते हैं, घर घर में दो चार बोतले रख देते है और उसका पैसा उनको देना पड़ता है, चाहे पीयें या न पियें। इस तरह का व्यवहार आदिवासियों के साथ ठेकेदारों के द्वारा हो रहा है और पुलिस-एक्साइज वाले इस काम में उन को सहायता करते हैं। हमने कई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों से इस के बारे में बात की लेकिन वे कहते हैं कि हम क्या करें, सरकार के छोटे अफसर, पुलिस के लोग ठेकेदारों की जीपों में चलते हैं और कहते हैं कि हम किस किस से दुश्मनी मोल लें। अगर हम कुछ करते हैं तो हमने देखा है कि चुनाव के अन्दर यही ठेकेदार नेता बन कर दौड़ते हैं। इस तरह से हम कैसे आदिवासियों का कल्याण कर सकते हैं?

मैं गृह मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से आदिवासी कल्याण के लिए दिया जाता है उसका चार आना भी इन आदिवासियो के पास नहीं पहुंचता, उसका बारह आना तो आपके अफसरों के खीसे में चला जाता है, मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। अफसरों को इस की कोई फिक्र नहीं है कि किस तरह से यह पैसा लूटा जा रहा है और आदिवासी अपढ भोले हैं इसी बजह सें कोई अफसर पकड़ में नहीं आता है वर्ना पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है इस लिये यह पैसा जो यहां से दिया जाता है आप उनको न दें लेकिन हमारे आदिवासियो की जो मिल्कियत है उसको कायम रखे और उनका जो दैनिक मजूरी इत्यादि का नाजायज तरीके से एक्स्प्लायटेशन होता है उसको अवश्य रोकें। इससे आदिवासी खुश रहेगा। वह अल्प-सन्तोषी है। इतने से ही वह सन्तुष्ट हो जायेगा। केन्द्र द्वारा करोड़ो रुपया देने पर भी उसका कोई खास लाभ नहीं हो रहा है।

आप ने आदिवासियो की बहुत सी कालोनीज बसाई है, मैं अपनी कास्टिटुएन्सी से 250 मील दूर सरगुजा जिले में उनकी कालोनीज को देखने गया, 31 कालोनीज में से सात को मैंने देखा शिफ्ट कल्टिवेशन वाले लोगों को वहां ला कर बसाया गया है, दो दो लाख रुपया प्रति कालोनी इस काम के लिए केन्द्र सरकार ने दिया लेकिन आज बीस साल के बाद उन की

हालत को जाकर देखिये, वहां कुछ भी नहीं है। न उनके पास जमीन की रसीदें हैं और न आदिवासी कल्याण कार्यों का उनका कोई फायदा होता है। मैं गृह मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि उनके लिए कमिशन मुकर्रर किया जायेगा। सरकार ऐसा कमिशन मुकर्रर करे ताकि वहां जाकर इन सारी बातों की जांच करे।

इन मांगों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

15.00 hrs.

SHRI BIRENDER SINGH RAO (Mahendragarh) : This is the most important Demand that we are discussing, because the Home Ministry is responsible for keeping law and order m the country, for maintaining the integrity of the country and providing security of life and property of the people. But during the period of our independence we have seen that the Home Ministry has not done its job. Ninety per cent of the ills of this country today can be laid at the door of the Ministry of Home Affairs. There is discontent all over. Violence is increasing. Whether it is a small thing or a big thing, the Home Ministry could have checked them, but we see today that there is a demand for separate States all over, communal forces are raising their heads and particularly because the party in power decided to enter into an alliance with one of the communal parties in the country, that is feeding someother communal forces and tendencies which are also rearing their ugly head. The Home Ministry has failed to check these tendencies.

Most of the troubles in India today are due to the fact that no principles, no rational criteria, have been kept in view in the most important matters in the country. The States Reorganisation Commission headed by Mr, Fazl Ali was appointed and it laid down that States in India should be re-organised on the basis of language, caltura administrative convenience, economic viability and various other factors. And we saw in that Commission the report of a very able Member, Mr. K. M. Panikkar, who strongly advocated the division of the largest State in India, Uttar Pradesh, which had nearly nine crores of people. If we consider U. P. as a country, it will be the ninth largest country on earth in terms of population, and yet nothing has been done so far about those recommendations.

Although certain States have been created recently, no criterion was kept in view. It was only due to political pressure and such other considerations that motivated the Government to accept the demands. People were forced to put forward their demands violently and it resulted in bloodhsed. But I see no reason why a separate Vishal Haryana, which would be a bigger State than the present Haryana, should not be created, why the demand for a separate Telengana should not be accepted. why the aspirations of the people of Goa should not be respected if they want a separate State. If Nagaland could be created why not Vidarbha, why not a separate Bhojpuri ? This is the time when we should seriously consider all these matters. It is high time another States Reorganisation Commission was appointed. I for one would not mind if the whole country is divided into zones, if all the States created on the basis of language and culture are done away with. But we should stick to one principle.

Haryana has been the worst sufferer. I believe our Prime Minister today is perhaps the strongest Prime Minister in many ways this country has had but she has failed to do justice to Haryana. I do not know for what considerations. There was the Shah commission's report. But Haryana was always made a scapegoat. When they wanted the Government in Bengal or Punjab to be toppled, Haryana was chosen and its Government dissolved inspite of the fact that it had the backing of the majority in the Assembly. In the evening there would be West Bengal ; the next day there would be Punjab. If they want Mahajan's report should not be implemented, they first ignore the Shah Commission's report so that Mahajan Commission report is not pressed by people. There are territorial disputes between the States in the country ; there is dispute between Haryana and Punjab and Himachal has now come in though it had no right to claim the property of erstwhile Punjab ; a new factor, topography, was introduced ; because certain places are higher than the plains, they should go to H.P.

[Shri Birender Singh Rao]

Himachal, as the name signifies, should be kept confined to the Himalayas. What right does it have on the lands and towns created by the people of Haryana and Punjab such as Simla and Dalhousie. There is dispute between Mysore and Maharashtra, between Manipur and Assam, between M. P. and Gujarat. The Home Ministry has failed to resolve any of these disputes. The Prime Minister's award with regard to the dispute between Haryana and Punjab over Chandigarh has worsened matters. There was enough confusion which has now become worse confounded. It is no award at all ; no criterion had been kept in view··· (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude ; your time is up.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : The Treasury Benches have not taken this discussion seriously. Most of the time the Home Minister, who happens to be the Prime Minister also, and the Minister of State were not present in the House. You should take a new decision that at least on matters connected with the budget, the time should be divided, half and half, between the opposition and the Governmet benches so that we can give our opinion in the House. The country is really going to dogs. Corruption is rampant ; Election Commission has been reduced to an ineffective machinery unable to conduct elections fairly. Governer's Office has been made ridiculous. Even under the nose of this Government in Delhi we know how corruption is going on even in the courts and judiciary ; people are not getting justice. These things should impel the Government to bring Delhi into a State. Why should the people of Delhi not get their democratic rights ? Why should they not have an Assembly. Delhi and Haryana should be merged. New Delhi can remain the capital like Washington D. C. and the area now under the New Delhi Municipal Committee can remain with the Government of India. Things like this should be seriously considered. There are people owing allegiance to foreign countries.

MR. CHAIRMAN : You better conclude you have already taken eleven minutes.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : I have not even started ; I have to speak about U. P.

Now, the Fazl Ali Commission report contained a dissenting note by Sardar K. M. Panikkar. The reason given is that a Vishal Haryana cannot be created because Uttar Pradesh cannot be divided, because Uttar Pradesh is the land of Rama and Krishna ; that this land of Rama and Krishna cannot be divided (*Interruption*) Now, while advancing that argument, this land which was the land of Buddha, which was the land of Bhagwan Mahavir, has been divided. This was the land of Rama and Krishna also in 1947 when it was divided. The land of Guru Nanak, which is Punjab, was also divided.

Uttar Pradesh has provided the Prime Ministers so far. Uttar Pradesh has supplied the Home Ministers so far most of the time. Yet, they say that they would not part even with one Bhagwan ; they want Rama and Krishna both with them. They would not be content. They want all this and Heaven too. This is too much.

MR. CHAIRMAN : There is no more time. You have taken much more time. Please finish.

SHRI BIRENDER SINGH RAO : With these few observations, I have got to stop because you are not allowing me. I cannot fight with you.

DR. MELKOTE (Hyderabad) : Mr. Chairman, Sir, the demand of this Ministry is a very important one. The Ministry has a comprehensive scope to deal with anybody in this country. But the time allotted to us is so meagre that to touch even one subject, one point, it is difficult. When problems like the minority communities, communal disturbances, law and order, internal security, crossing of the floor, Ompudsman, privy purses and privileges, river water disputes, prohibition, national language, etc., have got to be spoken about, you can understand what time one would like to take, These are all important points.

I would like to bring to your notice that after the first general election, this is the first year that the Treasury Benches have regained their strength and that was entirely due to the boldness, vision and statesmanship of the Prime Minister. From what she has been doing, one can very easily see that

she is a strong woman with concrete suggestions which have to be implemented. Therefore, people expect a good deal from her. To say *Garibi Hatao* is a very simple matter, but to implement it to the satisfaction of the people is not a small affair. In so implementing, all these points that I first mentioned, impinge one against the other, and therefore, it is not merely *Garibi Hatao* that is necessary but a kind of satisfaction to the whole country has got to be given, and this the Home Ministry alone can do and none else.

I was surprised to find in this report that has been presented to us, that possibly owing to reasons of economy, possibly to save the State Governments from the clutches of the Opposition benches, many things have not been said. The pages on Telengana and many other matters have not been given the necessary data which are expected. It is absolutely a drab affair.

There have been Members from Andhra Pradesh who have been crying hoarse and saying that "we do not mind improving the Telengana situation but the country's integrity should be maintained." Why only the integrity of Andhra Pradesh ? Why not there be a unitary type of Government so that every one could integrate ? So, it is not a question of Andhra Pradesh and Telengana. The question arises on account of the disparity that takes place in various parts of the country and so the disturbances arise. Where people's verdict is given in favour of a particular thing, democracy is sustained in this country because the Government tries to follow to the extent it can. But when particularly this Government comes out with the report two years after the Prime Minister mentioned here the eight-point programme for the relief in Telengana after the struggle there, what is it that we see ?

No details and facts whatsoever have been given. Why ? The only fact is that none of those things have been implemented. The implementation does not lie in the hands of the Central Government ; it lies with the State Government. If the State Government does not implement them, what kind of report can the Central Government give ? Therefore, if members from Andhra shed tears for the well-being of Telengana, it only means, just as gentleman's promises, promises should be held out here by the Prime Minister, to neglect Telengana altogether later.

I would only plead that Telengana problem is a very important one. Very delicate negotiations are going on. Of course, I want the economic prosperity and the well-being of the country, but at the same time, I cannot allow anybody to over-rule and to colonise in Telengana and exploit the Telengana people, as they have been doing all these years. This has been our contention and the Prime Minister knows it. Very delicate negotiations are going on. I only wish that the Chief Minister of Andhra Pradesh, the Andhra M.P's., the Telengana people, the Telengana M.P's. and the Prime Minister evolve a solution to the satisfaction of the Telengana people. The satisfaction of the Telengana people is the primary thing. M.P's. do not count for anything. We have told the Prime Minister : We will co-operate with you. Whatever decisions you take, if you feel they will satisfy the Telengana people, please put those decisions before them. If they are acceptable to the Telengana people, we shall not come in the way. What more promise can we give ? We do not want to say anything against anybody. The nation is facing on the one side the refugee problem from East Bengal and on the other, there are various other internal problems. There is the question of implementation of many of the promises that the Prime Minister is anxious to implement. I wish all strength to her and I hope and trust that in the coming few days, she will send for the Telengana people, sit with them, discuss the matter with the Andhra Chief Minister and the Andhra people and evolve a solution which will give peace to that part of the country. I do not want to say anything more. I only hope that the solution to the Telengana problem would be found very very early, as the people are getting very restless.

श्री मोहम्मद ताहिर (पूर्णिया) : जनाब चेयरमैन साहब, होम अफेयर्स के मुताल्लिक बोलते हुए मुझे यह कहना पड़ता है कि होम डिपार्टमेंट या हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की हैसियत से या पार्टी की हैसियत से, जो कहती है उस पर अमल नहीं करती । कहीं तो अमल करती है, कहीं बिल्कुल भूल जाती है । जो

[श्री मोहम्मद ताहिर]

कहती हैं अगर उस पर अमल करें तो यह मुल्क कहीं से कहीं पहुँच जाय ।

होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मुलहजा हो । फरमाते हैं :

"The communal situation in the country gives 'cause' for concern. Government have, in consultation with the State Governments, taken various legislative and administrative steps to deal with the situation."

मैं कहता हूं कि कौन सा लेजिस्लेटिव स्टैप या ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टैप आपने स्टेट्स में लिया है आज तक जिससे मालूम हो कि आपने कुछ किया है ? कोई लेजिस्लेटिव या ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टैप आप ने स्टेट्स में नहीं लिया कम्युनल सिचुएशन को ठीक करने के लिये । इस किस्म की बातें कहना, मुनासिब नहीं है ।

मैं आपको इलैक्शन मैनिफेस्टो की याद दिलाना चाहता हूँ । मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यहां नहीं है । मैं चाहता हूँ मिस्टर मोहसिन साहब, डिप्टी मिनिस्टर उनको इसकी याद दिला दें । इलैक्शन मैनिफैस्टो में एक चैप्टर माइनोरिटीज का है । इसमें कहा गया है :

"In keeping with its past tradition, the Congress is pledged to protect the rights and interests of all minorities.

The dark and evil forces of right reaction which masquerade in a variety of forms are intent upon destroying the very base of our democratic and socialist objectives. They are attempting to consolidate their position. They exploit some of the genuine grievances of the people and arouse the emotions of various sections by preaching religious fanaticism, racial supremacy and chauvinism. History records that fascist forces always emerge through such nefarious manoeuvres. The Congress is determined that this shall not happen in our country. And for this purpose, it will take effective measures in all fields, including education at all its stages."

जोरदार लफ्जों में आपने कहा है :

"The Constitution lays down that the State and local authorities should provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. It shall be our endeavour to implement this.

Secularism is one of the basic tenets of our Constitution. In accordance with his constitutional imperative, the Congress will strive to ensure that all minorities have full freedom to establish, manage and run educational and other institutions."

इसी किस्म की बहुत सी बातें हैं । बाद में आपने यह फरमाया है :

"The Congress, therefore, appeals to the people to return its candidates to the Lok Sabha and thus give it a clear mandate to :

(i) continue the advance to socialism through democratic process and devise administrative system capable of speeding implementation;

(ii) put down the forces of violence and disorder so that all our citizens can live in peace and harmony."

लोगों को यकीन था कि उनके लीडर्ज की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये जो वादे हुए हैं, इनको जरूर पूरा किया जाएगा । लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि होम मिनिस्टरी की रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । जो रिपोर्ट उसकी हमारे पास आई है, वह सिफर है, खाली है । इसके मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा गया है । कम्युनल डिसटरबेंसिस के बारे में हुआ यह है कि नैशनल इंटेग्रेशन काउंसिल बना दी गई है । मैं समझता हूँ कि वह सिफर है, कुछ नहीं कर रही है । आप देखें कि आपने 1968 में सिविल डिफेंस एक्ट पास करवाया था । क्या किसी स्टेट में इसको लागू भी किया गया है ? कम अज कम उसको लागू तो किया जाता । अगर उस पर अमल होता और उसको लागू

किया जाता तो मुमकिन है झगड़े फसाद न होते। लेकिन उसको लागू ही नहीं किया गया है।

होम मिनिस्टर जब पन्त जी थे तो उन्होंने उर्दू के बारे में एक सर्क्युलर भेजा था और उसमें यह कहा गया था कि इसको इसकी प्रापर प्लेस दी जाए। वह आपके दफ्तर में होगा और उसको आप देख सकते हैं। उसमें यह भी कहा गया था कि जहां जहां उर्दू रिजाइन लेंगुएज हो सकती है वहां-वहां इसको कोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाय। हालांकि उर्दू के बारे में इलैकशन मैनिफैस्टो में भी सब कुछ दिया गया है लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है और न ही इस रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ कहा गया है। बजट डिमांड्ज को भी मैंने देख लिया लेकिन कहीं भी कोई उर्दू के लिए प्रोविजन नहीं किया गया है। डिमांड्ज भी बिल्कुल खाली हैं, साफ हैं। यह बहुत डेंजरस चीज है। माइनोरिटीज के बारे में, मुस्लिम्ज के साथ, क्रिस्चियंज के साथ, सिखों के साथ आपने जो कुछ वायदे किये थे उन वादों को पूरा करने का आपको तैहया कर लेना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने अपनी जान पर खेल कर आप की मदद की हैं, क्या आप समझते हैं कि आगे भी वे ऐसा करेंगे ? माइनोरिटीज को यह समझ लेने का मौका आपको नहीं देना चाहिये कि गलत वायदे उसके साथ किये गये हैं या जो वादे किये गए है वे पूरे नहीं हो रहे हैं। वादे जो आपने किए हैं, उनको आपको पूरा करना चाहिये।

जहां तक कम्युनल डिसटरबेंसिस का ताल्लुक है, बजट स्पीच में इनके मुताल्लिक एक लफ्ज भी नहीं कहा गया है। हां, प्रेजीडेंट साहब का जो एड्रेस हुआ था उसमें इसका जिक्र जरूर किया गया था। मुझे खुशी है कि प्रेजीडेंट साहब ने इसका जिक्र किया। अपने ऐड्रस में उन्होंने कहा था :

"to achieve this my Government are firmly committed to implementing the economic and social transformation outlined in the mainfesto which has received such overwhelming support by the electroate."

फिर आगे चल कर वह कहते हैं :

"the persistence of communal tension in some parts of the country and occasional flaring up of violence constitute threat to our secular democracy and to the basic value of civilised life. The Government is determined to overcome this danger."

ये सब चीजें कही जाती हैं लेकिन कहीं भी हम इनके लिए प्रोविजन नहीं पाते हैं ताकि आप कुछ काम कर सकें।

अभी रेलवे बजट पर बहस हुई थी। मैंने एक चीज का जिक्र किया था। मैं उम्मीद करता था कि रेलवे मिनिस्टर उसका जवाब देंगे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर आ गई हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह सुन रही होंगी। जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंज हैं, देवबन में हैं, लखनऊ में हैं, अमरोहा में है, या दूसरी जगहों पर हैं, वहां के लड़कों को रेलवे के जरिये कंसैशन दिया जाता था। बजाय इसके कि और कुछ सहूलियतें दी जाती, नार्थ रेलवे के जनरल मैनेजर ने वह कंसैशन इन तमाम मदरसों को देना बन्द कर दिया है। इस कंसैशन को जारी रखा जाना चाहिए। इसको आपको रेस्टोर करना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि जनरल मैनेजर ने जो सर्क्युलर आर्डर इसके बारे में भेजा है उसको आप वापस लेंगे। जो कुछ मिल रहा था उसको भी आप छीन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह छीनने का वक्त था।

मैं प्राइम मिनिस्टर साहिब से बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इलैकशन मैनेफैस्टो में जो वादा किया गया हैं उसको वह पूरा करें। पूरा करने का इरादा और नीयत न हो तो खैर और अगर हो तो यह काम होना ही चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि आप माइनोरिटी कांडसिल कांस्टीट्यूट करें और उसकी सदारत आप करें, प्राइम मिनिस्टर उसकी चेयरमैन हो।

[श्री मोहम्मद ताहिर]

इसको कांस्टीट्यूट करना इसलिए जरूरी है कि कोई मशीनरी आपके पास नहीं है माइनोरिटीज की हिफाजत करने के लिए। आपके पास जो कुछ रिपोर्ट आती है वह वही आती है जो आफिस वाले तैयार कर के दे देते हैं। आप कोई मशीनरी बनाइये। बेहतर चीज तो यह होगी कि माइनोरिटी कांउसिल की आप तशकील करें और उसकी चेयरमैन आप खुद हों। उसके बाद जितने वादे किये गये है, वे उसके जरिये से पूरे होते रहेंगे। यह कोई नई चीज नहीं है। रशियन कांस्टीट्यूशन को आप देखें। उसमें माइनोरिटी कांउसिल है और उसके जरिये से लोग काम करते हैं। वहां अगर वह हो सकता है। तो यहां क्यों नहीं हो सकता है। इसके बिना आपको दिक्कत हो सकती है। इस वास्ते इस तरफ आपका ध्यान जाना जरूरी है। माइनोरिटीज काउंसिल को कायम करने में जो जम्हूरियत की रोशनी में हो कोई दिक्कत नहीं होगी।

फसादों को रोकने के लिये पुर असर कदम उठाने की भी अज हद जरूरत है। इनको रोकने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, प्राइम मिनिस्टर की है। हम देखते है कि बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो इन फसादों में शरीक तक होती हैं। इनको रोकने के लिए आप फैड्रल फोर्स सेंटर में कायम करें। जहां कहीं फसाद हो वहां फौरन आप इस फैड्रल फोर्स को उसको रोकने के लिए भेजें। फैड्रल फोर्स और मुल्कों के अन्दर भी है। यू० एस० ए० के अन्दर है। वहां पर अगर कहीं फसाद होता है तो उसको भेजा जाता है और वह उनको रोकती है। यहां भी ऐसा होना चाहिये।

हमारे मुल्क में स्ट्राइक्स वगैरह होती रहती है। कभी तनख्वाहें बढ़ाने की बात को लेकर होती हैं। और कभी कुछ और बातों को लेकर होती हैं। यह होम मिनिस्ट्री का काम है, इस डिपार्टमेंट का काम है कि यह लोगों को समझाये। मारल वैल्यूज जो हैं, उन पर आप जोर दें।

यह बात भी निहायत जरूरी है कि सेंटर और स्टेट्स में काम करने वाले हर एक एम्पलाई को ऊपर की तरफ हरगिज नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने नीचे की तरफ देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी 500 रुपये महावार पाता हैं, तो उसको यह देखना चाहिए कि 100 रुपये पाने वाला किस तरह अपना गुजारा करता है। इस तरह उसके दिल में तशफ्फी होगी। लेकिन अगर वह 2000 रुपये पाने वाले की तरफ नजर करेगा, तो उसको हमेशा यह परेशानी होगी कि मैं किस तरह अपनी जिन्दगी बसर करूं। हमारे सेंट्रल और स्टेट एम्पलाईज के दिमाग में यह बात रहनी चाहिए कि दुनिया में छोटे लोग भी हैं, बड़े भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। अगर वे यह देखें कि छोटे लोग किस तरह अपना गुजारा करते हैं, तो उनके दिल में तशफ्फी होने कि हम उन से अच्छे हैं। अगर इस तरह उनके जहन को सही कर दिया जाये, तो वे ज्यादा मांगें पेश करने और स्ट्राइक के रास्ते पर नही जायेंगे।

मैं एक बार फिर अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मेहरबानी फरमा कर अपनी सदारता में एक माइनारिटीज कौंसिल की जरूरत तशकील करें और सेंटर में एक फेड्रल फोर्स कायम करें। जिस वक्त और जहां जरूरत पड़े, वह उस फोर्स से काम लें। वह एक माइनारिटीज कौंसिल बना कर माइनारिटीज के हुकूकत की हिफाजत करने में मदद करें, ताकि आइन्दा किसी के जहन में यह ख्याल न आने पाये कि हमारे साथ जो वादा किया गया था, उसको पूरा नहीं किया गया है। मुल्क में इस किस्म का ख्याल नहीं पैदा होना चाहिये कि जो वादा किया गया है, उस पर अमल नहीं किया गया है, क्योंकि यह बात हमारे लिए बहुत नुक्सानदेह होगी। हमने अपने इलैक्शन मैनिफैस्टो में जो वादे किये हैं, हम उनको जरूर पूरा करेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि वह इस तरफ

कायम बढ़ायें, हम लोग उनके साथ हैं और हम सब मिलकर यकीनन इस काम को कामयाबी के साथ सर-अंजाम दे सकते हैं।

شری محمد طاہر پورنیا۔ جناب چیرمین صاحب۔ ہوم افیرز کے متعلق بولتے ہوئے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ یا ہماری گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کی حیثیت سے یا پارٹی کی حیثیت سے جو کہتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی ہے۔ کہیں تو عمل کرتی ہے کہیں بالکل بھول جاتی ہے۔ جو کہتی ہے۔ اگر اس پر عمل کریں تو یہ ملک کہیں کا کہیں پہنچ جائے۔

"The communal situation in the country gives 'cause' for concern. Government have, in consultation with the State Governments, taken various legislative and administrative steps to deal with the situation."

میں کہتا ہوں کہ کونسا لیجسلیٹیو سٹیپ یا ایڈمنسٹریٹیو سٹیپ آپ نے سٹیپس میں لیا ہے آج تک جس سے معلوم ہو کہ آپ کچھ چاہتے ہیں۔ کوئی لیجسلیٹو یا ایڈمنسٹریٹیو سٹیپ آپ نے سٹیپس میں نہیں لیا۔ کمیونل سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لئے اس قسم کی باتیں کہنا مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو الیکشن مینی فیسٹو کی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ پرائم منسٹر اس وقت یہاں نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں۔ محسن صاحب ان کو اس کی یاد دلا دیں۔ الیکشن مینوفیسٹو میں ایک چیپٹر مائینورٹیز کا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے۔

"In keeping with its past tradition, the Congress is pledged to protect the rights and interests of all minorities.

The dark and evil forces of right reaction which masquerade in a variety of forms are intent upon destroying the very base of our democratic and socialist objectives. They are attempting to consolidate their position. They exploit some of the genuine grievances of the people and arouse the emotions of various sections by preaching religious fanaticism, racial supremacy and chauvinism. History records that fascist forces always emerge through such nefarious manoeuvres. The Congress is determined that this shall not happen in our country. And for this purpose, it will take effective measures in all fields, including education at all its stages."

زور دار لفظوں میں کہا ہے۔

"The Constitution lays down that the State and local authorities should provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. It shall be our endeavour to implement this.

Secularism is one of the basic tenets of our Constitution. In accordance with this constitutional imperative, the Congress will strive to ensure that all minorities have full freedom to establish, manage and run educational and other institutions."

اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں۔ بعد میں آپ نے یہ فرمایا ہے۔

"The Congress, therefore, appeals to the people to return its candidates to the Lok Sabha and thus give it a clear mandate to :

(i) continue the advance to socialism through democratic process and devise administrative system capable of speeding implementation :

(ii) put down the forces of violence and disorder so that all our citizens can live in peace and harmony."

لوگوں کو یقین تھا کہ ان کے لیڈرر کی طرف سے۔ کانگریس کی طرف سے یہ جو وعدے ہوئے ہیں ان کو ضرور پورا کیا جائیگا۔ لیکن مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہوم منسٹری کی رپورٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ جو رپورٹ اس کی ہمارے پاس آئی ہے وہ صفر ہے۔ خالی ہے اس کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ کمیونل ٹنشنز کے بارے میں ہوا یہ ہے کہ نیشنل انٹیگریشن کونسل بنا دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صفر ہے۔ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے ۱۹۶۸ میں سول ڈیفینس ایکٹ پاس کروایا تھا۔ کیا کسی سٹیٹ میں اس کو لاگو کیا گیا ہے۔ کم از کم اس کو لاگو تو کیا تھا۔ اگر اس پر عمل ہوتا اور اس کو لاگو کیا جاتا۔ اگر اس پر عمل ہوتا اور اس کو لاگو کیا جاتا تو ضرور جھگڑے فساد نہ ہوتے۔ لیکن اس کو لاگو ہی نہیں کیا گیا ہے۔

ہوم منسٹر جب شری پنتھ تھے تب انھوں نے اردو کے بارے میں ایک سرکلر بھیجا تھا اور اس میں یہ کہا تھا۔ اس کو اس کی برابر پبلسٹی دی جائے۔ وہ آپ کے دفتر میں ہوگا۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہاں جہاں اردو ریجنل لینگویج ہو سکتی ہے۔ وہاں وہاں اس کو کورٹس میں استعمال کیا جائے۔ حالانکہ اردو کے بارے میں الیکشن مینی فیسٹو میں بھی بہت کچھ دیا گیا ہے۔ لیکن آج تک کچھ نہیں کیا گیا۔ اور نہ ہی اس رپورٹ میں اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے۔ بجٹ ڈیمانڈز کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ لیکن کہیں بھی کوئی اردو کے لئے پروویژن نہیں کیا گیا ہے۔ ڈیمانڈز بھی بالکل خالی ہے۔ صاف ہے۔ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے۔ مائنورٹیز کے ساتھ مسلمز کے ساتھ۔ کرسچنز کے ساتھ۔ سکھوں کے ساتھ آپ نے کچھ وعدے کئے تھے۔

ان وعدوں کو پورا کرنے کے لئے آپ کو اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہئے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں جس طرح سے انھوں نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کی مدد کی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی وہ ایسا کرینگے۔ مائنورٹیز کو یہ سمجھ لینے کا موقعہ آپ کو نہیں دینا چاہئے کہ جو وعدے ان کے ساتھ کئے گئے ہیں۔ یا جو وعدے کئے گئے ہیں۔ وہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ وعدے جو آپ نے کئے ہیں ان کو آپ کو پورا کرنا چاہئے

جہاں تک کیونل ڈسٹربنیسز کا تعلق ہے۔ بجٹ سپیچ میں ان کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ہے یہاں پر پریذیڈنٹ صاحب کا جو ایڈریس ہوا تھا اس میں اس کا ذکر ضرور کیا گیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ پریذیڈنٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا۔ اپنے ایڈریس میں انھوں نے کہا تھا

"to achieve this my Government are firmly committed to implementing the economic and social transformation outlined in the manifesto which has received such overwhelming support by the electorate."

پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں

"the persistence of communal tension in some parts of the country and occasional flaring up of violence constitute threat to our secular democracy and to the basic value of civilised life. The Government is determined to overcome this danger."

ابھی ریلوے بجٹ پر بحث ہوئی تھی۔ میں نے تب ایک چیز کا ذکر کیا تھا۔ میں امید کرتا تھا کہ ریلوے منسٹر اس کا جواب دیں گے لیکن انھوں نے نہ دیا۔ پرائم منسٹر آگئی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ سُن رہی ہونگی جو اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں۔ دیوبن میں ہیں۔ لکھنؤ میں ہیں یا دوسری جگہوں پر ہیں۔ وہاں کے لڑکوں کو ریلوے کے ذریعہ کنسیشن دیا جاتا تھا بجائے اس کے کہ اور اس قسم کے انسٹیٹیوشنز کھولے جاتے۔ ریلوے بورڈ نے وہ کنسیشن ان تمام مدرسوں کو دینا بند کر دیا ہے۔ اس کنسیشن کو جاری رکھا جانا چاہئے۔ اس کو آپ کو ریسٹور کرنا چاہئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو سرکار آرڈر اس کے بارے میں پاس کیا ہے۔ اس کو آپ وہ پورا کریں گے۔ جو کچھ مل رہا تھا اس کو بھی آپ چھین رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہ کیا یہ چھیننے کا وقت تھا۔

میں پرائم منسٹر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن مینی فیسٹو میں جو وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کو وہ پورا کریں پورا کرنے کا ارادہ اور نیت اگر ہو تو یہ کام ہونا ہی چاہئے۔ میں یہ بھی کہونگا کہ آپ مائنورٹیز کونسل کونسٹیٹیوٹ کریں اور اس کی صدارت آپ کریں۔ پرائم منسٹر اس کے چیرمین ہوں۔ اس کو کونسٹیٹیوٹ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ کوئی مشینری آپ کے پاس نہیں ہے مینورٹیز کی حفاظت کرنے کے لئے آپ کے پاس جو کچھ رپورٹ آتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو آفس والے تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ آپ کوئی مشینری بنائیے۔ بہتر چیز تو یہ ہوگی کہ مائنورٹیز کونسل کی آپ تشکیل کریں۔ اور اس کی چیرمین آپ خود ہوں۔ اس کے بعد جو وعدے گئے ہیں وہ اس کے ذریعے سے پورے ہوتے رہینگے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ رشین کانسٹی ٹیوشن کو آپ دیکھیں۔ اس میں مائنورٹیز کونسل ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ کام کرتے ہیں۔ وہاں اگر یہ ہو سکا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بنا آپ کو دقت ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اس طرف آپ کا دھیان جانا ضروری ہے۔

فسادوں کو روکنے کے لئے پُر اثر قدم اُٹھانے کی بھی از حد ضرورت ہے۔ انکو روکنے کی ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کی ہے۔ پرائم منسٹر کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سٹیٹ ایسی ہیں جو ان فسادوں میں شریک تک ہوتی ہیں۔ ان کو روکنے کے لئے آپ فیڈرل فورس سینٹرس قائم کریں جہاں کہیں فساد ہوں فوراً آپ اس فیڈرل فورس کو اس کو روکنے کے لئے بھیجیں۔ فیڈرل فورس اور ملکوں کے اندر بھی ہے۔ یو۔ ایس۔ اے کے اندر بھی ہے۔ وہاں اگر کہیں فساد ہوتے ہیں تو اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ ان کو روکتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہونا چاہئے۔

ہمارے ملک میں سٹرائیک وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اور کبھی کچھ اور باتوں کو لیکر ہوتی ہیں۔ یہ ہوم منسٹری کا کام ہے۔ اس ڈیپارٹمنٹ کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھائے مارل ویلیوز جو ہیں ان پر آپ زور دیں یہ بات بھی نہایت ضروری ہے کہ سینٹرل اور سٹیٹس میں کام کرنے والے ہر ایک ایمپلائی کو اوپر کی طرف ہرگز نہیں دیکھنا چاہئے بلکہ انھیں اپنے نیچے کی طرف دیکھنا چاہئے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ۵۰۰ روپے ماہوار پاتا ہے۔ تو اس کو یہ دیکھنا چاہئے کہ ۱۰۰ روپے پانے والا کس طرح اپنا گذارہ کرتا ہے اس طرح اس کے دل میں تشفی ہوگی۔ لیکن اگر وہ ۱۰۰۰ روپے پانے والے کی طرف نظر رکھے گا۔ تو اس کو ہمیشہ یہ پریشانی رہے گی کہ میں کس طرح اپنی زندگی بسر کروں۔ ہمارے سینٹرل اور سٹیٹس ایمپلائیز کے دماغ میں یہ بات رہنی چاہئے۔ کہ دنیا میں چھوٹے لوگ بھی ہیں۔ بڑے بھی ہیں اور بڑے سے بڑے بھی ہیں۔ اگر وہ یہ دیکھیں کہ چھوٹے لوگ کس طرح اپنا گذارہ کرتے ہیں تو ان کے دل میں تشفی ہوگی کہ ہم ان سے اچھے ہیں اگر اس طرح ان کے ذہن کو ماریلی صحیح کر دیا جائے تو وہ زیادہ مانگیں پیش کرنے اور سٹرائیک کے راستے پر نہیں جائیں گے۔

میں ایک بار عرض کرونگا کہ پرائم منسٹر مہربانی فرما کر اپنی صدارت میں ایک مائنورٹیز کونسل کی ضرور تشکیل کریں اور سینٹرس میں ایک فیڈرل فورس

قائم کریں جس وقت اور جہاں ضرورت پڑے وہ اس فورس سے کام لیں۔ وہ اس مائنوریٹیز کو نسل کو بنا کر مائنوریٹیز کے حقوق کی حفاظت کریں۔ تاکہ آئندہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے۔ ملک میں اس قسم کا خیال نہیں پیدا ہونا چاہئے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے۔ اس پر عمل نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ بات ہمارے لئے بہت نقصان دہ ہوگی۔ ہم نے اپنے الیکشن مینی فیسٹو میں جو وعدے کئے گئے ہیں ہم ان کو ضرور پورا کریں گے۔ میں پرائم منسٹر کہوں گا۔ کہ وہ اس طرف قدم بڑھائیں۔ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہم سب ملکر یقین اس کام کو کامیابی کے ساتھ سرانجام دے سکتے ہیں۔]

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

जहां तक देश में ला एण्ड आर्डर का सवाल है, उसका सम्बन्ध गृह मन्त्रालय से है और आज सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि ला एन्ड आर्डर की पोजीशन खराब हो रही है। अगर किसी स्टेट में या रेलवेज में सुरक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं है, तो हम यह कह कर छुटकारा नहीं पा सकते हैं कि यह स्टेट सबजेक्ट है या अमुक प्रान्त की पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है। हम सब भारतवासी है और यदि हमारे एक भी नागरिक पर विपत्ति आती है, तो समूचे देश को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यह ठीक है कि सेंटर और स्टेट्स के अलग-अलग अधिकार हैं और उन दोनों की पुलिस के अलग-अलग कार्य-क्षेत्र हैं। लेकिन केन्द्र का यह कर्त्तव्य है कि अगर किसी प्रांत में ला एण्ड आर्डर की पोजीशन डिसटर्ब होती है, तो उसको बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। आज जन-मानस में यह भावना पैदा हो रही है कि हमारी सुरक्षा का इन्तजाम नहीं है। आज कोई आदमी अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है।

पिछले दिनों रेलवेज के सम्बन्ध में बहस के दौरान कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अमुक एरिया में कोई भी यात्री रेल में सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकता है। कहा जा सकता है कि वह रेलवे पुलिस का काम है। इसी तरह अगर बिहार या बंगाल में ला एण्ड आर्डर की स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो कहा जाता है कि उन प्रांतो की पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, यह उसका काम है। मैं समझता हूँ कि देश का ला एण्ड आर्डर सेंटर का सबजेक्ट होना चाहिए और सेंटर को सम्बन्धित प्रान्त और उसकी पुलिस को लोगों की सुरक्षा का इन्तजाम करने के लिए आगाह करना चाहिए और इसके लिए दूसरे जरूरी स्टेप्स लेने चाहिए।

आज देश में करप्शन का जिक्र बार-बार हो रहा है। हम देखते हैं कि आये-दिन स्टेट्स के मिनिस्टर्ज, अफसरों और अन्य लोगों के खिलाफ करप्शन के चार्जिज लगाये जाते हैं। आम लोगों की भावना यह है कि किसी के खिलाफ करप्शन के कितने भी चार्जिज हों, उनकी जांच नहीं की जाती है, फाइलों को दबा दिया जाता है और सम्बद्ध व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर पब्लिकमैन-सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों—और अफसरों के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज हो, तो तुरन्त उसकी जांच करके उसका निराकरण किया जाये। हमें पोलीटिकल फील्ड में करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, वर्ना हमारा सार्वजनिक जीवन बहुत गिर जायेगा। सरकार को लोकपाल नियुक्त करके या किसी भी संस्था के जरिये इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक इस देश में करप्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, तब तक यहां वास्तविक प्रजातंत्र कायम नहीं हो सकता है।

हमारे देश में दो प्रकार की सर्विसिज हैं—एक सेंटर की और दूसरी प्रांतों की। बहुत से प्रांतों से, जैसे राजस्थान में, रिटायरमेंट की ऐज को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष कर दिया गया है। उन राज्य सरकारों ने यह मांग की है कि सेंट्रल सर्विसिज में भी रिटायरमेंट ऐज को 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष कर देना चाहिए, क्योंकि वे सेंटर से गाइड होते है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को सेंट्रल सर्विसिज में रिटायरमेंट ऐज को 55 वर्ष कर देना चाहिए। ऐसा करने से नये रिक्रूटमेंट में नये लोग सर्विस में आयेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशेंसी बढ़ेगी और देश में शिक्षित लोगों की बेकारी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट्रल सर्विसिज में रिक्रूटमेंट के कायदे में परिवर्तन किया जाना चाहिए। देश के कुछ क्षेत्र सेंट्रल

[श्री शिवनाथ सिंह]

सर्विसिज में बहुत बड़ा भाग प्राप्त कर लेते हैं, जब कि कुछ क्षेत्रों को उनमें बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। हो सकता है कि इस की वजह इंगलिश मीडियम हो, या कोई और वजह हो। देश में कुछ लोगों को तो अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और पिछड़े इलाकों में लोगों को शिक्षा प्राप्त का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है। इस वजह से वे इन परीक्षाओं में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। इन्टरव्यू का जो आधार है, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। सरकार को सेंट्रल सर्विसिज में इस इमबैलेंस को खत्म करके एक रिजनल बैलेंस कायम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए।

जहां तक राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्सिज का सवाल है, अभी स्वतन्त्र पार्टी के एक नेता महोदय ने श्री गायकवाड़ के स्टेटमेंट को उद्धृत करते हुए बहुत उदारता का प्रदर्शन किया। मैं कहना चाहता हूं कि अब उदारता दिखाने का वक्त निकल गया है। आज से छः आठ महीने पहले जब राजा-महाराजाओं के प्रिवी पर्स और प्रिविलेज खत्म करने का प्रश्न उठा था, अगर वे उस वक्त उदारता दिखाते, तो हम उसको समझ सकते थे। आज यह उन की उदारता नहीं है—उनकी मजबूरी है। जनता ने यह क्लीयर-कट वर्डिक्ट दे दिया है कि प्रिवी पर्सिज को बिना किसी मुआवजे के खत्म कर देना चाहिए। अगर अब सरकार इस प्रश्न के बारे में नेगोशिएशन्ज या समझौता करती है तो जनता इसको कुबूल नहीं करेगी। इस बारे में कोई नेगोशिएशन्ज नहीं होनी चाहिए। कानून या कांस्टीट्यूशन में परिवर्तन करके, बिना कोई नेगोशिएशन्ज किये बिना किसी मुआवजे के प्रिवी पर्सिज को खत्म कर देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो जनता उससे जवाब तलब करेगी, क्योंकि उसने इस बारे में क्लीयर-कट वर्डिक्ट दे दिया है। मैं प्रधान मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में किसी नेगोशिएशन्ज में न पड़े बल्कि वह बिल्कुल कानून के हिसाब से इस काम को करे, ताकि जनता का उत्साह और मनोबल बना रहे।

स्टेट्स की री-आर्गेनाइजेशन का मामला बार-बार उठाया जाता है। जैसा कि अभी हरियाणा के माननीय सदस्य कह रहे थे, कई स्टेट्स बहुत बड़ी हैं, कई बहुत छोटी हैं और कई इतनी छोटी हैं कि उनका अपना खर्च नहीं चल सकता है। इसलिए रिआर्गेनाइजेशन का मामला बिलकुल साइंटिफिक बेसिस पर हो हम किसी दबाव में आ कर या पोलिटिकल प्रेशर में पड़ कर यह काम न करें। जहां पर कि एक वायबिल यूनिट हो, एक अच्छी भौगोलिक स्थिति हो, एरिया हो, इनकम हो, यह तमाम बातें हों, इनको देखकर रिआर्गेनाइजेशन करे। आज तेलगाना की मांग होती है, कहीं दूसरी जगह की मांग होती है, इस पर बार-बार दबते जाएंगे, बार-बार इस चीज को मानते जाएंगे तो हमारे देश का अलग-अलग बटवारा होता चला जाएगा। मैं नहीं मानता कि इस देश का नागरिक जो पंजाब में रहता है वह कैसे खुश है और जो हरयाना में रहता है वह कैसे नाखुश होगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि बिलकुल साइंटिफिक बेसिस पर स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन किया जाये।

एक बात मैं कहना चाहता हूं जो राजस्थान के सम्बन्ध में है और गृह मन्त्रालय से सम्बंधित है। हमारे राजस्थान में एक हाई-कोर्ट थी और उसकी एक बेंच जयपुर में थी। यहां से कोई ला कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर या किसी और आधार पर उस बेंच को वहां से हटा दिया गया। उसमें यह कहा गया था कि एक मूलिफाइड कोर्ट हो लेकिन और कहीं उस पर अमल नहीं हो रहा है। केवल हमारे राजस्थान में जयपुर से वह बेंच हटा दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज-

स्थान का बहुत बड़ा विस्तार है। कई सौ मील में उसका विस्तार है। पूरब से पश्चिम पहुँचने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए गृह मन्त्रालय और माननीय प्रधान मन्त्री महोदय इस मामले में हस्तक्षेप करें। हालांकि यह मामला स्टेट का है, मैं मानता हूं। लेकिन स्टेट को इस बात के लिए कहें, उनको इसके लिए आगाह करें। जो बेंच जयपुर से हटाई गई है उसको फिर वहां कायम करना अत्यावश्यक है। हाईकोर्ट की बेंच जोधपुर में जो है वह रहे उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो जयपुर से बेंच हटी उससे लोगों को बड़ी हार्डशिप हो रही है। उसको दोबारा जयपुर कायम करना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे यहां कैबिनेट का जो फार्मेशन होता है उसमें चाहे ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे और कोई रिपोर्ट हो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपस में दल-बदलुओं की जो स्थिति है उसको लेकर यह होता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो पार्लियामेंट या असेम्बली के सदस्यों की संख्या के प्रोपोर्शन में कैबिनेट का फार्मेशन हो तो उससे एक्सचेकर को भी फायदा होगा, पब्लिक को भी फायदा होगा और ऐडमिनिस्ट्रेशन में सहूलियत होगी। इससे प्रांतों के अन्दर जो दलबदलुओं की जो स्थिति पैदा होती है उसमें भी रुकावट आएगी। इसलिए चाहे वह पांच हों, सात हों, दस हों कोई नम्बर उनका फिक्स्ड होना चाहिए और प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए और उसके अनुसार कैबिनेट फार्मेशन की इजाजत देनी चाहिए।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। इसको हमें और स्ट्रेन्थेन करना चाहिए। आए दिन ऐसे अफवाह आते हैं कि कहीं स्पाइंग हो रही है कहीं कुछ हो रहा है। वैसे हमारा इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसको और स्ट्रेन्थेन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Mr. Chairman, Sir, in this debate I would like to briefly touch four important problems—the problem posed by the Naxalites, then the problem of the communal and caste tensions resulting in conflicts and conflagrations, the threat that is posed to democracy by the institution of Governors with all their discriminating behaviours and attitudes and, lastly, the most crucial problem of reconciling the legitimate regional aspirations of the people with the wider claims of national unity and integration.

As far as the problem of Naxalites is concerned, we must realise that Naxalites are not just violent gangsters who are merely interested in dislocating the democratic fibre and life of our country. If they are mad men, there is a method in their madness. They are ideologically oriented. It is undoubtedly true that they have no loyalty to this country. The moment they gave the slogan that "Chairman Mao is our Chairman" and "power grows out of the barrel of gun," it became absolutely clear that they are not only believers in violence, not only have they extra-territorial loyalty but they are ideologically oriented. They accept the way of life of Communist China. They want to invite the Chinese aggressors to this country. They do not have any loyalty to this country. Therefore, we must remember that the breeding ground of the Naxalites in this country is not merely among those who are eccentric and those who believe in violence but among those who have certain totalitarian ideological orientations and want to exploit discontent among the people. Therefore, the problem of dealing with the Naxalites is both the problem of law and order as well as the problem of removing the root causes of exploitation in our socio-economic life which are responsible for throwing the young flowers into the lap of the Naxalites and thereby destroying the democratic and noble urges among the youth. Unless these steps are taken, I don't think the menace of Naxalites can be curbed. Just to give an illustration—not to elaborate the

[Prof. Madhu Dandavate]

problem—in some areas of Bihar, the infiltration of Naxalites has already been started. One has only to visit those areas and try to find out how the young among the landless are becoming Naxalities. They find there is the tyranny of the landlords ; there is the tyranny of the Zamindars. They are not able to do anything to fight against injustice. Unfortunately, their morale is completely broken.

If the disorganised adivasis and peasants are not able to fight these landlords and others who are exploiting them, there is some sort of vicarious satisfaction in them if some young man throws bombs at the landlords and tries to murder them. I have come across young men and adivasis and peasants who have said : "Sir, we want to fight these landlords but our economic independence on them is so complete that we have no strength left in us to fight them. So, we are not able to do anything. If a few young Naxalites are able to throw bombs, we get the mental satisfaction in a spirit of revenge that though our injustice is not removed, at least a few of the men responsible for the injustice have been eliminated."

Therefore, unless new direction is given to politics, new policies are formulated and content of socialism is put into our body-politic and all the root causes of economic and social injustices are completely removed, it will not be possible to fight the Naxalites. It is not possible to fight them only with bullets and bayonets. No doubt, they have to be dealt with in a firm way. We have to deal with the problem of law and order, but at the same time, the sociological and economic aspects of the problem must never be forgotten.

There is another problem, the problem of communal and caste tensions. There have been so many riots in the course of the year. The tragedy in this land of Mahatma Gandhi is this : In any communal riot when Muslims are killed, the Muslims are disturbed. When Hindus are killed, the Hindus are disturbed. But very few in this land of Mahatma Gandhi are disturbed because human beings are killed.

Therefore, a new consciousness has got to be created. It is no good putting the entire responsibility of riots only on one community—whether Muslims or Hindus. We must go to the root of the problem.

I have come to the conclusion that those of the old generation, who have seen the partition days, will never be able to tackle this problem of communalism at all. Only the rising new generation of youth may be able to do the job. Only those who are completely free from the hang-overs of the past will be able to tackle this problem of communalism and casteism.

Let us not try to fix up the responsibility of communalism only on Muslims or on Sikhs or on Hindus. It is basically a malady of our tradition-bound society and unless efforts are made by all sections of the Government, all wings of the Ministries,—the Education Ministry, the Home Ministry will have to play their role,—and there are all-round coordinated efforts, this problem will not be solved. We have to evolve proper training of the youth. A new modern mind has to be developed in the country. Only if the forces of medievalism and traditionalism are destroyed can communalism be destroyed in this country.

As a teacher, I tell you my experience. Right from school and college days when students read text-books of history they imbibe all passion and prejudice. They themselves compartmentalise life into Muslims and Hindus ; the heros of Muslims are different ; the heros of Hindus in history are different. Integration of society cannot be brought about on the basis of a biassed study of history and geography.

A new trend in Education will have to be evolved. The entire curricula will have to be modernised. At the same time, coordination of various departments will have to be brought about to evolve a new modern youth. When such a new modern mind of youth develops, then the remnants of communalism will be destroyed.

I only touched the communal riot problem ; but what about the problem of conflicts born out of casteism ? It is the tragedy of this country that if a few Hindus or Muslims are killed, right from the village, up to the forum of Lok Sabha, there is a big furore but when a few Harijans or Adivasis are killed and Harijan women molested in distant parts of our country, there is not a ripple on the surface of our public life, because, the victims of atrocities are condemned to the degrading life of Harijans and Scheduled Castes.

You will always find that whenever an educated man, a wealthy man, an aristocrat, is murdered in the train or anywhere else, headings are hit in the newspapers, but if a Harijan or adivasi woman is molested or murdered, nobody hardly takes note of it, because victims happen to be neglected Harijans and adivasis.

Therefore, this problem has to be solved. How many atrocities are being committed against the Harijans and adivasis ? If you go through the Government records, they themselves tell us about this, and you will see that these atrocities are on the increase. The caste tensions are on the increase. There must be preferential opportunities to Harijans and adivasis. A new climate in the country has to be created.

Then, there is the problem of the institution of Governors. Again, I do not want to elaborate this problem, but I want to tell you that the way the Governors have been functioning in different States, it appears that they are behaving in the most discriminating manner. Very often, we find that the fate of the Government and the character of the Ministry is decided not on the floor of the legislature but on the precincts of Raj Bhavan where secret confabulations with the leaders of various parties go on.

In the absence of anti-defection Bill many legislators have become transferable commodities in the country today. We find that sometimes, those from the Congress (R) join the SVD when the SVD increases the volume and size of its Ministry to accommodate even 53 members ; thus the SVD becomes strong. When the situation changes, the SVD goes down and Congress (R) comes up. All this happens because there is the politics of defections. As a Member of the Opposition, let me admit that it is not merely the Treasury Benches who are guilty of this crime but equally the Members of the sections of the Opposition as well. There was only one Acharya Narendra Dev who after leaving the Congress resigned his membership of the State legislature, faced elections again and got defeated. But in the defeat of Acharya Narendra Dev, there lay the triumph of ethics in Politics. How many of us are prepared to do that ? I think that is the malady of our politics. Therefore, both the Opposition and the Treasury Benches should sit together and try to evolve a code of conduct against defections. For some time, the Treasury Benches may gain by these defections, and for some time, the Opposition may gain, but in the long run, it is democracy that must gain, and, for this purpose, defections have to be completely eliminated.

As far as Governors are concerned, one of my colleagues in the last Lok Sabha, Shri Nath Pai had made a very valuable suggestion. The Governors are appointed not merely on the basis of their impartiality, but very often, the post of Governor happens to be a rehabilitation compensation in politics. Some one is defeated somewhere in the elections, and he is an old may and has no vitality and dynamism left in him. Therefore, an attempt is made to rehabilitate him as Governor. So, they to very often try to remain loyal to their masters, the ruling party and they try to serve the politics of piracy and of defections, Therefore, it is very necessary that even when the Governors are appointed by the President, at some stage, the Lok Sabha should ratified the appointment of Governors. The situation will not be changed otherwise.

Then, I would like to make a passing reference to another important problem. There are so many inter-State disputes, such as those between Haryana and Punjab, between Mahrashtra and Mysore and so on. Though I come from Maharashtra, I would not speak on behalf of Maharashtra State alone, but I would like to speak as a member of this sovereign Parliament. I would like to admit that when there is a dispute between Haryana and Punjab or a dispute between Mysore and Maharashtra, really my mind bleeds, for I find that all the national parties get split up when it is a question between Mysore and Maharashtra or a question between Haryana and Punjab. Where is the national integration then ? Therefore I would like to appeal to the Prime Minister who is present in this House that for God's sake, let her not treat the problem of inter-State disputes from the point of view of 'political expediency' but evolve agreed uniform principles for all inter-State disputes. Whenever there is any dispute, refer it to a boundary commission, and take a commitment from all the national parties that once definite principles are laid down for tackling any inter-State dispute, and once the boundary commission on the basis of those definite terms of

[Shri Madhu Dandavate]

reference tries to settle the dispute, there will be no agitation. After that let the Government take a firm attitude that no premium will be put on violence and agitations. Once the agreed principles are evolved and the matter is referred to the boundary commission and the inter-State dispute is solved, even if there is violence and even if hundreds of lives are lost, Government must take the decision that since all the national parties have accepted the uniform principles for the solution of inter-State disputes, even if the heavens fall on earth, they are not going to bow down before violence. Only if that attitude is taken can the law and order problem and the sociological and psychological problems involved in such inter-State disputes can be solved. I hope the Government will adopt a long-term perspective and not the perspective of shortsighted political expediency.

श्री एम०रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद): सभापति महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मुख्तसर बोलना चाहता हूं। अब तक जितनी स्टेट्स बन गई हैं उसके बाद अब कोई नई स्टेट नहीं बननी चाहिये। अगर कोई नई स्टेट बनाते हैं तो पहले उसकी लायबिलिटीज और असेट्स को बांटना पड़ता है, सर्विसेज को बांटना पड़ता है, बाउंड्री कमिशन मुकर्रर करना पड़ता है, उसके बाद वाटर डिस्प्यूट्स आते है, एलेक्ट्रिसिटी कामन ग्रिड को बांटना पड़ता है, इस तरह से हजारो झगड़े पैदा होते हैं। अगर हिन्दुस्तान में हमें काम करना है तो रोजाना स्टेट बनायेंगे, फिर उसको बिगाड़ेगें, फिर नई स्टेट बनायेंगे इस तरह से काम नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी प्राइम मिनिस्टर एक केटेगोरिकल स्टेटमेंट करें कि अब कोई स्टेट नहीं बनेगी।

अभी मेरे एक साथी ने तेलंगाना का जिक्र किया, मैं भी तेलंगाना का आदमी हूँ, मैं तीन कालेजों का संस्थापक और एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री का संस्थापक हूँ और उसका प्रेजिडेंट रहा हूं और जब तक चाहूंगा वे लोग मुझको वोट देते रहेंगे। दो हजार आदमी उस फैक्ट्री में काम करते हैं। एलेक्शन के जमाने में एक-एक गांव में मुझे मैजारिटी वोट मिली है और तेलंगाना की इस निजामाबाद कांस्टिट्यूएंसी से मैं 60,000 वोट की मैजारिटी से जीता हूं। मैं जब गावों में जाता था तब लोगों से बात करता था कि जितनी छोटी स्टेट बनेगी उतना ज्यादा खर्च होगा। अगर आज तुम 100 रु० मालगुजारी दे रहे हो तो दो स्टेट बनाओगे तो 200 रु० देना होगा और चार स्टेट बनाओगे तो 400 देना होगा। यह ठीक है कि जितनी छोटी स्टेट बनेगी, ज्यादा मिनिस्टर बनेंगे, पुलिस वाले उनके साथ चलेंगे। आज तो मैं मिनिस्टर बनने वाला नहीं हूं, लेकिन छोटी स्टेट में तो ज्यादा मिनिस्टर बन सकते हैं, इस लिए मैं चाहता हूं कि आप अब आप कोई स्टेट न बनायें।

यह ठीक है कि पिछले चुनावों में कुछ तेलंगाना वाले जरूर यहां आये हैं लेकिन मैं आप को उनकी हिस्ट्री बतलाना चाहता हूं। वहां खैराबाद में असेम्बली के एलेक्शन हुए, तेलंगाना प्रजा समिति की 17,000 की मैजारिटी आई, लेकिन अब परसों जो एलेक्शन हुये उसमें 5,000 की मैजारिटी आई। यानी 5 महीने में 12,000 की मैजारिटी गिर गई। सिद्दीपेट में उनकी 24,000 की मैजारिटी आई, लेकिन चार महीने के बाद वहीं पर 8,000 की मैजारिटी रह गई और अब जो एलेक्शन होगा उसमें उनकी जमानत भी जब्त हो जायेगी।

हमारी प्राइम मिनिस्टर ने तेलंगाना के लिये जो 8 प्वाइंट प्रोग्राम रक्खा है उससे तेलंगाना का बहुत फायदा हुआ है, हालांकि उससे आन्ध्र प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आन्ध्र वाले एजिटेशन नही कर रहे है। वे कहते हैं कि हमारा छोटा भाई रूस गया है, उसका फायदा हो जाने दो। (व्यवधान)... हमें भी पालिटिक्स में जिन्दा

रहना है और जिस तरह से चाहें एलेक्शन में मुकाबला करने को तैयार हूं...इस लिए मैं कह रहा था कि तेलंगाना का जो मसला है वह एक पोलिटिकल मसला है। जिन लोगों को पोलिटिक्स में जगह नहीं मिली वे लोग वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। इस वास्ते प्राइम मिनिस्टर को उनको मुंह नहीं लगाना चाहिये।...

श्री एम० सत्यनारायण राव : आप पहले कहां थे ? परसों कांग्रेस को गाली देते थे, अब कांग्रेस में आ गये हैं। You were not in Congress then. Now you have joined it. You have no right to speak like this. It is too much on your part to assume this pose. The Andhra members are here. They are not speaking. It is most unfortunate that a member from Telengana is speaking like this........

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सभापति महोदय, मैं उस वक्त इंडेपेन्डेन्ट था और एम० एल० ए० के एलेक्शन में दो दो कांग्रेसियों को हराया...

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : You were defeated again and again. (*Interruptions*)...Why should he go on with this kind of history, I was elected, this that and the other.

MR. CHAIRMAN : Let him continue.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सभापति, महोदय, मैं किसी पार्टी का मेम्बर नहीं था लेकिन दो कांस्टिटुएन्सीज से लड़ के दो कांग्रेसियों को हराया, लेकिन जब स्टेट के इंटेग्रेशन और सेपरेशन का मसला आया उस वक्त मैं कांग्रेस में शरीक हो गया और आप देखिये कि तेलंगाना की मेरी कांस्टिटुएन्सी में वह लोग 45 मोटरें रख कर, इनके सारे लीडर्स सी० बी० राजू, रामचन्द्र रेड्डी, वहां बड़ी मीटिंग्स करते थे, लेकिन इनकी मीटिंग्स में 200 आदमी भी नहीं होते थे। लेकिन जिन मीटिंग्स को मैं एड्रेस करता था उनमें हजारों आदमी होते थे।

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : I object to this. He has named persons who are not here. He is not supposed to do it.

MR. CHAIRMAN : You will have your turn.

16.00 hrs.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सभापति महोदय, मैं पार्लमेंट में बात कर रहा हूं तब ये गड़बड़ कर रहे हैं और जब मैं गांवों में बात करूंगा तो पता नहीं क्या करेंगे ?...(व्यवधान)..

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : Let us settle the matter there, not here.

MR. CHAIRMAN : Please do not mention any names.

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : We never mentioned any names. We never condemned anybody.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जब ये दोनों बोल रहे थे तो मैंने खामोशी से सुना। पार्लमेंट्री डिमोक्रैसी में जब एक बोलता है तो दूसरे को सुनना चाहिए। इतनी एलिमेंट्री डीसेंसी भी नहीं है।...(व्यवधान)...

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : What is decency ? Have you got any decency ? Without knowing the matter, you are shouting.

क्या बात कर रहे हो ? शर्म नहीं आती। समझने की कोशिश करो।...(व्यवधान)...

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : ये न कभी गांव में पंच बने, न कभी सरपंच बने, न कभी असेम्बली के मेम्बर बने। इत्तफाक से पार्लमेन्ट में आ गए हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पार्लमेन्ट में आने से पहले पार्लमेंट का प्रोसीजर भी मालूम होना चाहिए। ..(व्यवधान)...

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : You must understand our feelings also. I am representing the whole region. You are not representing.

[श्री एम० सत्यनारायण राव]

क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आता। असेम्बली में आओ, हम तैयार हैं। यह मत समझो कि हम तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं श्री पी० के देव कह रहे थे कि प्रिंसेज के साथ प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हो। मैं कहता हूं ग्रेस इसमें है कि अपनी तरफ से, पूरे जितने टाइटिल्स हैं उनको डिसओन कर दें और कल से ही प्रीवी पर्स लेना बन्द कर दें तभी आप भी देशभक्त कहलायेंगे। आज एक मजदूर दो रुपये में दिन भर काम करता है, एक रुपए खाता है, एक रुपये का पीता है और दूसरे दिन का उसे कुछ खयाल नही होता। आपके पास करोड़ों रुपया है। किस जन्म के लिए आप यह पैसा मांगते हैं। इसलिए मैं प्रिंसेज से कहना चाहता हू कि अपनी तरफ से सुओं मोटो उनको डिक्लेयर करना चाहिये कि कल से हम प्रीवी पर्स नही लेंगे। अभी आप यहां पर जीत कर आये है और दस पांच साल और जीत कर आ सकते हैं और देशभक्त भी कहे जायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हू। शशि भूषण जी भी कह रहे थे कि पूरे मुल्क में दस रुपये पर दो रुपये का सूद वसूल किया जा रहा है। ईरान से आये हुये खान और पठान जो हैं वे लोगों को बहुत सताते हैं। पूरी दिल्ली में, निजामाबाद में और सारे देश में वे फैले हुये हैं। मैं चाहता हूं कि ईरानी लोगों को यहां से निकाल दिया जाये क्योंकि ईरान के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध भी नही हैं।...(व्यवधान)... होम मिनिस्ट्री इस बारे में कदम उठा सकती है कि मुल्क मे जो कानून है कि सौ रुपये पर एक महीने में एक रुपया सूद लिया जाये, अगर उससे ज्यादा कोई लेता है तो उसको जेल में बन्द कर दिया जाये। मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस चीज को वे चाहें करें या न करें लेकिन कम से कम सौ आदमियों को अरेस्ट करके जेल में रखवा दें जो कि ज्यादा सूद ले रहे है।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : माननीय सभापति जी, गृह मंत्रालय की मांगों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि देश में जो कानून की व्यवस्था है उसमे निश्चित तौर पर सुधार किये जाने के लिये कुछ आवश्यक कदम उठाये जाने बहुत जरूरी हैं। हमारे देश को दो तरह के लोगों से खतरा है--एक तो उन लोगों से खतरा है जो लेफ्ट एडवेंचरिज्म में विश्वास करते हैं और दूसरा खतरा हमारे देश में राइट रिएक्शन से है। ये दोनों ही तरह के लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के हथकंडो को इस्तेमाल करते है। कभी भाषा के नाम पर कभी प्रान्त के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी विशाल हरियाणा के नाम पर, कभी और किन्हीं नामों पर सेनाये खड़ी करते है, कभी पार्टिया बनाते हैं और धर्म की दुहाई देकर लोगो को गुमराह कर देश में एक अशाति का वातावरण पैदा करते है।...(व्यवधान)...मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हू कि ऐसे सभी लोगो पर जिनकी भाषा कभी-कभी मेरे भाई कछवाय जी बोला करते है, रोक लगाई जानी चाहिये। इस देश का उद्धार न तो सस्कृति के नाम पर हो सकता है, न धर्म के नाम पर हो सकता है, न प्रान्त के नाम पर हो सकता है, न मजहब के नाम पर हो सकता है और न सम्प्रादक के नाम पर हो सकता है। अगर देश के लोगों की हालत को बदलना है, उनकी हालत को तब्दील करना है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर, आर्थिक नीतियों के निर्माण से ही ऐसा किया जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टियों को जिनका कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है चुनाव लड़ने की छूट नही होनी चाहिए। केवल उन्हीं पार्टियों को चुनाव में भाग लेने का

अधिकार होना चाहिए जिनका अपना आर्थिक प्रोग्राम है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो कहता हूँ कि स्वतंत्र पार्टी या ऐसी ही दूसरी पार्टियों को, जिनका अपना आर्थिक कार्यक्रम है, एक प्रार्थिक नीति है, छूट होनी चाहिये। लेकिन पंजाब में अकाली दल को नहीं होनी चाहिए, विशाल हरियाणा की मांग करने वाले लोगों को छूट नहीं होनी चाहिए, शिव सेना को छूट नहीं होनी चाहिये और जो दूसरे ऐसे संगठन हैं जैसे मजलिसे मुशवरात है या हिन्दू महा सभा है जोकि धर्म के नाम पर इस देश की राष्ट्रीयता को खतरा पैदा करना चाहते हैं उनको छूट नहीं होनी चाहिए।

सभापति जी, इसके साथ-साथ मैं लेफ्ट एडवेंचरिज्म को भी खतरनाक मानता हूं। कल यहां पर सी० पी० एम० की तरफ से श्री सरोज मुखर्जी कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में बंगाल में पुलिस का राज बन गया है। आज बंगाल की हालत यह है कि 1 जनवरी से 15 मार्च तक 156 घटनायें हुई है, राजनीतिक तरीके से हमले हुये हैं और इन 156 में से 134 हमलों में कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट के लोग शामिल थे। इसी तरह से तीन उम्मीदवारों को जो मारा गया उनमें भी दो में कम्युनिस्ट मार्क्सिटों का हाथ था। तो जब बंगाल में यह हालत हो तो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट का पुलिस राज की बात करना कहां तक ठीक है, यह, विचारणीय है। हमारे देश के अन्दर श्री नम्बूदरीपाद जब यह कहते हों कि शासन व्यवस्था को बदलने के लिये हमें बन्दूक का सहारा लेना पड़ेगा, तो हमको कदम उठाने पड़ेगे ऐसे ऐक्सिट्रिमिस्ट लोगों के खिलाफ।

यह सही है कि हमारे देश में नक्सलपंथियों की समस्या केवल राजनीतिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या है। लेकिन उसके साथ ही क्या आपको तथा देश के लोगों को गम्भीरता से नही सोचना चाहिए कि जो लोग देश के विधान मे विश्वास नहीं करते, जो लोग शासन व्यवस्था में आस्था नहीं रखते, जो लोग इस देश में दूसरे मुल्कों से इंस्पीरेशन लेकर के वहां की आइडियालाजी के आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था को बदलना चाहते हैं क्या उन लोगों को छूट मिलती रहनी चाहिये? इसलिये इस विषय पर गृह मंत्रालय को गम्भीरता से विचार करना चाहिये, और अगर सम्भव हो तो ऐसे लोगो पर भी कुछ रोक लगानी चाहिये। देश के प्रजातन्त्र को जो बन्दूक की नली से बदलने की और राजसत्ता प्राप्त करने की सोचते हैं और कांस्टीट्यूशन को बदलना चाहते हैं, वोटों के जरिये से नहीं बंदूक के जरिये और जो वोट को केवल मात्र का धन मानते हैं, उन पर भी रोक लगायी जाय।

साथ ही सभापति जी, आप का ध्यान देश के अन्दर जो एक बीमारी पैदा हो गई है, राजनीतिक लोगों में भ्रष्टाचार की उस पर भी दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में पिछले दिनों में पोलिटिकल तरह से पोलिटीशियन्स में भ्रष्टाचार एक अजीब तरीके से पैदा होने लगा है। सरकारें रोज बनती हैं, रोज गिरती हैं, रोज आया राम गया राम का खेल इस देश में चल रहा है, और इस खेल को बन्द करने के लिये, मुझे अफसोस है गृह मंत्रालय ने अभी तक कोई कदम गम्भीरता से नहीं उठाया। यह कहानी 1967 के चुनाव के बाद शुरू हुई लेकिन अभी तक गृह मंत्रालय इस पर विचार ही कर रहा है। अब समय आ गया है जब गृह मत्रालय को इस बारे में गम्भीरता से विचार करके इस राजनीतिक भ्रष्टाचार का हमेशा के लिए उमूलन करना पड़ेगा, और उसके लिये कदम उठाने पड़ेंगे। मैं गृह मंत्रालय पर अभियोग लगा रहा हूं। हमारे देश में यह जो राजनीतिक सौदेबाजी चलती है उसमें हम सब सरीक हैं, जैसा मेरे दोस्त प्रोफेसर कह रहे थे, कांग्रेसी ही दोषी नही हैं बल्कि विरोधी दल भी उतने ही दोषी हैं। इस बीमारी का माकूल इंतजाम किया जाना चाहिए और तुरन्त इंतजाम किया जाना चाहिए। गवर्नरों पर लगाये जाने वाले अभि-

[श्री नवल किशोर शर्मा]

योग अपने आप खत्म हो जायेंगे। अगर यह पोलिटिकल हौर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाय तो फिर गवर्नरों की समस्या नहीं रहेगी, गवर्नरों के लिये आचार संहिता का उतना सवाल नहीं रहेगा। 1967 के पहले गवर्नरों की आचार संहिता की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन आज जो राजनीतिक भ्रष्टाचार फैल रहा है उसकी वजह से इस बात की आवश्यकता महसूस होने लगी है। इस लिए इस पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए।

एक बात की ओर मैं गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप ने फैसला किया है, प्रिवी पर्स अबालिश करने का। मैं आशा करता हूं कि आप इस बिल को जल्दी लायेंगे। लेकिन मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि राजा लोग अपनी जमीनों को बड़ी तादाद में बेच रहे हैं। जयपुर का राजघराना अपनी हजारों बीघा जमीन को लोगों को बेच रहा है। आज अखबार में खबर है ग्वालियर के राजघराने के बारे में कि वह अपनी सम्पत्ति को बेच रहा है। और आप अभी विचार कर रहे हैं, निगोशियेशन्स के चक्कर में चल रहे हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप जल्दी कीजिए वरना जो सीलिंग का हाल हुआ, वह जो इनफक्चुअस हो गया, उसी तरह से इस प्रिवीपर्स से होने वाला बहुत सा फायदा निगेटिव कर देंगे, अपनी सम्पत्ति को आपका कानून लागू होने के पहले-पहले ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए इसकी व्यवस्था तुरन्त कीजिए। हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम को राजघरानो से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। इस लिये चुनाव से पहले ऐसी व्यवस्था कीजिये कि ये राजा लोग जिन के पास अतुल साधन हैं, साधारण आदमी जिनके मुकाबले चुनाव नही लड़ सकता, इनके साधनों पर कुछ रोक लगे।

इस के साथ-साथ मैं अपने प्रान्त की एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मिर्धा साहब मेरे ही प्रांत से आते हैं। मेरे एक साथी भाई कह रहे थे कि राजस्थान में हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में होनी चाहिए। मैं उसी बात का समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं: राजस्थान में हाई कोर्ट की बेंच इस वक्त जोधपुर में है। इस सदन के लोग इस बात को जानते हैं कि जोधपुर राजस्थान के एक छोर पर है और भरतपुर, धौलपुर और जयपुर का इलाका जोधपुर से बहुत दूर पड़ता है। जिस ला कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर, जिसके नाम पर एकीकृत हाई कोर्ट की स्थापना का निर्णय किया गया था, कैपिटल कमेटी ने यह फैसला किया था कि हाई कोर्ट जोधपुर मे हो। मुझे हाई कोर्ट की बेंच जोधपुर में रखे जाने के बारे में कोई एतराज नहीं है। जोधपुर मे हाई कोर्ट जाने से पहले जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच थी। इस ला कमीशन की रिकमन्डेशन और कैपिटल कमेटी की रिकमन्डेशन की वजह से वह जयपुर की बेंच खत्म हो गई। उस ला कमीशन की सिफारिश को भारत के ला मिनिस्टर्स की कानफरेंस ने रिजेक्ट कर दिया और यह फैसला किया कि एकीकृत हाई कोर्ट इस देश के लिए सूटेबिल नही है। और आज स्थिति यह है कि एकीकृत हाई कोर्ट के नाम पर जो हमारे देश में, आज भी हर प्रान्त में यू० पी०, एम० पी०, महाराष्ट्र और केरल को देख लीजिये, ऐसे बहुत से प्रान्तों के अन्दर दो, दो तीन, तीन बेंचे चल रही हैं। न्याय के लिए जरूरी है कि जयपुर में जो राजस्थान की कैपिटल है, वहां पर बेंच की स्थापना हो जयपुर के लोगों ने इस बारे में मांग की है, प्राइम मिनिस्टर से हम लोग मिले हैं, अपने डेपूटेशन में प्राइम मिनिस्टर से मिलकर मैमोरेन्डम दिया है। गृह मंत्रालय ने जवाब में लिखा है कि वह राजस्थान के मुख्य मन्त्री की सलाह से इस पर विचार कर रहे हैं। यह जवाब मुझे अक्तूबर में मिला था। और आज जून है जब गृह मंत्रालय की मांगो पर विचार कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि अब तक गृह मंत्रालय

सब ने इस पर विचार कर लिया होगा। यह मानवीय मांग है। इसका राजनीति से कोई तालुक नहीं है। दुर्भाग्य से राजस्थान के मुख्य मंत्री इस मांग को राजनीति से सम्बद्ध कर देते हैं। 80,000 किसानों ने इस बारे में जयपुर में प्रदर्शन किया है और मिर्धा साहब आपकी कांग्रेस ने हमें इजाजत दी है प्रदर्शन करने की, इसलिये हम कहना चाहते हैं कि या तो इस बात को मन्जूर कर लिया जाय नहीं तो मजबूर होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा और जरूरत होगी तो बलिदान करना पड़ेगा। यह मानवीय बात है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

SHRI FRANK ANTHONY (Nominated Anglo-Indian) : Sir, I had given notice of a cut motion on the need to strengthen the functioning of the courts at all levels. Unfortunately my notice was late. But I had advisedly given this notice *vis-a-vis* the Home Ministry, which is not unduly represented here today but my friend, Mr. Mirdha is here, because it has been my experience that the Law Ministry has been relegated relatively to a position of nonentity in the hierarchy of ministries and it is the Home Ministry that initiates and implements anything that tends to strengthen or weaken our courts.

Sir, it is axiomatic—you as a lawyer know—that our higher courts particularly represent today the bastion of our democratic viability. I believe that it is our courts that essentially give credibility to the Indian democratic ethos. And it is said—it has become rather a cliche—that they are the custodians of the rule of law. As a very distinguished former Chief Justice said : The Supreme Court is the sentinal on the *qui vive* to protect the fundamental freedoms of the Indian citizen.

Now, let us be quite honest. For more than 10 years there has been growing anxiety among the most responsible sections of the legal profession at the increasingly disturbing symptoms of the rapid decline in the standards and the quality of our judiciary from top to bottom. I say this with the deepest of regret. As a practising lawyer conditioned in the utmost of the respect for the judiciary I am allergic to irresponsible or wanton attack. So, what I say, Sir, is merely because I feel that the profession today must cherish the maintenance of democratic values and if I seem at all critical it is only because we dare not let matters drift any more. We are coming to the end of the road so far as our judiciary is concerned. We dare not be complacent any longer and we certainly dare not be self-righteous. I do not want the Minister to get up and attempt to delude this House by saying that everything in the garden of the judiciary is near perfect—if not perfect.

Sir, I was very happy to read in the newspapers of the transfer of certain magistrates because of the allegations of corruption. That step was long overdue. I want to make it very clear that many of these people in the lower echelons—magistrates and additional session judges—are not only competent people but also they are extremely upright people. But here also there was general perturbation at the increasing symptom of spreading corruption. Sir, some of my juniors who practise in the lower courts were aware that litigants increasingly caught up, either from choice or by compulsion, had to submit to this corruption. We were also aware that every profession has its black sheep ; some of the unsavoury elements among the lawyers were exploiting this corrupt element among the magistracy and indeed among the additional session judges.

Now, Sir, I have certain suggestions to make. Very often my juniors ask me : How is it, Sir, here is a first-class magistrate. At most he is getting Rs. 400 or Rs. 500 in hand. How does he run a new Ambassador car ; how does he send his children to expensive schools ? Very often they are from lower middle-class families without any ostensible original resources. Surely there can be a check. Then there is another fruitful source of corruption. I know it is rather rampant in Delhi. Magistrates and retired additional session judges are allowed to practise in the very courts where they have functioned. Blatantly the advertise the fact that they have access to their former colleagues and subordinates. You know, Sir, that there is a very salutary provision with regard to Hight Court judges. No High Court judge is allowed to practise in the area where he once served. No Supreme Court judge can practise in any court in India. I feel it is long overdue that you have similar provision

[Shri Frank Anthony]

with regard to magistrates and additional session judges. You may examine the position whether they should be allowed to practise in the local High Court but certainly they should not be allowed to practise in the courts where they once functioned.

So far as the enforcement agencies are concerned, they also contribute and aggravate these symptoms of corruption. I was glad to see that the Home Ministry seems to activate itself. I do not think they functioned. It was a report that certain station house officers were making so many tens of thousands of rupees a month. I do not know how accurate it was. But there were some transfers.

But I know, I think it is almost general knowledge today in Delhi, that with the Prevention of Food Adulteration Act being so draconian, compulsory jail sentence-people do not like to go to jail specially first offenders—that all manner of manipulation is taking place. One of my very responsible juniors told me that the food inspectors were making so much money that one of them could afford to send his son to an expensive college in Europe. I would like the Home Ministry to examine it.

I also know, because cases come to me in appeal, that there is ample room for manipulation. Innocent people who refuse to give bribe are often involved and guilty people who are prepared to give bribe are often acquitted.

Now I want to deal with the High Courts and the Supreme Court. Here I speak with deliberate restraint. The Law Commission, as far back as 1958, presided over by Shri M. C. Setalvad, referring to the High Courts said this :

> "We have visited all the High Court centres and at all hands we have heard bitter and revealing criticism about appointments made to the High Court judiciary during recent years. The almost universal chorus of comment is that the selections are unsatisfactory and that they have been induced by executive influence," It is a terrible indictment.

Then, they quote again from a very eminent Judge, who gave evidence before the Commission. This is what that eminent Judge said—it is reproduced in the Commission's report :

> "If the State Ministers"—

Ministers in State Government—

> "continue to have a powerful voice in the matter, in my opinion in ten years' time"—

it was in 1958—

> "or so, when the last of the Judges appointed under the old system will have disappeared, the independence of the judiciary will disappear and High Courts will be filled with Judges who owe their appointments to politicians."

We practising lawyers know what is happening. One of the Chief Justices of one of the largest High Courts in India, now retired, was a particular friend of mine and he confided in me that for two years he resisted the appointment of a particular person ; equally, the Chief Minister insisted on his appointment. The Chief Justice said, "I knew him to be one of the incompetent and least qualified persons from the point of view of character, but," he said, "I was utterly disgusted. Because of continuing pressure from a powerful Chief Minister, after two years I allowed that unsuitable person to be raised to the Bench."

I am glad that my hon. friend, Mr. Mohan Kumaramangalam is here. Then, we have got Mr. Gokhale. Both are eminent erstwhile colleagues of mine. I hope, they will use their influence and their conviction will receive an edge and will not be blunted by the fact that they have now been raised to ministerial rank. I have repeatedly pleaded for the amendment of article 217 of the Constitution.

You will remember that this establishes a condominium. It says that the President will act on the recommendation of the Governor, the Chief Justice of India and in the case of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court. But what has been the experience ? As soon as you bring in the Governor, through the backdoor if not through the front door, you bring in the Chief Minister. I do not want to enter into this controversy about the Governors here. But we know, in these matters Governors are merely the mouthpiece of the Chief Ministers ; they are rubber stamping agencies and with the Governor in the condominium invariably it means the Chief Minister. I know it. I remember,

a person who was once my junior went to a very powerful Chief Minister and I recommended him. The Chief Minister ensured that he was raised to the Bench but he was a qualified person." But the Law Commission has entered a powerful plea with regard to Article 217. It was in 1958 and since then I have pleaded with the Government that political patronage—I am quoting—"Political motives must be eliminated from the appointments to the judiciary."

What is the happening ? The whole position is escalating. Virtually, briefless lawyers are being appointed. In some High Courts—I do not want to name the High Courts—we know some of the lawyers who have not handled a single brief in the High Court are being raised to the High Court Bench. I know that suitable members of the Bar are not available. But the Government is responsible for the simple reason that they have resisted, because of some political gimmickry and slogon-mongering, this long overdue demand to give increased emoluments to Judges. I do not think we have touched the emoluments of our judiciary since Independenee. I do not think a High Court Judge gets more than about Rs. 2000 a month in hand. To some of our avant-gardc socialists, that may sound like untold wealth.

Let us recognise this that lawyers in the profession arc not there for their health. Because of the relative paltry salary, not even competent juniors will accept a High Court Judgeship today. Let us not talk about leading members of the Bar accepting. In order to qualify the complete lack of attraction in raising competent lawyers to the Bench, the Law Commission headed by Mr. Setalvad said, at least raise the age of retirement for High Court Judges to 65. Typically, our Government reacted with neither sense nor logic. Supreme Court Judges retire at 65. So, you thought you would strike a compromise at 62½ for High Court Judges. You thought that will be a compromise. Apparently, Government felt that a High Court Judge ages more rapidly than a Supreme Court Judge. At 62½ years age, his brain does not function adequately. But a Supreme Court Judge at the age of 65 has got the capacity.

I want to make this plea. The judiciary is *sui generis.* Don't compare it with any other service or institution. It is axiomatic that you cannot have a good judiciary on the cheap. That is what we are trying to do in India. We are trying to get a good judiciary on the cheap. Repeatedly, I have said. "All right. If you do not want to raise the salary, at least give them pensions that are equivalent or near-equivalent to the salary." Here is Mr. Mohan Kumaramanglam or Mr. Gokhale. Mr. Gokhale is a living example of the fact that people, leading members of the Bar, cannot live with any self-respect on the salary offered a High Court Judge. He resigned, I hope, Mr. Mohan Kumaramangalam and Mr. Gokhale will have this conviction—given a sharper edge—and that they are going to convince their slogon-mongering political colleagues who are bereft of reality so far as the judiciary is concerned as to what damage the policies are doing to our judiciary today.

I say this because I also want to stop increasing mal-practices among retired judges I am among those who have said that no retired judge should be allowed to practise. We know what is happening. I do not want to point a finger at the judiciary. But a finger is pointed by themselves at themselves. The High Court Judges go to the Supreme Court to practice. Some of them have never practised before. They start as juniors. They do not compete with even more competent juniors. They compete with the junior-most of the juniors. They have to compete in a fiercely competitive profession with every form of mal-practice. I do not know whether Mr. Mohan Kumaramangalam remembers that about 3 or 4 ex-Judges were indicted for touting.

What do you think happens ? You compel them to do this. You compel them to supplement a completely inadequate pension by coming back to the Bar. I know, on the eve of retirement, lawyers complain that certain judges inclive towards certain leading lawyers in the hope that when the Judges come to practice in the Supreme Court, they will feed them with briefs. Other Judges who know that they have no capacity even to function as juniors in the Supreme Court look around for jobs.

I had just come from one of the High Courts and the Bar had told me as to what was happening. I mentioned this at a party to the then Chief Justice of India, that Judges, on the eve of their retirement, are waiting on the Ministers hoping to get some kind of jobs. The then Chief Justice of India observed if they wait on the Ministers, that is some thing, but they are waiting on Deputy Ministers, they are wait-

[Shri Frank Anthony]

ing on Parliamentary Secretaries in the hope of getting some kind of jobs. (*Interruptions*)

So far as the Supreme Court is concerned, this is what the Law Commission has said. No one has greater regard for the Judges as individuals. This is what the Law Commission has said :

> "It is widely felt that communal and regional considerations have prevailed in making the selection of the Judges so that the best talent among the Judges of the High Courts have not found their way to the Supreme Court."

Sir, it was high time that we did something radical about it. That Law Commission said that we must not give any expectation of employment before or after they retire, to any Judge including a Supreme Court Judge. And here I want to deal with the other side of the matter --this irresponsible, wanton and ignorant criticism by, I am sorry to say, certain types of politicians. The Law Commission has nailed that to the counter. They have said that while politicians pay lip-service, by and large, to the Judiciary, in the next breath, they lower their dignity. They refer to a very leading personality in this country talking about Judges living in ivory towers. We to-day have heard the latest slogan, 'We must have committed Judges.' This is not only pernicious but even an utterly vicious slogan. What, in effect, are you saying ? That the Judges must bend their ideas, that they must bend their interpretation, in order to suit the political philosophy of the party that happens to be in power ?

Sir, finally look at what we have reduced our politics to ? The term 'politician' today is a dirty word. But, don't let the politicians make the term 'Judge' into a dirty word.

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, अभी हमने अपने एक विख्यात वकील का प्रवचन सुना । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और राजनैतिक परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि हमारी कमिटिड ब्यूरोक्रेसी न हो, कमिटिड अदालतें और सुप्रीम कोर्ट वगैरह न हों। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कभी नारे नहीं लगाते । हम ता उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं । संविधान में, जो खास तौर से सम्पत्ति को मूलभूत अधिकार है, हम उसको अलग करके सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करना चाहते हैं । माननीय सदस्य ने कई बार श्री मोहन कुमारमंगलम से कुछ अपील की । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरा तो अदालत से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता है, लेकिन एक पेटीशन मेरे खिलाफ हुआ है, जिसके लिये वकीलों ने मुझसे दो लाख रुपये मांगे हैं—दो हजार रुपये की फी पेशी और पांच हजार पहले । ये जितने बड़े-बड़े वकील हैं, इनकी लाखों करोड़ों रुपये की जायदादें हैं । ये क्या नसीहत देंगे कि कौन कमिटिड हो और कौन न हो ।

यह तो ऐसा खराब सर्कल है कि इसको तो बुनियादी तौर पर तोड़ना चाहिए । जब हम चाहते हैं कि जनता की आम आवश्यकता की चीजों के मामले में जो मिडलमैन बहुत मुनाफा कमाते हैं, उनको खत्म कर दिया जाये, तो न्याय के क्षेत्र में ये जो बीच के लोग हैं, उनसे भी छुट्टी मिलनी चाहिये, वर्ना जब मेरे जैसे आदमी से दो लाख रुपये मांगते हैं, तो ये आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करेंगे ? जैसी अदालतें, वैसे वकील । जब तक सूरज की रोशनी की तरह गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है, झोपड़ी में रोशनी जैसे जाती है वैसे ही न्याय उन्हें नहीं मिलता तब तक हम उसे न्याय नहीं मान सकते । मैं नहीं मान सकता कि यह अदालतें न्याय दे सकती हैं । गरीब आदमी तो उनकी चौखट तक भी नहीं पहुंच सकता । इसलिए इसमें बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है । बड़े-बड़े कांच के महलों में रहने वाले लोग गरीब की बात नहीं सोच सकते बेचारे जब रिटायर होते हैं तो कभी बिरला कभी मूंधड़ा की नौकरी करते हैं । इसके लिए यह नियम बनाइये कि वह जाकर कहीं बेकार [illegible] न करे जिससे हमारा सिर

नीचा होता है। अब मैं और ज्यादा बात नहीं कहना चाहता अदालतों के बारे में। जो अब नये कानून बनाये जायेंगे और जो नई सामाजिक क्रान्ति आएगी उसके मुताबिक उनको न्याय करना पड़ेगा।

खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो अभी एक बड़ा संकट आने वाला है बंगला देश के प्रश्न पर, बहुत जल्दी शायद हमें एमर्जेंसी भी लागू करनी पड़े क्योंकि और कोई तरीका नहीं है क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो सबसे ज्यादा कोशिश वह करेंगे वह यह करेंगे कि हिन्दू मुस्लिम दंगे वह हिन्दुस्तान के अन्दर करायें और दंगे कराने वाली संस्थायें अपने-अपने हथियार तेज कर रही है। उनको खूब इजाजत दी जा रही है, रोज सबेरे वह यहां के स्कूलों में अपनी परेड करते हैं। सरकारी कर्मचारी बहुत से ऐसे हैं, पचासों बार यहां कहा गया कि आर० एस० एस० राजनैतिक संस्था है लेकिन उसके बाद भी...(व्यवधान)...

श्री हुकम चन्द कछवाय (भुरेना) : गलत बिलकुल गलत बात है।

सभापति महोदय : कछवाय जी, आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य का अधिकार है बोलने का। आपकी जब बारी आएगी तब आप भी कह लीजियेगा।

श्री फूलचंद वर्मा (उज्जैन) : सभापति महोदय, वह सांस्कृतिक सस्था है, राजनैतिक संस्था नहीं है।

सभापति महोदय : यह अपना-अपना विचार है। आप बैठिये।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं केवल आपके माध्यम से इतना पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आर० एस० एस० का संविधान पढ़ा है?

श्री शशि भूषण : सभापति महोदय, यह अगर मानते हैं कि वह एक सांस्कृतिक संस्था है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मानते रहें। लेकिन लाठियां, भाले और जहरीले छुरे चलाना जो यह सिखाते हैं...(व्यवधान)...

श्री हुकम चन्द कछवाय : नहीं, क्या चूड़िया पहन कर नाचना सिखायें...(व्यवधान)

श्री फूलचंद वर्मा : 26 जनवरी को आदिवासियों की महिलाओं को नंगी करके सड़कों पर घुमाना सिखायें...(व्यवधान)...

श्री शशि भूषण : सभापति महोदय, यह बहुत परवर्स लोग हैं, इनकी बात में मैं नहीं पड़ना चाहता।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह जमायते इस्लामी और दूसरी जमातें भी है, मजलिसे मशावरात है, ये भी आज उसी की तैयारी कर रही हैं। उनके अखबार भी इसी तरह की राष्ट्र-विरोधी खबरें छापते है। तो जब एमर्जेंसी लागू हो तो मैं यह आपसे फिर प्रार्थना करना चाहता हूं, सदन में कई बार कहा गया है कि इस पर बैन लगाया जाना चाहिये जो साम्प्रदायिक मिलिटेंट आर्गेनाइजेशंस हैं क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। यह चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो बड़े-बड़े सरमायादार हैं उनके यह चौकीदार एक दूसरे का गला काटें और देश की प्रगति को रोकें। जहां जहां दंगे हुए हैं जो-जो अफसर वहां मौजूद थे उनकी जांच कराई जाय। उन्हें तरक्की देकर उन्हें केन्द्र में क्यों बुलाया गया? उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई? जहां-जहां भी जांच कमीशन बैठाया गया किसी को भी फांसी नहीं दी गई। अगर हिन्दू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिन्दू को मारा तो किसी को सजा नहीं दी गई। यह खुली इजाजत दी जाती है इसके लिए। तो आज जब एमर्जेंसी का वक्त आया है तो इसकी तरफ खास तौर से हमें ध्यान देना चाहिये और फौरन इन्हें बैन करना चाहिये।

[श्री शशि भूषण]

और जो सरकारी नौकरियों में इस तरह से जमायते इस्लाम और आर० एस० एस० के लोग काम करते हैं उनको बैन करना चाहिये। यह काम हम इम्मीडिएटली करें...

श्री हुकम चंद कछवाय : यह सरकार दस बार जन्म ले तब भी आर० एस० एस० पर बैन नहीं लगा सकती।

श्री शशि भूषण : बैन तो यह होगा ही।

दूसरे जो बड़े-बड़े देवस्थान हैं, बड़े-बड़े गुरुद्वारे हैं, उनका पैसा बुरी तरह इस्तेमाल किया जाता है। महारानी ग्वालियर अपने देवस्थान के पैसे को राजनीति में इस्तेमाल करतीं हैं। उन्होंने बहुत सी जमीन बेची। मध्य प्रदेश सरकार उन पर केस चला रही है। इसलिये ऐसे देवस्थानों को फौरन बैन करना चाहिये जो कि पैसा राजनीति में लगाती हैं और ऐसी संस्थाओं को देती हैं, जैसे महात्मा गांधी के मर्डर में दिया गया उसी तरह से देश के अन्दर हत्या के काम के लिये पैसा दिया जाता है, इसलिये इनको बैन करना चाहिए। देश के अन्दर चाहे वह किसी भी धर्म के लोग हों, वह बड़ी श्रद्धा से पैसे इनको देते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग होता है। यह दुरुयोग बन्द करें।

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है उसको हमें प्रोटेक्शन के लिये एक अम्ब्रेला देना चाहिये। पूरी एक यूनिट बनानी चाहिये आसाम, बंगाल और उड़ीसा का क्योंकि उस क्षेत्र के अन्दर नक्सलाइट्स की और दूसरी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं और जो वहां चायनीज और दूसरे विदेशों का खतरा हैं उसको दूर करने के लिये हमें कोई एक केन्द्रीय सेक्योरिटी बोर्ड बनाना चाहिये, एक प्रोटेक्शन अम्ब्रेला बनाना चाहिये ताकि उसकी देखरेख में वहां की सरकारें चल सकें क्योंकि वहां की सरकार इतनी समर्थ नहीं है कि इस तरह की चीजों को मैनेज कर सके। खास तौर से जब इतनी बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज बाहर से आए हैं तो उनकी देख रेख के लिये भी यह जरूरी है क्योंकि कुछ गलत लोग भी उसमें आ गये हों यह मुमकीन है। इसलिये यह जरूरी है कि एक पावरफुल सेक्योरिटी बोर्ड बनाया जाये और उसमें कुछ पब्लिकमैन भी रखे जायें तो कोई हर्ज की बात नहीं है।

इस सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि खास तौर से जो बंगला देश के नौजवान आए हैं और जो अपने राष्ट्र की आजादी के लिए अपने प्राण देना चाहते हैं, उनकी भी एक वालंटियर फोर्स अपने देश में हम बनायें तो कोई गलत बनायें नहीं है। जहां वह अपने देश में ट्रेनिंग ले रहे हैं, हजारों की तादाद में वहां इस देश में भी ऐसा करना चाहिये ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके और उनकी सुरक्षा का जो सवाल है वह पूरा हो सके।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो फारेन ट्रिप्स हैं आफिशियल्स की वह बन्द करनी चाहियें। यह जो बड़ी-बड़ी एजेंसीस हैं फोर्ड फाउंडेशन है, एशिया फाउन्डेशन को बन्द किया, मोरार जी ने इस हाउस में माफी मांगी कि मैं तो गलती से इसका मेम्बर था, कई ऐसी विश्व-पर्यटन की एजेंसीस हैं मैं चाहता हूं कि सरकार उनके ऊपर खासतौर से ध्यान दे और जो विदेशों के भी ऐडवाइजर्स आते हैं उनसे हमारा देश तंग आ चुका है। एक विभाग में चार सौ विदेशी ऐडवाइजर्स हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में कमी नहीं है।

सभापति महोदय, प्रिवी पर्स के सिलसिले में अभी एक राजा साहब ने बहुत करुणा कहानी कही। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त हम आनरेबल सेटिलमेंट उनसे करना चाहते थे, हमने हरचंद कोशिश की तो

तब उनको इन लोगों ने गुमराह कर दिया कि यह इंदिरा गांधी की सरकार तो दो मिनट में जा रही है, हमारी सरकार आ जाएगी तो प्रिवी पर्स दुगुना तिगुना हो जायेगा। तुम क्यों सेटिलमेंट कर रहे हो? मैं यह कहता हूं कि अगर आज इनके अधिकार नहीं खत्म किये गये तो देश की जनता आन्दोलन शुरु कर देगी। वह आज इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनके यह चौकीदार भी जनता में जाकर उनके लिये नहीं कह सकते। जनता में गये तो उनकी जमानतें जब्त हो गई। इसलिये प्रिवी पर्स और प्रिवीलेजेज को इसी बार और इसी सदन में खत्म करना चाहिये। यह बहुत जरूरी है और उसमें हम और ज्यादा इन्तजार नहीं कर सकते।

एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो बडे-बड़े अखबार हैं जो इनके बड़े-बड़े मालिक हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको इन मालिकों से अलग कर देना चाहिये। यह गोयनका वगैरह जो बड़े-बड़े लोग है जब कभी राष्ट्र पर संकट आया, देश की स्वतन्त्रता को खतरा आया या जैसे यह एमर्जेंसी अभी आने वाली है, तो इन्होंने कभी देश का साथ नहीं दिया। यह जो पी० टी० आई० है लाखों रुपया हम इनको देते हैं और यह जो रायटर को पैसे देकर उनसे गालियां खरीदते हैं। हमें अपनी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी बनानी चाहिये और जो उनके एजेंट यहां बैठे हैं उनको निकालना चाहिए। एक कमीशन बिठाकर उनकी एन्क्वायरी करानी चाहिये। इन बड़े-बड़े अखबारों के जरिए जितना देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाया गया है वह और किसी के जरिये नहीं पहुचाया गया।...(व्यवधान)...जनसंघ इनका प्रतीक है। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री सूलचंद डागा (पाली): सभापति महोदय, जब पुलिस की बात करते हैं तो मुझे गावों की याद आती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपके पुलिस विभाग से जनता आज तक संतुष्ट नहीं है, आज लोगों का विश्वास पुलिस में जमा नहीं है। यह मानी हुई बात है कि जब हम पुलिस की बात करते हैं तो हमारे गांव के लोगों पर आतंक, भय और दुख का भाव बना रहता है। हमने कई बार भूमि सुधार के कानून के मामलों में देखा है कि जब कभी आप की पुलिस को इंट्रक्शन्ज निकलते हैं कि गांव के लोगों के छोटे-छोटे मुकदमों में सहयोग दीजिये, गांवों में जितने मुकदमात होते हैं, उनमें पुलिस विभाग कभी मदद नहीं देता है। यही कारण है कि जनता का विश्वास पुलिस से उठ गया है और पुलिस इस बात को मानती हैं कि जनता का सहयोग उसे नहीं मिलता है। चाहे जितने "मे आई हैल्प यू" के बोर्ड लगे हों, काफी बड़ी रकम पुलिस पर खर्च करने के बाद भी आप जनता में पुलिस का विश्वास पैदा नहीं कर पाये हैं। मैजिस्ट्रेटों ने अनेकों बार पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं, लेकिन क्या कभी कोई एक्शन उनके खिलाफ होता है।

अदालतों की हालत भी आज इसी तरह की हो गई है—दिल्ली के अदालतों के बारे में मैं अखबार पढ़ता हूँ—हमारे मैजिस्ट्रेट की क्या हालत है, हमारे जजेज की क्या हालत है, लीगल कोर्ट्स में जहां हम न्याय चाहते हैं, वहां न्याय नहीं मिलता है। आज न्याय भी मंहगा हो गया है, सस्ता नहीं रहा है। जब हमें न्याय नहीं मिलता, पुलिस भी हमारी मदद नहीं करती तो फिर आप इस देश के नागरिकों की रक्षा कैसे कर सकते है?

एक बड़ा सवाल आज देश के सामने यह है कि जिन कोर्टों से हम न्याय लेना चाहते हैं, उन कोर्टों से हमारी भाषा में न्याय नहीं मिलता। आज जो हमारे कानून हैं, उनकी भाषा हमारी भाषा नहीं है। आज लोग चाहते है कि हमारी बोलचाल की भाषा में, हमारी हिन्दी भाषा में हमें न्याय मिले, उनको न्याय अपनी भाषा में नहीं मिलता है और हमारे सारे कानून उन भाषाओं में हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं,

[श्री मूलचन्द डागा]

हमारे साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। आज इंगलिश की पढ़ाई इसीलिये जरूरी है कि यह जनता के शोषण का साधन बन गई है, यह हमारे गांवों के लाखों-करोड़ों लोगों का शोषण करने का तरीका बन गई है, अंग्रेजी भाषा में बोलकर, कुछ वकील लोग बात करके, जनता के शोषण का तरीका चल रहा है। हमारा अपना डिपार्टमेंट हिन्दी की हिमायत तो करता है, लेकिन संविधान बनने से लेकर आज तक इस रास्ते में कोई प्रगति नही हुई है। आज भी हिन्दी की हिमायत करने वाले लोग दुनिया को धोखा देने के लिये, लाखों करोड़ों लोगों को धोखा देने के लिये अंग्रेजों में बात करना गौरव समझते हैं। दूसरे देशों के लोग अपनी बात अपनी भाषा में करते हैं और उसमें स्वाभिमान अनुभव करते हैं, लेकिर हमारे देश के लोग अपनी भाषा में बोलने के बजाय अंग्रेजी भाषा में गौरव समझते हैं और इसी कारण उनको देश में ऊंचे पद मिलते है। हाई कोर्टों में जजमेंट्स अंग्रेजी मे आते है, उन जजमेंट्स मे कुछ नही होता है, पिछले जजमेंट्स की नक्ल ही करते है, न अपने दिमाग से कुछ सोच सकते है और न कोई वकील ही बात करते हैं, लेकिन अगर अपनी भाषा मे बोले तो सही और सच्ची बात न्यायालयों म हो सकती है, संक्षेप में कह सकते है। लेकिन यह तो आज शोषण का एक तरीका बन गया है कि हम दूसरी भाषा को अख्तियार करें और दुनिया का शोषण करें, इसी कारण ये अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग लाखों-करोड़ों लोगों का शोषण करने के लिये अपनी भाषा को बोलना नहीं चाहते हैं।

23 साल की आजादी के बाद भी अदालतों में न्याय नहीं मिलता, सस्ता न्याय नहीं मिलता उच्च न्यायालय और अदालतों में भी भ्रष्टाचार पनप गया है। ऐसा भ्रष्ट हिन्दुस्तान कैसे जी सकता है। गरीब हिन्दुस्तान ने आजादी हासिल कर ली, लेकिन जो हिन्दुस्तान भ्रष्ट हो चुका है, जिसका न्यायालय भ्रष्ट हो चुका है, जहां हाई कोर्टों में भ्रष्टाचार चलता है, इन कोर्टों में हम लोग न्याय नहीं पा सकेंगे। 23 साल से हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारी अपनी भाषा में न्याय होगा, कानून सरल भाषा में होंगे जिसे लोग समझ सकें—लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है।

अभी एक वकील साहब ने हाई कोर्ट की बात की—उन्होंने कहा कि जयपुर में हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिये। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल ही नहीं था। जब राजस्थान बना था, उस समय बड़ा सोच-समझ कर निर्णय लिया गया कि राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में होगा, जगह-जगह हाई कोर्ट बनाकर खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। आखिर राजस्थान की पापुलेशन कितनी है, कियने मुकदमात होते हैं। ज्यादा मुकदमात तो डिस्ट्रिक्ट लेबल तक ही होते हैं, लेकिन वकील साहब यहां आये और उन्होंने अपने इलाके की वकालत कर दी और जोश में आकर कह कर चले गये। उस समय बड़ी छान-बीन के बाद निर्णय हुआ था कि जयपुर में राजस्थान का कैपिटल रहेगा और जोधपुर में हाई कोर्ट रहेगी—इस निर्णय में परिवर्तन की क्या आवश्यकता है।

जब मैं यहां पर पुलिस की बात कहता हूं—तो कौन नहीं जानता कि थानेदार बनना सब पसन्द करते हैं ताकि हजारों रुपया कमा सकें। कोई भी सर्किल इन्स्पैक्टर नहीं बनना चाहता, सब थानेदार बने रहना पसंद करते हैं। आज इन्वेस्टीगेशन्ज की हालत को देख लीजिये, हमारा पुलिस विभाग और प्रासीक्यूशन का जो तरीका है—उसमें क्या हो रहा है। मैंने पाली में देखा है, इतने कत्ल के केस हुए आम बाजार में कत्ल किये गये लेकिन आज तक उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सका। यह बड़े दुख की बात है, हम पर इतना टैक्स

लगाने के बाद, हमसे इतनी रकम वसूल करने के बाद भी आप हमको सुरक्षा नहीं दे सकते, पुलिस का आतंक बना रहता है, भय बना रहता है, बड़े-बड़े लोग भी उनसे डरते हैं, बिना मतलब के डरते है और आप उनको न्याय नहीं दे सकते।

हमने कई बार इस पर सोचा —हम आप से दो चीजें चाहते हैं—सबसे पहले तो न्याय चाहते हैं, लेकिन आज न्याय किसको मिलता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास बड़े-बड़े वकील करने की सामर्थ्य है। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्याय तो पैसे वालों के पास रहता है। जिनके पास दौलत है, जिनके पास पैसा है, ये कानून और नियम सब उन्हीं लोगों के लिये हैं और हक छीना जाता है हम जैसे कंगालों का। गरीब को मारने के लिये कानून एक जाल है, जिसमें बड़े-बड़े वकील जीत जाते हैं और गरीब मुंह देखता रह जाता है।

हमें अपने कानूनों में परिवर्तन करना होगा। आपका सिविल प्रोसीजर कोड, आपका क्रिमनल प्रोसीजर कोड, आपके आई० पी०सी० के सैक्शन्ज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर इन्हीं की मदद से राज को चलाना है तो 25 साल चला लो, 30 साल चलालो, 40 साल चला लो, लेकिन जनता को संतोष नहीं होगा। चेयरमैन साहब, आप भी बड़े अच्छे एडवोकेट हैं, आप जानते हैं कि प्रोसीक्यूशन में कितने अच्छे अच्छे मुकदमात भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि आज उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। आपको प्रोसीक्यूशन इंसपैक्टर जो-पैड आदमी होता है, वह आते ही सबसे पहले रिश्वत की बात करता है। इन सारी बातों को जानते हुये भी यहां पर कहना अच्छा नहीं लगता है। यहां चाहे जितनी ऊंची-ऊंची बातें कर लें, सुप्रीम कोर्ट की बातें करें, पार्टी की बात करें, लेकिन गांव का रहने वाला अगर थाने में जाता है तो उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जिन लोगों का वास्ता पुलिस से पड़ा है, वे आज यही कहते हैं कि भगवान करे पुलिस से कभी वास्ता न पड़े। ऐसी हालत में आप मुझे बताइये कि 24 साल के बाद भी हम अपने पुलिस विभाग को नहीं सुधार सके, उसकी गल्तियों को नहीं रोक सके, उसके आतंक को कम नहीं कर सके, तो फिर हमने क्या किया ?

17.00 hrs.

मैंने यहां आकर पढ़ा कि दिल्ली की अदालतों में तो गवाह भी किराये पर मिल जाते हैं। 10 रु०, 50 रु०, 100 रु० में चाहे जैसी गवाही दिलवा लो, जब हमारी अदालतों में ही न्याय नहीं रहा, पुलिस में न्याय नहीं रहा तो फिर हम क्या उम्मीद करें, आप किस तरह से गरीबों को न्याय देना चाहते हैं...

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, इतना सुन्दर भाषण हो रहा है, लेकिन मन्त्री महोदय बातों में लगे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं।

गृह-मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : मैं सुन रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आज 447 में केसेज होते है, अगर किसी गरीब काश्तकार की जमीन का मुकदमा होता है और वह गरीब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस कहती है कि हम तुम्हारा मुकदमा रजिस्टर करने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि वह गरीब है, उसके पास पुलिस से मिलने की ताकत नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं—कितने मुकदमात ऐसे हैं, जिनमें 107, 109 और 110 में पुलिस ने हजारों-लाखों लोगों को पकड़ कर जेल में ठूंस दिया है। वे गरीब लोग जो निर्दोष हैं, जिनको रोटी नहीं दे सकते, जो भूखे हैं, उनको हैबिचुअल-आफेण्डर कह कर जेलों में ठूंस दिया जाता है। इसलिए आज कानून में रद्दोबदल की जरूरत है, समय के साथ कानून को बदल दो, लेकिन न मन्त्री महोदय को फुर-

[श्री मूलचन्द डागा]

सत है और न डिपार्टमेंट को फुरसत है। वह यही समझते हैं कि जितना समय निकल जाये, उतना अच्छा है, उनकी मिनिस्ट्री निकल जाये तो अच्छा है, वक्त गुजरा काम खत्म हुआ। इससे नहीं होगा। सवाल है कि आप हिन्दुस्तान में तब्दीली चाहते हैं या नहीं? आपके जो कानून हैं उसमें जैसे सिविल प्रोसीजर का केस या मकान खाली कराने का केस है उसको आप कितने साल तक चलाना चाहते हैं? 15 साल में तो मुकदमा लड़ने वाला ही मर जायेगा मैं कहता हूं कि बीस-बीस साल तक मुकदमे का डिस्पोजल नहीं हो पाता है। इसके अलावा आप कोर्ट्स की फीस बढ़ाते जाते हैं। ये सारी बातें हैं। तो जिस राज्य में लोगों को न्याय न मिले वहां पर क्या आशा की जा सकती है कि देश आगे बढ़ेगा। आदमी सबसे पहले इंसाफ चाहता है। जब आप इन्साफ भी नहीं दे पाते तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि हमें और क्या मिलेगा। जनता आपसे इंसाफ मांगती है। आप इमानदार लोगों को मैजिस्ट्रेट बनाइये। मैं पूछता हूं कि आज तक आपने कितने मजिस्ट्रेटों का चालान किया और कितने पुलिस अफसरों को जेल में पहुंचाया? आज देश में पुलिस के लिए लोगों में कोई श्रद्धा नहीं रह गई है क्योंकि पुलिस में जनता के प्रति कोई सेवा की भावना नही है बल्कि उसकी भावना जनता का शोषण करने के लिए होती है। आज एक पुलिस का थानेदार रिटायर होने के बाद गांव में सरपंच या प्रधान बनता है और अपनी शक्ति की भावना से ही राज करता है। अगर आप जनता में लोकतंत्र की भावना पैदा करना चाहते हैं तो वह भावना तभी पैदा हो सकती है जबकि वह अपने को आजाद महसूस करेगा। इसके साथ आपको समाज में जीवन के मूल्यों में परिवर्तन करना होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने उम्मीद की थी, पिछले चुनावों के बाद हिन्दुस्तान की जनता को आशा दिलाई गई थी कि गरीबी मिट जायेगी और जनतन्त्र को मजबूत किया जायेगा जनतन्त्र को विस्तृत किया जायेगा, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया जायेगा और एक नये समाज की रचना की जायेगी—यह विश्वास जनता को दिलाया गया था और जनता ने यह विश्वास किया भी था लेकिन गृह मन्त्रालय के बजट में किसी भी बात की झांकी नहीं मिलती है। अगर इसमें कुछ है तो वह यह कि हिन्दुस्तान में पिछले 23 सालों से पूंजीपति वर्ग का जो क्लास रूल है, वर्ग शासन है उसको मजबूत करने की बातें कही गई है। इसलिए पुलिस को बिल्कुल निरंकुश बना दिया गया है, उसे ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, आन्तरिक सुरक्षा के नाम पर नया कानून बनाया गया है और दूसरे दमनात्मक कानून बनाने की बात चल रही है। इन सब बातों से, हमने जो उम्मीद की थी वह उम्मीद पूरी नहीं होगी, गरीबी तो नहीं ही मिटेगी और हम जनतन्त्र को भी विस्तृत नही कर सकेंगे, उसे जनता तक पहुँचा नही सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जनता की आशायें, आकांक्षाये पूरी हों तो सबसे पहले, जो मौजूदा संविधान है जिसमें आपने पंजीपति वर्ग को और सम्पत्ति रखने वालों को असीम अधिकार दे रखे हैं, उनके अधिकारों को तोड़ना होगा, उनके व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को सीमित करना होगा। तभी हम सही मायनों में देश में एक नयी व्यवस्था पैदा कर सकेंगे। आप फौरन इसके लिए संविधान में परिवर्तन लाने की बात कीजिए।...(व्यवधान)...यदि आप ऐसा करेंगे तभी आप को कहने का हक हो सकता है कि आप नयी समाज व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आपने इसका वायदा चुनाव के समय में किया था।

इतना ही नहीं, जब तक आप संविधान में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक बिना मुआविजे के प्रीवी पर्स को समाप्त करने में भी आपको कठिनाई होगी। आप राजाओं की थैली और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कीजिए। आप आई० सी० एस० अफसरों के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कीजिए और पुलिस के निरंकुश अधिकारों को कम कीजिए तथा साथ ही जनता की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी मांगों को समझने की कोशिश कीजिए। केवल यह कह देने से काम नही चलेगा कि समाज में अराजकता है और ला ऐड आर्डर गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? इसलिए गड़बड़ है कि आप आम जनता की भावनाओं को लेकर चलना नहीं चाहते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को लेकर चलना चाहते है तो जाहिर बात है कि मौजूदा पूंजीवादी समाज के घरौंदे में जो आपने अपने को कैद कर रखा है उससे निकले बिना आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि इस देश में जो साम्प्रदायिक तत्व हैं, साम्प्रदायिक दल है, संगठन है उन पर आप नियंत्रण नही कर पाते हैं। कहने के लिए तो हमारे आर० एस० एस० के भाई कहेंगे कि हमारा सांस्कृतिक संगठन है...(व्यवधान)... लेकिन पिछले चुनाव में मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि लाठी और बम लेकर वे लोग जनसंघ के उम्मीदवार के लिए वोट इकटठा कर रहे थे। क्या वोट इकट्ठा करना सांस्कृतिक काम है? लेकिन संस्कृति के आड़ में ये देश में फासिस्ट निजाम बनाना चाहते हैं, देश में हिन्दू, मुसलमान सिख, ईसाई—सभी को लड़ाकर इस देश का बंटाधार करना चाहते हैं। इस तरह के जो लोग हैं—चाहे वे जनसंघी हों, आर एस० एस० के हों, जमायते इस्लामी के हों, या शिव सेना के हों—जोकि एक जाति और दूसरी जाति के बीच में घृणा की भावना पैदा करना चाहते हैं उनको रोकने के लिए आपको सख्त से सख्त कदम उठाने होंगे और आर० एस० एस०, जमाअते इस्लामी, शिव सेना, इन सभी पर आपको पाबन्दी लगानी होगी। बिना पाबन्दी लगाये हुए आप इस देश की सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकते हैं और न देश को आत्म-निर्भर ही बना सकते हैं।...(व्यवधान)...

श्री हुकम चंद कछवाय : इस देश में जितनी भी राजनैतिक एवं अन्य हत्यायें हुई हैं उनकी जिम्मेदारी साम्यवादी दल के सिर पर हैं।...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : गवर्नमेंट कहती है कि नक्सलवादियों का बड़ा खतरा हैं तो यह बात ठीक है, उनका रास्ता बहुत गलत है और वह देश में चल नहीं सकता है लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की बातें देश में क्यों होती हैं? आप किसानों को जमीन देते नहीं हैं, मजदूरों की समस्याओं का समाधान करते नहीं हैं, जनतांत्रिक तरीके से आप देश को चलाना नहीं चाहते हैं इसी वजह से इस प्रकार के तत्व इस देश में उभरते हैं। आप असली मर्ज की दवा करते हैं नहीं हैं और ऊपर-ऊपर से दवा करने से कोई काम चलने वाला नहीं है।

सभापति जी, यह ठीक है कि देश की सम्पर्क भाषा हिंदी होनी चाहिए लेकिन हिंदुस्तान की जितनी भी भाषायें हैं जोकि हमारे शेड्यूल में लिखी हुई हैं वे तमाम राष्ट्र की भाषायें हैं और सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है? उर्दू को आप दबाते हैं, उसको संरक्षण नहीं देते। हमारे सूबे में यूनिवर्सिटीज में उर्दू में, बंगला में, उड़िया में लिखने वाले जो विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकायें लिखते हैं उन पर पाबंदी लगायी जाती है कि नहीं तुम्हें एक ही भाषा में लिखना होगा। वह हिंदी के विरोधी नहीं हैं। हिंदी का पर्चा हिंदी में

[श्री रामावतार शास्त्री]

लिखते हैं, लेकिन दूसरे पक्षों को अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं है। क्या इससे हमारे देश में सेक्युलरिज्म और आपसी एकता मजबूत होगी ? नहीं, इससे झगड़े बढ़ेंगे।

जिन सरकारी कर्मचारियों ने आज से तीन, चार साल पहले हड़ताल की थी उनमें से सबको आपने काम पर नहीं लिया और अब भी उन पर मुकदमे चल रहे हैं। 1500 लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं। उन पर से मुकदमा उठाने में आप को क्या दिक्कत है ? दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर से आपने मुकदमे उठा लिए, बड़ा अच्छा किया। अब आप खोसला कमीशन की रिपोर्ट को लागू कीजिये, कमीशन द्वारा मन्जूर किये गये वेतन-मानों को लागू कीजिये, उनके लिए रहने की व्यवस्था कीजिये, उनकी दूसरी कठिनाइयों को दूर कीजिये। तभी आप आगे बढ़ेंगे।

प्रिवी पर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट को समाप्त करने की बात नहीं कहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद को बढ़ाइये ताकि जो पूंजीपतियों की चाकरी करने वाले जज हैं, जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं ऐसे जजों को मनमानी करने का मौका नहीं मिले। इसलिए जरूरत है कि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन कीजिये, उनकी संख्या को बढाइये तभी आप जनता को सस्ता न्याय दे सकते हैं तभी जनता को विश्वास होगा। यह काम आपको करना होगा।

आखिर में सभापति जी, रिटायरमेंट की उम्र के बारे में कहना चाहूँगा। रिटायरमेंट की उम्र कम करने की बात कई लोगों ने कही। एक तरफ आप 58 से 55 ले आइये। लेकिन दूसरी तरफ अगर बेकारी की समस्या से आप लड़ना चाहते हैं तो जो हमारे लाखों नौजवान बेकार हैं, जिनको 25 साल के बाद सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उनकी उम्र की सीमा आप बढ़ाइये। देश की विशेष स्थिति को देखते हुए उनकी उम्र 25 साल से 28 साल कीजिये।

अन्त में नार्थ बिहार के बारे में कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र के विकास के लिये विकास बोर्ड बनाने की बात सरकार ने कही थी। इस पटल पर कागज भी रखे गये थे और प्रधान मन्त्री तक यह बात पहुँचायी गई थी। उस समय यह वायदा हुआ था कि हम इस पर विचार करेंगे। उत्तरी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, वैसे तो बिहार ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन उत्तरी बिहार काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके विकास के लिये एक बोर्ड का गठन कीजिये ताकि वहां विकास करने में आगे बढ़ा जा सके।

जो आपकी माग है यह मांग इन बातों को पूरा नहीं करती इसीलिये मैं इस मांग का विरोध करता हूँ।

श्री रामधन (लालगंज) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट हमारे सामने देखने को मिलती है तो हम यह देखते है कि सघ की राजभाषा हिन्दी घोषित होने के बाद भी जितना कदम उसे प्रयोग में लाने के लिये उठाना चाहिये वह नहीं उठाया जा रहा है।

"राजभाषा से सम्बन्धित सांविधानिक उपबन्धों, और राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के कार्यान्वयन तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकारी नीति तथा कार्यक्रम को तैयार करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है।" लेकिन गृह मंत्रालय के जो आदेश विभिन्न मंत्रालयों को हिन्दी के उपयोग के लिये जाते

हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि बहुत से मंत्रालयों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त करने की बात सभी मंत्रालयों ने गृह मंत्रालय द्वारा मानी गई थी। लेकिन आज तक सभी मंत्रालयों में हिन्दी अधिकारी नियुक्त नहीं किये जा सके हैं। वैसे ही हिन्दी का प्रश्न, हिन्दी शिक्षण योजना का जो सवाल है हम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी की शिक्षा देने की योजना कई वर्षों से चला रहे हैं। लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है। न तो हिन्दी टंकण या हिन्दी शार्टहैंड रिपोर्टर्स की जो शिक्षा देने की बात रिपोर्ट में कही गई है उसमें भी ज्यादा प्रगति नहीं दिखाई देती। यह जरूर है कि जैसे सरकारी आकड़े हम लोगों को भ्रम में डालते हैं वैसे ही कुछ आकड़े हमारे सामने इस रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने प्रस्तुत किये हैं। फिर भी उस से हमें संतोष नहीं मिलता। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि किस तरह से हिन्दी के साथ खिलवाड़ होता है। आप देखेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों में भारतीय भाषाओं के भी पत्रकार हैं। मैं भी उन भारतीय भाषाओं को समान स्तर पर मानता हूं। भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के साथ बड़ा अन्याय होता है और जो अंग्रेजी के पत्रकार है उनकी तरक्की बहुत शीघ्र हुआ करती है और भारतीय भाषाओं के पत्रकारों के साथ अछूतों का सा व्यवहार होता है जिस से वे बहुत दुखी होते हैं। इसके सम्बन्ध में कई सालों तक भारतीय भाषाओं के पत्रकारों ने कोशिश की लेकिन कोई वांछित फल अभी तक नहीं निकला।

हर मंत्रालयों से सम्बंधित सूचना अधिकारी होते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आदेश दे दिया गया है कि हिन्दी और अंग्रेजी में विज्ञप्तियां जारी की जायें। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि कैसा हिन्दी का काम होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब कहीं हमारे केन्द्र के मंत्री अथवा प्रधान मंत्री कहीं भाषण करने जाती हैं तो उन का भाषण हिन्दी में होता है और वहां उनके साथ जो अंग्रेजी के सूचना अधिकारी जाते हैं वह अपनी अंग्रेजी में भाषण तैयार करते हैं और उसका फिर आ करके आकाशवाणी में सूचना मंत्रालय में हिन्दी में अनुवाद होता है। यह नहीं कि जो मूल भाषण है चाहे हिन्दी में हो, उर्दू में हो, चाहे हिन्दुस्तानी में हो उसकी रिपोर्ट मूल भाषा में ही तैयार की जाय। लेकिन ऐसा न करके उस की रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में होती है। उसके बाद आ कर के उस का जो अनुवाद होता है आकाशवाणी और दूसरी जगह पर वह हिन्दी में होता है। यह कितनी हास्यास्पद बात है। यह किस तरह का खिलवाड़ हमारी राजभाषा के साथ किया जाता है।

उच्च न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग की बात रिपोर्ट मे कही गई है। लेकिन आप जानते हैं, जैसा हमारे साथी माननीय मूल चन्द डागा ने कहा, कि हिन्दी भाषा की कितनी उपेक्षा न्यायलयों में की जाती है। हम तो यह जानते हैं कि आज जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें इसलिये दूसरी भाषा में कामकाज चलता है कि जो देश का नागरिक है वह उस भाषा को न समझ सके और जो बीच के लोग हैं वकील आदि या अन्य दूसरे लोग, वह उसको बेवकूफ बना सकें। मैं तो कहता हूं कि यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि इतने दिनों की आजादी के बाद इस स्थिति मे कोई सुधार नहीं हो रहा है। बल्कि जो लोग हिन्दी में अपना निर्णय करते हैं, चाहे छोटी अदालतें हों, चाहे उच्च न्यायालय में हों, उनकी हंसी उड़ायी जाती है। जब तक हमारी विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह बात खत्म नहीं होगी।

इसके साथ-साथ हमारे उत्तर भारत में उर्दू जबान का प्रश्न है। हमारे नेताओं ने उर्दू जबान की उन्नति के लिये बहुत आश्वासन दिये लेकिन उर्दू जबान की शिक्षा दीक्षा के

[श्री रामधन]

लिए उचित व्यवस्था अब तक नहीं हो पायी है।

जन गणना की रिपोर्ट की भी चर्चा इस में की गई है। इस सम्बन्ध मे मैं एक बात कहना चाहता हूं। गिरिजन और हरिजन जो हैं उनकी ठीक प्रकार से जन गणना नही की जाती है। लेखपाल लोग या दूसरे जन गणना करने वाले जो कर्मचारी हैं वे कही बैठ कर, किसी प्रधान या दूसरे के घर मे बैठ कर रिपोर्ट तैयार कर देते है और घर घर जा कर गिनती नही करते हैं। वैसी स्थिति में गिरिजन और हरिजन भाइयो के सम्बन्ध मे यह काल्पनिक बात हो जाती है, सही तौर पर उनकी सख्या कितनी है, यह सामने नही आ पाता है, सही जानकारी जो आप प्राप्त करना चाहते है, वह आप को नही मिल पाती है।

रिपोर्ट मे स्वतत्रता सेनानियो को पेंशन देने की बात भी कही गई है। आप स्वय भी एक महान स्वतत्रता सेनानी रहे है। आप अ दमान की सैल्यूलर जेल से रहे है। अब यहा पर शर्त यह लगा दी गई है कि सैल्यूलर तथा भारत की किसी भी जेल मे जो पाच साल तक रहा होगा उसको पेंशन दी जाएगी। मै चाहता हू कि इस अवधि को हटा दिया जाये। अ दमान निकोबार आइलेंड जिस को काला पानी कहा जाता था, वहा की सैल्यूलर जेल मे जो एक बार हो आया, जेल काट आया उसको भी पेंशन मिलनी चाहिये और यह जो अवधि की शर्त लगाई गई है, उसको हटाया जाना चाहिए। हर एक स्वतत्रता सेनानी को जिसने स्वतत्रता सग्राम मे भाग लिया था, बलिदान किया था, अपनी सम्पत्ति आदि न्यौछावर की थी, नुकसान उठाया था, यह सहायता मिलनी चाहिए।

मैं यह भी चाहता हू कि जो भारत के बाहर की जेलों में रहे हैं, उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए और इसे आपको तत्काल स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई हिचकिचाहट नही होनी चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को जो पेंशन दी जाती है वह बहुत थोड़ी दी जाती है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार उस मात्रा को बढाने का प्रयत्न करे। राजनीतिक पीड़ितों को अधिक से अधिक पेंशन दी जानी चाहिए।

गृह मत्री के विवेकाधीन कोष से भी कुछ राजनीतिक पीडितो को सहायता दी जाती हैं। मै मत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कभी कभी तो बहुत ही कम सहायता दी जाती है और यह ऐसी होती है जो बहुत ही हास्यास्पद प्रतीत होती है। आपको चाहिए कि आप उचित मात्रा मे उनकी सहायता करे, उचित धनराशि इसको दे। आपने राजनीतिक पीडितो की लडकियों की शादी के लिये सहायता देने की बात कही है। यह जो राशि आप देते है, इसको आपको चाहिये कि आप बढाये। साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन दी जाती है उनकी राशि को भी बढाया जाना चाहिए, ज्यादा पशन लोगो को दी जानी चाहिए।

पुलिस और लोक सुरक्षा के सम्बन्ध मे मैं एक बात कहना चाहता हूं। सब से बड़ी बात आज पुलिस के बारे मे यह कही जाती है कि वह अपने कर्त्तव्यो का पालन ठीक प्रकार से नही करती है। आप कहेंगे कि केन्द्र मे इस का सम्बन्ध नही है। लेकिन जो लोक सुरक्षा की बात है, पब्लिक सिक्योरिटी की बात है, उससे आप अपने को अलग नही कर सकते हैं, अपने उत्तरदायित्व से आप वचित नही हो सकते है। आपने सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल और खुफिया विभाग आदि कायम किये हैं। ये आपके अंतर्गत आते हैं। ये सभी दल आपने इस वास्ते बना रखे हैं ताकि शान्ति और

व्यवस्था बनाई रखी जा सके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को जो संरक्षण दिये गये हैं, उनकी रक्षा के लिये पुलिस दल कभी काम करता है? जब परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो एक नया दल आप संगठित कर देते है। पिछले आम चुनावों मे आपने वादा किया था कि हरिजनों आदि पर जो अत्याचार हो रहे है उनको आप बन्द कर देंगे। लोगो ने आपको अपना समर्थन प्रदान किया। अब आपका यह परम कर्त्तव्य हो जाता है कि अनुसूचित जातियो और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे है, उन्हे आप तुरन्त बन्द करायें। आप हमे आर्थिक सहायता न दें, उद्योग धन्धे चलाने के लिये जो आप हमें सहायता देते हैं, वह आप न दें लेकिन हम से जो जबर्दस्ती काम कराया जाता है, उसको आप बन्द करायें। हमें मजदूरी करने की स्वतंत्रता नही है। देहातो मे क्या होता है? अगर कोई मजदूर अपनी मर्जी के मुताबिक कही शहर में जाकर काम करने की कोशिश करता है तो उसके घर को उजाड़ दिया जाता है, उसके परिवार के लोगो पर जुल्म ढ़ाये जाते है, उसके ऊपर तरह तरह के सार्वजनिक अत्याचार होते है और यहां तक होता है कि उनको कत्ल कर दिया जाता है। 23 साल की आजादी के बाद भी हरिजनो का आज यह हाल है। हम आपसे आर्थिक सहायता नही चाहते। हम केवल यह चाहते हैं कि हमें मजदूरी करने की स्वतंत्रता हो, जहां हमें पैसा अधिक मिले वहां जाकर हम मजदूरी कर सके। जो अत्याचार हम पर हो रहे हैं क्या इसको आपने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के नोटिस में लाया है और उन से कहा है कि वे इनको रोकने का प्रयत्न करें, राज्यों के पुलिस मन्त्रियो के नोटिस में लाया है? जिन पर अत्याचार होते हैं उन की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है, उनके मुकदमों की पैरवी तक नहीं हो पाती है। इन, दीन हीन गरीब लोगों को तरह-तरह के मुकदमों में फंसाया जाता है। पुलिस विभाग रोज झूठे मुकदमों में इनको फंसाता है। लेकिन आप कभी भी इन बातों पर ध्यान नही देते हैं। फिर आप कहते हैं कि नक्सलवादी और उग्रवादी देश में बढ़ते जा रहे हैं। नक्सलबादी और उग्रवादी क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर यही स्थिति देश की रही तो यकीन रखिये कि आदमी मजबूर हो कर नक्सलवादी बनेगा, उग्रवादी बनेगा। जब लोग गाड़ी मे चलते है, मार खाते है या दूसरी जगह जा कर मार खाते है तो मजबूर हो कर उनको कहना पड़ता है कि घबराओ नही, दस साल मे नक्सलवाद आने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि सही मानो मे जब तक आप गरीबी नही हटायेंगे तब तक नक्सलवाद, उग्रवाद की जो विचारधारा देश में फैल रही है, उसका मुकाबला आप नही कर सकेंगे। आपको उसके समकक्ष या उससे भी अच्छी व्यवस्था समाज में स्थापित करनी होगी। जब तक आप समाजवादी व्यवस्था सही मानों में कायम नही करेंगे तब तक यह नक्सलवाद और उग्रवाद का जोर देश में बढ़ रहा है उसे आप खत्म नहीं कर पायेंगे। इन बातों पर आपको ठंडे दिल से गौर करना होगा।

आम चुनाव में जो घटनायें घटी हैं, उनको लेकर चिन्ता व्यक्त की जाती है। जो दंगे होते हैं या व्यवधान उपस्थित होते हैं, उनकी भी निन्दा की जानी है। लेकिन आप देखें कि 23 वर्ष की आजादी के बाद भी हरिजन आज अपनी मर्जी के मुताबिक वोट नहीं डाल पाता है, उसे मतदान केन्द्र पर जाने से लोग राकते हैं। आप की हिम्मत नहीं होती है कि आप ऐसी व्यवस्था कर सकें कि मतदान केन्द्र पर जाने की उसको छूट हो और अपनी मर्जी के मुताबिक वह वोट दे सके और जो हक उसको संविधान द्वारा प्राप्त है, उसे वह काम में ला सके। आप जो संतोष प्रकट करते हैं वह बिल्कुल थोथा है। बहुत से बेचारे गरीब मारे डर के चुनाव में वोट देने नहीं आ सके हैं और

[श्री रामधन]

उसकी रिपोर्ट भी नहीं कर पाए हैं। नतीजा यह हुआ है कि आप मुतमईन हो कर बैठ गए हैं।

सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती। साम्प्रदायिकता के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1969 में 519 साम्प्रदायिक दंगे हुए और 1970 में 531 साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें घटीं और उन्हें रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। लेकिन जब तक साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा, तब तक साम्प्रदायिक दंगे नहीं रोके जा सकते। जब कहीं साम्प्रदायिक दंगा हो जाता है, तभी हमारा प्रशासन जागता है। उससे पहले उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किये जाते हैं। इस लिये साम्प्रदायिक संगठनों पर तुरन्त पाबन्दी लगनी चाहिए।

कुछ साम्प्रदायिक संगठन कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वे राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। आप जानते हैं कि जनसंघ के लोग कहते हैं कि आर० एस० एस० एक सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन जनसंघ में जो तत्व बाहर से आये थे, उन को आर० एस० एस० के तत्वों ने बाहर निकाल दिया और अब केवल आर०एस०एस० के तत्व जनसंघ में हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह बात गलत है।

श्री रामधन : यह बिल्कुल सही है। जनसंघ में जो आर० एस० एस० वाले हैं, वही मेयर हो सकते हैं, वही चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कार्यकारिणी से जनसंघ में शामिल होता है, तो उस को कोई स्थान नहीं मिलता है। इस लिये यह कहना गलत है कि आर० एस० एस० एक सांस्कृतिक संस्था है। वह एक राजनैतिक संस्था है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह उस का कोई उदाहरण दें।

आध०

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj) : Sir, some days back there was a discussion in the House about the treatment Government was meting out to freedom fighters and the hon. Home Minister had assured that he would look into the matter. Sir, I would like to point out that on page 32 of the demands of the Home Ministry, the provision made under this head for the whole year 1971-72 is Rs. 10 lakhs. The amount actually spent in 1970-71 under this head is zero. For the Privy Purses the provision is about Rs. 5 crores.

Sir, I wish to state before the House that the manner in which the freedom fighters have been or are being treated by our Government is shameful. They have fought for the freedom of the country, and sacrificed their all but what is given to them ? Some of them are given Rs. 25 or Rs. 40 per month by some State Governments to keep them alive. Sir, in every country its freedom fighters are honoured and respected and positions of honour are given to them. But, here, in all the 23 years of our freedom, we have provided an amount of just Rs. 10 lakhs only this year for political pensions to freedom fighters. In 1969-70 it was nil. This year it is Rs. 10 lakhs. So as a result of some discussion in the House, the amount under this head has risen from zero to Rs. 10 lakhs.

Sir, this is a very important matter. There must be lakhs of freedom fighters in this country and we should not humiliate and insult them by providing just Rs. 10 lakhs for their pensions for the whole year.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : That condition is there that only those who have put in a minimum of 5 years in jail are eligible for this pension.

PROF. S. L. SAKSENA : That means Rs. 100 per freedom fighter per year or Rs. 8 per month. Is that not an insult and humiliation to them ? You are providing Rs. 5 crores for privy purses to the Princes but, for freedom fighters, there is only Rs. 10 lakhs. Last year not a single pie was provided. This year the Budget provision is Rs. 10 lakhs. Is that not shameful and humiliating ?...(*Interruptions*) I have given a Bill which will be coming probably in this session in which I have asked the Government to appreciate the sufferings of the freedom fighters properly and to give them due honour and provide for proper pension. The sort of pension which is given at present is simply humiliating and insulting.

I want to tell something about the pensioners, who are old Government employees. The cost of living is increasing every day. You have increased the dearness allowance of all other Government servants, but in the case of the poor pensioners, you have not increased their pension even by a single paisa. You have not given any increment in their pensions to pensioners. Their pensions should also be increased in proportion to increase in dearness. It is very hard on them. They have served all their lives in the Government. Now you give pensions which are not enough to keep their body and soul together. Therefore, the pensions of those who are old Government employees should be revised, in accordance with the dearness allowance now prevailing.

About Police, I want to say something. It is very humiliating in our country to see that the public regard policeman with suspicion. In England, when I went there, I found that the public regarded them as angels employed to help them. That surprised me. Of course, Prime Minister is in overall charge, but Shri Pant, who is in defacto charge, should think over how the attitude of the public towards the Police should be changed. Police is the main arm of the Government. Unless people have confidence in it, the law and order situation cannot be improved.

I wanted a thana in an area in my constituency, but people said, "No ; we do not want a thana, because it will become one more engine of repression ; they will extort money from villagers." So, efforts should be made to see that the reputation of the Police improves and people have confidence in them, and they enjoy the same respect as Police does in England.

There was a discussion in the House about increasing Dearness Allowance. As a Trade Unionist, I feel that the workers' lot is not very happy. The hon. Minister said that cost of living index should increase by 10 points. I think this has increased but the Dearness Allowance has not been increased. Therefore, I want that increase in Dearness Allowance should be given immediately so that workers may be satisfied and inflation which is our greatest enemy may be properly neutralised and labour in Government Departments may be able to have two square meals a day. Thank you.

श्री डी० एन० तिवारी : सभापति महोदय देश में ला एण्ड आर्डर सिचुएशन दिन-ब-दिन डिटेरियोरेंट करती जा रही है । इस की तह में जाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है । मैं मानता हूँ कि संविधान के अनुसार ला एण्ड आर्डर का विषय एक प्रान्तीय विषय है । लेकिन जब देश में बिल्कुल बदअमनी हो जाये, ला एण्ड आर्डर सिचुएशन रोज डिटेरियोरेट करती चली जाये, तो भारत सरकार यह कह कर अपनी जवाबदेही नहीं टाल सकती है कि ला एण्ड आर्डर प्रान्तों का मामला है ।

इस बात पर विचार करने के लिए एक कमीशन बिठाया जाना चाहिए कि देश में ला एण्ड आर्डर सिचुएशन क्यों दिन-ब-दिन नीचे जा रही है । हम जब भी अखबार खोलें, तो देखते हैं कि ट्रेन मे डकैती हुई, ट्रेन में लोगों का सामान छीना गया । रेलवे मन्त्री जवाब देते हैं कि ला एण्ड आर्डर प्रान्तीय मामला है, मैं उस में कुछ नहीं कर सकता, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उसमें दखल नहीं दे सकता है । लेकिन जो लोग डकैती करते हैं, जिन लोगों का सामान लूटा जाता है, जिन लोगों की हत्यायें होती हैं, जो पीटे जाते हैं, वे यह नहीं समझते हैं कि किस की जवाबदेही है । वह चाहते हैं कि उनको राहत मिले, उनकी सुरक्षा हो । दिन दहाड़े बाजारों में भी लूट हो जाती है । पुलिस खड़ी रहती है, बोलती नहीं है । क्यों नहीं बोलती है,

[श्री डी० एन० तिवारी]

वह समझती है कि वे बोलेंगे तो दस आदमी मिलकर हमें भी मारेंगे, हमें भी पीटेंगे। इसके अलावा और भी बातें होती हैं, कुछ उन को आमदनी हो जाती है, कुछ उनके हाथों में मक्खन लगाए जाते हैं इसलिए वह यह भी नही देखते हैं कि कहां जायज है कहां नाजायज है। किसी भी काम के अन्दर किसी भी देश में प्रगति नही हो सकती जब तक ला एण्ड आर्डर सिचुएशन ठीक न हो। आप देखेंगे, फैक्ट्रियों में केवल हड़ताल की वजह से काम नहीं रुकता। वहां भी अराजकता है। आप पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स में चले जाइए या कहीं जाकर देखिये कोई सिलसिला नहीं है। एकदम बे-सिलसिला बना हुआ है। तो सब से जरूरी चीज है कि आप देश को अच्छा शासन दें। मैं मानता हूं एकोनामिक डेवलपमेंट में बहुत समय लगता है। मै यह भी मानता हूँ वेलफेयर स्टेट कायम करने में आप को समय लगेगा। लेकिन आप एक अच्छा और सुदृढ़ शासन तो दे सकते हैं। यह बहुत प्रेलिमिनरी बात है इस सरकार के लिए कि देश के अन्दर शासन अच्छा हो और लोग निर्भीकता से अपना काम कर सकें। अभी एक भाई ने कहा कि हरिजनों को बूथ पर नहीं जाने दिया गया। एलेक्शन का यदि जिक्र किया जाय तो यह जान पड़ेगी कि डेमोक्रेसी खतरे में है। सभापति महोदय, आप भी एलेक्शन में गए हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से बचकर आ गए। अगर सही वोटिंग होती तो जो कुछ लोग उधर बैठे हैं वह भी नही आ सकते थे क्योंकि ऐसी लहर देश में चली थी।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उधर भी नही आता कोई।

श्री डी० एन० तिवारी : इधर तो और ज्यादा आते।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर चुनाव ठीक होते तो उधर का एक भी जीत कर नहीं आता और जो आता वह इधर बैठा होता, हम उधर बैठे होते।

श्री डी० एन० तिवारी : कहीं भी आप एलेक्शन में जाकर देखते तो एक लहर फैली हुई नजर आती जिसको रोकने के लिए बूथ कैप्चर किए जाते थे, लोगों को वोट देने जाने नही दिया जाता था। यह कमजोरी तो थी एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी पंचायतों का एलेक्शन हुआ है, उसमें क्या हुआ है ? एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी से और ला एण्ड आर्डर की कमजोरी से लोगों ने उसमें मनमानी की। लोगों ने बूथ कैप्चर कर लिए। उस में कोई पार्टी की बात नहीं थी। देश में फिजा ऐसी चल गई है...(*व्यवधान*)...

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : पचायतो के एलेक्शन में भी वह लहर दिखाई पड़ी।

श्री डी० एन० तिवारी : हम लोगों ने उस में कैंडीडेट खड़े नहीं किए।...(*व्यवधान*)... आप जानना चाहते हैं तो आप काग्रेस में रहे हैं, आप जानते है कि हमारा यह सिद्धांत है कि हम पंचायतों के एलेक्शन मे कैंडीडेट्स खड़े नहीं करते। हम चाहते है कि वह गांव वालों का एलेक्शन है, गाव वाले लड़े।

दूसरी बात यह है कि देश में जो न्याय की परिपाटी है, सिस्टम है उन को हमें बदलना है। नहीं बदलेंगे तो जैसा और भाइयों ने कहा है कभी गरीब को न्याय नही मिल सकता ; आप कचहरियों में जाइये, पांच पाच, सात-सात और दस दस वर्ष के मुकदमें पड़े हुए हैं, उनका फैसला नहीं होता है एक मुकदमा जो करता है, वह मर जाता है उसके बाद उसका फैसला कहीं हो या न हो। यह लोअर कोर्ट्स की बात नहीं है, हाइकोर्ट तक मे दस दस, बारह-बारह और तेरह-तेरह साल तक के केसेज पड़े हुए हैं, उनका फैसला नहीं हुआ। तो आप को तो

सोचना होगा कि हम जजेज को बढ़ायें या और क्या परिपाटी कायम करें जिसमें लोगों को क्विक डेसीशन मिल सके। अंग्रेजी में एक कहावत है—जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो कभी आपके मंत्रालय ने बैठ कर सोचा है कि इसको कैसे करना चाहिए? कभी यह विचार किया गया है कि कैसे तेजी से कैसेज को डिस्पोज आफ करें? एक विधवा है, खोसीस नालिश करती हैं, उसके पास खाने को नहीं है, दस वर्ष मुकदमा चला, दस वर्ष में वह क्या खाएगी, क्या करेगी, कहां रहेगी?

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन): क्या आप वकील हैं...(**व्यवधान**)...नहीं तो ऐसी कहावत है कि खीसा हो बम, जूता हो तंग और गवाह हो सग तब आता है मुकदमें में रंग।

श्री डी० एन० तिवारी: मैं वकील नहीं हूं लेकिन ऐसी बातें जानता हूं। तो इस सिस्टम को आप बदलिए।

एक और मनोवृत्ति चल पड़ी है मन्त्रालयों में भी और दूसरी जगह भी कि काम को टालते जाओ। प्राबलम्स को ग्रिप में लाकर उस का फैसला कर लें यह नहीं है, मनोवृत्ति यह हो गई है कि कुछ टाल जाय, कुछ समय मिल जाये और यह टलता रहे, इस तरह वर्षों तक टल जाता है। इसलिये मैं कहूँगा कि न्याय की परिपाटी में, न्याय की प्रणाली में कोई आमूल परिवर्तन होना चाहिये और कैसे क्विक डिस्पोजल केसेज का हो, उसके लिये क्या किया जाये, मैं कानून का पंडित नहीं, कानून में क्या सुधार किया जाये, जिसमें यह हो सके यह भी आप को सोचना है। नहीं सोचिएगा तो देश में एक बेचैनी सी है। आपके जो कारकुन हैं, काम करने वाले हैं जो कचहरियों में बैठे हैं उनका रवैया क्या है? 107 का केस आता है जिस को वह फेवर करना चाहते हैं उसको जमानत दे देते हैं, जिसको दिक करना चाहते हैं, उस की जमानत मन्जूर नहीं करते हैं। हालांकि हाई-कोर्ट का आदेश है कि 107 के केसेज में जमानत दे देनी चाहिये लेकिन दिक करने के लिये वह नहीं देते। एक एस० डी० ओ० से मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि आप क्यों ऐसा करते हैं तो वह कहने लगे कि जिन को हमें दिक करना होता हैं, जो बदमाश होते हैं उन की जमानत हम नहीं लेते हैं मैंने कहा कि यही मनोवृत्ति खराब है। दिक करना क्यों चाहते हैं? आप तो न्याय करने के काबिल नहीं हैं। अगर यही मनोवृत्ति हमारी हो कि हम दिक करें किसी को तो यह ठीक नहीं है। नहीं तो 107 में तो जमानत होनी ही चाहिये। लेकिन आप जाकर देख लीजिए जेलों में हजारों आदमी ऐसे सड़ रहे हैं। कभी किसी ने विश्लेषण किया है कि जो हाईकोर्ट का आर्डर हो गया उसके मुताबिक लोगों को न्याय मिलना चाहिये वह मिलता है या नहीं? कितने केसेज में उसकी अवहेलना हुई, इसका कोई आंकड़ा आप के पास होगा? आप मंगाकर देखेंगे तब आप उसकी व्यवस्था कर सकेंगे। आज आप के पास वह आंकड़े नहीं हैं। तो आप का मन्त्रालय करता क्या हैं? देखता क्या है यह समझ में नहीं आता।

तीसरी बात है जो अभी शिब्बन लाल सक्सेना जी ने उठाई थी—पोलिटिकल सफरर्स की बात आज हम आप जो यहां बैठे हैं उन्हीं की वजह से बैठे हैं जिन लोगों ने त्याग किया, तपस्या की। उन के उस त्याग और तपस्या की वजह से ही हम यहां बैठे हुए है। मैं यह मानता हूं कि आज बहुत से ऐसे लोग भी यहां आये हैं इधर भी और उधर भी जिनका कोई त्याग, जिनकी कोई तपस्या नहीं थी। लेकिन आपकी गवर्नमेंट को लाने में उनका हाथ है जो पोलिटिकल सफरर्स रहे हैं। अभी तक जो कुछ हुआ वह हुआ, आगे का सोचें। आपने एक नियम बना दिया कि पांच वर्ष से नीचे वाले को कोई मदद न की जाये। अगर तीन वर्ष जेल में रहता है, उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, उसके लड़कों की पढ़ाई लिखाई खत्म हो

[श्री डी० एन० तिवारी]

गई तो उसको हमें सहयोग नहीं देना है ? हम लोगों को उसे पुनर्स्थापित करने में सहयोग नहीं देना है ? तो यह पांच वर्ष चार वर्ष के माने क्या हैं ? अभी लड़ाई में कोई फौज के आदमी मर जाते हैं या उनका अंग भंग हो जाता है तो हम उसकी रिहैबिलिटेट करते हैं। आपने कितने लोगों को रिहैबिलिटेट किया, जिनके अंग भंग हो गये, जिन्होंने गोलियां खाईं, जो 8 वर्ष जेल में रहे ? क्या कोई आंकड़े आप के पास हैं ? मैं जानता हूं कि आप दो-चार सौ रुपये दे देते है। अगर होम मिनिस्ट्री में कोई प्रार्थना आती है, किसी की लड़की की शादी के लिये या कोई और यज्ञ करने के लिये तो कुछ पैसा आप उस को भेज देते हैं, लेकिन उससे उसका रिहैबिलिटेशन नहीं होता है। जिस तरह से आप सैनिकों की सहायता करते हैं, अगर उसी तरह से आप उनकी भी सहायता कर दे तो ये रिहैबिलिटेट हो सकते है।

इसी सिलसिले मे मै यह भी कहना चाहता हूं कि महगाई बहुत बढ़ गई है। गवर्नमेंट के जो पेन्शनर्स है, बाबा-आदम के जमाने मे उनके लिए पेंशन तय हो गयी थी, वही आज भी चली आ रही है। पहले जमाने मे एक एसिस्टेंट इन्स्पेक्टर 80 रुपये मासिक पर काम करता था, और उसको उस समय 40 रु० पेंशन मिलती थी तो आज भी वही चली आ रही है। आप विचार कीजिये कि उस जमाने मे 40 रु० की जो कीमत थी, उसके मुकाबले आज क्या कीमत है। इसमें आप ने कोई वृद्धि नहीं की है, क्या आप चाहते हैं कि वह भी एजीटेशन करे, वह भी आपके यहां प्रदर्शन करे आज होम मिनिस्ट्री में यह प्रवृत्ति होनी चाहिये कि जो जायज बात है, चाहे कोई प्रदर्शन करे या न करे, स्वमेव, सुमोमोटो उस को कर सकें, इससे आप को ज्यादा श्रेय मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर देश में वही आन्दोलन और अव्यवस्था चलेगी। हम बहुत सी बातों में आन्दोलनों को रोक सकते हैं, लोगों के सफरिंग्स को दूर कर सकते हैं, अगर सुओमोटो कुछ करने की कोशिश करें।

पांचवी बात—गृह मन्त्रालय की एक खास जबाबदेही यह भी है कि देश में कहीं किसी कोने में कोई अव्यवस्था या गड़बड़ी होती है—भले ही किसी भी कारण से होती है—उस के कारणों को जान कर उसको सम्बन्धित मंत्रालय से ठीक कराने की कोशिश करे। मैं मानता हूं कि कही नाजायज बातें भी हो जाती हैं किसी स्टेट के साथ या किसी क्षेत्र के साथ, लेकिन जब आप की दृष्टि में वह बात आती है तो यह नही होना चाहिये कि उसको टाला जाये कि यह तो उस मन्त्रालय का काम है। आज जरूरत इस बात की है कि आप उसमें दखल दें और सम्बन्धित मंत्रालय पर जोर डाले ताकि वह काम हो सके।

आपने एक नियम बनाया था कि लोगों की नौकरी करने की हद 55 वर्ष तक होगी, उस के बाद 58 वर्ष कर दी गई। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग 58 मे भी आगे बढ़ जाते हैं, 60-65 तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को आप कहां भेजते हैं—पब्लिक अण्डरटेकिंग में ले जाकर बैठा देते है। वे लोग समझते हैं कि हमें दो-तीन वर्ष काम करना है, अपनी एनर्जी लगा नहीं सकते हैं, उनकी कोई जबावदेही वहां नही होती है। इस तरह के सुपरेनुएटेड स्टाफ को जगह जगह भर देने की परिपाटी चल गई है। कोई सैक्रेटरी रिटायर होता है, उसको गवर्नर बना दो, कोई डिप्टी सैक्रेटरी रिटायर होता है, उसको एम्बेसेडर बना दो। अगर आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप उन से सलाह लेने के लिए, उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाने के लिए कोई बोर्ड बना दें, उनको बोर्ड में रखिए, लेकिन एक्टिव सर्विस में क्यों रखते हैं। अगर किसी को किसी खास कारण से एक्टिव सर्विस में रखना है तो उसकी जबावदेही दीजिये

उसे कहें कि यदि नियत समय में काम नहीं होगा, तो पेन्शन छीन लेंगे। किसी सुपरेनुएटेड स्टाफ को अगर आप किसी अण्डरटेकिंग में भेजेंगे और फिर 6 महीने बाद हटाना चाहेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी। जल्द-जल्द बदलने से कोई काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर रखना है तो डेढ़-दो साल का समय दीजिये और कहिये कि इस काम को करके दिखलाओं, 6 महीने बाद बदल देने से तो नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे यहां नौजवानों की कमी नहीं है, 40-50 साल की उम्र तक अच्छा ज्ञान हो जाता है, ऐसे लोगों को तरजीह दीजिये जब नेहरू जी के बिना या गांधी जी के बिना हमारा काम चल सकता है, तो क्या ऐसे अफसरों के बिना काम नहीं चल सकता—यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि सुपरेनुएटेड स्टाफ के लिए आप कोई बोर्ड बना दें। मैं इस ख्याल का नहीं हूं कि उनके ज्ञान का लाभ न उठाया जाय, लेकिन किसी ऐसे काम में उनको न भेजिये और अगर भेजते ही हैं तो दो-ढाई साल का समय दीजिये और कहिये कि इसको नहीं करोगे तो तुम्हारी पेंशन जब्त कर लेंगे।

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar) : While supporting the demands for grants of the Home Ministry, I must congratulate the Prime Minister. At no time since Independence was the Home Ministry under the Prime Minister except at the present time. The Prime Minister is the custodian of the whole country. We have all been elected only on her name. There were so many things in our election manifesto but the main question before the electorate which was posed by the political parties was : Garibi Hatao or Indiraji Hatao. That was the main slogan. Now we have been voted to power. We have been given the mandate by the people.

MR. CHAIRMAN : You may continue your speech tomorrow.

17.59 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, June 24, 1971/ Asadha 3, 1893 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj. Delhi-6.